

पर्वतीय राज्यों की राजनीति
में
भूटान

राजस्थान प्रकाशन

त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2

पर्वतीय राज्यों की राजनीति में भूटान



डॉ० आर. सी. मिश्रा

दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



1989

प्रकाशक :
राजस्थान प्रकाशन
त्रिपोलिया बाजार,
जयपुर-2

संस्करण :
प्रथम, 1989

कम्पोजिंग :
जनरल कम्पोजिंग एजेंसी
किशनपोल बाजार,
जयपुर-3

मूल्य :
65.00

मुद्रक :
मॉडर्न प्रिण्टर्स,
गोघो का रास्ता
जयपुर-3

लेखक :
डॉ. आर० सी० मिश्रा

Parvatiya Rajyon Ki Rajniti, Mein Bhutan

परम पूज्य पिताथी स्व० प्रोफेसर हुक्मचंद चतुर्वेदी को
सादर समर्पित



[जन्म 10 फरवरी 1910]

[निधन 19 अप्रैल, 1988]



PROFESSOR R.P. AGARWAL
Msc. PhD (Lucknow), PhD (London), FNASC
VICE-CHANCELLOR

UNIVERSITY OF RAJASTHAN
JAIPUR-302 004

FOREWORD

I am glad that Dr. R. C. Mishra has written this book entitled. *Bhutan and the Himalayan Kingdom. I am sure, readers will find it useful in enriching their knowledge about the economic and political scene in the above region.

JULY 1, 1988

R. P. Agarwal

***Pervatiya Rajyan Ki Rajanti, Main Bhutan**

क्रम

1.	भारत और पर्वतीय राज्य (नेपाल-भूटान सिक्किम)	
2.	भूटान आर्थिक विकास की ओर	3
3.	भूटान में राजतंत्र और उसका भविष्य	4
4.	गोरखालैंड समस्या	5
5.	सिक्किम का राजनैतिक विकास व नवीनतम आयाग	6
6.	सिक्किम में नेतृत्व का स्वरूप	9
7.	भूटान-भन्तर्राष्ट्रीय मर्चों से	11
8.	भूटान में नेपालियों की समस्या	11
9.	पूर्वांचल की समस्या	12
10.	तिब्बत और भारत	13
11.	निष्कर्ष	14
12.	परिशिष्ट 1, 2, 3	14



प्रस्तावना

भूटान के किसी पक्ष पर लिखना एक दुर्लभ कार्य है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में मुश्किल से भूटान पर कुछ प्रकाशित साहित्य मिले पाता है। जिन विशेषज्ञों ने भूटान पर लिखा है वह 1947 से पूर्व का साहित्य है। परन्तु 1947 के बाद का आज तक का साहित्य ढूँढ़ना निसन्देह एक मुश्किल प्रयास होता है।

जिन विद्वानों ने भूटान के समसामयिक पक्ष पर लिखा है चाहे राज-नीतिक, आर्थिक या सामाजिक हो, वह सब व्यवस्था में बंधकर लिखा है। भूटान में चल रहा भारत के प्रति असंतोष शायद ही कभी भारतीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित होता हो। शोधकर्त्ताओं के समक्ष एक व्यावहारिक समस्या निरन्तर रहती है कि अभूत समस्या का विश्लेषण तथा समीक्षा किस स्तर से की जाय जिससे वह व्यवस्था की भाषा से दूर भी न हो तथा सत्य भाषण का निर्वाह भी हो जाय। यद्यपि दोनों का समानान्तर रूप से निर्वाह करना निश्चित रूप से मुश्किल कार्य हो जाता है। दो-तीन विद्वान लेखकों का यहाँ जिक्र करना जरूरी होगा जिनको भारतीय सरकार द्वारा उन्हें भूटान कुछ वर्ष रहने के लिए भेजा था। उन्होंने भूटान के आर्थिक सामाजिक तथा राज-नीतिक पक्ष पर पुस्तकें प्रकाशित की परन्तु जिस पक्ष की पाठकों को निरन्तर तलाश रही उसका पूर्णतया अभाव मिला। कहने का अर्थ है कि तीनों लेखकों ने भूटान के कमजोर पक्ष का कोई जिक्र नहीं किया। चूँकि तीनों लेखक व्यवस्था के अंग थे इसलिये उन्हें केवल व्यवस्था की भाषा का ही प्रयोग करना था। एक प्रश्न उठता है कि क्या शोधकर्त्ता भी व्यवस्था का अंग बन चुका है जिसे स्पष्ट बात लिखने में हिचकिचाहट होती है। इसका उत्तर भी 'हाँ' में उभर कर आता है। शोधकर्त्ता के एक कैरियर का सवाल है। उसे भी व्यवस्था के अभिन्न अंग रहकर आगे बढ़ना है। व्यक्तिगत आकांक्षाएँ तथा व्यवस्था से सम्भावित मिलने वाले लाभों ने शोधकर्त्ता को मुक्त नहीं होने दिया है। तो फिर शोध के क्षेत्र में उतरने वाले समस्त शोधकर्त्ता शोध तो कर रहे हैं लेकिन बात वही कर रहे हैं, जो व्यवस्था चाहती है। वैसे शोध की प्रक्रिया अत्यधिक सभी बंधनों से मुक्त मानी गई है परन्तु व्यक्ति की बाहरी सीमाएँ उसे इस

तरीके से बांध देती हैं जिनसे सामान्य व्यक्ति को छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। भूटान में जाकर जो कुछ मैंने देखा है उसका प्रकाशित साहित्य से संबंध दृढ़ता सा अनुभव करता हूँ। मेरी भी सीमाएँ हैं जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ।

हिमालयी क्षेत्रों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर-पूर्वी सीमा से जुड़े पर्वतीय प्रदेश नेपाल-भूटान की आन्तरिक समस्याओं को बढ़ाने में निरन्तर सहायक रहे हैं। नेपाल में भारतीय नेपाली तथा ब्रह्मो-पति वहाँ की आर्थिक व्यवस्था के संजोने में व्यवधान बने हुए हैं, भूटान में नेपाली समस्या उत्तमोत्तम जोर पकड़ती जा रही है। भूटान में ये दो नेपाली लोग हैं जिन्होंने भूटान में जनतांत्रिक आन्दोलन 1950 से 53 तक जारी रखा था। उन्होंने भूटान स्टेट कांग्रेस दल का गठन भी किया जिस पर बाद में भूटान मजदूर ने प्रतिबन्ध लगा दिया जो आज भी लागू है। प्रतिबन्ध लगाना एक बात है परन्तु असंतोष तथा आन्तरिक विद्रोह को आज भी शान्त नहीं कर पाये हैं। जो चीज निरन्तर व्याप्त है वह है असंतोष तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के प्रति आक्रोश। वषों से चल रहा असंतोष तथा आक्रोश निश्चित ही किसी दिन उनके सपने को साकार करेगा। जनतांत्रिक आन्दोलन यदि खुले रूप में नहीं आ पाया है तो प्रच्छन्न रूप से पूरी तरह मौजूद है। अनुकूल अवसर की तलाश स्वयं में इस तथ्य को उजागर करती है कि नेपाली लोग भूटान में जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। यह कैसे कह दिया जाय कि भूटान में सब कुछ ठीक है। नेपाली लोगों को किसी भी माध्यम से दबाया जा सकता है। उनके असंतोष तथा आक्रोश को पत्र-पत्रिकाओं, में छानने से रोक सकते हैं लेकिन यदि जवाब निरन्तर धँसक रही है तो वह किसी क्षण अपना विकराल रूप अवश्य धारण करेंगी।

भूटान की राजतंत्रीय व्यवस्था के अन्दर ही दरार पैदा हो रही है। इससे सम्बन्धित एक घटना तो बहुचर्चित है जब 1964 में भूटान के शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा प्रधानमंत्री जिग्मे दोरजी की हत्या कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप समस्त 'दोरजी' परिवार के सदस्यों को देश निकाला दे दिया था तथा 'प्रधानमंत्री' के पद को समाप्त कर दिया गया था। 1964 की उक्त महत्वपूर्ण घटना के बाद कुछ वर्षें शान्ति रही लेकिन दो शाही परिवार—'दोरजी व थांगचुक' के बीच आन्तरिक वैमनस्यता समाप्त नहीं हो पाई। यही कारण है कि भूटान आज भी इस आन्तरिक संघर्ष से पीड़ित है। आर्थिक विकास तथा आधुनिकरण के हो जाने से भूटान में एक नये प्रकार का समाज उभर कर आ रहा है जिसका लगाव पारंपारिक संभ्यता की ओर बढ़ रहा है।

प्रस्तुत कृति पिछले एक दशक का परिणाम है। हिमालयी क्षेत्रों में जाने का दो तीन बार अवसर मिला और उसका उपयोग करने का भी प्रयत्न निरन्तर जारी रहा। यह कृति आंशिक रूप से अपने स्वतंत्र चिंतन या समझ का परिणाम है। किसी भी शोधकार्य में उससे जुड़ी हुई उसकी शोध पद्धति बहुत महत्वपूर्ण होती है। कभी-कभी शोध प्रक्रिया में एक द्वन्द्व उठ खड़ा होता है वह यह कि किस स्रोत पर अपनी विश्वसनीयता निर्भर रखें—लिखित साहित्य पर या जो स्वयं की आँखें देख रही हैं। हिमालयी क्षेत्र के विशेषज्ञ Leo Rose ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि, "At times unpublished part of literature becomes more important and relevant than the published documents." इस वाक्य में भाव यही है कि शोधकार्य की प्रक्रिया में यदि स्वयं के नेत्रों में तटस्थ भाव रखने की ताकत है और उनमें अतिरिक्त भावना को दवाने की क्षमता है तो वह दृष्टि लिखित व प्रकाशित साहित्य से ज्यादा विश्वसनीयता रखेगी। आज के शोध कार्य में आम तौर से यह कहा जाता है कि अमुक लेखक ने यह मार्क्सवादी विचारधारा को साथ में रखकर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं या अमुक लेखक के विचार दक्षिणपंथी हैं। कहने का अर्थ है कि यदि शोधकार्य की प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की विचारधारा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी तो उस बौद्धिक कृति में तटस्थ दृष्टि का अभाव हुए बिना नहीं रहेगा। यदि समस्त तथ्यांकित विचारधाराओं का अनुकूल तथा परिस्थिति के अनुसार प्रयोग होगा तो शोधकार्य में निश्चित सन्तुलित दृष्टि होगी। यह सब कुछ मुझे इसलिये लिखना पड़ा कि जो कुछ भी मैंने अपने नेत्रों से हिमालयी क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति देखी है उसके ठीक विपरीत प्रकाशित साहित्य में पढ़ने को मिला है। मेरी आपत्ति सबसे पहले उस शोध पद्धति पर है जिसे लगभग गणितीय बना दिया गया है। शोध पद्धति में Questionnaire या Interviews की पद्धति का जो व्यावहारिक स्वरूप अपनाया गया है वह अत्यधिक यांत्रिक हो गया है। दोनों ही पद्धति में यांत्रिकता आ जाने के कारण उसके परिणामों में भी विश्वसनीयता घटती जा रही है। एक और अतिरिक्त विशेषता का होना आवश्यक है वह यह कि शोध कार्य के प्रति शोधकर्ता का दृष्टिकोण। यदि शोधकर्ता का दृष्टिकोण 'शोध समस्या' के प्रति उदासीन है या भारयुक्त है या उससे जल्दी से जल्दी मुक्त होने का भाव है ऐसी स्थिति में औपचारिक दृष्टि से तो उस कार्य को मान्यता मिल जायेगी लेकिन गुणात्मक पक्ष खोखला ही रह जायेगा।

भूटान दो बार गया। भूटान से सगी हुई सीमा जलपायगुडी, नई जलपायगुडी, सिलीगुडी, दार्जिलिंग तथा कलिमपोंग है और दूसरी ओर सिक्किम है। सिक्किम भी औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही दृष्टि से हो आया है। भूटान पर प्रकाशित साहित्य ने मेरी देखी हुई आँखों को झुठला सा दिया है। भारत-भूटान के संबंध कैसे हैं? भारत की हिमालयी नीति क्या रही है? भूटान तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में आपसी संबंध कैसे हैं? क्या समस्त पर्वतीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धा में जो रहे हैं या उनमें एकता की संसक है? समस्त पर्वतीय क्षेत्रों का भारत के बारे में क्या सोचना है? क्या भारत की हिमालयी नीति में कोई एकरूपता थी या उस नीति में अक्रामक या उपनिवेशवाद की गंध निरन्तर रही? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ता हुआ असंतोष एक यथार्थ है या उनमें माँगों की पूर्ति करवाने की नाटकीय शैली है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने का पुस्तक में प्रयास किया गया है।

लेखक कोई निर्णयात्मक दावा नहीं करता कि उसकी दृष्टि में पूर्ण तटस्थ भाव रहा है परन्तु तटस्थ भाव को निरन्तर रखने का प्रयास अवश्य किया है।

लेखक का यह मानना है कि भारत की भूमिका पर्वतीय क्षेत्रों में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी तथा समस्त पर्वतीय क्षेत्र चाहे वह नेपाल हो या भूटान सिक्किम-एकता के सूत्र में नहीं बंध पायेंगे और आपस में निरन्तर प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ही उनकी एकता के भाव को तोड़ती रहेगी जिससे भारत पर दबाव कम होगा।

प्रस्तुत कृति में घड़ी-घड़ी यान्त्रिक रूप से 'फुटनोट' लगाने की शैली को प्रोत्साहन नहीं मिला है। मेरी शैली अपनी समझ से हटकर है उसकी समीक्षा या आलोचना को स्वीकार करने का पहले से ही मानस है।

पुस्तक का प्रत्येक अध्याय अपनी अपनी स्वतंत्र समस्या का विश्लेषण करता हुआ समग्र क्षेत्रीय घटनाओं से अवश्य जोड़ता है। उत्तरांचल की समस्या भिन्न प्रकार की होते हुए एक मूल प्रश्न में अवश्य जोड़ती है कि पूर्वांचल के समस्त राज्यों के बीच पारस्परिक सीमा विवाद एक स्थायी पथार्थ होने के कारण औपचारिक पूर्वांचल लोक परिषद उसे एकता के सूत्र में बाँध नहीं पायेंगे। पारस्परिक विश्वास निरन्तर है उसका लाभ केन्द्र को मिलता रहेगा। इसी प्रकार GNLF की माँग में दिखने वाली एकता में दूरार स्पष्ट दिखाई देने लगी है। एकता के नाम पर मंच बनाना तथा मंच पर ऊँचे स्वर में बोलने से एकता नहीं होती। एकता का साकार रूप पार-

स्पर्शिक हितों के त्याग से होता है, झपटने से नहीं। आज दक्षिण एशिया के समस्त राष्ट्रों में विरोधी पक्ष क्यों कमजोर दिखाई देता है? कारण स्पष्ट हैं। एक दल में अंतःविवाद तथा विरोध इतने घर कर गये हैं कि उनमें सही रूप से एकता नहीं आ सकती जिसके परिणामस्वरूप सत्तापक्ष को उससे ओर भी बल मिलता है। यही स्थिति भारत में भी है। किसी भी विरोधी दल को लीजिये। चाहे वह जनता पार्टी हो या लोकदल (अ या ब)। चाहे तेलगूदेशम हो या ADMK। व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, संस्था नहीं। चरण-सिंह के चले जाने मात्र से ही संस्था टूट गई। रामचन्द्रन के निधन के तुरन्त बाद ADMK का हाल जो दिखाई दिया, उसका जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। जनतापार्टी में चंद्रशेखर या हेगडे ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में विरोधी पक्ष की अत्यधिक दुर्बल पक्ष ने सैनिक व्यवस्था को और मजबूत किया है। बांग्लादेश में जनरल इरशाद चुनाव कराने के बाद भी मन में यही भाव लिए हुए हैं कि विरोधी पक्ष में यदि पारस्परिक दरार नहीं होती तो क्या वे चुनाव में सफल हो पाते? नेपाल भूटान में यद्यपि राजतंत्रीय व्यवस्था होते हुए भी आंशिक रूप से जनतान्त्रिक व्यवस्था का आवरण है। दोनों ही पर्वतीय राष्ट्रों में विरोधी पक्ष सक्षम न होने के कारण राजतंत्रीय व्यवस्था को कम चुनौती है। श्रीलंका भी इसी रोग से पीड़ित है। वास्तविक दृष्टि से तो उस समय श्रीलंका में समस्या पैदा होगी जब तथ्यांकित 70% सिधली समुदाय की एकता में पहले से ही अंतःविवाद खुले रूप में आयेगा पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के बारे में भी यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों ही राष्ट्रों में सैनिक शासन अभी समाप्त होगा जब सैनिक प्रशासन के सत्ता पक्ष में अंतःविरोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचेगा।

उक्त सैद्धान्तिक पक्ष के आधार पर पुस्तक में एक तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास है कि समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में पारस्परिक विवाद पहले से ही मौजूद होने के कारण भारत पर किसी भी मंच से दबाव तो डाल सकते हैं लेकिन दबाव डालने की क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकते। भूटान ने 1980 के बाद से अपनी स्वयं की पहिचान का निर्माण किया है। अपनी विदेश नीति में भी सामान्य स्वरूप से हटकर परिवर्तन प्रस्तुत किये हैं। भूटान के अन्तराष्ट्रीय व्यवहार को देखकर यह लगने लगा है कि वह भारत के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल रहा है। साथ में विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भूटान ने नेपाल के रवैये को अपनाया है और नेपाल व भूटान एक मिलकर भारत पर किसी भी रूप में दबाव को बढ़ा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर बोट

के माध्यम से या अपनी अभिव्यक्तियों के जरिये उनमें तथाकथित एकता दिखाई दे लेकिन यथार्थ दृष्टि से उनमें निकटता आना संभव नहीं। नेपाल भूटान के बीच पारस्परिक स्पर्धा का भाव उन्हें निकट नहीं आने देगा।

जब गोरखालैंड की समस्या 1979 से शुरू हुई तो यह कहा जाता था कि पर्वतीय क्षेत्रों के सभी नेपाली समुदाय एकजुट कर नारा बुन्द करेंगे अपनी मांग की पूर्ति करवाने में सफल होंगे। लेकिन बाद में वह तथाकथित एकता धीरे धीरे टूटती गई और आज सुभाष चौसिम अपने ही समुदाय में अकेले पड़ गये।

प्रस्तुत कृति पूर्ण है या अपूर्ण, सार्थक है या निरर्थक, उपयोगी है या अनुपयोगी इस सब का निर्णय विषय से सम्बन्धित विद्वानों पर छोड़ रहा हूँ। जैसा समझ में आया उसको ज्यों का त्यों रख दिया है। हिन्दी भाषा को सरल तथा प्रचलित या बोलचाल की शैली में ही लिखने का प्रयास किया है। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द भी बीच बीच में आ गये हैं वह एक सहज अभिव्यक्ति का सूचक है।

जिन लोगों का सहारा मिला, उनको बिना औपचारिकता अपनाये अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना एक कर्तव्य समझता हूँ। सबसे पहले जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र से मैं 1975 से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें रहकर बौद्धिक कार्य निरन्तर करने का अवसर मिला। यह वह शोध संस्थान है जिसमें निरन्तर दक्षिण एशिया से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार विमर्श होते रहते हैं जिनको सुनकर हर जिज्ञासी अपने आपको शिक्षित हो सकता है। मैं समस्त रिसर्च स्टाफ के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सम्पर्क से ज्ञानवर्धन का अवसर मिल सका। मैं संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर इकबाल नारायण तथा वर्तमान निदेशक प्रोफेसर रमाकान्त के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझे दो बार भूटान तथा सिक्किम के लिए फील्ड ट्रिप करने का भोका दिया। परिवार एक ऐसी संस्था है जिससे व्यक्ति पहले सीखना प्रारम्भ करता है। परिवार का अर्थ है माता पिता जिनके सानिध्य में सभी अच्छी बातें सीखने की मिलती हैं। आज जब समाज की गति भोगवाद तथा सुखदवाद की ओर तेजी से बढ़ रही है तथा पढ़ने का लिखने का रुझान या दृष्टिकोण बौद्धिक क्षेत्रों से ही लोप होता जा रहा है उस स्थिति में भी यदि कुछ पढ़ने लिखने की रुचि शेष है उसे मैं परिवार के संस्कार की देन समझता हूँ। परिवार में

माता-पिता के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनसे मेरा निरन्तर विमर्श होता रहा है चाहे विषय सामाजिक हो या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय । निरन्तर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया ने मुझे अधिक शिक्षित किया है । इसके लिए डॉ. सुरेश मिश्रा (भाई) अध्यक्ष इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर डॉ. आर. एन. चतुर्वेदी, डा. उमेश चतुर्वेदी (रीडर-इतिहास विभाग-राजस्थान वि. वि. जयपुर) डा. आर. एस मिश्रा (इतिहास विभाग-राज. वि. वि. जयपुर) के योगदान महत्वपूर्ण हैं ।

भावनात्मक दृष्टि से निरन्तर जीवट बनाये रखने के प्रयास में मेरे सबसे छोटे चाचाजी श्री धर्मगोपाल चतुर्वेदी (एडवोकेट) भरतपुर के प्रति ऋणी हूँ बिबके सहज तथा सरल व्यवहार से एक अलौकिक प्रेरणा मिलती रही है ।

लेखक डा० आर. के. वशिष्ठ (वरिष्ठ प्राध्यापक फ़ैकल्टी ऑफ़ फ़ाइन आर्ट्स) राज. वि. वि. जयपुर) के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने बार-बार आप्रह्व कर हिन्दी पांडुलिपि को उचित प्रकाशक तक पहुँचाने में मदद की ।

—आर. सी. एम.

भारत और पर्वतीय राज्य (नेपाल-भूटान-सिक्किम)

अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर दो राष्ट्रों के संबंधों का विश्लेषण कई स्तरों पर करने के बाद ही निकटतम सही तस्वीर सामने आती है। लौकिक दृष्टि से जिन संबंधों की चर्चा होती है उनको किन्हीं मापदंडों को आधार रख कर पारस्परिक संबंध अच्छे-बुरे या ठीक-ठीक घोषित कर दिये जाते हैं। पर अकेले लौकिक दृष्टिकोण कभी-कभी पर्याप्त नहीं होते। उससे हट कर एक अलग दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसका प्रयोग कम ही किया जाता है। अच्छे या बुरे संबंध का निर्णय केवल निश्चित मापदंडों के आधार पर नहीं हो सकता। यदि दार्शनिक दृष्टिकोण भी हमेशा लौकिक दृष्टिकोण के साथ चले तो निर्णय एक दम सही न हो परन्तु निकटतम सही बैठ सकता है तथा संबंधों की भावी प्रवृत्ति के बारे में पता लगता है। जो प्रत्यक्ष नहीं है और कई वर्षों तक उसके बारे में भालूम भी न हो लेकिन भविष्य में उस अदृष्ट प्रवृत्ति के बारे में सोच भी लिया जाय तो वह दार्शनिक दृष्टिकोण की परिधि में आ जाता है।

1947 से आज तक यह कहते आ रहे हैं कि भारत के साथ भूटान के संबंध अच्छे हैं और मधुर हैं तथा भारत ने भूटान के विकास में पर्याप्त मदद दी है, और ऐसा भी लगता है क्योंकि ऐसे कोई लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति सामने नहीं आई जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भूटान के भारत के साथ कटु संबंध है या अच्छे नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में कुछ निश्चित मापदंडों ने संबंधों की व्याख्या कुछ इस-प्रकार की है जिससे एक दूसरे से संबंध अच्छे और बुरे सुनाई पड़ते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि क्या मे अच्छे या क्या में

सामान्य होना कोई ऐसी दृष्टि प्रदान नहीं करता जो दो राष्ट्रों की परिपक्वता जाहिर कर सके। यह ठीक है कि मित्रता या दुश्मनी स्थायी नहीं होती—राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं। यदि राष्ट्रीय हित भी समय के अनुसार घड़ी-घड़ी बदलते रहे तो एक स्थायी आधार भी निर्माण करने का डगमगा जाता है। जब कोई देश राष्ट्रीय हितों को निरन्तर इस प्रकार से प्रस्तुत करता रहे जो संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास हमेशा संकट में पड़ जाय—वह स्थिति अधिक शोभनीय नहीं होती।

आज आतंकवाद-हिंसा, युद्ध का और छुट-पुट दौर तथा पारस्परिक भय-संदेह की भावना का होना किस चीज के परिचायक है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक एक भूख सब जगह व्याप्त है—वह यह कि हर देश की अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाएँ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। छोटे से छोटा देश भी उन आर्थिक तथा राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति में लगा है जिसके फलस्वरूप स्वयं के देश में न राजनीतिक स्थायित्व है और न आर्थिक विकास। सभी विकासशील देश अपनी आंतरिक अशान्ति तथा तनाव से पीड़ित तो पहले से ही हैं और दूसरी ओर अन्य देशों से भी मन मुटाव-ट्रेप तथा संघर्ष को निमग्न हो दे तो उस देश का दुहरा दुर्भाग्य है। यह बात केवल उन विकासशील देशों के बारे में कही जा रही है जो अपने देश का एक ओर आर्थिक विकास चाहते हैं और दूसरी ओर अशान्ति के लिये उन भागों को अपना रहे हैं जिसमें आने वाले दिन युद्ध के लिये स्वयमेव खींच ले जायेंगे। यदि दक्षिण एशिया के देशों की गणना करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगला देश प्रमुख सामने आते हैं। तीनों ही देशों में राजनीतिक स्थिरता नहीं कही जा सकती। अपने देश में अशान्ति के कारण, आर्थिक विकास रुका हुआ लगता है लेकिन विदेश नीति का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत कर रखा है जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल लगता है।

भूटान एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जिसको भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निरन्तर संघर्ष करना पड़ा। 1947 से पूर्व अंग्रेजों की नीति भूटान के प्रति इस प्रकार की रही जिसमें चीन को भूटान पर प्रभाव बढ़ाने से रोकना और अपने प्रभाव को निरन्तर बढ़ाना। 1910 की संधि यह स्पष्ट करती है कि अंग्रेजों की नीति चीन के प्रभाव को बढ़ने से रोकने की रही है। 1910 की संधि ने पहली बार भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे को अर्ध सार्वभौमिक राज्य के रूप में बदल दिया। 8वीं धारा भूटान के दर्जे को पहले से कम करता है। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के साथ संधि की

बात घाई तो भूटान के प्रशासकों का आग्रह रहा कि भूटान को किसी भी प्रकार से संधि से न बांधा जाय। लेकिन संयोग और परिस्थितियाँ पुनः इस प्रकार की बढ़ी जिसके अन्तर्गत 1949 की संधि में धारा दो का जुड़ जाना उसके सार्वभौमिक सत्ता को झकझोरने वाला था। 1949 की संधि को अन्तिम रूप देने में 2½ वर्ष लगे लेकिन भूटान अपनी इच्छा की पूर्ति न कर पाया जो उसे भारत सरकार से अपेक्षा की। इतिहास की महत्वपूर्ण घटना यही की विशेष कर भूटान के प्रशासकों के लिये। भूटान सरकार नहीं चाहती थी कि संधि में किसी प्रकार से धारा 2 को जोड़ा जाय। किसी स्वतंत्र राष्ट्र पर किसी भी माध्यम से प्रतिबन्ध लगाना, चाहे उसकी औपचारिकता का अर्थ कुछ भी लिया जाय, एक प्रकार से उपनिवेष्ट-वाद की गंध आती है। यह बात दूसरी है कि भारत का राष्ट्रीय हित इसमें क्या था? भूटान एक छोटा, गरीब, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा तथा शान्ति प्रिय देश के साथ एक बड़े देश का व्यवहार क्या होना चाहिये इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दृष्टिकोण यह अवश्य उभर कर आता है कि भूटान तब से भारत के प्रति दृष्टिकोण तथा मत क्या बना होगा—यह किसी से छुपा भी नहीं है। यदि भूटान को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो भारतीय कूटनीतिज्ञ भारत सरकार की आलोचना करते और राष्ट्रवाद की दुहाई देते। यह कौसी विडम्बना है कि एक राष्ट्र की दृष्टि से वह ठीक है लेकिन दूसरे राष्ट्र की दृष्टि से वही बात एक दम गलत मानी जाती है। भारत-भूटान संबंधों का विश्लेषण भी इसी परिधि के अन्तर्गत कर सकते हैं। 1949 से भूटान का भारत के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण न रखना अच्छे संबंधों का परिचायक नहीं है। किसी देश की मजबूरी का लाभ लेना किसी भी मापदंड से सही नहीं है। ऐसा ही कुछ भूटान के माथ घटित हुआ। भूटान ने दबी जवान से हमेशा संधि के बारे में आलोचना की है और भारत की नीति को शोभनीय नहीं माना। इस प्रकार की स्थिति को किन शब्दों में स्वीकार किया जाय और कैसे भारत-भूटान के अच्छे संबंधों को आत्मसात किया जाय। यह माना कि भारत सरकार ने तब से आज तक संधि के माध्यम से प्रतिबन्ध की कीमत कितनी चुका दी होगी यह बात भी किसी से छुपी नहीं। लेकिन तथ्य तो यह स्पष्ट करता है कि बड़े देश ने छोटे देश की मजबूरियों का लाभ लिया। एक कूटनीतिज्ञ दृष्टिकोण से परीक्षण करें तो सभी यही कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जो कुछ हुआ ठीक हुआ। इन सब के होते हुए भी क्या भूटान का दृष्टिकोण बदल पायेगा—एक प्रश्न चिन्ह है।

भारत की पर्वतीय राज्यों के प्रति नीति : एक पक्ष

वैसे तो विद्वानों ने भारत की पर्वतीय राज्यों के प्रति नीति के बारे में कई मत व्यक्त किये हैं लेकिन उनमें कुछ महत्वपूर्ण मतों को प्रस्तुत करना और उसका सही विश्लेषण की प्रक्रिया स्वयं में एक सार्थक कार्य है। एक दृष्टिकोण जो सामने आया है वह भारत विरोधी तो है लेकिन उसके पक्ष में तर्क कुछ प्रासांगिक है तो उन्हें ग्रहण अवश्य करना चाहिये। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत जो बाहरी देश के तीन सौ वर्ष अधीन रहा उसने उपनिवेशवाद की नीति को विभिन्न पर्वतीय राज्यों के साथ संधियों को दुहरा कर उस आधिपत्य की भावना को क्यों और कैसे संतुष्ट किया? भारत की नीति सैद्धान्तिक दृष्टि से कुछ भी और कंसी भी नैतिकता युक्त है लेकिन उसका व्यावहारिक पक्ष अंग्रेजों की नीति से समतुल्य माना जा सकता है। आवरण में आधिपत्य रहा आये यह भारत की नीति का भ्रम रहा है। नेपाल, भूटान तथा सिक्किम के साथ अलग-अलग संधियों की प्रकृति तथा स्वरूप इस तर्क की पुष्टि करते हैं कि भारत की प्रछन्न आकांक्षा वही बनी रही जिसके 1947 से पूर्व हम आलोचक थे। भारत की स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय छवि एक मध्यम शक्ति के रूप में उभरी यद्यपि भारत के सामने आन्तरिक तथा बाह्य दिक्कतें हमेशा बनी रही। भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों के कारण पर्वतीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। भारत का सर्वोपरि राष्ट्रीय हित स्वयं की सुरक्षा। तीनों पर्वतीय राज्यों से भौगोलिक दृष्टि से जुड़ा हुआ चीन ही महत्वपूर्ण तत्व रहा जिसके कारण अंग्रेजों की नीति को लगभग ज्यों का त्यों अपना लिया गया। यह प्रश्न भूटान के दृष्टिकोण या अन्य पर्वतीय राज्यों के दृष्टिकोण से अभी भी बना हुआ है कि भारत जैसा जनतांत्रिक देश जिसने बड़े संघर्ष के साथ विदेशी शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त की—उसने वैसा व्यवहार करना क्यों उचित समझा जो कोई उपनिवेश भावना से कोई देश करता है। यहाँ यह प्रश्न आकर ठहर जाता है और उसका उत्तर मिलना कठिन भी है। दो देश के राष्ट्रीय हितों के बीच टकराहट हो तो एक सीधा हल निकलना तो मुश्किल है। यह बात दूसरी है कि सामान्य संबंधों को रत्न के लिये अन्य विकल्प की तलाश हो। 1947 से और आज तक प्रमुख राष्ट्रीय हित में भारत-भूटान के बीच टकराहट रही है। संधि 1949 की धारा दो भूटान के लिये उस समय भी आपत्तिजनक थी जब संधि पर हस्ताक्षर किये थे और आज भी। ज्यों-ज्यों भूटान अपनी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति उत्तरोत्तर कर

रहा है उसी गति से धारा दो उनके जिये अखरने वाली है। पर्वतीय राज्यों को मजबूरन उसी व्यवहार को अपनाना पड़ा जो भारत के उद्देश्य तथा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले थे। भारत की सन्नहित कमजोरियाँ दो प्रकार से सामने आईं। एक तो पर्वतीय नीति में विप्रमत्ताएँ थी और दूसरी चीन से निरन्तर शंका तथा भय। पर्वतीय राज्यों के लिये मुख्य देश भारत ही रह गया जिनके साथ अलग-अलग संधियाँ की और उन शर्तों से बंध गये जो उसमें उल्लेख है। नेपाल-भूटान-सिक्किम तीनों ही अपने-अपने तरीके से भारत के साथ नियंत्रित हो गये जो उनकी मजबूरी थी लेकिन स्वेच्छा नहीं। यदि न्यायसंगत होकर और तटस्थ होकर भारत के किसी नागरिक या सरकारी अधिकारी वर्ग से यह पूछा जाय कि जो कुछ पर्वतीय राज्यों के साथ राजनीतिक समझौते हुए (जिनको संधियों की संज्ञा दी गई है) वे क्या न्याय युक्त थे। तो शायद उत्तर यही मिलेगा कि विभिन्न राज्यों की तत्कालीन परिस्थिति की विवशता का अनुचित लाभ लिया गया। यह बात दूसरी है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक पक्ष भारत की ओर ही झुक जायेंगे क्योंकि राजनीति में नैतिकता की संज्ञा राष्ट्रीय हित है। लेकिन यह पक्ष या दृष्टिकोण समस्त पर्वतीय राज्यों की ओर से है और आज जो नेपाल व भूटान का उठता हुआ असंतोष व निराशा जो भारत के प्रति शुरू हुई है उसी का परिणाम है। नेपाल के साथ 1950 में की गई संधि का व्यावहारिक पक्ष इतनी संकीर्ण अवधि के बाद जो उभर कर आया है वह यह कि आर्थिक क्षेत्र में नेपाल भारत के व्यापारियों के हाथों में नियंत्रित है। भारत से पहुँचे बुजुर्ग व वहाँ के स्थानीय बुजुर्गों पर हावी हैं और उनको स्वतंत्र रूप से पनपने का अवसर प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। गोरखालैंड की समस्या भी आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई है।

1949 या 1980 की संधियों के बाद से भारत का नेपाल या भूटान पर आधिपत्य या नियंत्रण चतुराई पूर्ण नीतियों के कारण बढ़ा है। जब कभी भी नेपाल ने अपनी सीमा के अतिरिक्त स्वतंत्रता को उभारने का प्रयत्न किया है तो भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की परिधि के अन्तर्गत, ने उस पर नियंत्रण किया है।

दक्षिण एशिया में भारत का वर्चस्व कम न हो इस दिशा में निरन्तर प्रयास किया है। इस तथ्य में मुँह नहीं मोड़ सकते कि भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के राजनितिक स्थानीय अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने

का भरमसाक्त प्रयत्न किया है। भारत की स्वयं की इच्छा रही है कि विश्व उसे एक शक्ति के रूप में पहिचाने या मान्यता दे। इस भावना की पूर्ति पहली बार उस समय हुई जब भारत-पाक युद्ध (1965) के समझौते के लिये ताशकंद वार्ता हुई और रूस ने भारत की शक्ति को स्वीकार किया। उसके बाद अमरीका ने भारत के प्रभाव तथा प्रभावी भूमिका को राष्ट्रपति कार्टर ने मान्यता दी।

मह कहना कि भारत की पर्वतीय नीति में एकसूत्रता थी—इस कथन में सत्यता नहीं है, वरन् भारत की नीति को 'टुकड़ों' की संज्ञा दी जाय तो अधिक ठीक होगा। भारत की प्रारम्भ से नीति का स्वरूप इस प्रकार का रहा जिसके अन्तर्गत समस्त हिमालयी राज्य अलग-अलग तरीके से भारत की ओर निर्भरता भरी निराहों से देखते रहे। इसके पीछे एकमात्र यही इच्छा तथा उद्देश्य रहा है कि भारत के प्रतिरिक्त कोई और बड़ा देश उक्त पर्वतीय राज्यों पर प्रभाव रखने की नियत से भागे न बढ़े। अलग-अलग तरीके से संपर्क रखने की नीति ने पर्वतीय राज्यों के बीच एक संगठित दृष्टिकोण को उभरने के लिये कोई अवसर ही नहीं छोड़ा। भूटान-नेपाल के दर्जे को प्राप्त करने की शिकायत करता रहा और सिक्किम की शिकायत भूटान के दर्जे को प्राप्त करने की रही। सिक्किम का भारत में विलय भी निःसंदेह इसी कारण हुआ। यह बात दूसरी है कि परिस्थितियाँ कंती थी और राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण क्या था है। उक्त नीति के आधार पर भारत पर्वतीय राज्यों पर येन-केन-प्रकारेण अपना प्रभाव रखता रहा। भारत की सुरक्षा के परिधि में पर्वतीय नीति चलती रही।

पृष्ठभूमि—भारत की पर्वतीय नीति को समझने के लिये इतिहास के कुछ पन्नों पर नजर डालनी होगी। विशेष रूप से अंग्रेजों की एक पत्नी दृष्टि का भी विश्लेषण करना आवश्यक है। 18वीं शताब्दी से नेपाल, भूटान तथा सिक्किम ने बफर स्टेट की भूमिका अदा की है। चक्र की स्थिति कुल मिलाकर अधिक शोचनीय होती है। दो देशों के बीच फसे पर्वतीय राज्यों का मनोवैज्ञानिक भय तथा शंका का हो जाना भी कोई आश्चर्य नहीं। नेपाल की 'शान्ति का क्षेत्र' मांग में अंशतः सौचित्य है और भूटान की निरन्तर मांग यही है कि 1949 की संधि में उचित संशोधन किया जाय। सिक्किम ने तो अपनी मांग का आग्रह कर परिणाम भुगत लिया है। जो हो गया उसको चर्चा करना ही ध्येय है लेकिन मांग के रखने का परिणाम

सिक्किम के विरुद्ध गया। यहाँ प्रश्न इतना ही है कि अंग्रेजों के द्वारा अलग-अलग की गई संधियों को 1947 के बाद भारत ने उन प्रावधानों को ज्यों का ज्यों रखना क्यों उचित समझा? कम से कम पर्वतीय राज्यों का दृष्टिकोण निसंदेह भारत के दृष्टिकोण से एकदम विपरीत है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में एक तीसरी शक्ति के निर्माण करने का प्रयास किया। भारतीय राजनीति में तीसरी शक्ति के निर्माण का विचार केवल इसलिए था जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन सफलता की मंजिल को प्राप्त न कर सके। भारत में अंग्रेजों द्वारा Princely States का प्रावधान एक तीसरी शक्ति ही थी जिससे रियासती सभी नरेश अंग्रेजों को समर्थन देते रहें और आन्दोलन में बिखराव आ जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर एक आक्रमक तपका उभर कर आया जिसका मत था कि 'Native States' में एक क्रान्तिकारी कार्यवाही हो जिससे आन्दोलन एकता के सूत्र में बंधा रहे। लोकप्रिय राष्ट्रवादी विचारधारा, जो कि कानूनी बारीकियों से तनिक भी भिन्न नहीं थे, यही थी कि 'भूटान, नेपाल, काश्मीर तथा सिक्किम' सभी Native States हैं जिनको भारत में सम्मिलित करना अनुचित नहीं होगा। राष्ट्रवादी विचारधारा एक विशाल भारत के निर्माण की बात सोचने लगा जो अफगानिस्तान से बर्मा तथा हिमालय से कन्याकुमारी की समस्त भूमिखंड भारत में मिला ली जाय। इस प्रकार के विभिन्न मत सामने आते रहे और वह दिन भी आया जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ।

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद भारत सरकार ने पर्वतीय राज्यों से समझौता लगभग उसी प्रकार का किया जो अंग्रेजों ने किया था। विभिन्न संधियों का स्वरूप वही रहा और एक बार फिर से तीनों पर्वतीय राज्य भारत से किसी न किसी प्रकार प्रतिबन्धित हो गये। जब भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेजी शासक भारतीयों के हाथों में बागडोर थमा रहे थे। उस समय पर्वतीय राज्यों का भविष्य भी उसमें सन्नहित था। उस समय नेपाल, भूटान तथा सिक्किम के प्रजासकों ने अपनी सार्वभौमिकता को सुदृढ़ रखने की मांग की और अपने दजों को कायम रखने के लिये बाहरी देशों से संरक्षणता लेने की भी चेतावनी दी। नेपाल व भूटान दोनों देशों ने इससे सम्बन्धित मसले को लेकर चीन से भी गंभीर किया। नेपालने अपने अस्तित्व को उभारने के उद्देश्य से अमेरिका से कूटनीतिक संबन्ध स्थापित कर लिये। 1947 में पहली एशियायी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। नेहरूजी ने नेपाल व भूटान

दोनों को ग्राम सम्मेलन में शामिल होने के लिये आमन्त्रित किया था। दोनों ने ही इस अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से विदेशी शिष्टमंडल सपर्क किये और उनसे अपनी समस्या को सामने रखा परन्तु इस प्रकार की चर्चाओं को कोई लाभ न मिल सका।

भारत की पर्वतीय राज्यों के प्रति नीति का निरन्तर एक ही दृष्टिकोण सर्वोपरि रहा कि विरासत में लिया गया प्रभुत्व समाप्त नहीं करना है। ठीक इसके विपरीत, नेपाल व भूटान का सतत यही प्रयत्न रहा कि अपने अस्तित्व को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा हासिल करना है। इस अभियान में सिक्किम शामिल नहीं हो पाया। जब उसने प्रयास किया तो परिणाम सामने आ गया (1974 में सिक्किम का भारत में विलय)।

भारत की नीति भी यही रही कि पर्वतीय राज्यों पर अपना प्रभुत्व कम नहीं करना है। यद्यपि दूसरी ओर से प्रयासों को विफल करने के प्रयत्न बराबर जारी रहे। अपनी सार्वभौमिक स्वतन्त्रता को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उभारने के प्रयासों में धीरे-धीरे सफलता की झलक मिलने लगी विशेष रूप से 1960 के बाद जब भारत-चीन के संबंध कटु होते होते युद्ध में परिवर्तित हो गया। 1962 के युद्ध के दौरान तीनों पर्वतीय राज्यों ने भारत की कमजोरी का अधिकतम लाभ लेने का प्रयास किया। उन क्षणों में साफ जाहिर होने लगा कि भारत का प्रभाव पर्वतीय राज्यों पर धीरे-धीरे कम हो रहा है।

ग्राम तीर से कहा जाता रहा है कि पर्वतीय राज्यों ने 1962 के चीन के साथ युद्ध के दौरान अधिकतम लाभ भारत से लेने की कोशिश की और कोशिश में कामयाब भी रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सहायता से भी भारत ने परिस्थितियों के दबाव में पर्वतीय राज्यों को विवशता में रियायतें दी हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है कि बिना बाहरी सहायता लिये नेपाल-भूटान को अपने अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व को आगे लाने में जब तब सफलता मिली है। पर्वतीय राज्यों को अपने अस्तित्व की पूर्ण सुरक्षा के कभी-कभी विभिन्न चतुराईयां या रास्तों को अपनाना पड़ा है। उनमें से एक रास्ता तो यह रहा है कि वे अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करें या बाहरी देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करना या कुछ महत्वपूर्ण अवसरों (यानी राज्याभिषेक) पर बड़ी शक्तियों के सामने कुछ इस प्रकार का आयोजन करना जिसमें उनका अलग ही व्यक्तित्व भले के आदि या अपने देश की भलग से टिकिट जारी करना अपने देश का वक्त भारत

के समय से १/२ घंटा आगे पीछे कर देना अथवा भारतीय माल को प्रोत्साहन न देकर दूसरे देशों के माल का आयात करना। उक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि पर्वतीय राज्यों ने 1962 के बाद से इस प्रकार की तरकीबें निकाली जिससे उनका दया हुआ व्यक्तित्व ऊपर उठ कर आये। नेपाल ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये प्रार्थना की थी और वास्तविक रूप से सदस्यता 1955 में मिली। भूटान को सदस्यता 1971 में मिली, जबकि विश्वसनीय स्रोतों से यह जानकारी दी गई कि 1966 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गुप्त रूप से वायदा कर लिया था। भूटान ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाये जो उसकी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला था। भूटान कोलंबो योजना का सदस्य बना, अन्तर्राष्ट्रीय डाक संघ का सदस्य बना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों का भी सदस्य बना। यहाँ तक कि सिक्किम भी नेपाल-भूटान का अनुकरण करने में नहीं चूका यद्यपि उसका दर्जा उन दोनों से कहीं नीचा था। 1966 में सिक्किम ने अमरीका के प्रोत्साहन पर (श्रीमती गांधी का आरोप था) World Crafts Council के सम्मेलन में शामिल हुआ। भारत की आशाएँ पर्वतीय राज्यों से यही रही हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर वे उसकी ही में हाँ मिलाना रहे। लेकिन आज के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत की उक्त अपेक्षाओं का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कई बार नेपाल-भूटान ने संयुक्तराष्ट्र संघ में भारत के साथ समर्थन नहीं दिया है। उदाहरण के लिये—पर्वतीय राज्यों के अधिकारों के मसले, दक्षिण एशिया को आणविक स्वतंत्र क्षेत्र का मुद्दा था, कपूचिया या अफगानिस्तान। इन मुद्दों पर नेपाल-भूटान ने भारत का विरोध किया है।

चूँकि तीनों पर्वतीय राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था राजतन्त्रीय थी इसलिये तीनों में पारस्परिक एकता का हो जाना भी स्वाभाविक था तथा बाहरी विदेशी तत्वों के संपर्क में आने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय छवि तथा अस्तित्व के उभरने में अंशतः सहायता मिलती रही है। उदाहरण के लिये भूटान में अंग्रेजी डाक्टर्स, अध्यापक, कार्यकर्ता तथा फिल्म अभिनेताओं तथा सिक्किम में अमरीकी महिला होपक्रुफ के होने से पर्वतीय राज्यों में विदेशियों के आवागमन की समस्या बढ़ गई थी। सिक्किम ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये बार-बार आवाज भी उठाई थी। यह बात दूसरी है कि अन्तिम परिणाम क्या हुआ ?

राज्याभिषेक के अवसरों ने विदेशी लोगों से संपर्क बढ़ने में अधिक

मदद दी है। 1956 में नेपाल के राजा महेन्द्र का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर का साम उठाने हुए चीन के साथ नेपाल की एक गठि हुई और नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में एक विशेष स्थान निर्धारित हुआ। 1965 में मित्रता के राजा का राज्याभिषेक हुआ और अपने स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य में राज्याभिषेक के समय अपना राष्ट्रीय गीत (National Anthem) विदेशियों को सुनवा दिया जो कि गठि के अनुसार गतत था। 1974 में भूटान के वर्तमान राजा का राज्याभिषेक हुआ और इस अवसर का साम उठाने हुए राजा ने प्रशंगन के लिये विदेशी मेहमानों की उपस्थिति में वे सब काम किये जो उनके अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे को ऊँचा करते हैं। राज्याभिषेक के उत्सव पर केवल चीन, रूस, अमरीका, भारत की शामिल होने की इजाजत दी गई थी। 1975 में राजा महेन्द्र के अभिषेक के समय नेपाल के अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व को और अधिक उभारने के उद्देश्य से 'नेपाल की शान्तिक्षेत्र' की घोषणा की गई। कहने का अर्थ यही है कि पर्वतीय राज्यों की संधियों के माध्यम से भारत सरकार ने अवश्य प्रतिबद्ध किया लेकिन उनकी दली हुई आपाधापी ने रह रह कर यह अवसर कराया कि उनकी किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन ऐसी स्थिति हमेशा के लिये स्वीकार नहीं है।

1955 में राजा महेन्द्र के गद्दी पर बैठने के बाद, नेपाल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अन्तर्गत कई राष्ट्रों से अपने सम्पर्क बनाने शुरू किये। भूटान ने भी लगभग नेपाल का अनुकरण करना शुरू किया। भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना और अपने अन्तर्राष्ट्रीय आकाशमार्गों की वृद्धि के साथ उसने लगभग 14 देशों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। लेकिन सिक्किम का दर्जा अत्यधिक नीचा होने के कारण ऐसा कर नहीं सकता कभी जब साहस किया तो परिणाम सामने आ गये।

नेपाल व भूटान ने निरन्तर यही प्रयास किये हैं कि भारतीय सेना उनके देश की सीमा पर अधिक बढ़ने न पाये। नेपाल को इस दिशा में प्रशस्त सफलता मिली है, जबकि भूटान को उतनी सफलता अपेक्षाकृत नहीं मिल पाई है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में परिवर्तन दिखाई दिया है। इस परिवर्तन से पूर्व भारत नेपाल-भूटान की सेना को विधिवत प्रशिक्षण देता रहा है और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। कुछ वर्षों तक भूटान में तो सैनिक सुरक्षा की यह स्थिति थी कि भूटान की सेना में भारतीय सैनिक ऑफिसरों का होना जरूरी हो जाता था।

नैपाल-भूटान की सार्वभौमिक अस्तित्व के उभारने में बाहरी शक्तियों का भी सहयोग रहा है चाहे वह भारत सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी न हो। विशेष रूप से चीन और प्रथमरूप में पाकिस्तान ने पर्वतीय राज्यों के आन्तरिक असन्तोष तथा शिकायतों का लाभ लिया है। दोनों ने ही बाहरी देशों से विविध तरीकों से सहायता लेकर अपनी अन्तर्राष्ट्रीय छवि को ऊँचा करने का प्रयास किया है। भारत की स्वयं की अन्य देशों पर निर्भरता ने पर्वतीय राज्यों को पैसा ही करने के लिए अनुप्रेरित किया। 1971 से भारत की परिवर्तित स्थिति को देखकर, बाहरी शक्तियों ने भी पर्वतीय राज्यों की ओर से उदासीनता का व्यवहार अपना लिया था क्योंकि बांग्ला देश के जन्म के साथ दक्षिण-एशिया में भारत एक पर्याप्त शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आ गया था और उसे महाशक्तियों ने मान्यता भी दी थी लेकिन बांग्ला देश की विजय का प्रभाव कुछ वर्षों ही चल पाया और उसके बाद से पर्वतीय राज्यों से भारत का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता नजर आता है। जब कभी भारत की आन्तरिक कमजोरियाँ राजनीतिक व्यवस्था को असन्तुलन की स्थिति में लाई हैं—पर्वतीय राज्यों ने उन स्थितियों का पूरा-पूरा लाभ लिया है। उदाहरण के लिये जनता पार्टी के प्रशासन के दौरान जिस प्रकार अस्तव्यस्तता तथा अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई उन क्षणों में पर्वतीय राज्यों ने अन्य शक्तियों की सहायता से अपनी सार्वभौमिक शक्ति को उभारने का प्रयास किया है। विशेष रूप से 1980 के बाद से भूटान ने अपने दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन किया है। 1980 से आज तक लगभग भूटान ने 14 देशों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं तथा भारत पर शत-प्रतिशत निर्भरता को घटा कर 77% पर ले आये हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं से आर्थिक सहायता लेने से भूटान में आर्थिक विकास तीव्रगति से हो रहा है। भूटान कई अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना मत भारत के विरोध में देने से कोई संकोच का भाव प्रदर्शित नहीं करता। धीरे-धीरे भारत पर किन्हीं क्षेत्रों में निर्भरता को भूटान कम करने के प्रयास है।

चीन की निरन्तर प्रतिकूल नीतियों ने भी भारत की सशक्त भूमिका पर प्रभाव डाला है। चीन ने प्रारम्भ से भारत का पर्वतीय राज्यों पर प्रभाव को मान्यता नहीं दी। भारत-चीन के अच्छे सम्बन्धों के दौरान भी चीन की निजी इच्छा यही रही कि भारत के प्रभाव को किसी न-किसी प्रकार कम करना है और इस निरन्तरता के प्रयास ने चीन को जब तक सफलता प्रदान की है। आज के सन्दर्भ में पर्वतीय राज्यों (नैपाल-भूटान) की भूमिका को देखकर सकेत अवश्य मिलता है कि भारत का पर्वतीय राज्यों से प्रभाव घूमिल

हो रहा है। प्रश्न केवल यही उठता है कि इस विशेष क्षेत्र में श्रेय चीन को दिया जाय या उमरती हुई उन परिस्थितियों को जिनका हो जाना अपरिहार्य था। यह बात दूसरी है कि प्रभाव का कम हो जाना चीन के लिए एक प्रकार से मुख की बात हो लेकिन चीन को श्रेय देना या उसकी सफलता में प्रांकना अनुचित ही होगा। **मर्नः मर्नः परिस्थितियां कुछ इस प्रकार बन गईं जिन्होंने पर्वतीय राज्यों को भारत के प्रभाव से बाहर निकाला है।**

एक दृष्टिकोण और सामान्य तौर पर रखा जाता रहा है कि भारत सरकार का पर्वतीय राज्यों पर प्रभाव रखने का उद्देश्य उनको भरपूर आर्थिक सहायता देने से हो सकती है। आर्थिक सहायता देने से प्रभाव की मात्रा कुछ वर्षों ही चल पाती है, अन्त में यह माध्यम भी असफल इसीलिए हो जाता है क्योंकि आर्थिक सहायता किसी देश को बाध नहीं सकती या उसमें बाधने की क्षमता अब कम हो रही है। नेपाल-भूटान के सन्दर्भ में भारत की भरपूर आर्थिक सहायता ने मध्यम वर्ग को ऊँचा उठने में सहायता की है जिसके कारण भारत के प्रति दृष्टिकोण प्रतिकूल बना है। 1973 में नेपाल के नरेश बीरेन्द्र ने कहा था कि नेपाल एक एशिया का तो अंग हो सकता है परन्तु भारतीय सीमा से लगे होने के कारण उप महाद्वीप का अंग नहीं हो सकता। राजा ने नेपाल को स्विट्जरलैण्ड के दर्जे की मांग की थी जिसका सीधा अर्थ 'शान्ति के क्षेत्र' की मांग से था। नेपाल की सुरक्षा के लिए भारत को किसी भी दृष्टि से या आवरण या बहाने से अवसर नहीं देना चाहते। 'शान्ति के क्षेत्र' की मांग 1973 में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में अल्जीरिया में उठाई गई थी। उस समय तो मांग सुनी अनसुनी कर दी गई। 1975 में इसी मांग को पाकिस्तान-चीन-अमरीका तथा वागन्ना देश ने पूरा समर्थन दिया। भारत उक्त सुझाव पर धुप रहा लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत ने नेपाल को इस प्रकार की मांग को उठाने के लिये अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। 1977 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री भुवनेश्वरी देसाई जब नेपाल गये तो उन्होंने स्पष्ट कहा—“न केवल नेपाल अपितु सम्पूर्ण दक्षिण एशिया एक शान्ति का क्षेत्र घोषित होना चाहिये।” जनता पार्टी के प्रशासन का समय पर्वतीय राज्यों के लिये अधिक सुख देने वाला था। भुवनेश्वरी देसाई ने कुछ बयानों से इनका होसना या साहम बढ़ा दिया था। मित्रिकम के मामले में भी श्री देसाई के बयान उदात्त करने वाले थे। इसी प्रवाह के कारणों में भूटान के राजा ने हवाना में लौटते समय दम्बई में बयान दिया था कि ‘अब समय आ गया है जब भारत को 1949 की सन्धि में संशोधन करना चाहिये।’ वैसे भारत के प्रभाव को कम करने का प्रयास पर्वतीय राज्यों का भी रहा तथा आंशिक दृष्टि

से दक्षिण-एशिया में अतिरिक्त शक्तियों को इस भूमिका में जोड़ना अनुचित नहीं होगा। यद्यपि Himalayan Federation का विचार साकार नहीं हो पाया लेकिन यह योजना अभी तक जीवित रही है। ऐसा कहा जाता है कि 1979 में हनोई रेडियो ने भारतीय समाचार पत्र को पुष्टि करते हुए कहा था कि "अमरीका व चीन अभी भी Himalayan Federation के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं।" लेकिन इस दृष्टिकोण से सहमत होना अधिक आसान नहीं है कि "भारत भविष्य में परिस्थितियों के अनुकूल होने पर नेपाल-भूटान को अपने में विलय कर लेगा।" इस प्रकार की सूचना न केवल दक्षिण-एशिया देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में कटुता लाती है अपितु स्थायी रूप से गलत धारणा को जन्म देने का भी प्रयास करती है। एक अन्य दृष्टिकोण या विचार को फैलाने से भारत के प्रति राय ही नहीं बदलती बल्कि भारत के न्यूनतम हितों की पूर्ति में अत्यधिक रुकावट आती है। उदाहरण के लिए यह कहना कि "पर्वतीय राज्यों के लिए भारत एक खतरा है।" और इस मत का बार-बार प्रचार करने से छोटे देशों का दृष्टिकोण संशयात्मक हो जाता है जिसके फल-स्वरूप भारत के अच्छे उद्देश्यों को साकार प्रदान करने में भारी दिक्कत आ जाती है। 1947 से आज तक पर्वतीय राज्यों पर, राष्ट्रीय हित की परिधि में, प्रभाव रखने की तो अवश्य रही है लेकिन हड़पने की कमी नहीं रही होगी। सिक्किम के भविष्य को रातोंरात बदलना न केवल संयोग था बल्कि एक अनिवार्य बुराई थी। नेपाल-भूटान को भारत से सुरक्षा की दृष्टि से भय या आतंकित होना एक बुराई तो हो सकती है लेकिन इसमें वास्तविकता तनिक भी नहीं है। यह बात दूसरी है कि नेपाल या भूटान अपने अस्तित्व को ऊँचा करने में कुछ भी करें लेकिन भारत से भय की बात सोचना हर स्तर से अनुचित प्रतीत होती है।

दूसरा पक्ष— बैसे तो भारत की नीतियों के बारे में हर दृष्टिकोण से टिप्पणी होती रही है लेकिन समग्ररूप से परिस्थितियों का परीक्षण करे तो यह संकेत मिलता है कि भारत के दृष्टिकोण में परिपक्वता की भलक हमेशा बनी रही है। भारत की संस्कृति के कुछ लक्षणों का नीतियों में समावेश अवश्य रहा है। सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, उद्देश्य और साधन के बीच न्यूनतम फासला आदि ऐसे आदर्श हैं जिनका शतप्रतिशत व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन उक्त सिद्धान्तों का नीतियों के पालन में निरन्तर ध्यान रखना यह भी एक उपलब्धि है। आदर्श के नाम पर भारत की नीतियों की कटु आलोचना होती रही है। 1962 में तो भारत को एक ऐसा नैतिक धक्का लगा था जिसके फलस्वरूप पूर्ण आदर्श

का निर्वाह करना असंभव है का सबक उसके बाद से ही सीखा ।

पर्वतीय राज्यों के लिये प्रारंभिक काल कंसा रहा होगा लेकिन भारत के दृष्टिकोण से कठोर नहीं माना जा सकता । भारत के मुलभे हुए नेताओं का प्रयास यही था कि पर्वतीय राज्य भारत की विवशता को भली प्रकार समझ लें तो उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में कोई घाटा नहीं है । यदि भारत जनसंख्या, आकार तथा सैनिक शक्ति की दृष्टि से साम की स्थिति में था तो छोटे देशों की दृष्टि से शंका तथा भय की स्थिति भी पैदा करने वाली थी । अतः भारत का अथक प्रयास यही था कि हिमालयी राज्य भारत की नीति को खुले दिमाग से समझें । परन्तु शंकाओं को उठाने से भी नहीं रोका जा सकता था और यदि एक बार शंका प्रपन्न स्थायी रूप ले ले तो फिर प्रयास भी निरर्थक होते हैं । नीतियों को समग्र रूप से परीक्षण व विश्लेषण केवल विशेष प्रकार की उत्पन्न परिस्थिति को गौर से देखना होगा तभी यह एक प्रकार की राय बन सकती है कि भारत के अथक प्रयास केवल पर्वतीय राज्यों को अपने समर्पण में रखने की नियत के अलावा कुछ भी नहीं था ।

यदि हम तत्कालीन गृहमंत्री पटेल के मत को लेकर एक बुनियादी विचार बना लें कि भारत सरकार की तो नियत यही थी कि नेपाल-भूटान-सिक्किम भारत में विलय हो जाय । यह विचार यदि था भी तब भी शंका का कारण तो बन सकता है लेकिन शंकाओं को स्थायी स्वरूप देने से आपसी संबंधों में हमेशा के लिये कटुता आ जाती है । भारतीय नेताओं की परिपक्वता के दर्शन हमेशा होते रहे हैं कभी केवल इस प्रयास की रही है कि भारत के उद्देश्य तथा इरादों को समझें । कुछ वर्षों से भारत के बारे में उन पड़ोसी देशों की भी राय तथा दृष्टिकोण एक दम विपरीत दिखाई देता है जो पहले नहीं था । प्रतिकूल दृष्टिकोण बदलती हुई परिस्थितियों के साथ होता गया है । नेहरू काल एक ऐसा युग समझा गया जिनके अन्तर्गत न केवल पड़ोसी देशों की पूर्ण आस्था थी बल्कि भारतीय नागरिकों की नेहरू पर पूर्ण समर्पित विश्वास था । यहां तक कि विरोधी पक्ष का भी व्यक्तिगत नेहरू पर विश्वास था । भारत में बदलते नेतृत्व ने पड़ोसी देशों के हृदय में संदेह तथा अविश्वास पैदा किया । यह पक्ष विश्वमनीय माना जा सकता है । जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारतीयों के हृदय में क्रोध की ज्वाला थी । लेकिन नेहरू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास प्रकट किया लेकिन तत्कालीन मुरदा मंत्री श्री. के. कृष्णामनन ने जल्ता ने स्वीकृत आग्रह व प्रदर्शन के साथ ले ही लिया यद्यपि स्वयं

नेहरू नहीं चाहते थे कि कृष्णमनन मंत्रिमंडल से जाय। कहने का आशय यही है कि नेहरू का प्रशासन संदेह तथा विवाद से मुक्त था। पड़ोसी देशों की भी आस्था थी कि जो कुछ उनको आश्वामन दिया जाता है उसमें एक-निष्ठा व ईमानदारी का भाव है। परन्तु बाद के प्रशासन की शैली नेहरूजी से पूर्णतया भिन्न होने के कारण पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ। जोड़-तोड़ की राजनीति की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण उत्तरोत्तर अविश्वास बढ़ता गया। 1971 में बांग्लादेश एक नये राष्ट्र के रूप में उभर कर आया लेकिन श्रेय या दोषारोपण भारत को गया। एक तरफ तो भारत दक्षिण एशिया में एक शक्ति के रूप में उभरा और 1962 की घुमिल छवि को पुनः यथास्थिति तक पहुँचाया लेकिन दूसरी ओर पर्वतीय राज्यों में भय व शंका हो जाना भी स्वाभाविक था। विशेष रूप से 1974 में सिक्किम के विलय के बाद तो न केवल नेपाल-भूटान अपितु श्रीलंका भी शंकाओं की निगाहों से देखने लगा। इतिहास में कुछ ऐसे दृष्टान्त घटित हो जाते हैं जिनके आधार भाषी राय बनाने में कोई कष्ट नहीं होता और राय और भी मजबूत होती जाती है। यदि इसी प्रकार के उदाहरण और प्रस्तुत हो जायें। 1971 में बांग्ला देश तथा 1974 में सिक्किम का भारत में विलय ने पर्वतीय राज्यों के प्रशासन में हलचल पैदा कर दी। सिक्किम के विलय के तुरन्त बाद भूटान नरेश दिल्ली आये और अपनी शंकाओं को सामने रखा। यद्यपि शंकाओं को समाप्त करने में भारतीय नेतृत्व ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी लेकिन शंकाएं एक बार उठ खड़ी हो जायें तो उनको किसी गणितीय आधार पर मिटाना दुर्लभ कार्य है। नेपाल के नरेश भी दिल्ली आये और अपनी शंकाएं व्यक्त कीं। इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि श्रीमती गांधी का काल निसंदेह उथल-पुथल की राजनीति को जन्म देने वाला समझा गया। कांग्रेस पार्टी ने ही कितनी बार टुकड़े नहीं हुए लेकिन श्रीमती गांधी हर बार सफल नेता के रूप में उभर कर आईं। कहने का अर्थ यही है कि घरेलू नीति या नेहरू से भिन्न शैली ने पर्वतीय राज्यों के दृष्टिकोण पर भारी प्रभाव डाला। शंकाएं इतनी घर कर गईं कि नेपाल-भूटान अपने अस्तित्व को उभारने का अतिरिक्त प्रयास करने में जुट गये। उन्हें 1947 की वे घटनाएं ताजा होने लगी जब भारत के नेतृत्व का एक छोटा सा समूह, जिसमें सरदार पटेल भी शामिल थे, जिन्होंने नेपाल-भूटान तथा सिक्किम को भारत में विलय होने की न केवल राय दी थी बल्कि आग्रह भी किया था। सिक्किम के विलय के बाद अतीत में लुप्त हो जाने वाले स्वयं तथा संबंधित घटनाएं सभी याद आने

लगी। यदि नेपाल-भूटान के सामने सिक्किम के विलय की आन्तरिक कहानी स्पष्ट रूप से सुनाई गई होती और भारी दबाव की परिस्थितियों को समझा होता तो भय व शंका दोनों का लोप हो गया होता। परन्तु ऐसा होना संभव नहीं था अतः पर्वतीय राज्यों के दृष्टिकोण की भी उपेक्षा करना उनके प्रति अन्याय करना है। कोई भी राष्ट्र उनके स्थान पर वही राय या धारणा बनाता जो उन्होंने बनाई थी। परन्तु महजभाव से उठी शंका व भय धीरे-धीरे एक कूटनीति के रूप में सामने आने लगी। पर्वतीय राज्यों के मन में भय व शंका तो धीरे-धीरे समाप्त हो गई लेकिन उक्त दोनों तत्वों को हिमालयी राज्यों ने एक हथियार के रूप में अब तेजा शुरू कर दिया है। भारत अब चाहे कुछ अन्याय पूर्ण नीति को अपनाये या न अपनाये—नेपाल-भूटान की कूटनीति भारत विरोधी भावना को निरन्तर व्यक्त करना एक आम बात हो गई है। दोनों ही पर्वतीय राज्य सम्भवतः यह सोचते हैं कि विरोधी भावना को व्यक्त करने से भारत की ओर से अतिरिक्त धन की सहायता तथा अन्य रियायतें प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार की कृत्रिम तथा असत्य भावना को फैलाने से भारत पर अकारण एक नैतिक दबाव पड़ा है। भारत सरकार स्वयं कभी-कभी पर्वतीय राज्यों के व्यवहार से हतप्रभ रह जाती है। विशेष रूप से उन क्षणों में जब भारत सर्वाधिक आर्थिक सहायता के बारे में सोचती है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नेपाल-भूटान का भारत से सुरक्षा की दृष्टि से डर न केवल कृत्रिम है अपितु एक कूटनीति है जो दोनों को भारत से सर्वाधिक लाभ दिलवाने में सहायक सिद्ध हो रही है। भारत का एक मात्र राष्ट्रीयहित किस प्रकार पर्वतीय राज्यों की गलत भावना व व्यवहार को सहन करने के लिये विवशता बनाये हुए है।

भारत ने अपनी विवशता का स्वरूप अपनी अस्पष्ट नीति के कारण बनाया है। आदर्श व धर्माच के बीच झूलती हुई नीतियों ने पर्वतीय राज्यों के मन में आस्था को तोड़ा है। यह सही है कि नेहरू कात के ऊँचे आदर्श, आने वाले नेतृत्व की क्षमता के बाहर था कि उनका रुचित मात्र भी निर्वाह कर पाते। नेहरू के व्यक्तित्व में न केवल भारत बल्कि समस्त दक्षिण एशिया के देशों के बारे में एक दृष्टि थी जिसको समझने के लिये एक उच्च स्तरीय समझ की आवश्यकता है। आज भी उनके विचार तथा भाषणों को पढ़कर यह लगता है कि पर्वतीय राज्यों के बारे में नेहरूजी की समझ बिल्कुल सफाई थी। इसीलिये उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल की भाव को स्वीकार नहीं किया। पंडित नेहरू के मिद्धान्त तथा व्यवहार में

फासला न्यूनतम था। सरदार पटेल तो अन्तिम क्षण तक यही आग्रह करते रहे कि समस्त पर्वतीय राज्यों को भारत में मिला लेना चाहिये। परन्तु नेहरूजी ने उन संधियों (1949-1950) को सम्मान दिया जो अंग्रेजों ने नेपाल-भूटान तथा सिक्किम के साथ की थी। कहने का आशय यह है कि सब से अच्छा मौका भारत के लिये प्रारंभिक काल का था जब पर्वतीय राज्यों का विलय बिना किसी आपत्ति तथा विरोध के साथ संभव था। आज पर्वतीय राज्यों का संदेह तथा भय उसी स्थिति के स्मरण से उठ जाता है कि भारतीय नेतृत्व का वर्तमान दृष्टिकोण अधिक आक्रामक है और सरदार पटेल का विचार कभी भी साकार हो सकता है। नेपाल व भूटान की आशंकाओं को दूर करना वर्तमान नेतृत्व के बस की बात नहीं लगती क्योंकि नेतृत्व में उन मूल्यों का व्यावहारिक पक्ष दिखाई नहीं देता जो नेहरू काल में शतप्रतिशत था। ऐसी स्थिति में भारत की नीति में अतिनी स्पष्टता होगी उतना ही पारस्परिक समझ की मात्रा बढ़ेगी। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ आदर्श युक्त मापा को पुनः परिभाषित करना होगा जिससे राष्ट्रीय हितों का संतुलन कायम रहे। मूल्यों का ह्रास उत्तरोत्तर भारत में हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप आस्था व विश्वास भी भारतीय नेतृत्व पर निरन्तर घट रहा है।

नेपाल व भूटान ने भारत में जो घटनाएँ घटी हैं उसको भी बड़े गौर से समझने का प्रयास किया है।

पंजाब की समस्या—आसाम तथा उत्तरी-पूर्वी सीमा की समस्याओं के बारे में भी पर्वतीय राज्य अनभिज्ञ नहीं रहे हैं। इन समस्याओं की जटिलता से नेपाल-भूटान अधिक सतर्क हुए हैं। यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि भारत की जनतांत्रिक तथा पूँजीवादी व्यवस्था ने भारतीय नेतृत्व को अधिक उलझाया है। भारत की धरेलू नीति पर्वतीय राज्यों को बराबर सजग किये रही है जिससे उनके व्यवहार में भारत विरोधी भावना प्रवेश कर गई। तटस्थ भाव से विचार करने पर यह बात सामने आती है कि धरेलू समस्याएँ पड़ोसी देश के व्यवहार को बदलने में अधिक सहायक रही हैं। पर्वतीय राज्यों की एक सीमा तक विवशताओं का विचार करना भी एक सार्थक प्रयास है। भारत की 'राष्ट्रवाद' की भावना को रखकर और उसी को एकमात्र बिन्दु मानकर पर्वतीय राज्यों के दृष्टिकोण को नहीं समझा जा सकता। नेपाल-भूटान दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं को बढ़ा चुके हैं और यह उनकी वास्तविक विवशता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं का विश्लेषण भी एक यथार्थ परिधि में हो सकता है। 1949 व 1950 की संधियाँ भारत के साथ होना

तथा उसके माध्यम से उन पर जहाँ तहाँ नियंत्रण का प्रावधान सम्मिलित करना एक ऐसी वास्तविकता है जिगमें भारत के न्यूनतम तथा भीमित राष्ट्रहित सन्नहित हैं। यदि पर्वतीय राज्य मधियों में संशोधन चाहते हैं तो केवल उसी नाजुक बिन्दु पर आकर ठहर जाते हैं जहाँ भारत का राष्ट्रीय हित शुरू होता है। अतः संशोधन की माग का प्रयास एक ऐसा दबाव है जिसको कुछ वर्षों से भारत सरकार बिना कुछ टिप्पणी किये हुए सहिष्णुता के भाव की झलक दे रहा है। इस मामले में भारत की विषमता है और उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में रिश्तों के समीकरण घनते व टूटते रहते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है उसका प्रथम रूप कुछ और ही होता है। प्रथम स्वरूप का निकटतम ज्ञान होने से दो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों की चर्चा अधिक सार्यक सिद्ध होती है। यदि छोटे राष्ट्र के दृष्टिकोण व अनुभव को अपेक्षाकृत महत्व दिया जाय। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और भूटान छोटा। भूटान के दृष्टिकोण व उसकी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत लेख में विश्लेषण का प्रयास है। इस प्रयास में आदर्शात्मक व मधार्थवाद के सिद्धान्त का भी ध्यान रखा गया है।

भारत-भूटान सम्बन्ध का इतिहास यद्यपि लम्बा है लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व रखते हैं। पिछले कुछ महीनों से यह कहा जाने लगा है कि भूटान का हाल भारत के प्रति उदासीन हो रहा है और उसकी विदेश नीति में अधिक परिवर्तन दिखाई देने लगा है—जो भारत के राष्ट्रीय हितों के सर्वथा प्रतिकूल रहेगा। इन समाचारों में कितनी सत्यता है यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु तथ्यों को और निकट दृष्टि से गौर करे तो यह स्पष्ट लगता है कि जो देताने में आ रहा है, वह यथार्थ नहीं है।

प्रारम्भिक काल—भारत-भूटान संबंध का श्रीगणेश 1949 की संधि से प्रारम्भ होता है और संधि की धारा 2 के अनुसार “भारत-भूटान के विदेशी मामलों में परामर्श देना।” धारा दो का अर्थ या उसकी व्याख्या विवेचकों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से की है। किसी ने भूटान के दर्जे को अर्द्ध सार्वभौमिक मात्र तो किसी ने भूटान को भारत का आरक्षित राज्य कहा, लेकिन जो व्याख्या भारत तथा भूटान के बीच पारस्परिक सम्बन्ध व सूझबूझ के द्वारा सामने आई है उसको तरीके से नहीं समझा गया है। यही कारण है कि भारत-भूटान के सम्बन्धों में यदा-कदा मलीनता की झलक भी दिखाई दी।

1949 की संधि के बाद से और आज तक यदि कभी भूटान ने भारत को गलत समझा तो केवल एक मुद्दे पर और वह संधि की धारा दो जो उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर या दर्जे को स्पष्ट नहीं करती। संधि की उक्त धारा को शामिल करने का उद्देश्य दोनों देशों के पारस्परिक हितों की पूर्ति का, भारत की पर्वतीय नीति प्रारम्भ से कुछ इस प्रकार रही है कि जिसने अथक प्रयासों के बावजूद पर्वतीय राज्यों के निवासियों को सही दिशा में सोचने का मौका नहीं दिया। इस सम्बन्ध में चाहे वह नेपाल हो या भूटान, चाहे कश्मीर हो या उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र। भारत की नीति में एकरूपता न होने के कारण भिन्न-भिन्न पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों ने भारत को गलत समझा। यद्यपि भारत की नीति उन सभी के लिये लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ही क्यों न की गयी हो; परन्तु व्यावहारिक स्वरूप ने यदा-कदा कुछ ऐसी दिशा ली जिसके कारण भारत को गलत समझा गया और उसका फायदा उन पड़ोसी देशों ने लिया जो भारत के विरुद्ध आजादों के बाद से ही वैमनस्यता का भाव देखते रहे।

इसी संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि भूटान का दृष्टिकोण 1949 की संधि के बाद में किस प्रकार बदलता रहा, जिसमें अन्य शक्तियों का कितना हाथ है तथा भूटान की भौगोलिक स्थिति दोनों देशों के लिये कितनी महत्वपूर्ण है तथा भूटान की राजनीतिक आकांक्षाएं उत्तरोत्तर कितने भ्रंश तक बढ़ती गईं जिसके उत्तर में भारत ने उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति में कितना योगदान दिया—ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनका उत्तर इस लेख में देने का प्रयास किया गया है।

1949 की संधि बाद भूटान ने विदेशियों के प्रवेश के लिये अपने द्वार बंद किये। यहां तक कि भारत के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित रखा, लेकिन ज्यों-ज्यों भूटान के शासक वर्ग भारत की नीति को समझते गये उन्हीं अनुपात में कठोर नीति में ढिलाई आती गई। भारत की नीति इस दौरान में एक पक्षीय कही जा सकती है लेकिन निरन्तर व निष्ठापूर्ण व्यवहार ने भूटान के राजा को विश्वास दिलाया कि भारत हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में सहयोग देता रहेगा। 1958 में स्व० जवाहरलाल नेहरू की कष्टप्रद भूटान की यात्रा ने भारत को अधिक नजदीक से समझने का मौका दिया। इस यात्रा के बाद से भूटान ने भारत के बन्द दरवाजों को खोल दिया। भूटान की नीति में नरमाई की झलक मिलती ही गई। इस यात्रा से पूर्व कहां भूटान भारत की दी गई किसी भी आर्थिक सहायता

को भी स्वीकार नहीं करता था परन्तु मात्रा के बाद भारत के दिये गये मुभावो को स्वीकार करने की झड़ी सी लग गई। भूटान ने भारत के उस मुभाव को सहर्ष स्वीकार किया जो आर्थिक विकास योजना में सम्बन्धित था। 1961 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का सिलसिला शुरू हुआ जिसका आज तक निर्वाह हो रहा है। सन्धि की धारा दो जिसने भूटान के शासक वर्ग में संदेह उत्पन्न कर दिये थे वे धीरे-धीरे मिटते गये। 1971 में भूटान के राजा ने संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने की इच्छा व्यक्त की और भारत के अधिक प्रयास से भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भूटान कोलम्बो योजना का सदस्य भी बना और धीरे-धीरे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्स्थाओं का सदस्य बनता गया। आज भूटान अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता जा रहा है। भूटान के प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतन्त्र राय व्यक्त बड़ी ही बुलन्दी से करते हैं।

आर्थिक क्षेत्र—[1961 से और आज तक भूटान की पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक सहायता सर्वाधिक रही है। पहली दो पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए भारत ने शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने 1750 लाख रुपया दिया और दूसरी में 2000 लाख। लेकिन तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की आर्थिक सहायता के अलावा भूटान ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्स्थाओं से भी सहायता प्राप्त की है। भूटान अब कोलम्बो योजना व संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्स्थाओं से भी आर्थिक सहायता लेने लगा है। ऐसा कहा जाने लगा है कि भूटान अब धीरे-धीरे भारत के पूर्ण प्रभुत्व से हटता जा रहा है और भारत के प्रति रुखा व्यवहार दिखाने लगा है।] यह बात अधिक उचित नहीं लगती। यदि आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण को रखकर यह बात कही गई है तो और भी अनुपयुक्त है। भारत तो प्रारम्भ से यही कामना करता रहा है कि भूटान एक स्वतन्त्र तथा द्वन्द्व राष्ट्र के रूप में उमरे। यदि भूटान अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेने लगा है तो इससे यह बात तो स्पष्ट नहीं होती कि भूटान के भारत में सम्बन्ध कुछ हल्के पड़ रहे हैं। 1949 से 1961 तक भूटान ने जब भारतवासियों के लिये द्वार बन्द किये थे वह विशेष अवधि एकान्त तथा दूसरे देशों के प्रति शंका का काल था। परन्तु 1961 से और आज तक भूटान की नीति में एक प्रकार से सूझबूझ व समझ में परिपक्वता की झलक मिलती है। भारत की सतर्कता हमेशा उसके व्यावहारिक पक्ष पर रही है जिसने भूटान को कभी संदेह नहीं होने दिया कि भारत कभी भी उसके प्रति अहित की सोच सकता है। कभी-कभी महत्वपूर्ण घटना चक्रों ने भूटान को संदेह के लिए मौका अवश्य दिया

लेकिन विशेष संदेहों को तुरन्त ही मिटाने का प्रयास किया गया जिससे वे संदेह इतने गहरे न हो जायें जिनको मिटाना मुश्किल हो। यह सच है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध होने के कारण भूटान में चीन के प्रति अधिक आतंक तथा भय बैठ गया जिसके परिणामस्वरूप आज भी भूटान निर्णयात्मक दृष्टि से फैसला नहीं कर पाया है कि क्या उसको चीन से सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये। चीन के बारे में भूटान की संसद में बार-बार यह मुद्दा सामने आया है और विषय भी बना है कि "क्या अब समय आ गया है कि भूटान चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध रखे। इस प्रश्न को भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वागचुक (28 वर्षीय) ने किसी न किसी प्रावर्ण में अपने संसद सदस्यों को टालने के लिए समझाया है। भूटान का चीन के बारे में भय अभी भी व्याप्त है जिसके कारण उक्त विवादास्पद विषय टलता ही जा रहा है। चीन की ललक भूटान के प्रति मात्र इसलिये है कि भारत का उस पर प्रभाव कम हो। वैसे चीन 1949 से ही भारत भूटान के विशेष सम्बन्धों को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाया था जिसके कारण उक्त सम्बन्धों को कोई मान्यता नहीं दी।

भारतीय समाचार पत्रों में यह भी यदा-कदा पढ़ने को मिला है कि भूटान का भारत के प्रति प्रतिकूल रख एक बात से और मिलता है कि आज की तारीख में भूटान में भारत के द्वारा भेजे गये विशेषज्ञ या तकनीकी लोग अब नहीं के बराबर रह गये हैं। यद्यपि यह आधार अधिक ठोस नहीं है परन्तु यह सूचना अवश्य पूर्णतया निराधार है। शोध कार्य से सम्बन्धित मेरा भूटान 1981 में जाना हुआ था। भूटान की राजधानी थिफू तथा आसपास के जिलों में मैं गया था। देखने पर लगा कि भारत किस-किस क्षेत्र में भूटान को अपनी ग्रहमयित उभारने का पूर्ण अवसर दे रहा है। हर विभाग में भारतीय विशेषज्ञ भूटानी लोगों को प्रशिक्षण देते हुए पाये गये। उल्लेखनीय है कि भारतीयों का बहा होना न तो इस बात का प्रतीक है कि भारत भूटान पर अधिक हावी हो रहा है और भारतीयों के न होने से यह भी हवाला नहीं मिलता कि भूटान का भारत के प्रति रख बदल रहा है। वह तो भूटान तथा भारत दोनों के लिये सौभाग्य का दिन होगा जब भूटान को भारतीय विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत के निरन्तर प्रयास इसी दिशा में है भी।

भूटान का भारत के प्रति बदला हुआ रख इस बात से भी कहा जाने लगा है कि भूटान की घड़ी भारतीय समय से आधा घण्टे आगे चलती है और वहां के मूल निवासियों को उस समय अधिक परेशानी होती है जब कोई

भारतीय अपने देश की घड़ी के अनुसार समय बतलाता है। इस परेशानी को अभिव्यक्ति को भारत के प्रति यदि बदला हुआ रख बतलाया जाता है तो यह निरापार ही तर्क है। हर विकासशील राष्ट्र की राजनीतिक भावनाएँ होती हैं और सच्चे राष्ट्रवाद की भूलक इन्हीं छोटी-छोटी बातों में मिलती है। भूटान एक स्वतन्त्र सार्वभौमिक राष्ट्र है और उसे अपनी घड़ी के समय को निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है। भूटान यदि अपने देश के समय को भूलना चाहता है तो क्या आपत्ति हो सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भूटान ने भारत का विरोध किया है या महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत को समर्थन नहीं दिया। उदाहरण के लिये कंचुबिया के मामले में भूटान ने भारत का विरोध किया। विरोध करने का अर्थ कभी यह नहीं है कि भूटान-भारत के सम्बन्धों में अन्तर आ रहा है। कई मामलों में भूटान ने भारत को समर्थन दिया लेकिन समर्थन देने का अर्थ कभी यह नहीं लगाना चाहिए कि भूटान भारत का पिछलग्गू है। बांग्ला देश को यदि भारत के बाद कोई दूसरा देश मान्यता देने वाला में था तो वह भूटान था। उस समय भी कुछ इस प्रकार के मत प्रकाशित हुए जो भूटान के स्वामिमान को धाधात पहुँचाने वाले थे। उदाहरण के लिए पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा भूटान का उपहास किया गया और यह कहा गया कि भूटान भारत का क्यों न समर्थन करे—उसकी तो विदेश नीति भारत के हाथ में है। चीन तो खुले शब्दों में भारत पर आरोप लगाता रहा कि भारत तिब्बत की तरह भूटान को भी हड़प लेना चाहता है। इन प्रकार की प्रकाशित सूचनाओं ने भूटान को यदा-कदा भकभोरा भी है तथा भारत को दसत समझने का पूरा मौका दिया है। इसी कारण भूटान नरेश ने अपने वयान में 1949 की सन्धि में सशोधन करने का भारत से आग्रह किया था। यह वयान उस समय दिया था जबकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के शिखर सम्मेलन (हवाना) में शामिल होकर अपने देश लौट रहे थे। सन्धि के सशोधन की बात भूटान नरेश ने की तो थी लेकिन अपने वयान को तुरन्त स्पष्ट करते हुए तथा भारत की नीति की सराहना करते हुए कहा “भारत-भूटान सन्धि व्यवहार में सफल जा रही है लिखित में क्या है वह महत्वपूर्ण नहीं” भूटान नरेश भारत के प्रयासों के बारे में सार्वजनिक रूप से सराहना करते रहे हैं। साथ में भारत के हितों के बारे में भी भूटान अनभिज्ञ नहीं है। भूटान 1949 की सन्धि से किसी भी प्रकार से भारत से बन्धा हुआ नहीं है। सन्धि की धारा नं० 10 के अनुसार दोनों देशों की पारम्परिक सहमति से सन्धि को समाप्त किया जा सकता है। भूटान ने अपने इस तन्त्रे अवधि का अनुभव बड़े गौर से किया है जिसने उसे

पक्के रूप में आश्वस्त कर रखा है कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति भारत के साथ अटूट सम्बन्ध बनाये रखने में है—तोड़ने में नहीं।

यदि भूटान ने बांग्ला देश तथा नेपाल से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं तो इसका अर्थ यह कभी नहीं समाना चाहिये कि वह भारत से अपना सम्बन्ध घूमिल कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का अध्ययन व विश्लेषण इस नजरिये से नहीं हो सकता कि अमुक राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ हमेशा बंधा रहे या प्रतिबद्धता जाहिर करता रहे। हर राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हित होते हैं और उनकी पूर्ति के लिये उसे कुछ न कुछ रास्ता ढूँढना पड़ता है। यदि भारत को अमरीका से यूरेनियम प्राप्त करने में देरी हुई तो तुरंत फ्रांस से यूरेनियम मंगाने का प्रयास किया गया। यदि भूटान अपने माल का निर्यात बांग्ला देश को कंचिन्चिंगा के मार्ग से न कर कलकत्ता के मार्ग से करता है तो भारत को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन इस मुद्दे को मी.प्रेस ने अधिक महत्व देते हुए प्रकाशित किया कि भूटान के सम्बन्ध बांग्ला देश से अधिक घनिष्ट हो रहे हैं अपेक्षाकृत भारत के। भूटान का राष्ट्रीय हित समय की बचत है और समय की बचत के कारण ही भूटान ने अपने माल के निर्यात का रास्ता बदला। केवल मार्ग बदलने से भारत-भूटान सम्बन्ध की निकटता को कम नहीं आंका जा सकता। इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि भूटान पहले अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति इतना जागरूक नहीं था जितना अब। हितों के प्रति जागरूकता एक शुभचिन्ह है जो उसे प्रगति के मार्ग पर अवश्य ले जायेगा।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्वयंसेवी योजना के अन्तर्गत पश्चिमी देशों से या तो नवयुवक प्रशिक्षित लोग भूटानियों को प्रशिक्षण देने हेतु भूटान में आने लगे हैं। आज उनकी संख्या 20 हो गई है और भारतीय विशेषज्ञ वहाँ से अपने देश वापिस लौट रहे हैं। उक्त विशेषज्ञों को भूटान सरकार की प्रार्थना पर भेजा गया है जिनकी संख्या 20 से 50 तक हो जायेगी। इस सूचना को कुछ इस प्रकार से लिया जा रहा है कि भारत भूटान संबंधों में अन्तर का रूप कहा जा सकता है। क्या भारत ने विदेशी विशेषज्ञों को अपने देश में स्थान नहीं दे रखा है? क्या भारत तकनीकी के क्षेत्र में विदेशों से अधिक योग्य या कुशल होने का दावा रखता है? यदि इनका उत्तर हा में है तब भारत के लिये आपत्ति उठाने का प्रश्न उठ सकता है। परन्तु यथार्थ कुछ और ही है। भूटान में यदि भारतीयों के अलावा पश्चिमी देशों से विशेषज्ञों का आना शुरू

है तो इससे यह तो हवाला नहीं निकलता कि भूटान भारत से अपना मुंह मोड़ने लगा है या भूटान-भारत की किन्हीं मामलों में उपेक्षा करने लगा है। भारत की नीति भूटान के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग की रही है। भूटान निवासियों के सदेहपूर्ण स्वभाव को भी भारत ने अच्छी तरह जाना और समझा है। सदेहों लोगों के साथ सतर्कता की आवश्यकता होती है। साथ में धैर्य की। भारत सरकार ने 1949 से और आज तक धैर्य, सहानुभूति तथा सतर्कता का परिचय दिया है। चीन ने 1962 के संकटकाल से और पिछले कुछ वर्षों तक ऐसी कोई कसर नहीं उठा रखी थी जो भारत की विरोधी न रही हो। भूटान को भारत के विरुद्ध चीन ने क्या कुछ नहीं कहकर बहकाया होगा। परन्तु भूटान की सूझबूझ तथा प्रशासकों की परिपक्वता ने भारत-भूटान के झूट सवधों में कहीं भी कमी नहीं माने दी।

भूटान ने भारत के अतिरिक्त, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अरब देशों से सहायता लेना आरम्भ कर दिया जिसके कारण यह कहा जाने लगा है कि भारत का भूटान पर वह प्रभुत्व नहीं रहा जो पहले था। अच्छे सवधों का अर्थ यह कमी नहीं होता कि एक देश दूसरे के प्रति अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर वही करता रहे जो अतीत में कर रहा था। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक राष्ट्र की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। भारत और भूटान पारस्परिक सूझबूझ के द्वारा इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि भूटान भारत पर हमेशा के लिये निर्भर नहीं रह सकता और व्यावहारिकता भी यही कहती है कि एक राष्ट्र पर पूर्णतया निर्भर रहने का अर्थ होता है कि निर्भर राष्ट्र की अपनी कोई सार्वभौमिक स्वतन्त्रता नहीं है। यह तो भूटान के हित में ही है कि वह जहां तक हो भारत पर अपनी निर्भरता को कम करता जाये। पूर्ण निर्भरता अन्य देशों को सही विश्वास में सोचने के लिये भी मौका नहीं देती। पहली दो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत की भूटान को शतप्रतिशत आर्थिक सहायता थी जिसके कारण पड़ोसी देशों ने विशेष रूप से चीन व पाकिस्तान ने भूटान के सार्वभौमिक स्तर का अवमूल्यन किया। वर्तमान के सदर्भ में जब भूटान के अपनी एक मात्र निर्भरता को कम किया तो यह कहा जाने लगा कि भारत-भूटान सवधों में कटुता आने लगी है। यदाकदा मतभेदों का हो जाना स्वाभाविक है परन्तु मतभेदों को अन्याय लेना सतुलित या निष्पक्ष विचारों का परिचायक नहीं है। भारत भूटान संबंध को लेकर यह समाचार भी छापा गया कि भूटान के विकास और उत्थान के बारे में सोचने का अधिकार नई देहली के स्यान पर जिनेवा को प्राप्त हो गया है। नई देहली के

अधिकारों में कमी आ रही है क्योंकि 9 तथा 18 मई, 1983 को जिनेवा में हुई वार्ता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनडप (UNDP) की भूटान को उत्तरोत्तर आर्थिक सहायता बढ़ती ही जा रही है तथा उसी अनुपात में भारत की सर्वाधिक सहायता में भारी कमी आ गई है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ आर्थिक सहायता 50 मिलियन डॉलर तक पहुँच गयी है, जबकि भारत की अब तक कुल सहायता 140 मिलियन डॉलर है। अन्य स्रोतों से यह भी समाचार है कि भूटान भारत की कुल दो गई मात्रा के मुकाबले विदेशी सहायता जल्द ही पार कर लेगा। भूटान विश्व बैंक तथा एशियन विकास बैंक का सदस्य हो गया है, जिसके कारण यह मभावना व्यक्त की जा रही है कि इससे भारत के संघों में अन्तर आयेगा तथा प्रभाव के क्षेत्रों में कमी आयेगी। उक्त तथ्यों के आधार पर समावित संबंधों में कमी की बात अधिक उचित नहीं है। भारत की सर्वाधिक आर्थिक सहायता के दौरान भी भारत की नीति प्रभाव बढ़ाने की नहीं थी। यह तो पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में संतुलन बनाने की थी। भारत भूटान पर किसी भी क्षण हावी नहीं रहा। भूटान से आर्थिक सहायता के बदले में न्यूनतम अपेक्षाएं अवश्य रही हैं और आज भी हैं जिनका सम्मान भूटान के अधिकारी वर्ग ने हमेशा किया है। इसलिये भूटान की दूरदर्शिता तथा समझ में परिपक्वता पर शंका करना ठीक नहीं है। जिन शंकाओं से भूटान जब तक पीड़ित रहा, उनको आपसी वार्तालाप के माध्यम से मिटाया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारत संचार की व्यवस्था पर अधिकार तथा इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम (IMTRAT) के माध्यम से भूटान की सेना पर निगरानी करने से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। इसी संबंध में यह समाचार भी सामने आया कि भूटान में उक्त दोनों क्षेत्रों पर अधिकार लगभग समाप्त हो गया है और इम्टराट (IMTRAT) को किसी भी समय भूटान सरकार द्वारा अपने विस्तर बाधने के लिये कहा जा सकता है। भारत सरकार का अधिकार यदि अब तक रहा है तो वह भूटान सरकार की इच्छा से ही तो था। यदि भूटान के अधिकारी वर्ग आज यह सोचते हैं कि दूसरे देश का प्रभाव उक्त दायरे में होना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है तो उसमें नई दिल्ली को क्या परेशानी हो सकती है। भारत की नीति में आजादी के बाद से और आज तक भूटान के क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की भावना कभी नहीं रही। यदि सहायता व सहयोग को प्रभाव बढ़ाने का इरादा समझा जाता है तो अनुचित था।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारत-भूटान संबंधों का

विश्लेषण भूटान के दृष्टिकोण से यदि किया जाये तो निरर्थक निर्णय किर्ना हृद तक सेही बैठेगा । इसी आधार को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों की चर्चा हुई है । 1949 की संधि की आपत्ति जितनी पड़ोस के देशों ने की है उतनी भूटान स्वयं ने भी नहीं की होगी । भूटान ने यद्यपि यदाकदा भारत को गलत समझा है, लेकिन उन क्षणों में भूटान के अधिकारी वर्ग के मोचने को दिशा बाहरी विचारधारा से अधिक प्रभावित हुई जिसके फलस्वरूप भारत विरोधी भावना की अभिव्यक्ति सामने आई । परन्तु इस सम्बन्ध में भूटान नरेश की प्रशंसा करनी होगी कि वर्तमान राजा जिग्मेसिंह वांगचुक तथा उनके स्वर्गीय पिता जिग्मेदोरजी वांगचुक दोनों ने ही कोई भी कदम असह्योगी में नहीं उठाये । भूटान के अधिकारी वर्ग अपने देश की सीमाओं व परिस्थितियों से अनभिज्ञ नहीं हैं । भूटान नरेश अपने देशवासियों की भावनाओं व संवेदनाओं से अच्छी तरह परिचित हैं । वे जानते हैं कि संधि की धारा दो का अर्थ अन्य पड़ोसी देश कुछ भी लगते रहें लेकिन व्यवहार में जिस सफलता से संधि का पालन हो रहा है वही अच्छे संबंध कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ।

अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत भूटान संबंध में कोई अन्तर नहीं आया है, चाहे भूटान अन्य स्रोतों से आर्थिक सहायता ले या भूटान अन्य देशों से कूटनीतिक संबंध कायम करे या भूटान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का विरोध करे । इस तथ्य में कोई दो मत नहीं हैं कि भारत भूटान दोनों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में बराबर संतुलन बना हुआ है । जिस क्षण हितों की पूर्ति में अधिक असंतुलन आयेगा उस दिन भूटान निस्संदेह सीमा का उल्लंघन करने में नहीं हिचकिचायेगा । भारत की नीति ने आदर्श व धर्माध्य में निरन्तर संतुलन बनाये रखा है और नये संदर्भ में भी भारत की भूटान के प्रति नीति यथार्थ से हटकर कभी नहीं रही अर्थात् राष्ट्रीय हितों का हमेशा ध्यान रहा है । कभी-कभी भारत पर यह आरोप लगाया गया है कि उसकी भूटान के प्रति तुष्टि की नीति रही है । यह आरोप उचित सा नहीं लगता है । भूटान की शकाओं को दूर करना तथा सहानुभूति भाव से धार्ता करना तुष्टि की नीति नहीं कहीं जा सकती । कठोर नीति अपनाने से तो शंकाएं और भी बल पकड़ती हैं जिससे समस्याएं सुलझने के बजाय उलझती ज्यादा हैं । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति में यथार्थ तो हमेशा साथ रहा है लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक सहायक रहा है । दार्शनिक दृष्टिकोण का अर्थ कभी भी आदर्शात्मक नहीं लेना चाहिये क्योंकि 'दर्शन' तो यथार्थ का अन्तिम अंग है ।

संदर्भ सूची

1. श्री कान्त दत्त —भारत तथा हिमालयी राज
एशियन ऐफेयर्स
Feb., 1980
2. श्री. पी. मेनन —The Integration of
Indian States—London, 1956
3. Asian Relations Conference—March-April, 1947
Report of Proceeding
New Delhi, 1948
4. Asian Survey Vol. XVII No. 2—Feb., 1978
5. धार. सी. मिश्र —भारत भूटान संबंध
(Unpublished Ph. D. Work,
1977)
6. — — — Sikkim Join the Mother Land
(1977)
7. — — —India's Aid to Bhutan,
SAN Jamp (1982).
8. — — —India's Allition to Bhutan
(Unpublished Paper prented
in the National Seminar SAN)
9. राममनोहर लोहिया —धरती माता (1983)
10. Kuensel (Bhutan Weekly Bulletin)—1980-86.

भूटान-आर्थिक विकास की दिशा में

1960 से पूर्व भूटान राजतन्त्रीय व साम्राज्यों का पर्याप्त समझा जाता रहा। दोनों ही संस्थाओं ने भूटान की परम्परावादी समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति भी की। इस प्रकार की स्थिति तभी तक सम्भव थी जब तक भूटान ने अन्य राष्ट्रों से अलग-थलग रहने की नीति का पालन किया। 1958 में प० जवाहरलाल नेहरू ने भूटान की कण्टप्रद यात्रा की और भूटान के राजा को बड़े आग्रह के साथ समझाया कि 'अलग-थलग' रहने की नीति भूटान के राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। पंडित नेहरू के उक्त आग्रह का राजा ने स्वीकार किया और तभी से भूटान ने पर्वतों से घिरे राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के लिये दरवाजे धीरे-धीरे खोलने शुरू किये।

1960 के बाद से भूटान में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की झलक दिखाई देने लगी। आधुनीकरण तथा बाहरी शक्तियों के सम्पर्क होने से दो वैश्व संस्थाएँ यानि राजतन्त्रीय व साम्रा एक प्रकार से दबाव में आ गये। आधुनीकरण ने स्वयमेव एक नये सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के निर्माण करने की आवश्यकता को जन्म दिया। भूटान में कई जातीय समाज होने के कारण, एकता तथा अल्पता की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया। ऐसा तभी सम्भव था यदि आधुनिक आर्थिक विकास धार्मिक तथा भाषायी आधार पर विखरे समाज को एकता के रूप में बांधने के लिये सफल हो सके। आर्थिक विकास होने से जो विषमताएँ पैदा होती हैं उनको भी रोका जा सके। इसे भूटान के प्रशासन ने प्राथमिकता दी गई। चूँकि साम्राज्यों का एक सीमित धार्मिक समाज होने के कारण इसकी भूमिका नहीं के बराबर हो गई और 'राजतन्त्रीय व्यवस्था' की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण उभरती दिखाई दी। दोढ़ समाज जो परम्पराओं से अधिक जकड़ा हुआ था उसमें अब परिवर्तन मानने माने लगे। भूटान की संस्कृति तथा अस्तित्व का भाव अब राष्ट्रीय भावना

की ओर मुड़ने लगा। इस नये दृष्टिकोण को उभारने में राजतन्त्र की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही है।

भूटान में नया विशिष्ट वर्ग तथा मध्यम वर्ग आधुनीकरण के कारण उभर कर आ रहे हैं। इन दो वर्गों के उभरने के फलस्वरूप आर्थिक-सामाजिक संघर्ष पैदा हो गये हैं तथा पुराने परम्परावादी समाज के अन्दर असन्तुलन उठ खड़ा हुआ है। नया विशिष्ट वर्ग न केवल शहरी क्षेत्र में सीमित है अपितु वह ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार हो गया है जिनमें व्यापारी वर्ग तथा जमींदार भी शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में, सत्ता के साथ हिस्सेदारी तथा सरकार व उक्त नये विशिष्ट वर्ग के पारस्परिक सम्बन्ध भी संकट में आ गये हैं। जन-तान्त्रिक व्यवस्था में सत्ता के साथ भागीदारी सम्भव हो जाती है लेकिन राजतन्त्रीय व्यवस्था में जहाँ कार्यकारिणी का अध्यक्ष केवल राजा हो वही सत्ता के साथ हिस्सेदारी की सम्भावना अत्यधिक सीमित होती है। भूटान में, राजतन्त्र को विभिन्न हित समूहों के द्वन्द्वों को आत्मसात करना बहुत मुश्किल होता है। आज की संस्थाओं में वह तरेब मिलना कठिन है जो राजा और जनता के बीच सीधा सम्पर्क करने में सफल हो पाये। सामाजिक ढाँचा भी इतना लचीला (Resilient) नहीं है जो राजा व जनता के बीच की भूमिका भेदा कर सके। क्या यह सम्भव है कि भूटान में उभरते हुए नये विशिष्ट वर्ग के हितों की पूर्ति एक सर्वोपरि राजा कर पायेगा? यह सही है कि भूटान में आधुनीकरण के कारण सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएँ धीरे-धीरे अपनी सर ऊपर उठा रही हैं और राजतन्त्रीय व्यवस्था का मविष्ट में क्या स्वरूप होगा जो उक्त समस्याओं का समाधान कर पायेंगी। साथ में राजतन्त्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत कौनसे हल हैं जो क्षेत्रीयवाद, ग्रामीण जागरूकता तथा जातीय समस्या को अपनी व्यवस्था में स्वीकार कर पायेंगे।

भूटान की जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता तथा भौगोलिक परिस्थितियों ने हिमालयी राज्य में आर्थिक व सामाजिक तनाव व अन्तः-विरोधों को उत्पन्न होने में अधिक मदद दी है। आज भूटान की जनसंख्या लगभग 15 लाख आती गई है तथा उसका क्षेत्रफल 46,000 वर्ग कि. मी. है। जनसंख्या का घनत्व भी न केवल दक्षिण-एशिया में अपितु एशिया में सबसे कम है अर्थात् भूटान में प्रति वर्ग मीटर पर 28 व्यक्ति रहते हैं। आधुनीकरण के अव्याय के प्रारम्भ करने से पूर्व भूटान में न तो आर्थिक दबाव की समस्या थी और न भूमि की। भूटान की जनता अपने आप में संतुष्ट

धी और आधिक व्यवस्था का स्वरूप भी वार्टर व्यवस्था जैसा ही था । फिर भी जातीय मित्रता तथा सांस्कृतिक द्वन्दों के कारण आधिक-सामाजिक तनाव उससे पूर्व विद्यमान थे । इसको समझने के लिए आवश्यक है कि भूटान का भौगोलिक तथा जातीय विभाजन को समझें ।

भूटान में तीन मुख्य जातियाँ हैं जिन्हें हम शारचोप्स (Sharchoops) नालोप्स (Nglops) तथा नैपालियों के नाम से पुकारते हैं । शारचोप्स सबसे पहली जाति थी जो भूटान के पूर्वी भाग में आकर बसी थी । शारचोप्स भारत के उत्तरी पूर्वी भाग तथा बर्मा के उत्तरी भाग से आये । नालोप्स (Nglops) तिब्बत से आकर बसने वाली जाति थी और अपने साथ बौद्ध धर्म लाये थे । नैपाली लोग अधिकांश हिन्दू जो 19वीं शताब्दी के बाद के समय मजदूर के रूप में आये, जिन्हें भूटान के दक्षिणी भाग में प्रतिकूल जलवायु में काम करने के लिये बुलाया गया था । उक्त तीनों जातियों की संस्कृति, धर्म तथा ग्रहणित भिन्न थी । नालोप्स (Nglops) भूटान में आकर शासक बन गये और मूल निवासी शारचोप्स (Sharchoops) को या तो अपने अधीन कर लिया या उनको अपने धर्म में बदल कर उनसे शादी विवाह के सबन्ध जोड़कर अपने में मिला लिया । नैपाली लोगों को दक्षिणी भाग में बसने के लिये सीमित रखा तथा उन्हें राज्य के ऊपरी भाग में आने या बसने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । भूटान में विभिन्न जातियाँ अपने-अपने जोन में बसी हुई हैं । शारचोप्स (Sharchoops) अधिकांश पूर्वी भाग में, नालोप्स (Nglops) पश्चिमी व मध्य भाग में तथा नैपाली जाति दक्षिणी भाग में । भूटान की भौगोलिक स्थिति का विभाजन तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(1) दक्षिणी पहाड़ी का निचला भाग (2) घनदरुनी पहाड़ी भाग (3) ऊपरी पहाड़ी भाग [Southern foot hills, Inner Himalays Upper Himalays]

पहाड़ी का निचला भाग मैदानी क्षेत्र से 1500 मीटर की ऊँचाई तक जाता है जो कि 25 कि. मी. है । यह क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से ग्रीष्म है तथा ऊमम रहती है तथा वर्षा भी काफी होती है । लगभग समस्त क्षेत्र में नैपाली जाति बसी हुई है । नैपाली लोग या तो कृषि का धंधा करते हैं या छोटा मोटा व्यापार । इन नैपालियों को दो जातियों से संपर्क करने का न मौका कभी मिलता है और न कानून ने इन्हें संपर्क करने की छूट दी है । यद्यपि हाल में कानून में संशोधन से पारस्परिक संपर्क का अवसर मिलने लगा है लेकिन इस प्रकार की छूट नगण्य है । पिछले 100 वर्ष का इतिहास संकेत देता है कि नैपालियों

को भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग सांही रखा गया है। इस प्रकार के व्यवहार होने से उनको अपनी संस्कृति, धर्म तथा व्यक्तित्व उभर कर आया है। पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक विकास की योजनाओं के कारण पारस्परिक संपर्क का दौर शुरू होता दिखाई दिया है।

भूटान का दूसरा भौगोलिक क्षेत्र जिसको आन्तरिक पहाड़ी भाग कहा जाता है जो कि चौड़ी नदी घाटियों से घिरा हुआ है वह है : पारो, पुनारवा, थिबू, बूमलोग तथा ताशीगोम। इन क्षेत्रों में नालोप्स (Ngalops) तथा शारचोप्स (Sharchoops) रहते हैं। इन जातियों की अपनी अलग आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक शैली है। आर्थिक तथा राजनीतिक मत्ता का मादुर्भाव इन्हीं क्षेत्रों से शुरू हुआ। भूटान की स्वयं की अहमियत भी जो इतिहास तथा संस्कृति से आती है उसका भी श्रोगण इन्हीं क्षेत्रों से हुआ। यद्यपि शारचोप्स (Sharchoops) पूर्वी आन्तरिक भाग में रहते आये हैं लेकिन इन निवासियों को बौद्धधर्म में आरमसात करने से अब एकीकरण हो गया है। यद्यपि भूटान के मूल निवासी शारचोप्स जो तिब्बत की संस्कृति के साथ घुल-मिल गये हैं लेकिन फिर भी आज वे अपनी अलग संस्कृति, परम्परा, रहने के तौर-तरीके आदि के निर्वाह करने में एक गौरव अनुभव करते हैं। उनको देखने से यह अभी भी लगता है कि वे अपनी परम्पराओं में जकड़े रहने में एक सुख अनुभव करते हैं। परन्तु भूटान में आर्थिक विकास की गति धीरे-धीरे बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप यहाँ के मूल निवासियों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। एक काला पहाड़ (Black Mountain) जिसने पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से बिल्कुल अलग कर रखा था। अब संचार व्यवस्था उपलब्ध हो जाने से दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आसानी से सम्पर्क होने लगा है तथा एकीकरण का भाव भी देखने को मिलता है।

जहाँ तक भूटान का ऊपरी हिस्सा है (Upper Himalays) वह उत्तरी भाग कहलाता है जो अधिकतर वर्ष से ढका रहता है जिसके कारण वहाँ बसने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। इस सीमा का भाग भूटान को तिब्बत से भी जोड़ता है। इस हिस्से में चारागाह अधिक होने के कारण जानवरों की चराई के लिये Yaks भेज दिये जाते हैं और भूटान में Yaks भवेली की महत्वपूर्ण पूंजी भी है।

भूटान के तीन मुख्य क्षेत्रों में जनसंख्या बंटो हुई है और तीनों जगह अपने-अपने तरीके से जीविकोपार्जन करने का रास्ता भी उन लोगों के पास है। शासक वर्ग के आर्थिक हितों में हस्तक्षेप या हिस्सेदार बनने का प्रयास

किसी भी दिशा से नहीं हुआ। भूटान के मूल निवासी शार्चोप्स (Sharchops) यदि पूर्वी क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था अलग से चलाते थे जिसे हम स्वयं में पर्याप्त कह सकते हैं तो दक्षिण में नेपाली लोग कृषि तथा लघु उद्योगों के जरिये अपना जीविकोपार्जन करते रहे। जहाँ तक भूटान देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण उन लोगों का रहा जो तिब्बत में आये थे और अपने साथ बौद्ध धर्म भी लाये थे जिसको उन्होंने लागू किया। देश का व्यापार तथा Fiscal Policies पर नियंत्रण Ngaltos (नालत्स) का रहा। बौद्ध मठों तथा उससे सम्बन्धित धार्मिक परम्पराओं पर इन्हीं लोगों का नियंत्रण है। ग्रामतौर से हर बौद्ध परिवार से एक पुरुष वर्ग को मिश्रु (Monk) बनने के लिये भेजा जाता रहा लेकिन वर्तमान सन्दर्भ में अब यह परम्परा का निर्वाह कम हो रहा है। कम होने का कारण केवल यही है कि भूटान में आर्थिक विकास ने अपनी गति को ठीक दिशा में मोड़ लिया है और लोगों की आर्थिक विकास के सहयोग की आवश्यकता है।

उक्त गतिविधियों से दो प्रमुख बातें (तत्त्व) उभर कर आते हैं :—

(1) भूटानी समाज का इतिहास तथा दर्शन वहाँ के इतिहास की गतिविधियों से निर्माण हुआ है। जहाँ तक इतिहास की गतिविधियों का प्रश्न है वह पर्याप्त तथा प्रतिद्वन्द्वता तथा शोषण से परिपूर्ण है। भूटान की सामाजिक व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण तथा आधिपत्य धार्मिक तथा लौकिक मठाधीशों का था तथा मत्ता को प्राप्त करने का निरन्तर संघर्ष एक ग्राम बात समझी जाती थी। इस प्रकार की घटनाओं ने भूटानी समाज के हर सदस्य में अविश्वास व कुटिलता का भाव भर दिया तथा 'भूत्यों की व्यवस्था' को पूर्णतया भ्रष्ट कर दिया। 19वीं शताब्दी के अन्त तक पारस्परिक संघर्ष तथा अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ते रहने का तौर-तरीका लगातार चलता रहा। इसलिये हर भूटानी व्यक्ति में यदि अविश्वास व सन्देह की भूलक दिखाई देती है वह केवल अतीत के अनुभव का परिणाम है। आज आधुनिकरण तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का काम शुरू होने के बावजूद भी अपनी हुई बुराइयों को तब मिट नहीं पाई है।

भूटान की एकान्त रहने की नीति तक अपनी संस्कृति व परम्परा की रक्षा करने का रूढ़ संकल्प कुछ और वर्षों तक निम जाता यदि चीन की तिब्बत में गतिविधियाँ शुरू न हुई होती। चाहे वह गृह नीति हो या विदेश नीति-परिवर्तन सभी होता है जब कोई विशिष्ट परिस्थितियाँ अस्तित्व के लिये चुनौती बनकर सामने नहीं आतीं। चीन ने 1959 में तथा 1962 में क्रमशः जो कुछ तिब्बत तथा भारत के साथ व्यवहार दिखाया वह भूटान के लिये अत्यधिक भय व आतंक प्रस्तुत कर देने वाला था। भूटान को इस प्रकार की असाधारण परिस्थितियों से विश्वास हो गया कि अब पुरानी नीतियों में परिवर्तन करना अपरिहार्य है। यदि वह अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहता है। उक्त घटनाओं के घटित हो जाने के बाद ही भूटान ने अपने दरवाजे भारत के लिये खोल दिये और पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ।

1960 से पूर्व भूटान की अर्थव्यवस्था का स्वरूप केवल बार्टर व्यवस्था के समान था। चावल तथा हाथ से बुने हुए कपड़े ही बार्टर के माध्यम थे। वह रुपया जो भारत सरकार की ओर से Royalty के रूप में मिलता था, उसका प्रयोग या तो आवश्यक वस्तुओं के खरीदने में खर्च होते थे या राजा के शाही ठाठ बाट संजोने में। भूटान के दक्षिणी भाग में वैसे नेपाली लोग ही शेष थे जो या तो कृषि के माध्यम से या लघु उद्योगों के सहारे से भारत की सीमा से जुड़े हुए व्यापारियों के साथ मुद्रा का आदान-प्रदान तथा उसमें कुशलता प्राप्त कर चुके थे।

तिब्बती संस्कृति तथा धर्म का वर्चस्व तथा आधिपत्य जो वर्षों से रहा अब आधुनीकरण के प्रारम्भ करने से संकट में दिखाई देता है। अब नेपाली जातीय समस्या तिब्बती धर्म व संस्कृति के वर्चस्व को प्रभावित करने लगी है। अनुमान से नेपाली जनसंख्या आज लगभग भूटियाओं के बराबर हो गई है जो एक चिन्ता का विषय बन चुकी है। परिवार नियोजन की योजना एकपक्षीय नेपालियों पर लादी नहीं जा सकती। इसलिये तिब्बती लोगों की जनसंख्या की वृद्धि के लिये योजना सोची जा सकती है। नेपाली लोग बहु-पत्नीय जाति होने के कारण जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती है। नेपाली लोगों की वृद्धि 2.8% गति से बढ़ती है। जबकि भूटियाओं की 1.8% से। आने वाले कुछ वर्षों में भय यही है कि कहीं नेपाली लोग भूटियाओं से अधिक न बढ़ जायें जिसके फलस्वरूप वर्षों से चला आ रहा आधिपत्य हाथ से न निकल जाय। यह कोई आसान समस्या नहीं जिसका कोई हल निकल आये। साथ में भूटान एक इतना छोटा देश है जिसको और अधिक जनसंख्या की आवश्यकता है

जिससे देश के आर्थिक विकास में योग योगदान दे सकें। सिविक्रम का उदाहरण भूटानी शासकों के मामले है जहाँ नेपाली जनमंडया ने सिविक्रम का नवशा ही बदन दिया।

दक्षिणी भाग में रह रहे नेपाली लोगों का आर्थिक-राजनीतिक संस्थाओं में उचित स्थान न होने के कारण भी नेपालियों में घोर असंतोष है। पूर्व व वर्तमान नरेश ने नेपालियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के कुछ प्रयास किये हैं जिससे राष्ट्रीय चेतना का भाव समग्र रूप से जागृत हो। ऐसा कहा जाता है कि अब नेपालियों को आर्थिक-राजनीतिक मुख्य धारा में लाया जा रहा है और वह असंतोष कुछ कम भी हो रहा है लेकिन जिस गति से नेपालियों को सुविधाएँ मिलनी चाहिये बँसा नहीं हो रहा है। धर्म व भाषा दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर नेपालियों की शिकायत है। भूटान सरकार ने नेपालियों की धर्म व भाषा को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है। पहले नेपालियों को अपने त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता नहीं थी लेकिन अब यह छूट उनको दे दी गई है। पहले भूटान का राष्ट्रीय दिवस केवल थिफू राजधानी के आस-पास ही मनाया जाता था लेकिन अब दक्षिणी नेपाली भी राष्ट्रीय चेतना की परिधि में आ चुके हैं और उसका महत्व समझने लगे हैं। अन्तर्विवाह भी सपन्न कराने की ढील मिल चुकी है। राजा की बहिन की शादी एक नेपाली भूटानी से हुई है, यह इसका एक ज्वलंत प्रमाण है। अब राजा की ओर से नेपालियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ऐसा परिवर्तन करने के बावजूद भी आर्थिक-सामाजिक ढाँचे में विरोधामात्र दिखलाई देते हैं। राष्ट्रीय भावना तथा एकीकरण तभी संभव है जब आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएँ नेपालियों को सत्ता के पटल पर समान अवसर प्रदान कर सकें। छोटी मोटी सुविधाएँ केवल मन बहलाने की तो हो सकती हैं लेकिन ठोस, दृढ़ दिशा में सुधार अभी दिखाई नहीं देता। भूटान के धर्म व तिब्बती भाषा व उसकी संस्कृति में विरोधाभास होने के कारण राष्ट्रीय चेतना का भाव नेपालियों में आज संभव नहीं। भूटान में कोई ऐसी शक्तिशाली धर्म-निरपेक्ष या उससे जुड़ा हुआ संस्थागत आधार नहीं है। यद्यपि राष्ट्रीय एकता के लिए एक परिपक्व का गठन किया गया है जिसके सदस्य केवल राजा के सगे संबंधी लोग हैं जिसमें उसके बहन का पति भी है जो नेपाली है। परन्तु समस्या सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भावुकता से जुड़ी हुई है। सत्ता (Power), चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक, एक सीमा के

बाद तक साभेदारी हो सकती है उसके परे नहीं। भूटान का समस्त शाही परिवार उक्त समस्या से ग्रस्त है। एक ओर नेपालियों से यह अपेक्षा है कि वे राष्ट्रीय चेतना की मुख्यधारा से जुड़ जायें और दूसरी ओर उन्हें आर्थिक-राजनीतिक सुविधाओं से वंचित रखें—ऐसा होना संभव नजर नहीं आता। भूटान का राजतंत्र तथा वहां के लामा लोग या धार्मिक मठाधीश भूटान की सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक भूमिगत की रक्षा कर सकते हैं। जहां तक शिक्षण में रह रहे नेपालियों का मुख्यधारा में जुड़ जाना, आज की परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता।

भूटानी समाज को भी पदोन्नोपान की स्थिति में भर दिया है। जहां तक बौद्ध समाज की बात है—वह वर्गहीन तथा जातिविहीन है लेकिन पिछले 20 वर्ष के आर्थिक विकास ने विपमताएँ उत्पन्न कर दी हैं। 1960 से पहले भूटान की अर्थ-व्यवस्था स्वयं में पर्याप्त कृषि से जुड़ी वार्टर व्यवस्था थी जिसने आर्थिक-सामाजिक ढांचे को उन परम्पराओं तथा संस्कृति को प्रदान करने में सहायता की जिसका आर्थिक दृष्टिकोण अत्यधिक सीमित तथा नियंत्रित था। यह सीमित आर्थिक दृष्टिकोण केवल शाही परिवार तथा कुछ लोगों से निमित्त उच्च वर्ग व्यापार तथा आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। राज्य की आय अधिकांश स्वरूप में हुमा करती थी, नगद रूपों में नहीं। धर्म तथा कृषि से उत्पादित चीजें ही राज्य की Revenue हुमा करती थी। थोड़ा बहुत नगद रूपों की आवश्यकता की पूर्ति या तो Excise duty से हो जाती थी या भारत सरकार के द्वारा दी गई वार्षिक Subsidy से। 1950 के प्रारम्भिक काल में भूटान का Revenue Budget 100 लाख रु. (एक करोड़) से भी कम था। 1961 के बाद से वार्टर अर्थव्यवस्था समाप्त होती गई और उसका स्थान मुद्रा ने ले लिया। मुद्रा के चलन हो जाने से भूटान के विकास में एक जीवन आ गया है। उक्त विकास में भारत सरकार को श्रेय देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो भूटानी लोग आर्थिक विकास में सहयोग देते रहे वे एक नये उभरते वर्ग के रूप में सामने आने लगे हैं और उनका एक विशिष्ट वर्ग हो गया है। यह नया वर्ग शिक्षित है, युवक है, कम रुढ़िवादी है तथा इसकी जड़ें संपन्नता व समृद्धता से ओत-प्रोत हैं। इन 20 वर्षों में यह वर्ग भूटान के नये सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण तपका उभर कर आया है। परम्परावादी-रुढ़िवादी शिक्षु व लामा लोग अब नये उभरते हुए वर्ग के सामने पिछड़ से गये हैं। भूटान का भविष्य अब नये वर्ग के हाथों में जाता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि राजा का यह निरन्तर प्रयास है कि भूटान की संस्कृति व परम्पराओं की कीमत पर नये वर्ग के

नये-नये मूल्यों का सामंजस्य या मंतुलन तो बना रहे लेकिन नये मूल्य या आधुनिकीकरण का पक्ष देग पर हावी न हो। 1960 से पूर्व विनिष्ट वर्ग केवल परम्परावादी या लामा या भिक्षुओं का एक समूह हुआ करता था जो राजतंत्रीय व्यवस्था को मजबूत रखने में सहयोग देता था। धीरे-धीरे इन लोगों की शक्तियां तथा सुविधाएँ Middle class ने ले ली हैं और Monks तथा लामाओं को उन सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया है जो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। एक ज्वलंत उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि भटो के पुजारियों को किस प्रकार आधुनिक बताया जा रहा है या उनके दकियानुसी विचारों या दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिये क्या शैली अपनाई जा रही है। Monks या पादरियों को भी देश के आर्थिक विकास में सम्मिलित करने का प्रयास हो रहा है जो इससे पूर्व नहीं था। अतः सामाजिक स्तर पर परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा है। नया विनिष्ट वर्ग आक्रामक है और परम्परामो का केवल आवरण रखने पर विश्वास करता है। पुराना वर्ग अब घूमित हो रहा है लेकिन बिना किसी शक्ति के उसे किसी न किसी क्षेत्र में लगाये हुए है। इस प्रकार नये मूल्यों की व्यवस्था उभर रही है तथा पुराना परम्परावादी आधार धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। रोचक बात तो यह है कि जो लोग पुरानी दकियानुसी विचारधारा से चिपके हुए थे, वे अब देश के आधुनिक आर्थिक विकास की शैली को अपनाने में अपना गर्व समझते हैं और पुराने मूल्यों व विश्वासों को हेय-दृष्टि से देखते हैं।

वर्तमान संदर्भ में चिन्ता इस बात से नहीं कि पुराने मूल्य समाप्त हो जाते दिखाई देते हैं बल्कि चिन्ता तो भूटान की राजतंत्रीय व्यवस्था में इस बात की है कि भूटान में उभरता मध्यम वर्ग पूर्णरूपेण परिभाषित संस्थागत व्यवस्था की अनुपस्थिति में स्थायी आधार प्रस्तुत करने में असमर्थ दिखाई देता है। देर से या जल्दी एक दिन चला आ रहा परम्परागत संस्थामो में आशिक संशोधन लाना होगा तथा विकासशील समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल नया ढांचा प्रस्तुत करना होगा। किसी भी व्यवस्था को स्थायी रखना है तो उसमें संस्थागत परिवर्तन समय के अनुकूल निरन्तर करने पड़ेंगे। उसके बिना व्यवस्था सड़ जाती है और उसको स्वीकार नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, भूटान में आज आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक संस्थामो का स्वरूप किसी भी प्रकार से उल्टे हुए नये मूल्यों के साथ तारतम्य नहीं रखने। नये सामाजिक ढांचे का दृष्टिकोण आर्थिक विकास

के साथ बदल रहा है। भूटान की संसद (राष्ट्रीय सभा) का स्वरूप अभी भी परम्परागत है और उसमें कोई जीवन नज़र नहीं आता क्योंकि राष्ट्रीय सभा एक प्रकार से राजा का पर्याय है। राष्ट्रीय सभा का यद्यपि जन्म तो 1952 में ही हो गया था। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय समस्याओं का प्रश्न है—संसद एक मृत परिपद है। राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व भी विषमताओं से युक्त है। उसमें नये वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। राष्ट्रीय सभा में सार्वजनिक समस्याओं या विवादों के लिये कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं के बारे में संसद कोई बहस नहीं करती। यह ठीक है कि इस प्रकार की स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। जहाँ तक न्यायालय व्यवस्था का प्रश्न हो या कार्यकारिणी का प्रश्न हो—ये दोनों संस्थाएँ अभी भी प्राचीन ढाँचे पर चल रही हैं, जबकि नये वर्ग की विचार-धारा तथा दृष्टिकोण आधुनिक है। दोनों का तत्काल या समन्वय कितने दिन तक चलेगा—समय बतायेगा। भूटान आज के संदर्भ में बाहरी देशों से अपने विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में मदद लेने लगा है और विकास के लिये मूलभूत आवश्यकताओं के लिये वे भावन भी जुटाने हैं जिनको ढाला नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय प्रश्न यही है कि भूटान की आर्थिक नीति का क्या प्रारूप हो जो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अच्छा संतुलन बनाये रखे। राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की वर्तमान व्यवस्था शायद एक छोटे से विशिष्ट वर्ग की सहायता से काम चल जाय लेकिन घाते वाले वर्गों के लिये वर्तमान व्यवस्था पूर्णतया न केवल अनुपयुक्त है अपितु आपत्तिजनक भी बन जाय। निराशाएँ, कुंठाएँ, असफलताएँ शायद देश में आर्थिक व राजनीतिक उलझनें पैदा कर दें। जब तक पुरानी संस्थाओं में पुनः बदलाव नहीं आयेगा तथा उनमें पुनर्गठन की दिशा में नहीं सोचा जायगा, भूटान उन सभी समस्याओं से बिर जायगा जिनसे अन्य विकासशील देश पीड़ित हैं। गरीब व अमीर के बीच विषमताएँ अधिक गहरी होती जायें तो सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है और विद्रोह की भावना घर कर जाती है। जातीय समस्या अपना उग्र रूप धारण कर लेती है और कुछ दिन बाद वह राजनीतिक व्यवस्था में असंतुलन ला देती है। अतः समय की मर्यादा में राजतन्त्रीय व्यवस्था में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन अवश्य हो जो बदलती हुई परिस्थितियों के दबाव को सहन कर सके और तनाव को कम कर सके।

भूटान का आर्थिक विकास 1960 के बाद प्रारम्भ हुआ। इससे

पूर्व आर्थिक ढांचा स्थायी, स्वयं में संतुष्ट तथा भूमि व श्रम के बीच संतुलन की स्थिति थी। बाहर की दुनिया से संतर्क न्यूनतम था। 1960 के बाद से, यद्यपि ग्रामीण ढांचा बदला नहीं है, एक नया आधुनिक वर्ग उभर कर आ रहा है जिसके ऊपर अब तक नियंत्रण था। 1961 के बाद जब देश के विकास की प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना के रूप में शुरू हुई तो आर्थिक दृष्टि से वहां के समाज पर प्रभाव होना अपरिहार्य था। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्थ-व्यवस्था ने भूटान को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। 1971 तक भूटान भारत से शत-प्रतिशत सहायता लेता था और निर्भरता की स्थिति कुछ हल्की हुई जब भूटान ने भारत से अतिरिक्त विदेशी सहायता लेना शुरू किया। भूटान की तीसरी पंचवर्षीय योजना में भूटान ने अन्य स्रोतों से 15.8 मिलियन रुपये की आर्थिक सहायता ली तथा चौथी योजना में राशि बढ़कर 193 मिलियन हो गई। पांचवी योजना में भूटान ने विदेशी सहायता 521 मिलियन रुपये ली और भारत की सहायता 1340 मिलियन रुपये रही। इस प्रकार भूटान की नीतियों में परिवर्तन दिखाई दिया जहां तक आर्थिक सहायता लेने का प्रश्न है। यह बात स्पष्ट है कि भूटान भारत पर आर्थिक दृष्टि से पूर्ण निर्भर नहीं होना चाहता था और इसी इच्छा ने भूटान को अन्य देशों की ओर देखने के लिये बाध्य किया। दूसरा परिवर्तन जो भूटान की नीति में दिखाई दिया वह यह कि 1971 के बाद से भूटान की आर्थिक नीति का प्रारूप या गठन स्वयं भूटान के प्रशासक ही करते हैं। इससे पूर्व भूटान की आर्थिक नीति के बारे में भारत का योजना आयोग देखता था। 1972 में भूटान का स्वयं योजना आयोग का जन्म हुआ जिसकी देख-रेख स्वयं राजा करते हैं। इन परिवर्तनों ने भारत पर पूर्ण निर्भरता को कम किया है। इस आयोग के तीन भाग कर दिये गये हैं— 1. Planning 2. Resources 3. Statistics। ऐसा विभाजन करने के बावजूद भी काम उस पद्धति से नहीं हो पाता जैसा होना चाहिये। कारण यह है कि अनुमती व तकनीकी कर्मचारियों की कमी होने के कारण लोगों की जिम्मेदारी एक दूसरी जगह बदलती रहती है। कार्य की कुशलता तथा गति में अन्तर आ जाता है। ऐसा होने से नियंत्रण लेने का बिन्दु अन्तिम रूप से राजा पर ही केन्द्रित हो जाता है। लेकिन उक्त दो परिवर्तनों से भारत पर शत-प्रतिशत निर्भरता को अंशतः कम किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूर्ण निर्भरता राष्ट्र की मार्बगौमिक भाव में कमी ला रहा था और उसके अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे में कुछ फर्क पड़ने लगा था। इसलिये यह

आवश्यक समझा गया कि भारत पर पूर्ण निर्भरता में शीघ्र कमी होनी चाहिये और उस दिशा में काम हुआ ।

पंचवर्षीय योजनाओं को अमल में लाने के माग में बहुत-सी बाधाएँ आती रही हैं । उसमें सबसे पहली बाधा तो यही कि मूटान की अधिकांश जनसंख्या कृषि में लगी रहने के कारण कुशल तथा तकनीकी श्रमिकों की कमी आती रही है तथा इस प्रकार की कमी आने वाले वर्षों में भी रहेगी क्योंकि जनसंख्या का वितरण ही कुछ इस प्रकार का है । यद्यपि ग्रामीण लोगों को शहर के आर्थिक प्रलोभन का अभियान शुरू तो हुआ है जिसने गांव वालों को काम तथा अधिक पैसा मिलने के सासच से शहर की ओर गतिशील बनाया है लेकिन प्रभाव केवल आंशिक है । चूंकि शिक्षा तथा आर्थिक अवसर अब अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं इसलिये नई पीढ़ी के युवा वर्ग पुराने धंधों मानि कृषि का काम अब छोड़ने लगे हैं और आधुनिक व्यापार तथा धंधों में अपने आपको लगाने लगे हैं । दूसरा सामाजिक परिवर्तन जो आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास के साथ हो रहा है वह है 'मूल्यों का परिवर्तन' । नई पीढ़ी का युवा वर्ग अब धार्मिक भिक्षु या Monk बनना पसंद नहीं करते । पहले Monk बनना एक गर्व की बात समझी जाती थी । यह गर्व की भावना धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । इन प्रकार आर्थिक विकास के मूल्य व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो रहा है । उल्लेखनीय है कि अब तो काफी अधिक संख्या में Monks लोग देश के आर्थिक विकास में आगे आने के इच्छुक हो रहे हैं और वे धार्मिक कर्मकांड से मुक्ति पाना चाहते हैं । Monks की संख्या तो बताई नहीं जा सकती लेकिन संकेत बराबर मिल रहे हैं कि आर्थिक विकास व आधुनिकीकरण ने धार्मिक कर्मकांडियों को भी किसी हद तक आकर्षित किया है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल धन राशि पहली से दुगनी हो गई । इस योजना में प्राथमिकताएँ बदलीं और सड़क निर्माण से सामाजिक सेवाओं पर अधिक जोर दिया गया । शिक्षा पर 18%, कृषि पर 14% तथा स्वास्थ्य पर 8% । आवागमन के साधनों पर केवल 41% घट कर रह गया । इस योजना में मुद्रा का चलन अधिक गति से हुआ तथा मध्यम वर्ग भी इसी अवधि में अधिक उभर कर आया । एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी घटित हुआ जब 1968 में प्रणामनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का जन्म हुआ । राजा ने मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होने की भूमिका स्वीकार की । इस प्रकार राजा ने दो प्रकार की भूमिका घटा करना प्रारम्भ किया । एक ओर देव का अध्यक्ष और दूसरी ओर सरकार का अध्यक्ष । यह बात स्पष्ट हो गई कि अब भविष्य में प्रधानमंत्री का पद, जो 1965 तक जीवित रहा, कभी भी पुनर्जीवित

नही होगा और उसे हमेशा के लिये गमाप्त कर दिया गया। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जिसके अन्तर्गत राजा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में सक्रिय भाग ले सकता था।

जहाँ तक मुद्रा (Money) का चलन का संबंध है—इमने रहने के तीर तरीके में वदसाय प्रस्तुत किया तथा मुद्रास्फीति भी भूटान में दिखाई दी। चूँकि योजनाओं के लिये प्रतिबद्धता होने के कारण भूटान में Money तथा Men का प्रवेश एक साथ हुआ। इसलिये वस्तुओं की कीमतें भी उपभोग की मात्रा बढ़ने से ऊँची हो गईं। चीजों की कीमतें दुगनी हो गईं और Infrastructural Cost भी उसके साथ बढ़ गई। एक ग्राम आदिमी एक नये स्वरूप में उभरने लगा। एक प्रकार से, एक किसान को अपनी उत्पादित वस्तुओं की कीमत दुगनी मिलने लग गई। दूसरी ओर उसकी आवश्यकताएँ भी उसी गति से बढ़ी। बाटें अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति अपने चावल के बदले हाथ का बना हुआ कपड़ा लेकर अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन मुद्रा व्यवस्था में अब कपड़ा बाजार में बिकने लगा जहाँ हाथ के बुने वालों को ऊँचे दाम मिलने लगे। लेकिन हाथ के बुने हुए कपड़े की कीमत इतनी ऊँची हुई कि भारत के व्यापारियों ने उसी प्रकार का कपड़ा बनाने की नकल करना शुरू किया जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। भारतीय व्यापारियों ने भूटान में प्रवेश करना शुरू किया और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक दृष्टि से घाटा होने लगा। सरकार को भूटानी परम्परागत के स्वरूप के बने हुए कपड़ों पर बाहर से आना बन्द कर दिया जिससे स्थानीय व्यापारियों की जीविकोपार्जन पर प्रभाव न पड़े।

तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में राशि बढ़ाकर 135% हो गई जिसके अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दी गई तथा आवागमन (Transportation) पर राशि घट कर 20% ही रह गई। शिक्षा के मद पर राशि 19% बढ़ गई। कृषि 17% बढ़ा दी। सामाजिक सेवाओं पर कुल Outlay बढ़ कर 27% वृद्धि की गई। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस योजना में दिखाई दिया वह यह कि भूटान ने भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र मंडल से सहायता 3% बढ़ गई तथा आन्तरिक स्रोत में अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7% हो गई। इस योजना के अन्तर्गत यह भी अहसास हुआ कि भूटान अपनी सांख्यिक भाव को अच्छी तरह पहचानने लगा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय

आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये पड़ोसीय राज्य भरसक प्रयत्न में जुट गया है। भूटान अपनी योजना आयोग के कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई देने लगा। आर्थिक विकास में लग जाने के कारण अन्य आवश्यकताओं का जन्म हुआ। तकनीकी विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी। कई विद्यापियों को विशेषज्ञता हासिल करने के लिये विदेशों में भेजा गया। अधिक कुशल तथा होशियार विद्यापियों को विकास के कार्यक्रमों में समा दिया गया तथा कुछ पढ़े लिखे युवाओं को प्रशासनिक पदों पर आसीन कर दिया गया।

चौथी योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास से संलग्न कृषि, औद्योगिक पक्ष, Hydro power तथा Forestry थे। कृषि को अधिक प्राथमिकता दी गई। कुल खर्चा 1106 मिलियन रु० का 29% कृषि पर खर्च करने की योजना रखी गई—उद्योगों पर 16%। ऐसा केवल इसी उद्देश्य से किया गया कि अधिकांश लोगों को आर्थिक लाभ हो। भारत अभी भी सर्वाधिक आर्थिक सहायता (यानी 77%) में देने में नाम लिखवाता रहा। UN System से सहायता 3% से बढ़ कर 18% हो गई (यानी 6 गुनी)। आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भूटान ने दो वाचाओं पर विजय प्राप्त की। एक तो यह कि भूटान की गणतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकासशील देशों में आंकी जाने लगी और दूसरी ओर यह कि या यों कहा जाय कि भूटान अपनी 17वीं शताब्दी की छवि से दूर हो गया। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि में सहायता मिली। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास अब एक सूत्री कार्यक्रम बन कर सामने आया। शिक्षा पर अधिक जोर देने के कारण literacy 0% से बढ़ कर 10% हो गई। Asian Development Bank के सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि होती है कि भूटान ने आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में काफी विकास किया है। 1961 में भूटान में एक भी प्रशिक्षित भूटानी नहीं था। 1976 में लगभग सभी विभागों में प्रशिक्षित भूटानी तैयार होकर विभिन्न विभागों को कुशलता से देख रहे हैं।

पांचवी योजना के अन्तर्गत जो पांच वर्ष की व होकर 6 वर्ष की मानी गई है (1981-1987)—विशेष प्राथमिकताएँ अधिकांश लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होना तथा विकेन्द्रीकरण की नीति जो गांव तक पहुँचानी है।

पड़ा है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। देश के मूल्यों की ध्वस्तता में परिवर्तन हो रहा है तथा और अधिक परिवर्तन होने की संभावना है। मार्पिक विभाग हर देश में संस्कृति तथा मूल्यों में परिवर्तन करता रहा है। इसलिये भूटान कोई अपवाद नहीं होगा।

यद्यपि भूटान में निर्माण तथा सामाजिक सेवाओं के कार्यों में 1961 के बाद से लगातार प्रगति हो रही है लेकिन फिर भी भूटान की पर्यवस्था का मूल स्वरूप परम्परागत ही है। 90 प्रतिशत लोग कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से ही जीविकोपार्जन करते हैं। भूटान का GDP (Gross domestic Product) 1500 million NU है तथा प्रति व्यक्ति आय लगभग 125 डालर है जो दुनिया में सबसे कम प्रांकी गई है। कृषि तथा उससे सम्बन्धित उद्योगों से जो उत्पादन होता है वह सम्पूर्ण परेल उत्पादन का भाग है, Forestry से 15%, Industry तथा Mining से 5% तथा विविध स्रोतों से 30%। मुख्य खाद्य फसल गेहूं, चावल, जौ, मक्का है परन्तु देश की पर्याप्त समस्या की पूर्ति के लिये 20% प्रतिरिक्त खाद्य पदार्थों का बाहर से आयात करना पड़ता है। मुख्य उद्योग है—Cement Factory, A Fruit Processing Factory तथा तीन Distillaries है। लगभग 2000 आदमियों को रोजगार मिला हुआ है या सम्पूर्ण Labour Force का एक प्रति मजदूर औद्योगिक क्षेत्रों में लगा हुआ है। लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भूटान भी खनिज पदार्थों से वंचित नहीं है लेकिन उसकी किस्म अपेक्षाकृत घटिया होने के कारण उनका ग्रन्थ बाजारों में स्थान नहीं है। कुछ खनिज स्रोतों के स्थान इतने दुर्गम हैं जहां पहुँचना या निकट जाना अधिक मुश्किल है। केवल कोयला, dolemite, Slate तथा Lime stone स्थानों में कुछ ही मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। भूटान जंगलों से भरपूर घिरा हुआ है। भूटान Power resources के क्षेत्र में भी परिपूर्ण है। हानि ही में इन दो क्षेत्रों पर जो प्रयास हुए हैं। वे भूटान के जीवन स्तर बढ़ाने में मदद दे सकते हैं।

भूटान की आधुनिकीकरण की नीति ने विकास स्तरों पर अपना अधिक बढ़ाया है लेकिन Taxes को generate करने की क्षमता कम है। राष्ट्रीय स्तर तथा आमदनी में बहुत बड़ा फासला है। 1984 के Fiscal year के अन्त तक जो हिमाव बिठाया है वह यह है कि GDP (Gross

Domestic Product) 40 percent है तथा Revenue 10% है। 1970 के बाद से Modernization की योजना में सर्व और घामदनी के बीच बहुत बड़ा फासला रखा है जिसकी पूर्ति भारत सरकार से होती आ रही है। राष्ट्रीय त्चों पर नियंत्रण करने के लिये भूटान ने केन्द्रीय सेवाओं पर 3% की कटौती कर दी (1981-82)। उन केन्द्रीय कर्मचारियों को जिलों में Decentralization Programme में बाहर भेज दिया गया (1982-83) 1982-83 में भूटान सरकार ने अपनी समस्त workshops, Telephone Company तथा Tourist Agency को Private Management को सौंप दिया। ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार के कदम उठाने से efficiency में वृद्धि होगी और सरकार की Subsidies में कमी होगी।

भूटान के Foreign Trade में वृद्धि हुई है। भूटान का Imports Gross Domestic Product का 40% है, जबकि Exports 10%। लगभग भूटान का Trade भारत में ही है। भविष्य में बंगला देश, नेपाल तथा श्रीलंका से होने की सम्भावना है। भूटान के लिये निकटतम बाजार भारत का ही पड़ता है। भूटान में Imports बहुत कुछ Aid Programme के अन्तर्गत आता है। भारत के अलावा भूटान का अन्य देशों से व्यापार 1979 से शुरू हुए थे लेकिन उनकी उपलब्धियां नगण्य ही हैं।

Development Strategy

भूटान के विकास व निर्माण की योजनाओं का प्रारम्भिक काल उन प्राथमिकताओं से भरा हुआ था जो उसके अस्तित्व के लिये अनिवार्य थे। लेकिन बाद में यानि देश की पांचवी योजना में (1980-81 से 1986-87) प्राथमिकताएँ पूर्ण रूप से बदल गईं। पांचवी योजना में कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। कृषि में विकास यदि करना है तो स्थानीय स्रोतों पर निर्भर रहना होगा तथा स्थानीय नेतृत्व की भूमिका अधिक महत्व रखेगी। खाद्य क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का निरन्तर प्रयास है।

भूटान के जंगलों पर देश की आर्थिक योजना बहुत कुछ निर्भर है। इस समय भूटान में टिम्बर का अनुमान (500 मिलियन Cubic meters) है, जबकि हर वर्ष टिम्बर जो काटा जाता है वह केवल 2.5 million Cubic meters है। जबकि वास्तव में व्यापार में काम में आने वाला टिम्बर की मात्रा केवल 3 लाख Cubic meters है (हर साल)।

पाचवी योजना में यह प्रयास किया गया था कि भूटान के जंगलों की लकड़ी का सही प्रयोग हो। जंगलों में जाने वाले दुर्गम रास्तों पर भी सहज सड़क बन जाये। सरकार अभी भी लकड़ी के लट्टों तथा सागवान लकड़ी के निर्यात पर नियन्त्रण रने हुई है। अब लकड़ी के कारखानों का निर्माण शुरू हो गया है। 1983 में लकड़ी पर आधारित औद्योगिक Complex का निर्माण हुआ है जिसमें Plywood, Black board तथा Door frames के उपलब्ध कराने की सुविधा होगी। इसका उत्पादन सिर्फ भारत को निर्यात करने का रहेगा। दूसरा Complex भी 1985 तक बनने की मागा है। इस Complex के निर्माण में आर्थिक सहायता UNO, Kuwait से आयेगी।

यद्यपि भूटान ने अपने देश में मुद्राओं व सिकों का चलन 1950 में कर दिया था लेकिन वास्तविक रूप से भूटान की मुद्रा का चलन 1960 के बाद से माना जाता है क्योंकि आर्थिक विकास के लिये असली कदम 1961 की पंचवर्षीय योजना से उठाये गये। इसके फलस्वरूप भारतीय रुपया भा नोट भूटान में सामान्य से स्वीकृत किये जाते हैं। NU की मुद्रा भूटान में पहली बार 1974 में चलन में आई। माघ में भूटान के दूर क्षेत्रों में अभी भी डाटर की अर्थव्यवस्था है। यदि आर्थिक संस्थाओं का जिक्र करें तो भूटान के नाम की एक बैंक है जिसका नाम बैंक ऑफ भूटान है तथा तीन गैर बैंक सस्थाएँ हैं। बैंक तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से वषत का माघ अंशतः फैलाया है।

सबसे महत्वपूर्ण भूटान के Industrialization programme में पानी के स्रोतों का सही दिशा में प्रयोग है जिससे देश को पानी के प्रयोग से जो बिजली प्राप्त होगी वह अर्थव्यवस्था को संतुलित रखेगी। Chukhe Hydel Project, जिसका निर्माण 1974 से शुरू हुआ था, अब लगभग पूरा हो गया है। यह Project भूटान का सबसे बड़ा निर्माण कहा जा सकता है। इस Project की Highest Capacity 336 Megawatts है। इस Project से अंशतः बिजली भूटान प्रयोग में लायेगा और अधिकांश बिजली की मात्रा पश्चिमी बंगाल को भेजी जायेगी। इससे जो भूटान को revenue प्राप्त होगी वह Loan के अदा करने में adjust होगी। भारत ने उक्त Project के लिये लगभग \$ 200 million रु दिया है। जिसमें 60% grant के रूप में और 40% Loan। Loan की 15 वर्ष में चुकाना है जिसकी ग्याज दर 5% होगी।

भूटान में Lime Stone का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। Cement Plant बनाने के लिये Lime Stone का प्रयोग होता है इसलिये उन क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जा रहा है जिससे इस दिशा में भी पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। 1981 में पहला Cement Plant का श्रीगणेश हुआ था। इस Factory की उत्पादन शक्ति एक दिन में 300 metric tonnes सीमेन्ट निकालने की है। लगभग आधी मात्रा तो सीमेन्ट Export कर दिया जाता है और सीमेन्ट ही भूटान से सबसे ज्यादा बाहर जाता है। दूसरा Cement Plant जिसकी Capacity 1500 metric-tonnes प्रतिदिन निकालने की है, 1985 में पूरा हो गया था। इसके अतिरिक्त एक Calcium Carbide Factory भी शुरू हो गई है जो Lime Stone Deposits का प्रयोग करेगी। इससे उत्पादित माल का निर्यात भारत को होगा।

Public Sector की भूमिका को संतुलन में लाने का प्रयास—

पिछले दो दशक से आधुनिकीकरण की दिशा में जो प्रयास किये गये हैं उससे लगता है कि सरकार ने अपनी शक्तियों का अधिक केन्द्रीयकरण अपने हाथ में ही रखा जिसके फलस्वरूप लोगों में आत्म निर्भरता की भावना जागृत नहीं हो पायेगी। इसीलिये पाँचवी योजना में Decentralization की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। लगभग कुल खर्च में से $\frac{1}{4}$ भाग उन Projects पर होगा जो स्थानीय आधार पर बनाये गये हैं।

एक प्रश्न यही है कि राजतंत्रीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा ? जब आर्थिक विकास घर्म तथा संस्कृति की अलग से व्याख्या करेगा तथा नये मूल्य क्या पुराने मूल्यों को हटाने में सफल होंगे। □□

भूटान में राजतन्त्र और उसका भविष्य

जिम प्रकार नेपाल, अफगानिस्तान, स्विटजरलैण्ड स्वतन्त्र देश हैं वैसे ही भूटान भी है। सन् 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो हिमाचल के अंचल में स्थित तीन राज्य ऐसे थे जिनकी गणना संवैधानिक दृष्टि से भारतीय राज्यों में नहीं थी। एक था नेपाल दूसरा था भूटान और तीसरा सिक्किम। सम्प्रभुता की दृष्टि से ब्रिटिश शासन काल में सिक्किम की स्थिति एक संरक्षित राज्य की, नेपाल की एक सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य की तथा भूटान की प्रद्वे-सम्प्रभुता राज्य की थी।

भारत के स्वतन्त्र होने पर नेपाल की सम्प्रभुता यथावत बनी रही। उसमें कोई अन्तर नहीं आया। सिक्किम के अधिकांश नागरिकों की इच्छाओं का आदर करते हुए सिक्किम को 1975 में भारत में मिला लिया गया। सन् 1949 में जो भारत-भूटान सन्धि हुई उसकी धारा 2 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भूटान विदेशी मामलों में भारत के मार्ग-दर्शन का अनुसरण करेगा। यह प्रावधान कोई नया नहीं है। 1910 की ब्रिटिश-भूटान सन्धि में भी यह प्रावधान था। किन्तु इस प्रावधान के कारण भूटान की सम्प्रभुता कुछ लण्डित होती है और इस कारण भूटान की सम्प्रभुता की स्थिति प्रद्वे-सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य की है।

भूटान एक पहाड़ी राज्य है। यह छोटा भी है क्योंकि उसका कुल क्षेत्रफल 18000 वर्गमील तथा 47000 वर्ग किलोमीटर तथा सन् 1971 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या 13 लाख है। दुर्गम पहाड़ियों से परिवेष्टित इस छोटे से भू-भाग के आन्तरिक भागों में भी आवागमन सुगम नहीं है। उत्तर-दक्षिण अभिमुख पर्वत-श्रेणियों के कारण यह छोटा भू-भाग अनेक परस्पर अलग-थलग उपभागों में विभक्त हो गया है। इन श्रेणियों की मध्यवर्ती घाटियों में ही भूटान की प्राकृतिक संरचना का उसकी धार्मिक आदि का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

भूटान में राजतन्त्र की स्थापना इसी
किन्तु एक राजनीतिक इकाई के रूप में

चुका था एवं यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो नालन्दा विश्वविद्यालय के स्नातक पद्मनाभ नामक बौद्ध भिक्षु के आगमन के साथ आठवीं शताब्दी में सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ ।

सत्रहवीं शताब्दी से लेकर 1907 ई. में राज्यतन्त्र की स्थापना पर्यन्त की दीर्घ अवधि को भूटान के राजनैतिक इतिहास में सत्ता केन्द्र विवर्तन काल माना जा सकता है । आरम्भ में धर्म राज की सत्ता सर्वोच्च थी । कालान्तर में लगभग समान शक्ति सम्पन्न दो सत्ताओं का उदय हुआ— एक धर्म राज और दूसरा देव राज । उन्नीसवीं शताब्दी में पोनलोपो के रूप में क्षेत्राधिकारियों की भत्ता प्रबल रूप में उभर कर आई । देवराज प्रबल पोनलोपो का मनोनीत व्यक्ति मात्र रह गया । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में विभिन्न पोनलोपो में जो भयंकर संघर्ष चला उनके परिणाम-स्वरूप 1907 में राज्यतन्त्र की स्थापना हुई जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों ने भी अपना योगदान किया । सन् 1903 में धर्मराज के निधन के पश्चात् उनका अवतरण नहीं हुआ । इससे भी भूटान में वंशानुगत राज्यतन्त्र की स्थापना का मार्ग सुगम हुआ ।

धर्म राज की अवतरण-व्यवस्था के प्रसंग में इतना उल्लेख करना है कि यद्यपि तीन प्रकार का अवतरण (शरीर, वाणी और स्मृति का) मान्य था किन्तु व्यवहार में स्मृति के अवतरण की ही प्रधानता थी । अवतरण की अवधारणा में भूटानियों की अद्वैत श्रद्धा है, अतः यह स्पष्ट है कि धर्मराज के अवतरण का पतृक राज्य तन्त्र के मुद्द होने में जो प्रारम्भिक वर्षों का योगदान रहा, वह नगण्य नहीं है ।

भूटान के राजा की ड्रक ग्यालपो संज्ञा है । इसके विपरीत सिक्किम का राजा चोगियाल कहलाता था । दोनों शब्द सर्वोच्च अधिकारी के लिए प्रयुक्त होते हैं किन्तु इनमें अन्तर यह है कि सांसारिक विषयों के सर्वोच्च अधिकारी को ड्रक ग्यालपो एवं सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों विषयों के सर्वोच्च अधिकारी को चोगियाल कहा जाता है । व्यवहार में भी भूटान के ड्रक ग्यालपो की यह नीति रही है कि वे जनता की धार्मिक आस्थाओं को पूरा सम्मान देते हैं तथा उनमें हस्तक्षेप नहीं करते ।

भूटान में राज्य तन्त्र का जीवन केवल 73 वर्ष का है । इस समय

जैसा उल्लेख किया जा चुका है प्रथम दो डूक ग्यालपो का पूरा ध्यान 1907 में नव-स्थापित राज्यतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने में सया रहा। इस दिशा में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1. भूटान की राजधानी को पश्चिमी भाग से हटा कर पूर्वी भाग में स्थानान्तरण किया गया क्योंकि वह वांकचुंग लोगों का गढ़ था तथा आनुवंशिक राज्यतन्त्र के डूक ग्यालपो वांकचुंग वंश के थे।

2. शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में जोंग पीनों या क्षेत्रीय अधिकारियों की शक्ति को निर्मूल किया गया। 1907 से पूर्व जोंगपीनों का पद पैतृक सा बन गया था। राज्यतन्त्र की स्थापना के उपरान्त जोंगपीनों की नियुक्ति स्वयं भूटान नरेश द्वारा की जाने लगी। अब तो भूटान में बितने जिलापीन या जोंगपीन हैं वे सब डूक ग्यालपो द्वारा नियुक्त हैं। वे या तो राजा के सान्निध्य में हैं या राज्य कर्मचारी हैं।

3. भूटानी लामाओं के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया में अनेक बातों का समावेश होता है जैसे धार्मिक बातों में राज्य का अहस्तक्षेप, भूटानी प्रमुख लामा की नियुक्ति, शर्न-शर्नः राज्य के कारबार में लामाओं के प्रभाव को कम करना, लामा-परम्परा के अनुसार धार्मिक भावनाओं आदि के प्रति पूर्ण सम्मान आदि।

4. भूटान को बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने की चेष्टा की गई। इसके अन्तर्गत आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का अभाव, सड़क निर्माण कार्यक्रमों का बहिष्कार, गैर-कानूनी पर्यटक जो फिर भूटान पहुँच जाए उनकी गतिविधियों पर निगरानी आदि। यही कारण था कि मन् 1958 में जवाहर लाल नेहरू की भूटान यात्रा के समय तक भारत-भूटान संयोजक किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था।

तीसरे डूक ग्यालपो ने यह अनुभव कर लिया कि भूटान को श्रेष्ठ संसार से भाज के वातावरण में पूर्णतया अलग रख सकना असम्भव है। अतएव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में सुधारों का संसारम्भ किया गया।

उल्लेखनीय बात यह है कि जो भी शासन व्यवस्था अन्य क्षेत्रों में

चौथे ड्रक ग्यालपो राजगद्दी पर ग्राह्य हैं। आनुवंशिक राज्यतन्त्र भूटानी परम्परा के अनुरूप नहीं था। राजनीतिक इकाई के रूप में भूटान के उदय से घर्मराज और देवराज के दो सर्वोच्च पद रहे। घर्मराज के अवतरण की व्यवस्था भी एवं देवराज का नामा-समुदाय द्वारा चयन होता था। आनुवंशिक का भूटान की राज्य व्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। छतना एवं 1907 में जब आनुवंशिक राज्यतन्त्र की स्थापना की गई तो भूटान एवं वहां की जनता के लिए यह नई चीज था। योग्य और शक्तिशाली किसी व्यक्ति का सर्वोच्च शासक बने रहना एक बात है और उस पद को आनुवंशिक बना देना भिन्न बात है। अतएव नवजात आनुवंशिक राजतन्त्र का मुद्दा बनाने में ही यदि प्रथम दो ड्रक ग्यालपो का समय बीता तो कोई आश्चर्य नहीं। सन् 1907 से 1952 तक किसी भी प्रकार के राजनीतिक सुधारों की ओर उन्मुखता के कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ते। दो विश्व युद्ध विश्व व्यापी आर्थिक मंदी आदि के क्षुब्ध वातावरण में अपने प्राकृतिक दुर्ग रूपी कुटीर सम देश में अप्रगतिशील परम्परा जीवन यापन करते हुए भूटानी अविचल बैठे दिखाई पड़ते हैं। गैरभूटानी अन्वेषकों का राजनीतिक-सुधार विहीन इस स्थिति पर आँसू बहाना व्यर्थ है।

दोमबी शताब्दी के चतुर्थ चरण में वास्तविक मत्ता सम्पन्न राजतन्त्र एक पुरावशेष ही माना जाता है। किन्तु वह यदि भूटान में है और बिना किसी शासन संकट के चल रहा है तो इसके प्रबल कारण होने चाहिए। प्रबल जनमत के विरोध के समक्ष ईरान के भूतपूर्व शाह को कोरे सेना बल के महारे टिके रहना असम्भव हो गया एवं उसे अपने देश और सिंहासन दोनों से हाथ धोने पड़े। भूटान का जनमत राजतन्त्र के विरुद्ध क्यों नहीं हो पाया है—इसकी छानबीन भी समीचीन होगी। इस प्रसंग में भूटान की शासन प्रणाली के उन तत्त्वों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा जो राज्यतन्त्र विरोधी शक्तियों को उभरने का म्यूनतम अवसर देने हैं। साथ ही शासन प्रणाली की उन विशेषताओं को भी प्रकाश में लाना होगा जो प्रगति-उन्मुख होने पर जनमत को राज्यतन्त्र के समर्थक बनाये रखने में सहायक हैं।

जो अब तक की स्थिति है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भूटान नरेण ड्रक ग्यालपो सम्पूर्ण शक्तियों का केन्द्र है। वह उन सभी गतिविधियों का उद्गम स्रोत है—जिनका सूत्रपात गत तीस वर्षों में भूटान के जीवन की प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए किया गया है।

जैसा उल्लेख किया जा चुका है प्रथम दो ड्रक ग्यालपो का पूरा ध्यान 1907 में नव-स्थापित राज्यतन्त्र की जड़ों को मजबूत करने में लगा रहा। इस दिशा में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1. भूटान की राजधानी को पश्चिमी भाग से हटा कर पूर्वी भाग में स्थानान्तरण किया गया क्योंकि वह वांकचुंग लोगों का गढ़ था तथा आनुवंशिक राज्यतन्त्र के ड्रक ग्यालपो वांकचुंग वंश के थे।

2. शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया में जोंग पौनो वा क्षेत्रीय अधिकारियों की शक्ति को निर्मूल किया गया। 1907 से पूर्व जोंगपौनों का पद पतृक सा बन गया था। राज्यतन्त्र की स्थापना के उपरान्त जोंगपौनों की नियुक्ति स्वयं भूटान नरेण द्वारा की जाने लगी। अब तो भूटान में जितने जिलाधीश या जोंगपौन हैं वे सब ड्रक ग्यालपो द्वारा नियुक्त हैं। वे या तो राजा के खानदान के हैं या राज्य कर्मचारी हैं।

3. भूटानी लामाओं के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया। इस प्रक्रिया में अनेक बातों का समावेश हुआ है जैसे धार्मिक बातों में राज्य का अहस्तक्षेप, भूटानी प्रमुख सामा की नियुक्ति, शनैः-शनैः राज्य के कारखानों में लामाओं के प्रभाव को कम करना, लामा-परम्परा के अनुसार धार्मिक भावनाओं आदि के प्रति पूर्ण सम्मान आदि।

4. भूटान को बाहरी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखने की चेष्टा की गई। इसके अन्तर्गत आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का अभाव, सड़क निर्माण कार्यक्रमों का बहिष्कार, रैर-कानूनी पर्यटक जो फिर भूटान पहुँच जाए उनकी गतिविधियों पर निगरानी आदि। यही कारण था कि सन् 1958 में जवाहर लाल नेहरू की भूटान यात्रा के समय तक भारत-भूटान संयोजक किसी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था।

तीसरे ड्रक ग्यालपो ने यह अनुभव कर लिया कि भूटान को शेष संसार से आज के वातावरण में पूर्णतया अलग रख सकना असम्भव है। अतएव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में सुधारों का समारम्भ किया गया।

उल्लेखनीय बात यह है कि जो भी शासन अथवा अन्य क्षेत्रों में

प्रगति-मूलक चरम उठाए गए उनमें यह ध्यान रखा गया कि ये विकामात्मक हों, विप्लवकारी न हों।

सौगड प्रथम राष्ट्रीय सभा की स्थापना 1953 में की गई। उसके गठन में सभी क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधित्व का तो प्रावधान किया गया किन्तु पाश्चात्य ढंग की निर्वाचन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। न बालिग मताधिकार है, न गुप्त मत पद्धति है और न प्रत्यक्ष निर्वाचन है। भूटान के केवल दक्षिणी भाग में निर्वाचन होता है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में भूटानी नागरिकता प्राप्त नेपाली निवास करते हैं। वहाँ भी पारिवारिक मत प्रणाली अपनाई गई है। प्रत्येक परिवार का एक मतदाता होता है और उस मत को परिवार का मुखिया ही सामान्य रूप से दाखलता है। भूटान के शेष तीन भागों में अर्थात् पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भूटान में राष्ट्रीय सभा सदस्यों का चयन होता है। जिलाधीश गांव के मुखियों तथा परिवारों के बालिग मुखियों की सभा करता है तथा यह प्रयास रहता है कि सर्व सम्मति से सदस्य का चयन हो जाए। किसी एक व्यक्ति पर सहमति न होने पर चयन का निर्णय अद्वैत के सहारे छोड़ दिया जाता है। गोली बालकर या इसी से मितली-जुलती पद्धति से चयन कर लिया जाता है। इस पद्धति के गुण-दोषों पर टिप्पणी करना यहाँ उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि शासन में जनमत को स्थान देने की भूटान ने अपनी पद्धति अपनाई है।

राष्ट्रीय सभा में सामाजिकों का भी प्रतिनिधित्व होता है। किन्तु वहाँ भी केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान है।

राष्ट्रीय सभा में भूटान नरेश द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी भी होते हैं।

इस प्रसंग में यह बात उल्लेखनीय है कि सन् 1973 में सौगडू के समक्ष यह प्रश्न आया कि दक्षिण-भूटान की भाँति सम्पूर्ण भूटान में निर्वाचन पद्धति को लागू कर दिया जाए तो सौगडू ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया।

भूटान के जनजीवन में जो विशिष्ट लोग छाए हुए हैं—वे राज परिवार के हों, लामा समुदाय के हों, अथवा परम्परागत कुलों वर्ग के हों—सभी दृष्टिकोण फूँक-फूँक कर कदम बढ़ाने का प्रतीत होता है। सौगडू में किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए यह प्रावधान है कि उसके पक्ष में कम से कम

दो-तिहाई मतों का समर्थन होना चाहिए। ऐसी कठोर व्यवस्थाओं/इस बात की चोटक है कि भूटान का विशिष्ट वर्ग परिवर्तन के विरोध में न होते हुए भी उसकी दिशा और गति को इस प्रकार नियमित करना चाहता है कि अधिक सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों की गति मन्द्यर भले हो रहे किन्तु वे बातावरण को न्यूनतम सीमा से अधिक शुद्ध करने वाला न हो।

भूटान की न्याय प्रणाली में भी यही दृष्टिकोण स्पष्ट भ्रजकता है। नीचे से ऊपर तक सभी न्यायालयों का यह तथ्य रहता है कि वादियों-प्रतिवादियों के मध्य भगड़ों को समझौते से तै कराराया जाए। कानून की बारीकियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा एक पक्ष को विजयी और दूसरे पक्ष को पराजित घोषित करने में न्याय के दर्शन करने की परम्परा वहाँ विकसित नहीं होने दी गई है। कानून की बारीकियों के आधार पर महिनों-घण्टों की समस्या के पश्चात् जो न्याय प्राप्त होता है वह जटिल समाज व्यवस्था में विभुद्ध बरदान होने पर भी सम्भवतः आवश्यक समझा जाय किन्तु भूटान की सरल समाज-व्यवस्था में यदि उसे अभिज्ञाप माना जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। अतएव गैर-भूटानियों द्वारा भूटानी न्याय प्रणाली को हास्यास्पद मानना या समझना इसी बात का चोटक है कि भूटानी न्याय व्यवस्था को वहाँ परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा नहीं की गई।

यह तो तथ्य है कि राष्ट्रीय सभा के विधान में जो 1953 में लागू किया गया वह प्रावधान था कि ड्रक ग्यालपो की स्वीकृति होने के पश्चात् ही उसके द्वारा पारित किया गया कोई प्रस्ताव कानून बन सकता था। सौगडू के गठन में ही यह सतर्कता बरती गई थी कि उसके निर्णयों में कोई आतुरता न माने जाए। उसके पश्चात् भी ड्रक ग्यालपो का निषेधाधिकार यह स्पष्ट कर देता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में वैयक्तिक अथवा खानदानी द्वेष, वैमनस्य या महस्यकाक्षा को प्रत्यक्ष अथवा प्रच्छन्न रूप से उग्र रूप धारण करने से पूर्व ही प्रभावहीन बनाना आवश्यक समझा गया। ड्रक ग्यालपो की पहल पर यह निषेधाधिकार तो सन् 1973 में समाप्त हो गया। किन्तु यह व्यवस्था तो अब भी यह देखी गई है कि ड्रक ग्यालपो के मन में किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में आशंका हो तो यह सौगडू में अभिज्ञापण देकर उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता है। ड्रक ग्यालपो का पद आनुवंशिक ही नहीं प्रभावी भी है और जब तक भूटानी विशिष्ट वर्ग के लोग भूटान को राजनीतिक इकाई बनाये रखने में तीव्र रुचि रखते हैं एवं इस हेतु

राज्यतन्त्र को आवश्यक समझने हैं तब तब भूटान नरेश का अप्रभावी बनने का प्रयत्न भी निष्फल ही रहेगा। इस विचार के मूल में स्वयं भूटान की विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं। स्थल-रुद्ध पहाड़ी छोटा देश, स्वकीय धर्म प्रधान संस्कृति से जगरी एवं बिगरी हुई थोड़ी जनसंख्या, विभिन्न सांस्कृतिक विचार धाराओं के दो विजात देशों के अर्थात् चीन और भारत के मध्य स्थिति, एवं अग्रदिग्ध स्वातन्त्र्य प्रेम-प्रेमी बातें हैं जो भूटानियों को गैर-भूटानी ध्यतियों, विचारों पद्धतियों, तथा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी समस्याओं के प्रति अत्यन्त शंकाजु बनाए हुए हैं। उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में विश्व के रगमच पर घटित घटना चक्रों के अनुभव ने इस शका को और भी अधिक बढ़ा दिया है। किन्तु भारत एवं अन्य विदेशों में शिशित उदीपमान विशिष्ट वर्ग ज्ञान-विज्ञान, टेक्नोलॉजी के सुफलों से भूटान को परिपुष्ट देखने को आतुर है।

इस उदीपमान विशिष्ट वर्ग में उन भूटानी-नागरिकता प्राप्त नेपालियों का उल्लेख आवश्यक है जो भूटानी राज्यतन्त्र व्यवस्था के विरोधी हों या न हों किन्तु भक्त नहीं हैं। वे राष्ट्रीय सभा सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न बनाने के प्रबल समर्थक हैं। मूल भूटानी और भूटानी नेपालियों के बीच एक दरार है जो इस बात से स्पष्ट भलकती है कि दक्षिण भूटान में जहाँ भूटानी-नेपाली बसे हुए हैं, निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था है जबकि भूटान के अन्य तीन भागों में पूर्व, पश्चिम और मध्य चयन-पद्धति है। यह दरार अन्तर्निहित सन्देह की भी चोतक है।

जैसा उल्लेख किया जा चुका है भूटानी नागरिकता प्राप्त नेपाली भूटान के दक्षिण भाग में बसे हुए हैं। इस भाग की सागर-स्तर से ऊँचाई 2500-3000 फीट है। भूटान के शेष तीन भागों की सागर-स्तर से ऊँचाई 1 हजार से 14-15 हजार फीट तक है एवं यहाँ मूल भूटानियों की वस्तियाँ हैं। जब कभी कोई भूटानी-नेपाली कार्यवश अथवा वैसे ही वहाँ पहुँच जाता है तो सन्देह-दृष्टि का शिकार बने बिना नहीं रहता। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि कम से कम निकट भविष्य तो भूटान के इन दो प्रकार के नागरिकों का राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मत होकर शान्त या अशान्त तरीके से अपनी आवाज को बुलन्द करना अत्यन्त सन्दिग्ध है।

भूटान में राजनीतिक दल नहीं हैं। आधुनिक प्रकार के राजनीतिक

दलों के पनाने के लिए अनुकूल जलवायु मैदानी-स्थलों में उपलब्ध होती है। पहाड़ी इलाकों में नहीं। सन् 1952-53 में दक्षिणी भूटान में बसे कुछ भूटानी-नेपालियों ने भूटान-कांग्रेस की स्थापना की थी और यह सोचा था कि उसकी गति-विधियों का संचालन केन्द्र भारत के किसी स्थल पर होगा। किन्तु भारत सरकार के अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी रूप में सहायता समर्थन के अभाव में उसका जीवन अवस्था में ही अन्त हो गया।

सारोश यह है कि भूटान का जहाँ जन-जीवन सरल है, वहाँ की स्थिति उलझनों से परिपूर्ण है। वांगचुंग एवं दोर्जी वंशों के अलावा और भी वंश हैं। भूटानी कोमी भाषना लामा-धर्म और भूटानी भाषा इन्हें एक सूत्र में बांधे हुए है। जो भी यंत्रानुगत ईप्यो और द्वेष अवशेष हैं वे दबे हुए हैं। दो-दो विशाल देशों के बीच स्थिति, भूटानी-नागरिकता प्राप्त नेपालियों की उपस्थिति आर्थिक दृष्टि से अल्प-विकसित, कम जनसंख्या का पहाड़ी एवं स्थल रुद्ध देश ऐसी बातें हैं जिनमें दूरदर्शी भूटान बिशिष्ट वर्ग के लोगों के मन में यह बात दड़ता से बैठा दी है कि पारश्चात्य प्रणाली के लोकतन्त्र को लाने का प्रयास करना भूटान के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने के समान होगा। वांगचुंग वंशीय राज्य तन्त्र जब तक चलता है तभी तक भूटान की स्वतन्त्र सत्ता है। सभी भूटानी वंशों के लोग यह समझ गये प्रतीत होते हैं। वांगचुंग राजवंश की स्थापना ऐतिहासिक घटनाचक्रों का परिणाम मात्र था। उसके बाद समाप्त होने अथवा आशंक होने का परिणाम क्या होगा—यह तो भविष्य के गर्भ में है। किन्तु उन्हें यह भी स्पष्ट दीखता है कि इस राज्य वंश की समाप्ति के साथ वहाँ राज्य तन्त्र की समाप्ति हो जाएगी। उन्हें यह भी स्पष्ट दीखता है कि वहाँ यदि भूटाना लोकतन्त्र स्थापित हो भी जाएगा तो वह अत्यन्त अल्पायु होगा। वह किस विचारधारा का शिकार बनेगा, यह तो निश्चित नहीं किन्तु भूटानी जन-जीवन की पद्धति निर्भूत हो जाएगी एवं भूटान किसी बड़े देश का एक छोटा जिला अथवा तहसील मात्र रह जाएगा। भविष्य की यह आशंका विभिन्न वंशों के आधिपत्य को स्वीकार कराए हुए है।

हिन्दू शास्त्रों में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है कि राजा में ईश्वरीय अंश होता है। यूरोप में राज्य उत्पत्ति का दैवी सिद्धान्त मध्यकाल में प्रतिष्ठित रहा। किन्तु बौद्ध धर्म में ऐसी किसी मान्यता को स्थान नहीं है। भूटान का

राज्य तन्त्र केवल उपयोगिता के आधार पर प्रतिष्ठित है। जिस दिन अधिकांश भूटानियों का यह संकल्प हो जाएगा कि इस राज्य तन्त्र को या वर्तमान राजवंश को समाप्त करना है—भूटान की स्वतन्त्र सत्ता रहे या न रहे, तभी वहाँ से राज्य तन्त्र को या वर्तमान राजवंश को समाप्त करना है—भूटान की स्वतन्त्र सत्ता रहे या न रहे, तभी वहाँ से राज्य तन्त्र समाप्त हो जाएगा। भूटान के ड्रक ग्यालपो पर यह निर्भर करता है कि वे राष्ट्रीय सभा के माध्यम से भूटानियों को कितना अपने साथ ले चलने में समर्थ होते हैं तथा अपने लिए भूटानी कब तक राज्य तन्त्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहते हैं। राष्ट्रीय सभा की गठन प्रणाली, भूटान की ग्याय पद्धति अन्य धर्मों के प्रचार पर प्रतिबन्ध आदि सब इसी बात की ओर संकेत करते हैं। भारतीय सहायता से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होना तथा भूटानियों को अपने पँरो पर खड़े होने के योग्य प्रत्येक दिशा में बनाने की चेष्टा करना भी इस बात के द्योतक हैं।

भूटानियों को दो में से एक अप्रिय वस्तु स्थिति को चुनना होगा—या तो आनुवांशिक संप्रभावी राज्य तन्त्र अथवा भूटान की स्वतन्त्र सत्ता का लोप।



गोरखालैंड समस्या

दार्जिलिंग के निकट कलिंग पोंग में अचानक ही हिंसा की वारदातें शुरू हुईं। हिंसा की वारदात गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष श्री सुभाष घीशिंग द्वारा शुरू हुई। जिन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र के द्वारा चेतावनी दी कि जब तक गोरखालैंड के प्रान्त की मांग स्वीकार नहीं होगी तब तक दार्जिलिंग तथा उससे लगी हुई पर्वतीय क्षेत्र में आग की ज्वाला धधकती रहेगी। मुख्य मांग में से ये कहा गया था कि भारत नेपाल के बीच जो 1950 में सन्धि हुई थी उसमें सातवीं धारा को समाप्त कर देना चाहिये। जिसके अन्तर्गत वे सभी लोग नेपाल के सदस्य के रूप में भूलकाये गये हैं न कि भारत के। 13 जुलाई को अध्यक्ष ने अपने समर्थकों से कहा था कि यदि 1987 तक गोरखालैंड की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो, "हम उन सभी सरकारी कर्मचारियों को राज्य से बाहर फेंक देंगे। यही नहीं हम डिप्टी कमिश्नर, एस० पी० को दार्जिलिंग से भगा देंगे और प्रशासन को अपने हाथों में ले लेंगे।" 17 जुलाई को यह घोषणा कि हमारे आन्दोलन का स्वरूप शीघ्र ही ऐसी स्थिति में हो जाएगा जिसमें या तो हम समाप्त हो जायेंगे या गोरखालैंड प्राप्त करके रहेगे। हम अपनी कटारें अपनी म्यान से निकाल लेंगे और उन सिपाहियों को कत्ले आम कर देंगे। अध्यक्ष की यह भी शिकायत है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग क्षेत्र की उपेक्षा की है। नेपाली भाषा प्रान्त की दूसरी सरकारी भाषा मानी गयी है। यद्यपि पश्चिमी बंगाल के विकास के लिये बहुत कुछ धन राशि दी है यहां तक की दार्जिलिंग जिले को स्वायत्तता दी है। परन्तु अध्यक्ष का यह आग्रह है कि उसे पश्चिमी बंगाल से सहायता नहीं चाहिये अपितु केन्द्र में चाहिये।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि क्या इस प्रकार निरन्तर उठती हुई ममम्याओं विभिन्न प्रकार का स्वरूप धारण कर सेंगी ।

उक्त आन्दोलन से जितनी परेशानी केन्द्र को नहीं है उतनी कि पश्चिमी बंगाल सरकार का यह मदेह है कि आन्दोलन कांग्रेस के नेताओं तथा गोरखा नेपाली गठबन्धन की साजिश से शुरू है । पश्चिमी बंगाल सरकार इस आन्दोलन को बड़ी गंभीरता से ले रही है और इसे मिटाने का पूरा-पूरा प्रयास कर रही है ।

ग्रामपथी सरकार का यह भी सन्देह है कि उनके प्रान्त में उमी प्रकार की स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं जैसे कि असम, मिजोरम में हुई थी । अतः एक बार पुनः केन्द्र राज्य-सम्बन्ध की ममम्या उठ गयी हुई है और इस केन्द्र राज्य सम्बन्ध का समाधान तभी हो सकता है यदि केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक मामला समझे । पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र को चेतावनी भी दी है गोरखा नेपाली नेताओं से सीधे बात न करे । गोरखा नेपालियों के लिए चलाया गया आन्दोलन इस बात का संकेत देता है कि 1950 से चली आ रही भारत नेपाल संधि में कहीं न कहीं ऐसी खामी है जिसने आज भारतीय नेपालियों को विद्रोह करने के लिए बाध्य किया, आन्दोलनकारी अध्यक्ष सुभाष घोषिंग का कहना है कि संधि के तहत धारा 6 व 7 हमेशा से आपत्तिजनक रही है और इसीलिए आन्दोलनकारी नेता धारा 6 व 7 को समाप्ति के समर्थन में है ।

धारा 6 व 7 उन भारतीयों तथा नेपालियों को सुविधा प्रदान करता है जो एक दूसरे राष्ट्र में रह रहे हैं । कहने का अर्थ यह कि नेपाल में रह रहे भारतीयों और भारत में रह रहे नेपालियों को पारस्परिक सुविधायें देने का प्रावधान है । धारा 7 में उन सुविधाओं का जिक्र किया गया है जो एक दूसरे में निवासी रह रहे हैं । उदाहरण के लिए रहने की सुविधा, आपत्तियों का स्वामित्व, व्यापार करने की सुविधा और अन्य इसी प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान है । परन्तु संधि में दी गयी सुविधाओं का ठीक प्रकार से पालन न होने के कारण यह असन्तोष प्रारम्भ हुआ है । धारा 7 के समाप्त कर देने का अर्थ होगा कि वे भारतीय जो नेपाल में रह रहे हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित कर दिया जाये ।

पृष्ठ भूमि :—

भारत स्वतन्त्र होने के बाद से ही निरन्तर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए प्रयास होते रहे हैं । परन्तु कुछ वर्षों से भारतीय एकता

को खतरा बना हुआ है और भारत की अखण्डता पर आज एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब व आसाम दो ऐसे प्रान्त थे जिन्होंने अपनी स्थानीय समस्या को ऐसा रूप दिया कि वह क्षेत्रीय समस्या न रह कर राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में उभर कर आयीं जिसके परिणामस्वरूप भारत के अन्य प्रान्त भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इन दो प्रान्तों की समस्या सुलझ भी नहीं पायी थी कि निरन्तर ज्वलन्त बनी हुई है जो कि गोरखालैंड की समस्या के रूप में अधिक प्रचलित हो गयी। दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र में कुछ गोरखा नेपालियों ने अपनी उस पुरानी समस्या को एक बार फिर से ताजा कर दिया जब जी. एन. एल. एफ. के नेता घीशिंग ने तमिल समस्या की तरह एक जातीय प्रश्न उठा दिया। 1980 से पूर्व सुभाष घीशिंग एक अपरिचित और अनजान व्यक्ति थे लेकिन 1980 में जी. एन. एस. एफ. की स्थापना की और उसी से जुड़ी हुई प्रमुख मांग को क्षेत्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। पश्चिमी बंगाल की विधान सभा में इस समस्या को महत्व इसलिए भी दिया क्योंकि सुभाष घीशिंग के नेतृत्व में घटित दार्जिलिंग व कलिंग पोग में हिंसात्मक वारदातों के कारण इस समस्या को और भी महत्व मिल गया। यद्यपि पश्चिमी बंगाल की सरकार तथा विरोधी नेताओं का यह मत था कि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही केवल उन मुठ्ठी भर भटके हुए तथा विक्षिप्त लोगों का काम है जिसको विधान सभा के स्तर पर महत्व नहीं मिलना चाहिये। उनका यह मानना है कि हॉल ही में गोरखालैंड की समस्या ज्वलन्त हुई है उसके तीन सम्भावित कारण हैं :—

(1) मेघालय से हाल ही में 5000 नेपाली खान में काम करने वाले निकाल दिये गये जिसके कारण सुभाष घीशिंग को एक ऐसा मोका मिला जिसको उसने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। यदि ये नेपाली निकाले न गये होते तो अपनी मांग का आधार नहीं मिल पाता। इन 5000 नेपालियों के साथ मेघालय सरकार ने न केवल उनको निकाला उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया उससे वो दौखला गये। मेघालय सरकार ने उनको बेरहमी से ट्रक में डालकर गोहाटी छोड़ दिया। उसके पश्चात् असम सरकार ने 5000 नेपालियों को उठाकर उत्तरी बंगाल की सीमा पर डाल दिया। उसके पश्चात् पश्चिमी बंगाल ने अपनी बत्ता को टालने के लिए उनको नेपाल की सीमा पर ले जा पटका। इस प्रकार तीन प्रान्तों की सरकार ने खान में काम करने वाले नेपालियों के साथ घोर अन्याय किया। इस अन्याय को समग्र नेपाली जाति सहन नहीं कर सकती थी और परिणामस्वरूप जातीय प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर उभर

कर आ गया। यह बात दूसरी है कि गोरखानेन्द्र नेपालियों की भलाई के लिये नेतृत्व कौन करता है यह एक संयोग ही है कि एक अपरिचित व अनजान व्यक्ति के हृदय में अचानक आग भट्क उठी, नेतृत्व गुमाप घोशिंग के हाथ में आ गया। गुमाप घोशिंग के द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा उत्तम जुड़ी हुई माँगों को एक हृद तक स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि 1950 की मन्त्रि के अनुसार भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यह समग्र नेपाली जाति की भलाई के लिए सन्निहित सुविधाओं को प्रदान करे। उनके जीविषोपार्जन की व्यवस्था करे।

(2) दूसरा सम्भावित कारण यह हो सकता है कि गुमाप घोशिंग के द्वारा उठायी गयी माँग का सम्बन्ध उन ऐतिहासिक जड़ों से है जिनकी एक पुरानी कहानी है अधिक अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं केवल यह कहना पर्याप्त होगा कि दार्जेलिंग और इसका पर्यावरण हमेशा से ही नेपाल, सिक्किम तथा भूटान के बीच झगड़े का कारण बना रहा है। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में इन झगड़ों का प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजों के उपनिवेश नीति ने नेपाल के एक छोटे से हिस्से को हड़प कर सिक्किम को उपहार के रूप में दे दिया और फिर कुछ दिन बाद फिर नेपाल को दे दिया। लगभग सौ साल तक नेपाली लोग नेपाल से दार्जेलिंग में बसते रहे और फिर बाद में कुछ हिस्सा सिक्किम की ओर बढ़ गया चूंकि ये नेपाली लोग शारीरिक रूप से तन्दुरुस्त और मेहनती थे, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में इनका उपयोग एक श्रमिक के रूप में ही किया गया।

यह एक बड़ा विचित्र संयोग रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी थी जिसने 1946 में यह माँग उठायी थी कि गोरखाओं को एक अलग से भूखण्ड मिलना चाहिये। 1959 में इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गलती का सुधार करते हुए इस माँग की आलोचना की, जो उन्होंने 1946 में की थी। अपनी गलती को सुधारते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि पर्वतीय निवासियों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता होनी चाहिये। तब तक पहिया अपना पूरा चक्र पूरा कर चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी की सुधारी गयी गलती का असर गोरखा नेपालियों पर न्यूनतम था। एक बार नेपालियों को अपने अस्तित्व के लिए रास्ता मिल जाने के बाद वापस जाना उनके लिए असम्भव था।

किसी भी आन्दोलन को प्रारम्भ करना आसान होता है लेकिन उसकी निरन्तरता का निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता है। जब गुमाप घोशिंग ने

आन्दोलन को प्रारम्भ किया था तब ऐसा लगता था कि उसका जोश केवल कुछ ही दिनों तक चल पायेगा क्योंकि आन्दोलन का प्रारम्भिक स्वरूप अव्यवस्थित तथा योजना विहीन था। परन्तु ज्यों ज्यों दिन बीतते गये आन्दोलन न केवल जोर पकड़ता गया अपितु उसमें वे सभी सक्षम स्वतः ही शामिल होते गये, जैसे कि किसी योजना युक्त आन्दोलन होता है। इसका श्रेय सुभाष घोषिग के कुछ विशिष्ट आन्तरिक गुणों को दिया जा सकता है। घोषिग जी एन. एल. एफ. को गोरखालैण्ड सेना कहकर पुकारते हैं। उनका यह बार-बार दोहराना यद्यपि बड़ा सीधा सादा लगता है लेकिन उनकी बात में कहीं न कहीं औचित्य है। उनका कहना है कि “बंगालियों के पास बंगाल है, गुजरातियों के पास गुजरात है, मिजो के पास मिजोरम है, तथा मणिपुरी के पास मणिपुर है तो हम गोरखाओं के पास गोरख क्यों नहीं है।” सुभाष घोषिग का यह तर्क भी किसी हद तक ठीक लगता है जब वो कहते हैं कि “उस छोटे से सिविकम को विधान सभा में 30 सदस्य हैं जबकि उसकी तुलना में दार्जलिग की जनसंख्या तिगुनी होते हुए भी यहाँ से केवल तीन सदस्य विधान सभा के लिए चुने जाते हैं।” घोषिग उस दहाड़ती हुई भीड़ के सामने अपनी छुखरी निकाल लेते हैं और घोषणा करते हैं, “यह छुखरी वपों से चले जा रहे केन्द्र तथा प्रान्त के अन्याय को जवाब है।”

भारत की प्रमुख चौदह दलीय समिति ने कलकत्ता में यह घोषणा की कि घोषिग का यह आन्दोलन राष्ट्र विरोधी, विध्वंसकारी, तथा व्यक्ति विरोधी है। इस समिति ने यह भी अभियान छेड़ने का निर्णय किया कि घोषिग के द्वारा छेड़ा गया यह आन्दोलन किसी न किसी तरह समाप्त किया जाये। परन्तु क्या ऐसा हो पायगा इसमें बड़ा सन्देह है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ज्योति बसु वचनबद्ध हैं कि दार्जलिग क्षेत्र को एक स्वायत्तता मिले परन्तु साथ में इनको उन सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हैं जो कि मिलनी चाहिये थी। दार्जलिग का जिला वपों से उन सुविधाओं से वंचित है जिनको कि हम आवश्यकताओं की दृष्टि में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिये दार्जलिग जिले में वपों से विजली की समस्या है। पानी का अत्यधिक अभाव, भयभीत कर देने वाली बेरोजगारी तथा अन्य ऐसी समस्याएँ हैं जिससे वहाँ के लोग पीड़ित हैं। परन्तु पश्चिमी बंगाल सरकार के पास इन समस्याओं का उपचार करने के लिए कोई समाधान नहीं है।

मुख्य मंत्री ज्योति बसु अपने आंकड़ों के सहारे से समाधान चाहते हैं कि दार्जिलिंग की तुलना में ऐसे और भी जिले हैं जहाँ पर समस्या और भी गम्भीर है। ज्योति बसु ने अपना तर्क इस प्रकार प्रस्तुत किया कि "दार्जिलिंग जिले के विकास के लिए प्रति व्यक्ति खर्च 250/ = प्रति वर्ष रखा गया है, जबकि इसकी तुलना में अन्य जिलों पर केवल 112/ = रुपये खर्च किया जाता है।" यह आंकड़े यद्यपि सही हैं और निसन्देह पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों जैसे बंकुरा तथा पूरलिया अत्यधिक पिछड़े हुए हैं परन्तु धीरिंग इन आंकड़ों के भुलावे में नहीं आने वाला है उसके हृदय में अन्याय की आग इतनी घघकी हुई है कि उसके लिये यह सभी तर्क निरर्थक है। उसका यह भी कहना है कि मैदानी लोग बड़े ऊँचे पद पर हैं परन्तु दार्जिलिंग के मूल निवासी रोजगार के लिये भीख मांगते हैं। ज्योति बसु धीरिंग के आन्दोलन को राजनीतिक दृष्टि से दबा देना चाहते हैं।

ज्योति बसु को यह शक्ति से बाहर है कि वह भारत व नेपाल के बीच सन्धि में कोई परिवर्तन ला सकें। उन्हें नई दिल्ली व नेपाल से भी कोई आशा नहीं है कि वो इस समस्या को सुलझाने में मदद कर पायेंगे। हजारों नेपाली भारत में प्रवेश करते हैं और रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं। ये इन नेपालियों को अपेक्षाकृत भारत सरकार द्वारा अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं यजाये वे लोग जो जहाँ के मूल निवासी हैं। यह भेदभाव भी धीरिंग को अधिक पीड़ित कर रहा है। ज्योति बसु के पास विकल्प न्यूनतम है। ज्यादा से ज्यादा वे यही कर सकते हैं कि भारतीय नेपाली जो मूल निवासी हैं उनको रोजगार व तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्राथमिकता प्रदान करे।

गोरखालैंड की समस्या से जुड़ी हुई भारत नेपाल सन्धि का विश्लेषण

गोरखा नेपालियों की समस्या का सम्बन्ध बहुत कुछ 1950 की सन्धि से है जो भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। भारत और नेपाल के बीच की सीमा इतनी खुली हुई है जिसके जरिये व्यापार का आयात-निर्यात होता रहता है।

भारत के व्यापारियों का पैसा नेपाल में पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है और नेपाली लोग भी भारत से प्राप्त उन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं जो मूल नेपाल निवासियों तक को प्राप्त नहीं हैं और इसी कारण से सुमाय धीरिंग को यह शिकायत है कि 1950 की सन्धि में उन धाराओं को समाप्त कर देना चाहिये जो नेपालियों के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती है। भारत और नेपाल के बीच में जो 40 वर्षों से सम्बन्ध बन पाये हैं उनकी प्रकृति कुछ इस

प्रकार की बन पड़ी है जिसमें दोनों ही देश अपने अच्छे राष्ट्रवाद से अनुप्रेरित हैं जिसके फलस्वरूप अविश्वास की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ी है। यह बात सही है कि दोनों ही राष्ट्र अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हैं लेकिन यदि कही मतभेद भी है तो उसको पारस्परिक समझ से सुलझाया जा सकता है। भारत की सीमा के अन्तर्गत नेपालियों की समस्या इसलिये भी प्रबल हो गई है क्योंकि प्रान्तीय सरकार गोरखालैंड की मांग करते समय घीशिंग ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि उनकी मांगों को तभी पूरा किया जा सकता है कि जब केन्द्र सन्धि में भारी परिवर्तन करें।

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

पंजाब, आसाम, मिजोरम तथा अन्य प्रान्तों की तरह पश्चिमी बंगाल में उठी गोरखालैंड की समस्या ने केन्द्र-राज्य सम्बन्ध को एक बार फिर से ताजा कर दिया है जब कभी भी किसी प्रान्त में कोई समस्या उठ खड़ी होती है तो एक सविधानी संकट सामने आता है कि क्या अमुख समस्या को प्रान्त का आन्तरिक मामला समझा जाये या उस मामले को सुलझाने के लिये केन्द्र का हस्तक्षेप हो जिस प्रकार पंजाब में अकाली दल की समस्या उठी थी तो केन्द्र के सामने एक भारी समस्या थी कि पंजाब की समस्या को क्या उसे आन्तरिक मामला समझा जाय या राष्ट्रीय हित में हस्तक्षेप किया जाये। ऐसी घटनायें अन्य प्रान्तों में भी हुई थी और बाद में वे राष्ट्र के लिये सिरदर्द हो गईं, जब जुलाई के महीने में पहली बार सुभाष घीशिंग ने हिंसात्मक कार्यवाहियों के साथ गोरखालैंड की समस्या को उठाया तो पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री पर अधिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने केन्द्र पर आरोप लगाया। यह आन्दोलन कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं के भड़काने से हुई है। केन्द्र ने गोरखालैंड की समस्या को पश्चिमी बंगाल का आन्तरिक मामला न समझकर उसे राष्ट्रीय समस्या का रूप दिया। पश्चिमी बंगाल की सरकार यह नहीं चाहती थी कि केन्द्र किसी भी प्रकार से मामले में निहस्तक्षेप करे। इस संघर्ष में केन्द्र-राज्य के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। इस प्रकार जब से यह समस्या उठी है तब से दोनों में आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। समस्या का रूप और भी उग्र होता जा रहा है जिससे यह भय उत्पन्न हो गया है कि कही गोरखालैंड की समस्या राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभर कर न आ जाए। बहतर यही होगा कि केन्द्र-राज्य अधिक विवाद में न पड़ते हुए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाये जिस पर राष्ट्रीय एकता व अखण्डता पर कोई आंच न आये।

गोरखालैंड की माँग दार्जलिंग में इतना जोर पकड़ गया कि गोरखालीग ने सी. पी. एम. सरकार से अपने काम चलाऊ समझौतों को रद्द कर दिया और अपने सम्बन्ध तोड़कर जी. एन. एल. एफ. के आन्दोलन में शामिल हो गये। गोरखा सीग के अध्यक्ष पी. टी. साम्बा ने दार्जलिंग में उन सभी कार्यकर्त्ताओं को एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि उचित ही है बलि कानूनी व संवैधानिक दृष्टि से आवश्यक भी है। इस प्रकार गोरखा सीग को अलग हो जाने से वामपंथी सरकार के लिये एक सरदर्द है। पश्चिमी बंगाल के मावसंवादी कार्यकर्त्ताओं ने गोरखा सीग के निर्णय से अधिक चिन्तित हुये हैं जिन्होंने गोरखालैंड के समर्थन में अपने आप को शामिल कर लिया है। गोरखा सीग के शामिल होने से इतनी चिन्ता बढ़ गयी है कि उन्होंने सुभाष घोषिण की माँगों का उपहास अपने समाचार पत्रों के कार्टूनों से जाहिर करना शुरू कर दिया है।

ये कार्टून न केवल समाचार में दिखाये गये अपितु कलकत्ते की सभी दीवारों पर चिपकाये गये जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रान्त के केन्द्र से सम्बन्ध धीरे-धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक कार्टून का जिक्र कर देना यहाँ आवश्यक है जिससे लगता है कि वामपंथी सरकार केन्द्र से नाराज है। एक कार्टून में सुभाष घोषिण को उस पहाड़ी बस्ती के मीनार के ऊपर जिसके आस-पास के सभी घर जल रहे हैं और वह खुबरी को हाथ में उठाये हुए कह रहा है कि "मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि राजीव गाँधी मेरे साथ है।" ठीक इस कार्टून के पास एक कार्टून चिपकाया गया है जिसमें सी. पी. एम. का नारा इन शब्दों में लिखा हुआ है कि "हम अपनी रून की अन्तिम बूँद तक गोरखालैंड के आन्दोलन को पराजित करेंगे।"

यह दोनों कार्टून यद्यपि गोरखालैंड की माँग तथा केन्द्र के रवैये को व्यंग्यात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि गोरखालैंड का आन्दोलन केन्द्र के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है। केन्द्र पर यह आरोप है कि वपों से चली आ रही वामपंथी सरकार को कमजोर कर देना चाहती है। दूसरी ओर इस आरोप का खण्डन करते हुये केन्द्र का कहना है, गोरखालैंड की माँग प्रान्त का आन्तरिक मामला नहीं समझा जा सकता और केन्द्र का हस्तक्षेप करना जरूरी है।

सिक्किम का राजनीतिक विकास व नवीनतम आयाम

भौगोलिक परिचय

दुनिया के नक्शे को देखकर यह मालूम होता है कि सिक्किम एक बहुत छोटा राज्य है जिसके पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल है। दक्षिण में दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र स्थित हैं। उत्तर में तिब्बती क्षेत्र हैं जो कि चीन के कब्जे में हैं। इसका क्षेत्रफल 2,818 वर्ग मील है।

सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है। कोई भी स्थान मैदानी नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण नदियों में दो मुख्य नदियों का नाम लिया जा सकता है। पहली नदी का नाम दिचू है जिसने सिक्किम और भूटान के बीच में एक प्राकृतिक सीमा को निर्धारित कर दिया है। सिक्किम के उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर बहुत से पहाड़ हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। सबसे ऊँचे पहाड़ का नाम कंचनजंघा है जिसकी ऊँचाई 28,146 फीट है। इस पहाड़ को दुनिया में तीसरे नम्बर का गिना जाता है। दूसरी नदी का नाम टीस्ता है जिसका सिक्किम के लिए भौगोलिक महत्व हमेशा से रहा है। इस नदी का पानी सम्पूर्ण राज्य में बहता हुआ भारत के मैदानी क्षेत्र में उतरता है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून के सीधे रास्ते में होने के कारण सिक्किम में अधिक वर्ष होती है।

सिक्किम निवासी

इतिहास वेत्ताओं का कहना है कि सिक्किम के निवासी मूल रूप में मंगोल के लोग हैं। ये लोग भिन्न समय में सिक्किम में प्रवेश हुए थे। ये लोग भिन्न जाति के थे और अपनी सुविधानुसार इस राज्य में बसने के लिये आये। सबसे पहले आने वाली जाति लॅप्चा थी जो कि अपने आपको रांगपो (अर्थात् जंगल निवासी) कहते थे। ये लोग कौन थे, कहां से आये थे तथा थे तथा इनकी क्या परम्पराएँ रहीं? इन प्रश्नों का उत्तर सही-सही आज भी नहीं मिल पाया है क्योंकि जो कुछ भी इस जाति के बारे में रिकार्ड्स थे उनको तिब्बत के मठाधीशों ने बड़े तरीके से नष्ट कर दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस जाति के पूर्वज सबसे पहले तिब्बत या चीन से आसाम होते हुए आये। इसके

पश्चात् भूटिया जाति लैप्चा लोगों से भिन्न थी। ये लोग शक्तिशाली, उग्र तथा साहसी थे। जिस स्थान से भूटिया आये उसकी भूमि अनुत्पादक व वंजर थी। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिये जिस प्रकार का इन्हे संपर्क करना पड़ा था। उसके कारण इन लोगों में उग्रता व साहसी होना स्वाभाविक था। इसी संपर्क ने इन लोगों को लड़ाकू व साहसी बना दिया था। इनकी तुलना में लैप्चा जाति विनम्र, ईमानदार व शान्ति प्रिय थी। लड़ाकू व स्वार्थी जाति के सामने टिक पाना मुश्किल ही था और इस प्रकार जो सिक्किम लैप्चा की भूमि से जाना जाता था। अब उस पर भूटिया लोगों का आधिपत्य हो गया। लैप्चा के लोगों ने लड़ाकू जाति के सामने हार मान ली और ये लोग भूमि हीन हो गये। यह जाति पूर्णतया जाति के अधीन हो गये और शासन भूटिया लोगों के पास आ गया।

तीसरी जाति जो सिक्किम में आकर बसी वह भी नेपाली। नेपाली जाति 19वीं शताब्दी में आये और इनको सिक्किम के भूतपूर्व राजा ने इसलिए स्थान दिया क्योंकि ये लोग कृषि के क्षेत्र में न केवल निपुण थे अपितु परिश्रमी भी थे। निसंदेह आज भी सिक्किम कृषि प्रधान देश है और जो कुछ भी कृषि के क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है, वह नेपाली लोगों की वजह से है। धीरे-धीरे नेपाली लोगों की संख्या इतनी हो गई कि लैप्चा-भूटिया जाति अल्पसंख्यक में दिखाई दी और जो कुछ भी 1973-74 में राजनीतिक व सविधानिक परिवर्तन आये उसका पूरा श्रेय 70 प्रतिशत नेपाली लोगों को दिया जा सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 से पूर्व सिक्किम राज्य का क्या दर्जा था और इस पर कौन शासन करता था तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है कि तीन प्रकार की जातियाँ सिक्किम में आकर बसी और किस प्रकार भूटिया जाति ने सम्पूर्ण सिक्किम पर आधिपत्य कर लिया। चूँकि भूटिया जाति तिब्बत से आकर बसी थी इसलिये इनकी निर्भरता भी तिब्बत पर ही थी। प्रशासन में तिब्बत का हस्तक्षेप हर जगह था। प्रशासकीय कार्यों में तिब्बत के अधिकारियों से न केवल परामर्श बल्कि आदेश प्राप्त किये जाते थे। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्वास किया जाता है कि जब भूटिया लोग तिब्बत से आये तो उन्होंने पहले से बसे हुए लोग लैप्चाना को अपने में परिवर्तित करना शुरू किया और जिन लोगों ने परिवर्तन होना स्वीकार किया और तिब्बत से आने वाली

भूटिया जाति में शामिल हो गये। दोनों में यह समझौता हुआ कि प्रशासन में लेप्चा लोगों को समान रूप से व्यवहार किया जाएगा परन्तु राजनीतिक सत्ता तिब्बत के शासक के हाथ में होगी। इस प्रकार का समझौता कुछ लेप्चा लोगों को स्वीकार नहीं था जिन्होंने बौद्ध धर्म न तो स्वीकार किया था और न बाहर से आने वाले व्यक्तियों का स्वागत। परन्तु धीरे-धीरे तिब्बत के लोग अपने प्रभाव को और भी बढ़ाते गये और अन्तिम रूप से सिक्किम का सम्पूर्ण प्रशासन भूटिया लोगों के हाथों में पहुँच गया। इस प्रकार तिब्बती राजतन्त्र की स्थापना करने का रास्ता और भी साफ हो गया।

जिस तरीके से सिक्किम में राजतन्त्र की स्थापना हुई उसका वहाँ की राजनीति पर गहरा असर पड़ा इस प्रकार की व्यवस्था करने में न तो कोई रक्तपात हुआ और न कोई तूफानी संघर्ष। तीन मुख्य और प्रभावशील लामा, जिनको धर्म के आधार पर नियन्त्रण करने में असफलता मिली, निश्चय किया कि राजतन्त्र की स्थापना करने से सिक्किम के प्रशासन पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1642 में इन्हीं लामाओं ने "फुट सांग नामग्याल" व्यक्ति को सिक्किम का राजा नियुक्त किया। इस प्रकार सिक्किम की राजनीति पर लामा और बौद्ध धर्म का प्रभुत्व जम गया। ये लामा तिब्बत के लोग थे और राजा भी तिब्बत का ही रहने वाला था। इतने लम्बे समय के बीच बौद्ध धर्म के आपसी झगड़े भी समाप्त हो चुके थे। इस प्रकार सिक्किम के राजा पर तिब्बत का पूरा-पूरा प्रभाव जम गया। जिन परिस्थितियों के आधार पर राजा की नियुक्ति हुई, शक्तियों में कमी हो जाना स्वाभाविक था। यहाँ के राजा को किसी न किसी प्रकार से भूटिया लोगों को सन्तुष्ट करना पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप सिक्किम में जमींदारी व्यवस्था पनपना प्रारम्भ हुआ। कभी-कभी ये जमींदार राजा के आदेशों की न केवल अवज्ञा करते थे, अपितु उपहास भी।

सिक्किम राज्य 12 जिलों में विभाजित कर दिया गया। राजा ने 12 लेप्चाम जो कि उच्च श्रेणी के परिवारों से थे, जिला-अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और 12 भूटिया प्रमुख को राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करने के लिए एक परिषद् का गठन किया। स्थानीय प्रशासन को जमींदारों के हाथों में सौंप दिया जो काजी या टीकादास के नाम से जाने जाते थे। इन जमींदारों की ये जिम्मेदारी थी कि अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था कायम करें। इनको यह भी काम दिया गया था कि वहाँ के राजस्व को एकत्रित करें और राज्यकोष में जमा करावें।

राजतन्त्रीय व्यवस्था

व्यावहारिक स्वरूप—भूटिया द्वारा राजतन्त्रीय व्यवस्था जिस दिन से सिक्किम में कायम हुई तबसे ही इसमें कमियों का आ जाना स्वाभाविक था। इस व्यवस्था में शोषण करने की प्रवृत्ति पहले से ही व्याप्त थी। राजा और उसके शाही परिवार के सदस्यों ने सर्वाधिक उत्पादक भूमि को निजी सम्पत्ति के रूप में कब्जा कर लिया। सिक्किम में कृषि के योग्य कुल भूमि 90,130 हेक्टरों थी। 12,740 हेक्टरों जमीन राजा के नाम थी। जिसको काश्तकार बिना कुछ लिये हुए जोरते थे और जमीन से प्राप्त हुई सम्पूर्ण राशि शाही परिवार के व्यक्तिगत खर्चों के लिए चली जाती थी।

इतनी भारी भारा में राज्य की निजी सम्पत्ति काबू करने के बावजूद भी राजा ने जनसाधारण की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। वस्तुस्थिति यह थी कि राजा ने प्रशासन को सुधारने के लिए कभी समय मुश्किल से ही दिया होगा। राज्य के प्रशासन का काम प्रधानमन्त्री और दीवान के हाथों में सौंप रखा था। जो कि परिपक्व के सदस्य थे और जिसको राजा के सहायक के रूप में नियुक्त किया था। परन्तु इन प्रशासकों ने व्यक्तिगत स्वार्थों की अधिक परवाह की बनिस्बत राज्य की भलाई के। यही नहीं, यहाँ का राजा अधिकतर समय तिब्बत में व्यतीत करता था। इस प्रकार सिक्किम की सम्पूर्ण पूँजी विदेशों के लिए (अर्थात् तिब्बत के मठाधीश) खर्च होता था। राज्य की सार्वभौमिकता व सम्मान तिब्बत की दया पर निर्भर थी। राजा ने अपनी स्थिति को इतना कमजोर बना दिया था कि जब कभी भी विदेशी राष्ट्र सिक्किम पर आक्रमण की धमकी देते थे तो या तो राजा तिब्बत से मदद की भीख मांगता था और या वह स्वयं तिब्बत भाग जाता था और जनता को छोड़ जाता था। नामम्यालशाही परिवार ने किसी भी योग्य प्रशासक को जन्म नहीं दिया। अधिकांश स्थानीय अधिकारी वर्ग ने राजा के आदेशों की न केवल अवहेलना की बल्कि कभी-कभी राजा को भी अपने क्षेत्र में भगा देते थे।

राज्य के लगभग सभी निर्णयों में उच्च तामाज्यों की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका होती थी। राजा की तरह, मठों के लिए भी सम्पत्ति पहले से ही सुरक्षित थी। लगभग 8,550 हेक्टरों कृषि योग्य जमीन इनके लिये दे दी गई थी। वे सभी लोग जो मठों के क्षेत्र-परिधि में बसे हुए थे उनको भूमि राजस्व देना पड़ता था तथा कुल फसल का हिस्सा भी मठों के अधिकारियों को समर्पित करना होता था। इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को वर्ष में सात दिन का मुफ्त श्रम का दान देना होता था। मठों के अधिकारी वर्ग न केवल अपने क्षेत्र

के प्रशासन में स्वतन्त्र थे अपितु न्यायिक शक्तियाँ भी इनको प्राप्त थीं। राजा और सामाजों की सोठगाँठ से "काजी" के माध्यम से लोगों पर अत्याचार करते थे और उनकी मनमानी का मोतवाला था। राज्य की पूरी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की बनी हुई थी जिसके माध्यम से केवल कुछ भूटिया और उच्च सैन्चा जाति को ही सर्वाधिक लाभ होता था। परिणामस्वरूप, राज्य में भूटिया और सैन्चा जाति के बीच निरन्तर संघर्ष रहता था।

उक्त राजनीतिक व्यवस्था के कारण दुष्परिणाम होना भी स्वाभाविक था। आधुनिक दृष्टि से राज्य की कोई प्रगति नहीं हुई। 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का समभग सिविकम पर पूर्ण प्रभुत्व जम गया तब तक सिविकम की आन्तरिक स्थिति आदिवासियों-जैसी हो गई थी। न तो किसी सड़क का निर्माण कराया गया न कोई पुलिस की व्यवस्था। न्यायालय की व्यवस्था भी नहीं थी। सार्वजनिक निर्माण शून्य और शिवा का क्षेत्र अछूता तथा राज्य के खजाने में भी दिवाला निकाला हुआ था। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य अस्तव्यस्त था। शाही परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक झगड़े रहते थे। प्रशासनिक परिपक्व के अधिकारी वर्ग में भारी मतभेद थे। परिपक्व के कुछ सदस्यों ने राजा की सत्ता को धुनीती दे रखी थी और शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था। भूटिया और सैन्चा के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। कभी-कभी इन झगड़ों के कारण राज्य में कानूनी अव्यवस्था इतनी अधिक हो जाती थी जिसके कारण राजा को तिब्बती लोगों से हर प्रकार की सहायता लेनी पड़ती थी। इस तरह की हालत या अव्यवस्था राज्य में अनेकों बार हुई। तिब्बत पर इतना अधिक निर्भर हो जाने के कारण सिविकम के लोगों ने यह बात धर कर गई कि सिविकम की प्रशासनिक बागडोर तिब्बत के हाथ में है और राजा केवल नाममात्र का पुतला है जो कमजोर, निस्सहाय और गुलाम है। जब तिब्बत स्वयं चीन के अधीन बन गया तो सिविकम के लोग यह साफ तौर से कहने लगे कि सिविकम की बागडोर चीन के हाथ में है। वैसे चीन ने कभी भी सिविकम पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया।

विदेशी आक्रमण

सच ही कहा है कि यदि घर में झगड़े हैं तो उसका बाहर वाले लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और प्रयास में सफल भी होते हैं। यह शाश्वत सत्य सिविकम राज्य पर लागू किया जा सकता है। सिविकम के आन्तरिक झगड़ों तथा राजा की स्वयं की कमजोरी ने विदेशी राष्ट्रों को उसका लाभ उठाने का मौका दिया। सिविकम राज्य ने कई आक्रमणों का सामना किया और सबसे

बड़ा आक्रमण नेपाल की तरफ से था। जिसका फल यह हुआ कि सिक्किम को बहुत से भूखण्ड से हाथ धोना पड़ा। नेपाल की योजना तो यह थी कि वह पूरे ही सिक्किम को अपने अधीन कर ले परन्तु यह योजना इसलिए भी सफल नहीं हो पाई क्योंकि तब तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आधिपत्य हो चुका था। अंग्रेजी शासक किसी अन्य विदेशी राज्य का सिक्किम पर आधिपत्य सहन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका स्वयं का स्वार्थ इसमें निहित था। अंग्रेज लोग सिक्किम के माध्यम से तिब्बत से अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। इसलिए सिक्किम पर पूरा नियन्त्रण भी होना जरूरी था। अंग्रेजी शक्ति ने बढ़ती हुई नेपाली सेना को हराया और गोरखा के बंगुल से सिक्किम को बचा लिया। इस अहमन का बदला सिक्किम के राजा ने एक संधि के रूप में चुकाया जो कि 1861 में दोनों के बीच हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत और तिब्बत के बीच व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई जो कि बिना सिक्किम के सम्भव नहीं थी। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी ही अपनी व्यापार की सुविधा के लिए सड़को का निर्माण कराया। यह काम 1880 तक पूरा कर दिया गया परन्तु तिब्बत के अधिकारी वर्ग ने इस प्रकार की गतिविधियों को पसन्द नहीं किया क्योंकि तिब्बत से सिक्किम को हमेशा से ही आरक्षित राज्य समझा था। उन्होंने छम्म घाटी की ओर अपनी सेना भेजी। अंग्रेजी लोग ऐसे कदम से चौंक गये और कुछ समय के लिए उन्होंने अपने इरादे बदल लिये। अंग्रेजों की इस कमजोरी को समझ कर तिब्बत के लोगों ने सिक्किम पर पूरा नियन्त्रण करने की नीति अपनाई और इस दिशा में कुछ कदम भी उठाये। अंग्रेजी प्रशासनिक वर्ग ने सिक्किम के राजा से शिकायत की कि 1861 की संधि के अनुसार तिब्बत को कोई अधिकार नहीं है कि वह सिक्किम के किसी भी आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। अब सिक्किम के राजा ने इस प्रकार की आपत्तियों का कोई उचित उत्तर नहीं दिया। तब अंग्रेजी अधिकारी वर्ग के पास और कोई विकल्प नहीं था कि वे सिक्किम की दिशा में अपनी सेना भेजें और सिक्किम से तिब्बत की सेना को खदेड़ दें। अंग्रेजों की शक्ति के सामने तिब्बत की सेना मुकाबला न कर सकी और अन्त में तिब्बत और चीन दोनों ने ही अंग्रेजी के प्रभाव को पूरी मान्यता दी, 19 मार्च, 1890 ई. में अंग्रेज और चीन के बीच एक सम्मेलन हुआ जिसमें चीन ने अंग्रेजों के सिक्किम पर प्रभुत्व को स्वीकार किया।

इस प्रकार अंग्रेजों का प्रभुत्व सिक्किम पर पूर्णतया जम गया और उन्होंने सिक्किम के प्रशासन के लिए अपनी कुछ नीतियाँ बनाईं। उन्होंने एक सिक्किम का संविधान 1889 ई. में बना। इसके अनुसार राज्य की शक्तियाँ

राजा के हाथों में सौंप दी गईं परन्तु संविधान में यह भी लिख दिया गया कि शक्तियों का प्रयोग राज्य की परिपद की सलाह से करेगा। यदि कभी दोनों के बीच में मतभेद हो तो उसका अन्तिम फैसला अंग्रेजी राजनीति अधिकारी करेगा। वस्तुतः राज्य की वास्तविक शक्तियाँ अंग्रेजी शासक के पास ही पहुँच गईं क्योंकि परिपद का गठन किस प्रकार हुआ था उसमें अधिकतर सदस्य अंग्रेजों के थे। राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अंग्रेजों के थे। राजा के पास और अधिकारी वर्ग की बात माने। राजा को हमेशा इस बात का भी भय था कि कहीं वह अपने पद को खो न बैठे। अंग्रेज अधिकारी वर्ग को इस बात की चिन्ता नहीं थी कि जनसाधारण की समस्याएँ क्या हैं और उनका जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। उन्हें इस बात की भी चिन्ता नहीं थी कि वहाँ का सामान्त वर्ग कुछ उनके लिये खतरा पैदा कर सकता है। वे जानते थे कि सामान्त वर्ग भी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए उन्हीं की ओर ताकेगा और ऐसा हुआ भी। सामान्तवर्ग ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना प्रारम्भ किया और अंग्रेजी अधिकारी वर्ग के गुलाम हो गये। इस प्रकार राज्य में सामन्ती प्रथा अधिक शक्तिशाली और अधिक अत्याचारी हो गई।

अंग्रेज लोगों ने नेपाली जाति को प्रवेश होने के लिए प्रोत्साहन दिया। इस प्रोत्साहन के पीछे अंग्रेजों की एक कूटनीति स्पष्ट थी। वे चाहते थे कि पहले से बसे हुए भूटिया और लँच्चा नेपाली लोगों से डर जायें। इस योजना के अनुसार भारी संख्या में नेपाली लोगों का सिक्किम में प्रवेश होना शुरू हुआ और धीरे-धीरे संख्या इतनी बढ़ गई कि लँच्चा और भूटिया सिक्किम में अल्प-संख्यक हो गये। प्रशासनिक दृष्टि से कुछ ऐसे सुधार किये गये कि जिसने अंग्रेजों के हितों की पूर्ति में पूरी सहायता की। राजा को यह कहा गया कि तिब्बत में तीन महीने से ज्यादा न ठहरे और राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्यालयों में भेजा गया। अंग्रेजों की नीति इसमें सफल हुई और धीरे-धीरे सिक्किम तिब्बत के चंगुल से बाहर निकलने लगा। उक्त प्रशासनिक सुधारों ने पूर्ण रूप से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। भारत सरकार की स्वतन्त्रता के पश्चात् सिक्किम की क्या नीति रही उसके इस सन्दर्भ में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

इस प्रकार की अंग्रेजी नीति में प्रभावशाली भूटिया जाति पर गहरा असर डाला। जब 19वीं शताब्दी में भूटिया जाति ने सिक्किम पर प्रभुत्व कायम किया तो उन्होंने उच्च घराने के लँच्चा परिवार से ऐसा समझौता किया

जिसमें अधिकांश नीचे परिवार के संपत्ति अधून रह गये। इस समझौते ने उन पर शोषण करने के लिए पूरा-पूरा मौका दिया। समझौते का पहला प्रभाव यह हुआ कि संपत्ति की उत्पादक भूमि को जब्त कर लिया गया, उनके धर्म को नष्ट किया और उनको न केवल बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया अपितु उनको सामा की व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मिला उनको एक फकीर का दर्जा ही प्राप्त हो सका जो कि प्रभावशाली भूटिया की दया पर निर्भर थे। इस अन्याय ने ही जातियों के बीच निरन्तर संपर्क को जन्म दिया परन्तु अंग्रेजों शासन ने नेपाली लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहन बराबर दिया जिसके कारण दोनों जातियों को नेपालियों से छतरा हो गया। नेपाली लोग न केवल संख्या में अधिक थे अपितु वे साहसी, परिश्रमी और कृषि के क्षेत्र में निपुण थे। इस छतरे के कारण उसे शोषक भूटिया जाति ने शोषित संपत्ति जाति से समझौता करना प्रारम्भ किया जिसने कि वे नेपालियों से मुकाबला कर सके। संपत्ति लोगों ने इस समझौते को समर्थन दिया क्योंकि उन्हें भी नेपालियों से अधिक डर था परन्तु यह समझौता अधिक सुविधाजनक नहीं था क्योंकि यह सामान्य नियम है कि समझौता दो बराबरों के बीच होता है न कि ऊँचे और नीचे के बीच। नेपाली लोगों को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व के भाग में बसाया गया। उनके प्रति हर प्रकार का अन्याय किया गया और इस प्रकार नेपालियों के हृदय में उनके प्रति घृणा पैदा हो गयी।

नेपाली विद्रोह

नेपालियों का असन्तोष सभी तक नियन्त्रण में बना रहा जब तक अंग्रेज लोग सिक्किम पर शासन करते रहे, क्योंकि नेपाली लोग अंग्रेजों के मित्र से बन गये थे। अंग्रेजों के चले जाने के बाद से ही जिन्होंने कि सिक्किम के शासकों को लगभग शक्तिहीन कर दिया था, वहाँ कोई भी ऐसी शक्ति बच न रही थी जो कि नेपाली असन्तुष्ट भावना को नियन्त्रण में कर सकता उनके जाति ही दोनों के बीच संपर्क होना स्वाभाविक था। राजा की स्वयं की भूमिका भी कभी निष्पक्ष नहीं रही। यह अल्पसंख्यक भूटिया संपत्ति को ही समर्थन देता था जिसके परिणामस्वरूप राजा नेपालियों से न तो कभी सम्मान ही प्राप्त कर सका और न ही आदेशों को पालन करवा सका। जितना अधिक राजा भूटियों पर निर्भर था उनको समर्थन देता था उतना ही अधिक नेपालियों के हृदय में उनके प्रति विद्रोह पैदा हो गया था। अंग्रेजों के तुरन्त जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि नेपालियों पर कैसे काबू पाया जाय क्योंकि सिक्किम में न तो पुलिस और न मिलिट्री की व्यवस्था थी।

नेपाली लोग हमेशा इसी भाव में रहते थे कि कब राजा उनसे सिक्किम से चले जाने के लिए कह दे। उनका यह डर सच भी निकला, जब राजा ने उन

लोगों को सिक्किम से बाहर निकल जाने की चेतावनी दी और तब से ही सिक्किम के प्रशासनिक वर्ग ने यही प्रयास किया कि वह दिन कब आये जब नेपालियों को राज्य से बाहर निकाला जाय। नेपालियों को हमेशा विदेशी के रूप में ही समझा गया। पारस्परिक घृणा की भावना ने अनवरत् संघर्ष को जन्म दिया।

अंग्रेजी प्रशासन के चले जाने के बाद सिक्किम में आन्तरिक झगड़े पैदा हो गये। नेपाली लोग जानते थे कि उनके प्रति घोर अन्याय हो रहा है। उनमें राजनीतिक जागरूकता स्पष्ट नजर आने लगी थी। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन व जनतान्त्रिक भावना के बारे में नेपाली लोग अनभिज्ञ थे। सिक्किम में भी जनतान्त्रिक भावना धीरे-धीरे फैल रही थी। नेपाली लोगों में भी वे सभी जनतान्त्रिक आदर्श घर कर रहे थे जिनको राष्ट्रीय आन्दोलन में मुख्य स्थान दिया जा रहा था। भारतीय नेताओं से प्रभावित नेपाली लोग उसी मार्ग को अपनाने के लिए अग्रसर हुए जिसकी हवा भारत में पहले से ही व्याप्त थी। बहुसंख्य नेपाली लोग यह जानते थे कि यदि सिक्किम में जनतान्त्रिक व्यवस्था कायम हो जाये तो शासन उनके हाथों में होगा। इसी उद्देश्य को हाथ में लेकर नेपालियों ने जनतन्त्र शासन के लिए आन्दोलन प्रारम्भ करने की घोषणा की। सिक्किम में जनतान्त्रिक मूल्यों का प्रचार भारत के द्वारा हुआ और नेपालियों ने ऐसे मौके का पूरा-पूरा लाभ उठाने की कोशिश की। भूटिया-लैप्चा लोगों को यह बात अच्छी तरह मालुम थी कि सिक्किम में जनतन्त्र व्यवस्था का क्या परिणाम होगा। वे अपना हित अच्छी तरह जानते थे इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया।

उक्त जनतान्त्रिक आन्दोलन के विरोध में कौन लोग सामने आये वे भी छुपे हुए नहीं थे। सिक्किम के पूंजीपति, शाही परिवार, सामन्त लोग, उच्चलामा, व्यापारी, ठेकेदार, धनी कुपक—ये सभी लोग जनतान्त्रिक व्यवस्था के विरोध में थे। इन बुजुर्ग वर्ग में बहुत से नेपाली भी शामिल थे जो राजतन्त्र के पक्ष में थे। उसी प्रकार लैप्चा भूटिया लोगों में भी ऐसे दलित लोग थे जिनकी यह इच्छा थी कि जनतान्त्रिक व्यवस्था हो जाने में उनका उद्धार है।

जनतान्त्रिक आन्दोलन

सिक्किम में जनतान्त्रिक आन्दोलन का प्रारम्भ अंग्रेजी शासन के चले जाने के बाद हुआ। 1947 के तुरन्त पश्चात् दो शक्तियां साफ तौर से दिखाई दीं—वे थीं जनतान्त्रिक शक्ति एवं सामन्त शक्ति। सत्ता को अपने हाथ में

सेने का मुकाबला इन दोनों शक्तियों के बीच शुरू हुआ। भारत में जनतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना होने के पश्चात् सिविक्रम में तीन राजनीतिक दलों के बीच गठबन्धन हुआ और इन की अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तीनों दलों का एक दल बनाया जिसका नाम सिविक्रम स्टेट कांग्रेस रखा। जिन दलों को मिलाया वे थे—(1) प्रजा मुधारक समाज, (2) प्रजा सम्मेलन, (3) प्रजा मण्डल। एक दल के बनते ही शक्ति का संचार हुआ, आन्दोलन की घोषणा कर दी गई। नये गठित दल ने तीन मांगें रखी थीं—(अ) लोकप्रिय और उत्तरदायी सरकार का निर्माण और सामन्तवादी व्यवस्था को समाप्त करना, (ब) अन्तरिम जनतान्त्रिक सरकार का गठन, (स) सिविक्रम को तुरन्त भारत में विलय कर देना। यह आन्दोलन महाराजा के विरुद्ध था जो कि पहले से ही जनतान्त्रिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए सामन्त शक्ति से महापता से रूपा था। राजा के पास कम शक्ति होने के कारण उसने निम्न तरीके अपनाये जिससे आन्दोलन टूट जाय और शक्ति बनी रहे।

दल में मतभेद करना

राजा ने उक्त तीन मांगों में से केवल एक मांग को स्वीकार किया और वह थी अन्तरिम लोकप्रिय सरकार का गठन जिसमें उसने तीन प्रमुख नेताओं को अपनी सहायता के लिए "संक्रैटरी" के रूप में नियुक्त किया। राजा यह पहले से ही जानता था कि दल के नेताओं में निष्ठा का अभाव है और इस कमजोरी का उसने लाभ भी उठाया। तीन "संक्रैटरी" की नियुक्ति के बाद राजा के उनको अपनी चतुराई से स्वयं के पक्ष में कर लिया और कांग्रेस संक्रैटरी धीरे-धीरे राजा का पक्ष लेने लगे तथा आन्दोलन की गर्मी को भूल गये। सिविक्रम कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आक्रोश पैदा हुआ और तीनों संक्रैटरी से त्याग-पत्र माँगा। उन्होंने त्याग-पत्र देने के लिए मना कर दिया और इस प्रकार दल की एकता समाप्त होने लगी।

राजभवन दल का गठन

जनतान्त्रिक दल का सामना व विरोध करने के लिए राजा ने एक ऐसे दल का गठन किया जिसका नाम "नेशनल पार्टी" रखा। इस दल का मुख्य काम यही था विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करना और अस्थिरता को बनाये रखने का पूरा-पूरा प्रयास। जिन लोगों से दल बना वे थे लेफ्टा, भूटिया, मर्से, शेरया तथा शुद्र। यह पार्टी सामन्तवादियों के हितों की रक्षक थी। कांग्रेस के तीन नेताओं की इस स्वार्थपरता का देखकर यह स्पष्ट अवश्य होता है कि दल में जनतान्त्रिक परिपक्वता का पूर्ण अभाव था।

वास्तविकता से समझौता

राजा का यह प्रयास कि दल में फूट पड़े-उसमें आंशिक सफलता तो मिली लेकिन उसने वास्तविक स्थिति को समझ लिया था। राजा यह जानता था कि भारत सरकार का रुख जनतान्त्रिक शक्ति की तरफ है। वह यह भी समझ रहा था कि जब तक भारत का रुख उसके पक्ष में नहीं होगा तब तक स्थानीय दल का आन्दोलन शान्त नहीं किया जा सकता।

जब 1 मई, 1949 को जनतान्त्रिक शक्ति ने पूरी ताकत के साथ राजा के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो उस समय राजा का मानस मयाय स्थिति से उन्मुख था। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों को देखकर राजा ने तुरन्त "भारतीय रेजीडेंसी" में शरण ली और भारतीय "पोलीटिक्स आफिसर" की राय को मानने के लिये तैयार हो गया। राजा को यह सलाह दी गई कि वह एक लोकप्रिय सरकार का गठन करे जिसमें तीन सदस्य सिविकम काफ़ेस के हों तथा दो राजा के मनोनीत व्यक्ति। इसकी अध्यक्षता काफ़ेस का अध्यक्ष करेगा। राजा ने उक्त सलाह को तुरन्त मान लिया।

भारत सरकार सिविकम के मामले को हल करने में अधिक जल्दबाजी करना नहीं चाहती थी। उसकी स्पष्ट तस्वीर केवल 1950 की संधि से ही हो सकी जिसने सिविकम को भारत का "आरक्षित" दर्जा दिया। संधि के अनुसार सिविकम के विदेशी मामले, सुरक्षा तथा न्याय-व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत सरकार के हाथों में सौंप दी। घरेलू मामले में राजा को लगभग अपरिमित शक्ति प्रदान कर दी गई। राजा ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया। सामान्य लोगों के स्वायत्त की पूर्ति करने में राजा ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। स्वयं के स्वायत्त की पूर्ति का कानूनी रूप देने के लिए राजा ने 1953 में संविधान का निर्माण किया जिसने केवल अल्पसंख्यक भूटिया लैप्चा को और अधिक सुविधायें प्रदान कीं तथा 75 प्रतिशत नेपाली लोगों को सुख-सुविधाओं से वंचित किया, उसको जानना भी आवश्यक है।

1953 का संविधान

इस संविधान का मूल आधार "पैरिटी फार्मूला" था जिसके अन्तर्गत यह निश्चय किया गया कि "राज्य परिषद" की सीटों का वितरण समान अधिकार के आधार पर होगा। इन सीटों का विभाजन भूटिया, लैप्चा और नेपाली के बीच होगा। यद्यपि बहुसंख्यक नेपालियों के लिए परेशानी का कारण था क्योंकि उक्त नियम हो जाने से नेपालियों के लिए सत्ता का रास्ता अवरोध हो गया। राजा ने फिर भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझा और इसी असुरक्षा की भावना से संविधान में एक प्रावधान और जुड़वाने के लिए बाध्य किया। राजा ने पाँच सदस्य मनोनीत करने का अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित

रखा। निर्वाचित सदस्यों से गठित "राज्य परिषद" का महत्त्व और भी कम करने के लिए राजा ने "द्वैध शासन" की व्यवस्था को प्रारम्भ किया। प्रशासन के मुख्य विभाग राजा के हाथों में सौंप दिये गये और कम महत्त्वपूर्ण विषय परिषद को दिये गये। राज्य परिषद के सामने और भी अड़चनें डाल दी गईं। परिषद को प्रतिबन्धित विषयों पर वहस करने की अनुमति नहीं दी गई। नये संविधान ने परिषद को उन उचित शक्तियों से भी संचित कर दिया जो उसे स्वतः मिलने ही चाहिये थे। संविधान ने परिषद को इतना कमजोर कर दिया कि वह केवल राजा के निर्देशन का पालन करने वाली एक संस्था बनकर रह गई। ऐसे संविधान ने धीरे-धीरे 1973 तक राजा को इतनी भारी शक्ति प्रदान कर दी थी कि वह सिविक्रम में सबसे अधिक धनवान व्यक्ति में गिना जाने लगा।

राजा के प्रति विद्रोह

राजा ने अपने उन सभी तरीकों को प्रशासन में लागू किया जिससे वह लोकप्रिय हो सके। जिस आवरण में वह ज्वाति प्राप्त करना चाहता था वह बहुसंख्यक नेपाली व जनतान्त्रिक शक्ति को इतना स्पष्ट था कि राजा ने अन्यायपूर्ण व्यवहार सभी के सामने आ गये। राजा का प्रशासन वस्तुतः केवल कुछ सामन्तवादी लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुँचाने के लिए था। उनके अन्याय और दमन की पराकाष्ठा थी। केवल मठों के उच्च लामा और जमींदार लोग राजा की छत्र-छाया में बनप रहे थे। 26,700 हेक्टेर्स भूमि का नियंत्रण पचास परिवार के बीच में था। करीब 8560 हेक्टेर्स भूमि 6 मठों को दे रखी थी। सिविक्रम की दलित जनता इस प्रकार के शासन से तंग ब हु.खी थी। नेपाली लोग अच्छे मीके का इन्तजार करने लगे। वे राजा को अहसास कराना चाहते थे कि जो कुछ भी उनके सानिध्य में हो रहा है वह भयंकर, अन्याय और भ्रष्टाचार है और वह घड़ी आई भी जब बहुसंख्यक नेपाली लोगों ने अवसर का लाभ उठाया।

1973 के चुनाव ने नेपाली लोगों को वह मीका दिया जिसका वे इन्तजार कर रहे थे। सिविक्रम नेशनल कांग्रेस ने राजा पर यह दोषारोपण किया कि चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः स्थिति यह भी कि जिस चुनाव पद्धति को राजा ने कानूनी रूप से नेपालियों पर थोप रखा था वह मूलतः अन्यायपूर्ण थी। चुनाव पद्धति भूटिया-लँप्चा लोगों के पक्ष में थी। अतः हर स्थिति में चुनाव का परिणाम केवल सामन्त लोगों के पक्ष में जाता था। अतः 1973 के चुनाव परिणाम के पश्चात नेपालियों में घोर असन्तोष फैल गया और विद्रोह चोगयाल (राजा) के खिलाफ छेड़ दिया। सिविक्रम

कांग्रेस ने चोगालम के सामने प्रदर्शित किये और जनतान्त्रिक व्यवस्था के आधार पर चुनाव कराने की मांग रखी। राजा ने ऐसी मर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके ठीक विपरीत आतंक का वातावरण फैला दिया। इस विद्रोह और असन्तोष की कोई सीमा नहीं थी। राजा ऐसे विद्रोह का सामना नहीं कर सका। सिविकम प्रश्न सन का सम्पूर्ण ढाँचा चरमरा गया। राजा के सामने और कोई विकल्प नहीं रह गया और उसने भारत सरकार को प्रशासन की बागडोर सौंप दी।

समझौते की व्यवस्था

भारत सरकार ऐसी स्थिति की देखकर सरल रास्ता ढूँढने का प्रयास करने लगी जिससे सिविकम का राजा किसी प्रकार से गलत न समझे। नई दिल्ली में उच्च अधिकारी वर्ग राजा से यही आशा करते रहे कि आन्तरिक व्यवस्था को सूझबूझ से राजा सम्भाल लेगा। परन्तु स्थिति और भी बिगड़ती देख कर भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे सिविकम की जनता न्याय और व्यवस्था से रह सके। अन्त में एक समझौते की व्यवस्था हुई जिसमें राजा जनतान्त्रिक शक्ति के प्रतिनिधि और भारत स्वयं 8 मई, 1973 को तीनों के बीच यह समझौता किया गया जिसमें एक पूर्ण उत्तरदायी जनतान्त्रिक सरकार के गठन का निर्णय लिया गया जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर छोड़ी गई। समझौते ने यह भी निर्णय लिया कि एक कार्यकारिणी के प्रमुख की सलाह पर राजा द्वारा होगी। कार्यकारिणी प्रमुख को समझौते के अनुसार यह भी शक्ति प्राप्त हुई कि वह कार्यकारिणी की मीटिंग की अध्यक्षता करें। 1973 के समझौते ने यह भी तय किया कि यदि राजा और कार्यकारिणी के बीच में कोई मतभेद हो तो उस मामले को सिविकम में "इण्डियन पोलिटीकल आफिसर" को सौंप दें और उसका निर्णय अन्तिम होगा। समझौते से यह अवश्य निष्कर्ष निकला है कि जनतान्त्रिक शक्ति को राजा पर बिस्फुल भरोसा उठ गया था और भारत सरकार पर अधिक।

उक्त समझौते से राजा यद्यपि नाराज था लेकिन हस्ताक्षर करने पड़े। राजा ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि सिविकम नेपालियों को उसके खिलाफ उकसाने में भारतीय नेताओं का हाथ है। राजा ने हस्ताक्षर के रूप में तो समझौते को स्वीकार किया परन्तु आन्तरिक द्वन्द्व ने उसे शान्ति से नहीं बैठने दिया। अपने हाथों से शक्ति जाते देख राजा सहन नहीं कर सका। समझौते के अनुसार अप्रैल, 1974 को सिविकम विधान सभा चुनाव हुए जिसमें सिविकम कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आयी। दुर्भाग्य की बात है कि राजा मठ की एक मात्र सीट भी हार गया।

1974 का संविधान

चुनाव होने के बाद काजी लैंडप दोरजी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। सरकार बनते ही सिविकम कांग्रेस के सामने प्रमुख काम था। नये संविधान का निर्माण करना जिससे 1973 के समझौते की भावना को सम्मिलित किया जा सके। 1974 का संविधान तैयार हुआ और उसको विधानसभा ने 20 जून, 1974 को सर्वसम्मति से पारित किया। इस संविधान ने नेपाली लोगों को प्रशासन में उचित स्थान दिलाने के लिए कई प्रावधान रले। नये संविधान के अन्तर्गत कार्यकारिणी प्रमुख को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। चोगयाल को संवैधानिक राजा के रूप में स्वीकार किया गया।

उक्त संविधान ने राजा की शक्ति को काफी कम कर दिया था परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न ही दिखाई देती थी। प्रशासन को देखकर यह नहीं लगता था कि राजा की शक्तियों में किसी भी प्रकार से कमी आई है। बाह्य दृष्टि से यह स्पष्ट हो चुका था कि राज्य की वास्तविक शक्ति निर्वाचित सदस्यों के पास पहुँच चुकी है लेकिन आन्तरिक स्वरूप कुछ और ही था। कारण स्पष्ट था कि राजा (चोगयाल) ने यथार्थ स्थिति को स्वीकार नहीं किया। जब उसने यह समझ लिया कि भारत सरकार का रुख भी जनतान्त्रिक शक्ति की ओर है और जो कुछ भी आन्दोलन हुआ उसमें भारत का पूरा पूरा हाथ था तो उसने अन्य राष्ट्रों की सहायता लेने का अभियान शुरू किया। नये संविधान के अन्तर्गत राजा को अपने राज्य से बाहर जाने से पूर्व विधीबद्ध अनुमति लेना आवश्यक था। परन्तु राजा ने अपनी हठधर्मी का परिचय दिया।

राजा का अन्तिम प्रयास

यद्यपि जनतान्त्रिक सरकार बन चुकी थी, मुख्यमंत्री काजी लैंडप दोरजी, ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया था और प्रशासन की बागडोर भी जनता के हाथों में चली गई फिर भी राजा वास्तविक स्थिति को समझने में असमर्थ दिखाई देता था। उसका भ्रम अन्तिम क्षण यही था कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में है। इसी भ्रम को लिए एक दिन राजा (चोगयाल) मार्च 1975 को चुपचाप नेपाल की ओर चल दिये जहाँ कि उन्हें राजा बीरेन्द्र के राज्याभिषेक में शामिल होना था। इस तरह से संविधानिक सरकार को बिना किसी सूचना दिये चला देना असंविधानिक समझा गया। नेपाल में जाकर राजा ने अन्य राष्ट्रों के मागे हुए प्रतिनिधियों को सिविकम की स्थिति से अवगत कराया और सहायता भी माँगी। राजा की यह पूर्णविश्वास था कि इस सम्बन्ध में चीन, पाकिस्तान और नेपाल उसे अवश्य मदद देगा। परन्तु उसका दुर्भाग्य ही रहा कि इस मुद्दे पर किसी ने भी हस्तक्षेप करना

नहीं चाहा। चीन ने प्रतिक्रिया अवश्य जाहिर की परन्तु सिक्किम के नये परिवर्तन में दखल देना अपने हित में ठीक नहीं समझा।

सिक्किम का भारत में विलय

सिक्किम को 22वां राज्य बनाने से पूर्व संविधानिक अड़चनों को भी दूर करना आवश्यक था। इसकी पूर्ति के लिए भारतीय संसद में 36वां संविधानिक बिल को प्रस्तुत किया गया। संसद से जब इसको पारित कर दिया, उसके पश्चात् समस्त राज्यों की विधान सभाओं में पारित होने के लिए भेजा गया। जब विधान सभाओं ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। उसके पश्चात् राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये और इस प्रकार सिक्किम को भारत का एक अंग मान लिया गया। चोग्याल के पद को समाप्त कर दिया और सिक्किम के नये राज्यपाल बी.बी.जाल को नियुक्त कर वहा भेज दिया गया।

काजी दोरजी व प्रशासन

मुख्यमंत्री काजी दोरजी के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ। अपने पांच वर्ष के प्रशासन में काजी दोरजी उन वायदों को पूरा करने में असमर्थ रहे जिनको चुनाव घोषणा-पत्र में सम्मिलित किया गया था। घोषणा पत्र में भूमि मुद्रार करने का वायदा किया हुआ था परन्तु काजी दोरजी का प्रशासन कुछ भिन्न ही सिद्ध हुआ। स्वयं दोरजी गामस्त वर्ग से अधिक निकट थे। कहा जाता है कि दोरजी का प्रशासन भ्रष्ट और बेईमानी से परिपूर्ण था। उन शोषित नेपाली व लैप्चा लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं किया गया। सिक्किम के सभी लोग दोरजी के प्रशासन से दुःखी हो गये।

सिक्किम विधानसभा भंग

मुख्यमंत्री काजी दोरजी के प्रशासन से कुछ विधान सभा के सदस्य नाराज हो गये। कहा जाता है कि कुछ दोरजी के समर्थक ही उससे इसलिए अप्रसन्न हुए क्योंकि दोरजी भूटिया लैप्चा के लिए 12 सीट का रिजर्वेशन करने के लिए बिल विधान सभा में प्रस्तुत करने वाले थे। उससे पहले कि यह बिल पास होता एक मन्त्रिमण्डल के सदस्य ने स्तीफा दे दिया और शेष समर्थकों में ही दोरजी के प्रति विद्रोह उठ पड़ा हुआ। काजी दोरजी को यह साफ अहसास हो गया कि उनकी सरकार गिरने वाली है। उसी प्रतिक्रिया के दौरान दोरजी ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दे दी और तुरन्त विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव की घोषणा भी साथ में कर दी गई।

विधानसभा चुनाव

सिक्किम विधान सभा चुनाव के लिए 2 अक्टूबर की तारीख निश्चित कर दी गई। यह चुनाव 1974 के चुनाव से अपना अलग स्थान रखता था। इसकी भिन्नता निम्न प्रकार से थी—

(1) पहले चुनाव का वातावरण जनताग्निक आन्दोलन की भावना से अनुप्रेरित था, जबकि इस चुनाव में राजा से संघर्ष न होकर मुख्यमन्त्री के भ्रष्ट प्रशासन से था।

(2) पहले चुनाव में सिक्किम की जनता यानी नेपाली भूटिया-लैप्चा सभी एक झण्डे के नीचे (सिक्किम कांग्रेस) आकार राजा के अत्याचारी शासन से मुक्त होना चाहते थे और स्वतन्त्र वातावरण में सरकार बनाने के लिए बड़े आतुर थे। परन्तु इस बार बहुसंख्यक नेपाली लोगों में भी भारी मतभेद थे।

(3) 1974 के चुनाव में मत देने का अधिकार केवल नेपाली भूटिया-लैप्चा ही लोगों को था। परन्तु इस बार भारतीय मैदानी नागरिकों, भारी विरोध के बाद भी, को भी मत डालने का अधिकार दिया गया यह कहा जाता है कि काजी दोरजी ने मैदानी नागरिकों (मारवाड़ी, हरिजन, बिहारी और मुस्लिम) का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनको मताधिकार दिलाया। इस कारण भी सिक्किम के मूल-नागरिक नाराज हो गये।

(4) 1974 में मतदाताओं को परिचय-पत्र वितरित नहीं किये गये, जबकि इस बार ऐसा हुआ। लगभग 80,000 लोगों के बीच परिचय-पत्र बाँटे गये।

चुनाव के परिणाम

12 अक्टूबर को सिक्किम में विधान सभा के 32 सीटों के लिए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हुए। चुनाव का परिणाम इस प्रकार रहा :—

घोषित परिणाम

सिक्किम जनता परिषद (क्रान्तिकारी)	सिक्किम कांग्रेस	सिक्किम प्रजातन्त्र पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस (उर्स)	सी० पी० (एम०)	स्वतन्त्र
16	11	3	0	0	0	1

उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वह सिक्किम कांग्रेस जिसने 1974 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था इसी पार्टी का नाम 1977 के आम चुनाव के पश्चात् जनता पार्टी हो गया था। वह 1979 के चुनाव में एक

भी सीट प्राप्त न कर सकी। यहाँ तक स्वयं भूतपूर्व मुख्यमन्त्री काजी लैंडर दोरजी अपने क्षेत्र से पराजित हुए। जो दल बहुमत में आया उसका किसी भी राष्ट्रीय दल से कोई सम्बन्ध नहीं था। राष्ट्रीय समाचार पत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि सिविक जनता परिषद का गहरा सम्बन्ध भूतपूर्व राजा से था और वस्तुतः राजा से अनुप्रेरित दल ने विधान सभा में बहुमत प्राप्त किया है। दूसरे नम्बर की पार्टी जिसने 11 सीटें प्राप्त कीं उसका सम्बन्ध नेपाली जाति से जोड़ा गया है जो बिद्रोही थे और काजी दोरजी के प्रशासन से नाराज होकर सरकार से अलग हो गये।

इस प्रकार बहुमत दल के नेता नर बहादुर भण्डारी को मुख्यमन्त्री बनाया गया और उसके भण्डारी ने अपने मन्त्रिमण्डल की सूची राज्यपाल को भिजवा दी।

नवीनतम आयाम

1975 में सिविक भारत का 22वां राज्य बना और तब से राजनीतिक घटनाचक्रों का अजीब तरीके से सिलसिला प्रारम्भ हुआ। भारत में बिलीन हो जने के बावजूद वहाँ के निवासियों में राष्ट्रीय भावना की झलक अभी भी दिखाई नहीं देती। यद्यपि केन्द्र की ओर से सिविक के विकास के लिए करोड़ों रुपये तथा हजारों गैलन पेट्रोल खर्च हो गया होगा लेकिन वहाँ के लोग भावनात्मक दृष्टि से अभी भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं लगते। श्रेयवाद सिविक में इस हद तक दिखाई देता है जैसे उन्होंने भारत में बिलय को स्वीकार ही नहीं किया हो। अलगवादी विचार-धारा से वहाँ के निवासी ओतप्रोत लगते हैं।

चोगियाल के हटने के बाद काजी लैंडर दोरजी पहली बार जनतान्त्रिक पद्धति के आधार पर वहाँ के मुख्यमन्त्री बने। आश्चर्य की बात है कि जिम मुख्यमन्त्री ने 1975 के जनतान्त्रिक आन्दोलन के आधार पर वहाँ की 32 सदस्यीय विधानसभा में शत-प्रतिशत सीट जीती वही 1979 के चुनाव में न केवल अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने में पूर्णतया असफल रहा अपितु वह स्वयं अपने क्षेत्र से जीत न सके। 1975 से 79 तक सिविक की राजनीति कुछ ऐसी स्थिति में पहुँच गई जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था।

पाँच वर्ष के अल्पकाल में प्रशासन का ढाँचा पूर्णतया बिखरता हुआ नजर आया। जिस संघर्ष से मामतवादी शक्तियों से लड़कर जनतान्त्रिक शक्ति को विजय दिलाई वह संघर्ष व यातना कुछ ही महीनों बाद में धुँधली हो

गई तथा नेपाली राजनेता भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाते हुए सामने आये। काजी दोरजी का प्रशासन भ्रष्टाचारियों से भर गया यही कारण था कि 1979 के चुनाव में काजी दोरजी की पार्टी व स्वयं दोनों की ही करारी हार हुई। 1979 के चुनाव में क्षेत्रीयवाद पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। चुनाव अभियान में प्रत्येक दल ने क्षेत्रीय भावना का शोषण या लाभ लेने का प्रयास किया। हर दल ने "सिक्किम को सिक्किमी निवासियों का ही है" नारा लगाया। गह नागा राष्ट्रीय भावना पर आपात करने वाला था।

चुनाव के परिणामों ने सिक्किम परिपद पार्टी को विजयी घोषित किया। यह चुनाव 1975 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न थे। पहला चुनाव आन्दोलन का परिणाम था लेकिन दूसरे चुनाव में आपसी मतभेद तथा टकराहट छुलकर सड़क पर आ गई थी। 1979 के चुनाव ने एक ओर संकेत दिया वह यह कि राष्ट्रीय भावना शेष मात्र भी नहीं रह गई थी। क्षेत्रीय भावना की ओर झुकाव रखने वाली शक्ति की न केवल विजय हुई अपितु चोगियाल (राजा) समर्थकों की सख्या बहुमत में हो गई। नर बहादुर भंडारी भारी बहुमत से सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। सिक्किम परिपद एक ऐसा दल उभरकर आया जो सामंतवादी शक्तियों का समर्थक हो गया। जिन गुटों का सिक्किम परिपद को समर्थन प्राप्त था वे थे—लँप्चा-भूटिया, कबीले-आदिवासी-लिम्बू तथा नेपालियों में निवार उपजाति, जिनको चोगियाल के गुट से अधिकांश जोड़ा जाता रहा है। पहली जून, 1981 को चोगियाल ने अपने बयान में कहा था कि, "काजी दोरजी की सरकार मेरे विरोध में थी लेकिन वर्तमान सरकार के साथ मेरे सम्बन्ध अच्छे हैं" यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि सिक्किम परिपद पार्टी के सदस्य तथा उनके नेताओं का चोगियाल से न केवल मधुर सम्बन्ध है अपितु उनकी यह विचार धारा दृढ़ है कि सिक्किम का भारत में विलय असंविधानिक था।" सिक्किम परिपद की नीति भी लँप्चा भूटिया आदिवासी तथा निवार नेपाली जाति को पूरा समर्थन देने वाली थी। उक्त विशेष गुट के लोगों को रोजगार देना सिक्किम परिपद सरकार का परम कर्तव्य हो गया था। मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी स्वयं ने बयान में कहा था—"सिक्किम केवल मूल निवासियों का ही है और बाहर के लोगों का यहां कोई भी स्थान नहीं है।" हमने उन सभी लोगों को वापस भेज दिया है जो यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आये हुए थे।

सिक्किम परिपद की सरकार ने लिम्बू भाषा को मान्यता दे दी थी। इसी सरकार के अन्तर्गत "लँप्चा संगठन" को उभरने का पूरा मौका मिला।

इस प्रकार सिविक्रम परिपद पार्टी के साथ लैप्चा-भूटिया-लिम्बू तथा निवार नेपाली थे जिनको सर्वाधिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त थी, जबकि अन्य निवासी आवश्यक सुविधाओं से पूर्णतया वंचित रहे गये। यही कारण था कि मुख्य-मन्त्री भंडारी सिविक्रम परिपद क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस (इ) में नहीं बदल सके जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री काजी दोरजी ने 1977 में कांग्रेस को जनता पार्टी में बदल दिया था। 1981 में भंडारी ने अपने वयान में अपनी असमर्थता को द्यवत करते हुए कहा कि, "यद्यपि केन्द्रीय हार्डकमान के द्वारा मुझे संकेत मिला है कि मैं सिविक्रम परिपद को कांग्रेस (इ) में परिवर्तित कर दूँ परन्तु मुझे जिस गुट का समर्थन प्राप्त है तथा जो लोग मेरे मंत्रिमण्डल में हैं वे दल को दूसरा स्वरूप देने के विरोध में हैं।" यह वयान पार्टी के बदलने का विरोध तो करता था लेकिन साथ में नई दिल्ली से उन सुविधाओं को भी लेना आवश्यक था जिनके आधार पर अपने दल के सदस्यों को लाभ पहुँचाना था। मुख्यमंत्री भंडारी की राजनीति तथा उसकी सूझ-बूझ ने उसे मजबूर किया कि वह केन्द्रीय हार्डकमान के संकेत को स्वीकार करे जिससे वह उन लाभों से वंचित न हो जाय जिसके न होने से सरकार चलाना असंभव ही हो जाय। इस प्रकार 8 जुलाई, 1981 को भंडारी अपने 46 सदस्यीय दल को दिल्ली लाये तथा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निवास स्थान पर उन्होंने सामूहिक तौर पर कांग्रेस (इ) की सदस्यता स्वीकार की। 8 जुलाई, 1981 से सिविक्रम से रातोंरात कांग्रेस (इ) की सरकार का निर्माण हुआ। केवल दल का परिवर्तन तो अवश्य हुआ लेकिन बहुसंख्यक नेपाली निवासियों के प्रति भेदभाव की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुसंख्यक निवासियों में असुरक्षा की भावना ज्यों की त्यों बनी रही।

समस्या यहाँ तक सीमित नहीं है। इनके अलावा अन्य भावी खतरे भी दिखाई देते हैं जो राष्ट्रीय भावना से हटकर हैं। उदाहरण के लिए, सिविक्रम में एक अल्पसंख्यक गुट और है जो बुद्ध-लैप्चा के नाम से जाना जाता है। यह गुट उन शक्तियों से गठबंधन कर रहा है जो भारतीय विरोधी शक्ति कहा जा सकता है। बुद्ध-लैप्चा उन बहुसंख्यक नेपालियों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सुशिक्षित रहते हैं जिनके नजदीक रहने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बुद्ध-लैप्चा दाजि-लिंग तथा सिविक्रम के लैप्चा ईसाई के साथ अधिक नजदीक दिखाई देते हैं। ईसाई लैप्चा लोगों का जैक्षणिक स्तर अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा है तथा रहन-सहन का दर्जा भी अधिक समृद्ध है। यही कारण है कि बुद्ध लैप्चाओं को

से है कि सिक्किम के मूल निवासियों का मैदानी लोगों के प्रति विनोद दृष्टिकोण। यह घृणा उन 60,000 भारतीय मैदानियों के प्रति है जिनको अधिक चतुर, होशियार तथा चालक समझा जाता है। उनका यह भ्रम है कि इन मैदानी लोगों ने वषों से बहुसंख्यक लोगों को यातना दी है तथा उनका हर दृष्टि से शोषण किया है। ये 60,000 मैदानी लोग वर्तमान परिस्थिति में हमेशा असुरक्षा की भावना से रह रहे हैं तथा उन्हें हमेशा यही डर बना रहता है कि इनको कभी भी वहां से भगाया जा सकता है।

असुरक्षा की भावना की पुष्टि मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी के बयान से की जा सकती है। 8 जुलाई, 1981 को पटना से प्रकाशित "इंडियन नेशन" में मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि बाहर से आने वाले लोगों को यद्यपि एक दम रोका तो नहीं जा सकता लेकिन भविष्य में रोकने के लिये ऐसे कदम उठा लिये गये हैं।" सिक्किम के एक विख्यात सेखर हेमनाथ भंडारी ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि, "भंडारी सरकार उन लोगों के बारे में चिन्तित है जो दार्जिलिंग, कलकत्ता, बिहार-राजस्थान-उत्तरप्रदेश तथा कलिंगपोंग से आकर बराबर बसने का इरादा कर रहे हैं।" अपनी टिप्पणी में लेखक ने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले लोगों का तांजा यदि इसी तरह बना रहा तो सिक्किम के मूल निवासियों (नेपासी-भूटिया-सैन्घः आदि) के लिये अतिरिक्त संकट पैदा हो जायेगा। भंडारी सरकार ने उन 60,000 मैदानी लोगों को सिक्किम का निवासी नहीं माना है यद्यपि वे सौर सिक्किम में उन्हीं दिनों आये थे जब नेपासियों का प्रवेश हुआ था। जबकि बेसुतियों को भंडारी सरकार ने पूर्णरूप से स्वीकार कर लिया है। मैदानी लोगों को इस प्रकार के भ्रमभासपूर्ण व्यवहार में डर है कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिन उनको राजनीतिक अधिकारों के उपयोग से भी हाथ धोना पड़े। यह डर हमलिये भी बढ़ गया है क्योंकि श्री रामचन्द्र पौडियाल ने कोर्ट में शपथकर्म किया था कि वह बाहर से आये हुए लोगों को प्रान्तीय विभाजन के प्रतिनिधित्व में नहीं जबकि राजनीतिक दृष्टि से उनको "पेरिटी एंड्रोज" के समान ही माना जायेगा। यद्यपि श्री पौडियाल का मैदानी लोगों के प्रति

इंसाईं लैप्चाओं ने अधिक आकर्षित किया है। इन दोनों श्रेणी के लैप्चाओं ने एक संगठन का निर्माण कर लिया है जो भारतीय राष्ट्र भावना से अपना संबंध नहीं रखना चाहते। लैप्चाओं के नाम से दो संगठन हैं जिनके नाम हैं (अ) सिक्किम लैप्चा साहित्य परिषद, (ब) सिक्किम लैप्चा परिषद। ये दोनों ही संगठन इतने भोले भोले तथा निर्बल नहीं हैं जितने वे बाहर से देखने में लगते हैं। भूटिया लोगों की भी भूमिका चोगियाल समर्थक शक्ति को निरन्तर बल देने की रही है। इस प्रकार चोगियाल के नाम पर चोगियालवाद धीरे-धीरे पनप रहा है। भूटिया लोगों ने बार-बार सिक्किम के निवासियों को आह्वान सा किया है कि सिक्किम की एक अलग संस्कृति है, अलग भाषा है तथा रहने सहने का तोर तरीका भी मैदानी लोगों से भिन्न है। सहने का अर्थ यही है कि सिक्किम के मूल निवासियों के मानस में अभी भी वही बात बैठी हुई है कि सिक्किम भारत की मुख्य धारा से आत्मसात नहीं कर सकता। यही बात चोगियाल भी 1975 से पूर्व वहाँ के निवासियों से कहा करता था। इस प्रकार अलग संस्कृति, अलग धर्म तथा धार्मिक संगठनों के माध्यम से जनतान्त्रिक विरोधी तथा भारत विरोधी तत्त्वों को अनवरत रूप से उकसाया जाता रहा है।

दूसरी ओर 70 प्रतिशत नेपाली लोग अभी भी सामन्तवादी शक्तियों के हाथों पीड़ित व शोषित हैं। उनको अभी भी प्रान्तीय विधानसभा में सुरक्षित सीट प्रदान नहीं की गई है। नेपाली भाषा को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि नेपाली बहुसंख्यक निवासियों का नेतृत्व श्री रामचन्द्र पौड्याल करते रहे हैं जिनके दल का नाम क्रान्तिकारी सिक्किम कांग्रेस है। भौगोलिक तथा राजनीतिक समानता दार्जिलिंग व कलिंगपोंग में देखने को मिलती है जिसका लाभ नेपाली लोग लेना चाहते हैं। नेपालियों ने भी एक नारा प्रस्तुत किया है वह है "अलग गोरखा प्रान्त"। यह नारा निश्चित ही समस्त नेपालियों को एक झड़े के नीचे ला देगा। यही नारा नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल करने में मदद देगा। इसी के दौरान नेपालियों ने समस्त भारतीय नेपाली भाषा समिति का गठन किया है। विधानसभा में भी सिक्किम कांग्रेस (क्रांति) का सबसे बड़ा विरोधी दल है जो जनता पार्टी से टूट कर बना है।

सिक्किम में अलगवादी तत्त्वों की राजनीतिक गतिविधियाँ किस प्रकार राष्ट्रीय भावना में प्रतिकूल दिखाई देती हैं? पहली झलक तो इसी बात

से है कि सिक्किम के मूल निवासियों का मैदानी लोगों के प्रति घेनोना दृष्टिकोण। यह घृणा उन 60,000 भारतीय मैदानियों के प्रति है जिनको अधिक घटुआ, होशियार तथा चालक समझा जाता है। उनका यह भ्रम है कि इन मैदानी लोगों ने वपों से बहुसंख्यक लोगों को मातना दी है तथा उनका हर दृष्टि से शोषण किया है। ये 60,000 मैदानी लोग वर्तमान परिस्थिति में हमेशा अमुरसा की भावना से रह रहे हैं तथा उन्हें हमेशा यही डर बना रहता है कि इनको कभी भी वहां से भगाया जा सकता है।

अमुरसा की भावना की पुष्टि मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी के बयान से की जा सकती है। 8 जुलाई, 1981 को पटना से प्रकाशित "इंडियन नेशन" में मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि बाहर से आने वाले लोगों को यद्यपि एक दम रोका तो नहीं जा सकता लेकिन भविष्य में रोकने के लिये ऐसे कदम उठा लिये गये हैं।" सिक्किम के एक विख्यात लेखक हेमलाल भंडारी ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि, "भंडारी सरकार उन लोगों के बारे में चिन्तित है जो दार्जिलिंग, कलकत्ता, बिहार-राजस्थान-उत्तरप्रदेश तथा कलिंगपोंग से आकर बराबर बसने का इरादा कर रहे हैं।" अपनी टिप्पणी में लेखक ने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले लोगों का तांता यदि इसी तरह बना रहा तो सिक्किम के मूल निवासियों (नेपासी-भूटिया-लंग्वा आदि) के लिये अधिक संकट पैदा हो जायेगा। भंडारी सरकार ने उन 60,000 मैदानी लोगों को सिक्किम का निवासी नहीं माना है यद्यपि ये लोग सिक्किम में उन्ही दिनों आये थे जब नेपासियों का प्रवेश हुआ था। जबकि नेपालियों को भंडारी सरकार ने पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया है। मैदानी लोगों को इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार से डर है कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिन उनको राजनीतिक अधिकारों के उपभोग से भी हाथ धोना पड़ जाय। यह डर इसलिये भी बढ गया है क्योंकि श्री रामचन्द्र पौडियाल ने कोर्ट में याचिका पेश कर दी है कि बाहर से आये हुए लोगों को प्रांतीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व न मिले जबकि संविधानिक दृष्टि से उनको "पेरिटी फामूला" के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त है। यद्यपि श्री पौडियाल का मैदानी लोगों के प्रति रुख बदल तो गया है विशेष रूप से इसलिये कि सिक्किम में राजनीतिक वातावरण भी तीव्र गति से बदल रहा है। राजनीतिज्ञों के मान में यह स्पष्ट किया है कि, "हमारी पार्टी मैदानी लोगों तथा व्यापार-प्रमदाय के खिलाफ नहीं है परन्तु उन्हें जरूरत से हटाकर महार नहीं दिया जायेगा।"

इस प्रकार सिक्किम की राजनीति को दिशा देने वाले वे विशिष्ट लोग हैं जो वहाँ के जाति व उपजातियों में बटे हुए हैं। यह सच है कि सिक्किम के विकास के लिये केन्द्र द्वारा करोड़ों रुपये का अनुदान का गलत तरीके से उपयोग इन्हीं विशिष्ट लोगों में विभाजित हुआ। योजना के अन्तर्गत केन्द्र ने सिक्किम को 121.82 करोड़ रुपये दिये थे जिसका दुरुपयोग इन्हीं लोगों ने किया।

चोगियालवाद

कहने को सिक्किम के चोगियाल (राजा) को 1975 में हटा दिया था और 21 राज्यों की तरह वहाँ जनतान्त्रिक सरकार बनी तथा प्रशासन का ढाँचा संविधानिक तरीके से गठित हुआ। 22 वाँ राज्य बनने के बाद ऐसी आशा की जाती थी कि सिक्किम के निवासी भारत के प्रशासन तथा राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ जायेंगे। ऐसी उम्मीद तीन बातों के आधार पर की जा रही थी।

पहला आधार तो यह था कि सिक्किम की जनता सदियों से चोगियाल प्रशासन से पीड़ित थी और उनके शोषण होने में जनतान्त्रिक आन्दोलन भी हुए। दूसरी बात यह थी कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान नये प्राप्त के विकास की ओर अधिक था। इसीलिये आर्थिक सहायता अपेक्षाकृत सिक्किम को अधिक प्रदान की यहाँ तक कि जम्मू-काश्मीर भी प्राथमिकता की श्रेणी में न रह पाये। छठी योजना के अन्तर्गत सिक्किम को 121.82 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता केन्द्र के द्वारा प्राप्त हुई। इतनी भारी आर्थिक सहायता देने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि सिक्किम के निवासी सभी तरह से मुखी रहे—उनको किसी भी प्रकार से कष्ट न हो। तीसरा आधार यह था कि केन्द्र का सिक्किम के नियासियों की भावना तथा सवेदना को पूरी तरह समझते हुए यह उद्देश्य था कि उन पर कोई भी चीज लादी या थोपी न जाये। उनकी देश की प्रति मही दिशा में निष्ठा बढ़े तथा वे धीरे-धीरे भारत के राष्ट्रवाद को समझने का प्रयास करें। केन्द्र की उक्त तीन आधारों पर सिक्किम के प्रति नीति उचित ही दिशा में मानी जा सकती है। परन्तु यह नीति आगे वाले दिनों में सफल होती हुई दिखाई नहीं दी।

परन्तु केन्द्र की तीन आधारों पर संजोयी गई उम्मीदें अमफल रही। कटु सत्य यह है कि सिक्किम में चोगियालवाद अभी भी जीवित है। यद्यपि चोगियाल पातुदेन नाम ग्याल की मृत्यु हो गई और उसका दाह-संस्कार

गंगटोक में परम्परागत पद्धति से किया गया। चोगियाल की चिता की लपटें अभी शान्त भी नहीं हुई थीं तभी एक पड़मन्य होता हुआ दिखाई दिया जो चोगियाल की संस्था को जीवित करने के लिये कटिबद्ध था। ऐसा लगने लगा जैसे सिक्किम के निवासियों ने भारत में विलय के विरोध में फिर से झड़े उठा लिये हैं। दूसरे शब्दों में चोगियालवाद सिक्किम में फिर से जीवित हो उठा है तथा भारतीय राष्ट्रवाद के लिये खतरे के संकेत मिलने लगे हैं। सिक्किम के अन्दर व बाहर कई ऐसी सशक्त शक्तियाँ काम कर रही हैं जो राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल हैं। जिन दिन (19 2.82) चोगियाल का राह-संस्कार किया गया, उसी दिन, क्षेत्रीय तथा विघटनकारी तत्त्वों ने भारतीय राष्ट्रवाद की चुनौती देते हुए कहा था कि "चोगियाल का पुत्र तेनजिम तोपग्याल नामग्याल सिक्किम का 13वां चोगियाल होगा।" यह चुनौती केवल भावना का उफान ही नहीं थी, बल्कि एक संकेत भी था कि चोगियाल के समर्थक अभी भी राजनीतिक व्यवस्था में शक्तिशाली हैं जो भारत के भूखंड से जुड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि सिक्किम विधानसभा के दस विधायकों ने उस कागज पर हस्ताक्षर करके चोगियाल के पुत्र को 13वां चोगियाल स्वीकार किया। उन दस विधायकों में से 6 कांग्रेस (इ) के, 3 कांग्रेस (शान्तिकारी) तथा एक स्वतन्त्र थे। जिस कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किये उस पर लिखा था, "19 फरवरी, 1982 को, तिब्बत के कलेंडर का वर्ष 'व्याकज्या व चुखी' सिक्किम की जनता ने 13वां चोगियाल को परम्परागत स्कार्फ भेंट करने का निश्चय किया है। भेंट करने का स्थान गंगटोक का शुक्ला खाग चुना गया तथा, समय साय 3 बजे।" उक्त राजनीतिक गतिविधियाँ स्पष्ट संकेत देती हैं कि सिक्किम का भारत में विलय एक वास्तविक तथ्य नहीं है। चोगियाल के पुत्र ने भी सिक्किम की स्वतन्त्र सत्ता के बारे में बयान देना शुरू किया। अपने बयानों में पुत्र ने यह भी कहा कि "जिस ढंग से सिक्किम को भारत में मिलाया गया वह गलत था।" अपने पिता की तरह पुत्र ने भी वही बात कहना प्रारम्भ किया कि सिक्किम में राजतन्त्र को वापस लाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसकी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखना।

इसी प्रकार की ध्वनि तथा गंध मुख्यमन्त्री नर बहादुर भंडारी के चुनावी अभियान के भाषणों में भी मिलती है। श्री भंडारी ने अपने भाषणों में सिक्किमी जनता से उसी प्रकार के वायदे पूरे करने को कहा जिनको चोगियाल के पुत्र वांगचुक ने अपने बयानों में बखाना किया था। श्री भंडारी तो अपने भाषणों में यहाँ तक कह गये कि "सिक्किम का भारत में विलय

असंवैधानिक तथा जल्दबाजी का परिणाम है।" भंडारी ने भाषणों में यह भी कहा कि "सिक्किम के बारे में सोचने तथा भविष्य में उसका दर्जा क्या हो यह सब उसके निवासियों को ही अधिकार है—बाहर वालों को नहीं।" भंडारी के इस प्रकार के भाषणों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अत्यधिक झकझोरा ही नहीं अपितु कमजोर किया है। सिक्किम के सभी राजनीतिक दलों का यही मत है कि सिक्किम की एक स्वतन्त्र सत्ता है और बनी रहनी चाहिये।

श्री भंडारी न केवल शब्दों में चोगियाल के शाही घराने का समर्थन करते रहे अपितु उन्होंने इस दिशा में प्रभावी काम भी किया। उन्होंने केन्द्र पर बराबर दबाव बनाये रखा कि चोगियाल के शाही परिवार तथा उनके सम्बन्धियों को उचित मुआवजा तथा सुविधायें मिलनी चाहिये जो कि रहन-सहन के स्तर को ठीक रख सके। यह भंडारी जी का ही केन्द्र पर दबाव था कि चोगियाल का दाह-संस्कार सरकारी तौर पर सम्मानपूर्वक हो। यही कारण था कि केन्द्र ने चोगियाल के दाह-संस्कार के लिये सिक्किम सरकार को 20 लाख रुपये दिये।

श्री भंडारी की राजनीति को "दुहरी नीति" की संज्ञा दी जाने लगी है। एक ओर तो भंडारी सिक्किम में हिन्दी भाषा का प्रचार तथा उसकी लागू करने के लिये केन्द्र से वचनबद्ध है जिससे की उम्हें आर्थिक सहायता बराबर सहूलियत से मिलती रहे तथा उनका व्यावहारिक स्वरूप तथा राजनैतिक गैली पूर्णतया प्रतिकूल दिखाई देती है। केवल हिन्दी के नाम पर केन्द्र से अनापशनाप आर्थिक सहायता लेना तथा काम उसके विस्तृत प्रतिकूल करना यह उनकी दुहरी नीति साफ नजर आती है। एक उदाहरण से दुहरी नीति स्पष्ट होती है वह यह कि जब मार्च, 1982 को विदेश मंत्री नरसिंह राव गंगटोक गये तो भंडारी जी ने पश्चिमी बंगाल की भाषायी नीति की आलोचना की, जबकि स्वयं ने कुछ महिने पहले ही गंगटोक डिग्री कालेज में हिन्दी विभाग को समाप्त कर हिन्दी के प्राध्यापकों की सेवाओं से मुक्त कर दिया। जिन हिन्दी प्राध्यापकों की सेवा को समाप्त किया उनका नाम है तबोदार झा।

अकेले भंडारी जी ही भारत विरोधी भावना को सिक्किम में नहीं फैला रहे अपितु विरोधी दल भी इस अभियान में शामिल हैं। सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) के प्रमुख नेता तथा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष बी. बी. गुरंग तथा उनके निकट साथी पी. एल. भुरंग दोनों का यही मत है कि सिक्किम की स्वतन्त्र सत्ता पुनः स्थापित होनी चाहिये तथा राजतंत्र घराने के सदस्यों

को उचित मुआवजा मिले जिससे वे स्तर से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। पी. एल. गुरंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि "सिक्किम को भूटान की तरह दर्जा मिलना चाहिये।" पी. एल. गुरंग भी उन 10 विधायकों में से एक थे जिन्होंने चोगियाल के पुत्र को 13वाँ चोगियाल घोषित किया था तथा स्कार्फ भेंट किया था। सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र पौदियाल न केवल वर्तमान संवैधानिक दर्जे के आलोचक ही हैं अपितु उन्होंने भाषणों में स्पष्ट कहा है कि, "सिक्किम को जम्मू-कश्मीर से अधिक विशेष दर्जा मिलना चाहिये।"

भारत विरोधी भावना तथा चोगियाल समर्थक केवल राजनीतिज्ञों तक ही सीमित नहीं है अपितु यह नौकरशाही तथा शैक्षणिक केन्द्रों तक पहुँच चुकी है। उल्लेखनीय है कि जिस समय चोगियाल के पुत्र का राज्याभिषेक उत्सव हो रहा था, उस सण न केवल 10 विधायक मौजूद थे बल्कि चार आई.ए.एस. वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे और उन्होंने खुलकर चोगियाल समर्थक विचार प्रस्तुत किये।

भारतीय तथा मैदानी निवासी विरोधी भावना इस हद तक पहुँच गई कि एक दिन पंजाब निवासी शिक्षा निदेशक श्री मधुसूदनसिंह पर वहाँ के उपद्रवी लोगों ने घातक प्रहार किया। उनके ऊपर भारत सरकार के एजेन्ट होने का आरोप लगाया गया। एक दक्षिणी निवासी महिला, जो कि पुलिस विभाग में इन्स्पेक्टर थी, को भी गैंगटोंक के एन्वी कैम्पस स्थान पर पीटा गया। उक्त हिंसात्मक घटनाओं से स्पष्ट जाहिर होता है कि सामतवादी शक्तियाँ, सिक्किम में फिर से किस प्रकार सर उठा रही हैं।

यहाँ तक कि धार्मिक मठाधीश लामा लोग भी सिक्किम के विलय के विरोध में अपनी राय खुले आम देने लगे हैं। लामाओं का प्रतिकूल रुख होना स्वाभाविक है क्योंकि जो अनाप-बनाप आर्थिक सहायता चोगियाल के शासन में मिलती थी वह विलय के बाद आर्थिक लाभ मिलना सम्भव नहीं हुआ। एक अन्य कारण भी स्पष्ट लगता है जिसके कारण लामा समुदाय वर्तमान परिस्थितियों से खुश नहीं है। कारण यह है कि अति आधुनिकता के पर्यावरण में सामायुक्त शिक्षा का प्रावधान स्वतः ही गायब हो रहा है जिससे उनकी महत्ता घट रही है।

चोगियाल के पुत्र का राज्याभिषेक उत्सव तथा उससे जुड़ी हुई राजनीतिक गतिविधियाँ कुछ मुद्दों की ओर संकेत अवश्य करती हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि भारत की अखण्डता तथा सुरक्षा-सिक्किम की वर्तमान समस्या

से जुड़ी हुई है। वहाँ के निवासियों ने विलय के अध्याय को पुनः खोलना शुरू कर दिया है। इस समस्या से क्षेत्रीयवाद तथा विघटनकारी शक्तियाँ भी उभर कर आयी हैं। इस प्रकार की समस्याएँ न केवल सिक्किम से ही सीमित हैं अपितु संपूर्ण उत्तरी पूर्व सीमा विघटित गतिविधियों ने पहले से ही पीछित है। विघटनकारी शक्तियों ने बाहरी तात्तों को भी मोका दिया है जो दिनों-दिनों अपनी कार्यवाहियों में सक्रिय होत चले जा रहे हैं।

उदाहरण के लिए चीन सभी से यह आपत्ति उठा रहा है कि "सिक्किम का भारत में विलय संविधानिक नहीं है।" ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि स्व चोगियाल के एक पुत्र शोनाम गियाल जो बीजिंग में रह रहे हैं उनका चीन अवश्य भारत विरोधी कार्यवाही में प्रयोग करेगा। भ्रम-रीका की तो पहले से ही भूमिका जारी थी जब एक महिला से चोगियाल की शादी हुई और विलय के बाद वह अपने पति को छोड़कर अमरीका भाग गई। नेपाल भी भारत की कड़ी आलोचना को भूला नहीं है जब नेपाल के राजा ने चोगियाल के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किये थे। पूर्व प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई के भोले भाले विचारों का नेपाल, चीन व सिक्किम निवासियों ने पूरा-पूरा लाभ उठाया है।

भंडारी सरकार प्रारम्भ से ही सिक्किम में रह रहे 30,000 नेपाली नागरिकों के बारे में चिन्तित रही है कि किस प्रकार उनको अपने प्रांत में सरकारी तौर पर मान्यता दी जाये। भंडारी सरकार की विशेष रूप से केन्द्र से शिकायत है कि 1975 से इस समस्या पर कोई गम्भीरता नहीं बरती गई है। एमो के साथ जुड़ी हुई समस्या यह भी है कि सुरक्षित सीटों के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया है तथा भारतीय संविधान में नेपाली भाषा को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। असली विवादास्पद समस्या 30,000 नेपालियों की नागरिकता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले कई दशकों से रहते आ रहे हैं फिर भी उनके स्थायी बसने की गारंटी नहीं है। इस समस्या ने केन्द्र व राज्य सम्बन्ध का भी विवाद उठा रखा है। मुख्यमन्त्री भंडारी के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी केन्द्र से दबाव डालते हुए भांग की है कि नेपाली निवासियों की नागरिकता का विवाद शीघ्र तय किया जाय।

नेपालियों की नागरिकता का प्रश्न और भी विकट होता जा रहा है, जितना केन्द्र इस समस्या को उदासीनता में ले रहा है। जब नव. 26-1983 को श्रीमती इन्दिरा गांधी गैगटोक गई थीं तो उन्होंने यही कहा था कि, "अभी उन नेपालियों को तरीके से पहचाना नहीं जा सका है जो दशकों से सिक्किम

में रह रहे हैं और यह समस्या अभी 'विचारधीन' है।" राज्यसभा में भी राज्य गृहमन्त्री एन. आर. लस्कर ने कहा था कि, "16 मई, 1975 को एक आदेश जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत 26 अप्रैल, 1975 से पहले जिन्होंने 1961 के एक्ट की शर्तों को पूरा कर दिया है वे भारत के नागरिक समझे जायेंगे।" उक्त आदेशों को व्यावहारिक रूप, में अभी भी केन्द्र द्वारा पूरा नहीं किया है।

विधान सभा भंग

नर बहादुर भंडारी की सरकार जब केन्द्र से अधिक तालमेल रखने में असमर्थ रही तो सिक्किम के राज्यपाल ने केन्द्र की सलाह से भग कर दिया। वस्तुतः स्थिति यही थी कि भंडारी सरकार की राजनीति लगातार नई दिल्ली को न केवल किसी न किसी मुद्दे पर परेशान किया जाय बल्कि निरन्तर दबाव बनाये रखने के आवरण में आर्थिक लाभ प्राप्त करती रहे। इस दुहरी नीति के बारे में केन्द्र जागरूक था। इसलिये देश की अखंडता तथा एकता को सुदृढ़ रखने के लिये यह जरूरी समझा गया कि भंडारी सरकार को हटा दिया जाय।

लोकसभा चुनाव

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के तुरन्त पश्चात् श्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री बने और उन्होंने आम चुनाव की घोषणा कर दी। सारे देश में 24 व 25 दिसम्बर को चुनाव सम्पन्न हुए तथा 31 दिसम्बर, 1984 को परिणाम घोषित होना शुरू हुए। चुनाव परिणाम में सिक्किम से अपदस्थ मुख्य मन्त्री श्री भंडारी लोकसभा सीट के लिये चुन कर आये।

निष्कर्ष

नर बहादुर भंडारी को मुख्य मन्त्री पद से हटाने के बाद भी सिक्किम जनता ने उन्हें लोक सभा के लिये चुनकर भेजा। इस विजय से यह संकेत अवश्य मिलता है कि सिक्किम में सामंतवादी शक्तियों का जोर है और उनकी समस्त उन मांगों को केन्द्र किस प्रकार संतुष्ट कर पायेगा जो राष्ट्र हित में नहीं हैं। शाही घराने के प्रति झुकाव कोई बुरी बात नहीं है परन्तु उससे जुड़ी हुई मांग अधिक खतरनाक है। सिक्किम को स्वतन्त्र सत्ता के रूप में कंते स्वीकार किया जा सकता है जब वह भारत का 22वाँ राज्य संविधानिक तरीके से घोषित हो चुका है। 30,000 नेपाली निवासियों की समस्या का हल निकट

भविष्य में संभव नहीं लगता क्योंकि हल करने से पूरे कुछ नाजुक क्षेत्रों की सम्मीरता तथा भावी परिणाम के बाद भी सोचना होगा। केन्द्र की नीति पर्वतीय राज्यों के बारे में सोचनीय समस्या है।

इतना आवश्यक है कि सिक्किम निवासियों को समझदारी से काम करना होगा। उन्हें भारतीय राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ना होगा तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिये निष्ठापूर्वक काम करना होगा।

संदर्भ सूची

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1—पॉलिटिक्स ऑफ सिक्किम | — | अवधेश कुमार |
| 2—सिक्किम जोइन्स दा मदरलैंड | — | डा. आर सी मिश्रा |
| 3—सिक्किम हेरल्ड | — | सैगटॉक |
| 4—सिक्किम टाइम्स | — | सैगटॉक |
| 5—सिक्किम एक्सप्रेस | — | सैगटॉक |
| 6—इंडिया टू डे | — | पटना |
| 7—दो इन्डियन नेशन | — | |

सिक्किम में नेतृत्व का स्वरूप

भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि स्थानीय समस्याओं का हल और उससे बढ़ता हुआ असंतोष के लिए वहाँ की भूगोल अधिक जिम्मेदार है। स्वतन्त्रता के बाद से लेकर आज तक परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अन्तर केवल इतना है कि 1947 के बाद की अवधि एक प्रारम्भिक काल की थी जिसमें घरेलू समस्याओं पर काबू पाने के लिए सभी भारतीयों का कर्त्तव्य बन जाता था कि तत्कालीन परिस्थितियों का सामना सहिष्णुता-कर्त्तव्यपरायणता तथा मानवीयता के आधार पर करें और ऐसा हुआ भी। सभी लोगो ने अपनी स्थानीय समस्याओं को महत्व नहीं देते हुए व्यापकता और विशाल दृष्टिकोण का परिचय दिया। परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया राजनीतिक नेता तथा नौकरशाही का व्यवहार उसी गति से प्रान्तों की स्थानीय समस्याओं के बारे में उदासीन तथा उपेक्षापूर्ण होता गया। असंतोष तथा कष्ट को ध्यस्त करने की शालीनता को भी प्रशासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सहिष्णुता की सीमा भी पार हुई। उसके पश्चात् तो केवल उन प्रस्तावों के अपनाने का विकल्प रह गया कि जिसके माध्यम से प्रशासकों का ध्यान मजबूरन जाय। असंतोष को जाहिर करने का तरीका उन लोगों की अच्छी तरह आ गया कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सिक्किम-कलिपोक-दार्जिलिंग-नई जलपाईगुड़ी आदि स्थानों पर नेपाली लोग बसे हुए हैं जो बड़े मेहनती होते हैं और शारीरिक कार्य करने में बड़े कुशल माने जाते हैं। चूँकि यह जाति बहुपत्नि जाति है इसलिये नेपालियों की जनसंख्या भी द्रुतगति से पिछले 40 साल में बढ़ी है। सिक्किम में 1973 का जनसांख्यिक विद्रोह इन्हीं नेपाली लोगों ने प्रारम्भ किया था और उस आन्दोलन में नेपालियों की सफलता भी मिली। जिस तरह का नेतृत्व सिक्किम में उभर कर आया है उसका भी विश्लेषण करने का प्रयास है।

भारत जैसे विकासशील देश में एक प्रान्त का समग्र विकास बहुत कुछ वहाँ के स्थानीय नेतृत्व तथा उसकी प्रकृति से गहरा सम्बन्ध रखता है। वहाँ के राजनीतिक नेता ही प्रान्त की नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार समझे जाते हैं, अतः विभिन्न क्षेत्रों में विकास व प्रगति को राजनीतिक विश्लेषण किये बिना नहीं समझा जा सकता। यहाँ राजनीतिक नेतृत्व का अर्थ प्रशासक वर्ग से है।

1975 के पश्चात् (सिविकम का भारत में विलय के बाद) सिविकम के राजनीतिक नेतृत्व का स्वरूप तथा उसकी उभरती हुई प्रकृति किस रूप में सामने आई है। इसका प्रयास प्रस्तुत लेख में किया गया है। जैसा कि सभी को विदित है कि एक दशक के बाद भी राजनीतिक दलों की स्थिति स्थिरता की ओर बढ़ नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में प्रशासकों द्वारा निर्मित सामाजिक-आर्थिक नीतियां भी उसके राजनीतिक झुकाव को स्पष्ट नहीं करती।

अतः सरकार के कृत्यों का विश्लेषण करने का प्रयास भी अपूर्ण सा ही होगा जब तक राजनीतिक दलों की तस्वीर स्पष्ट नहीं हो जाती। इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रशासक वर्ग का सामाजिक-आर्थिक परिचय प्राप्त करें। कारण यह है कि विधायकों की कोई विचार-धारा न होने पर उनके सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को जान लेने से उनकी नीतियों के बारे में ज्ञान हो सकता है।

पृष्ठभूमि

राज्य परिषद (State Council) का गठन 1953 में हुआ। इसके अन्तर्गत एक अध्यक्ष होता था जिसको वहाँ के महाराजा मनोनीत करते थे। परिषद के कुल घुने हुए 12 सदस्य होते थे जिसमें से 6 सदस्य लैप्चा-भूटिया तथा नेपाली होते थे और शेष राजा के द्वारा मनोनीत किये जाते थे। गाँवों के स्तर पर पंचायतों का गठन 1965 में किया गया तथा महानगर के स्तर पर बाजार समिती (Market Committee) का गठन 1969 में हुआ, इन संस्थाओं के गठन के दो प्रमुख उद्देश्य थे : (अ) जनतांत्रिक स्वरूप की रचना जिसके लिए वहाँ के राजनेताओं की माँग थी (ब) जाति के आधार पर मतों की प्रक्रिया की शुरुआत। ऐसा करने से अंशतः राजा की शक्ति वरकरार रही और लोकप्रिय प्रशासन का स्वरूप भी सामने आ गया। प्रान्त की नीतियों के निर्माण में राजा की ही भूमिका प्रमुख बनी रही। इसके साथ प्रशासन का ढाँचा द्वैध शासन प्रणाली जैसा सामने आया जब 1953 में दो प्रकार के विषयों की-अलग अलग सूची सामने रखी। पहली सूची उन विषयों की थी जो आरक्षित (Protectorate) के नाम से जानी गई तथा दूसरी वह जिसे स्थानान्तरण के रूप में जानी गई। आरक्षित विषय राजा के व्यक्तिगत माने गये जिन पर राज्य परिषद का अधिकार स्वीकार किया गया। आरक्षित विषय थे—धार्मिक, विदेशी, गृह व पुलिस तथा वित्त। स्थानान्तरण के विषय थे—शिक्षा, जनकल्याण, प्रेस व आवकारी, मातृशाला आदि।

उक्त ढाँचे में सिविक्रम का प्रशासन चलता रहा जब तक 1973 में जन-तान्त्रिक शक्ति ने एक राजनीतिक विप्लव उत्पन्न नहीं कर दिया।

नेतृत्व का दूसरा तत्व राजनीतिक दल को माना गया है। इस प्रकृति के नेतृत्व को समझने के लिए राजनीतिक दलों के विकास के बारे में भी जानना आवश्यक होगा।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सिविक्रम में राजनीतिक दलों का उद्भव यहाँ के किसान वर्ग की दयनीय स्थिति में मुधार लाने के लिए किया गया था। साथ में प्रांतीय स्तर पर जनतान्त्रिक लोकप्रिय सरकार का गठन भी करना था। 1940 के व 1947 के बीच राजनीतिक दलों की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी जैसे कमरे में बैठकर योजनाएँ बनाने की। यद्यपि उद्देश्य तो यही थे लेकिन चुनकर सामने आने जैसी स्थिति नहीं बन पाई थी। योजनायुक्त तथा औपचारिकता का रूप राजनीतिक दलों ने 1947 के बाद ही लिया। 1947 तथा 1975 के बीच जिन मुख्य दलों ने अपने अस्तित्व को ऊपर उठाया, वे थे :—

(1) 1947 में तामी सो नाम में रिग तथा जांग जेरिंग के नेतृत्व में प्रजा मुधारक समाज का गठन गैंगटोक में हुआ। प्रजा सम्मेलन का गठन गोवर्धन प्रधान तथा धन बहादुर तिवारी के नेतृत्व में तेभी तरकर स्थान पर हुआ। प्रजामण्डल का गठन पश्चिमी सिविक्रम के चाकुंग स्थान पर हुआ जिसका नेतृत्व काजी लैडपदोर जी ने किया। परन्तु दिसम्बर, 1947 को उक्त सभी दलों का विलय एक नई पार्टी में हो गया जिसका नाम सिविक्रम स्टेट कांग्रेस रखा गया।

(2) सिविक्रम राष्ट्रीय दल का गठन केवल सिविक्रम स्टेट कांग्रेस की मांगों का विरोध करने के लिए हुआ। इस दल का गठन 1948 में हुआ।

(3) स्वतन्त्र दल का निर्माण काजी लैडपदोर जी ने किया जो सिविक्रम स्टेट कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर आये थे।

(4) 1960 में सिविक्रम नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इस दल का निर्माण चार दलों के विलय हो जाने में हुआ। वे चार दल थे। स्वतन्त्र दल, प्रजा सम्मेलन, स्टेट कांग्रेस के विरोधी पक्ष तथा नेशनल पार्टी के असंतुष्ट तत्व।

(5) सिविक्रम जनता कांग्रेस का गठन 1972 में हुआ।

(6) सिविक्रम कांग्रेस का गठन 1974 को हुआ।

उक्त दलों के गठन की प्रक्रिया से यह जानकारी मिलती है कि सिविक्रम में राजनीतिक विकास दलों के द्रुतगति से बदलने के कारण हुआ

ऐसा होते हुए भी दसों की प्रभावशीलता में कोई कमी नहीं आई। दसों का निरन्तर प्रभाव विधायकों पर रहा तथा उनके व्यवहार को प्रभावित करते रहे।

सिक्किम विधान सभा 1974-85

गठन—(अ) जातीय प्रतिनिधित्व

1973 के राजनीतिक उपस-युत्तन के बाद सिक्किम का भारत में विधायित्व विलय हुआ और 1974 में पहली सिक्किम विधान सभा का गठन हुआ। 1974 ■ 1985 तक तीन बार विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। 32 सदस्यीय सिक्किम विधान सभा के तीनों चुनावों की जातीय स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है।

तालिका—1

1974 के चुनाव में जातीय स्थिति

भूटिया-लैप्चा के लिए आरक्षित सीट	15
नेपालियों के लिए आरक्षित सीट	15
एस० सी० आर० एस० टी०	1
मठों के लिए	1
कुल	32

तालिका—2

1979 व 1985 के विधान सभा चुनाव में सीटों का वितरण

भूटिया लैप्चा की आरक्षित सीट	12
एस. सी. आर. एस. टी.	■
मठों की आरक्षित सीट	1
अन्य सीट	17
कुल	32

(ब) विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व

1974 के चुनाव में सिक्किम कांग्रेस का एक क्षेत्रीय बहुमत रहा और यह प्रमुख दल के रूप में उभर कर आया। एक सीट को छोड़कर सभी सीट सिक्किम कांग्रेस को मिली। वह एक सदस्यों जो सिक्किम नेशनल पार्टी का था, उसने भी बाद में अपने आप को सत्ता दल में शामिल कर लिया। 1975

के अन्त तक सत्ता दल राष्ट्रीय स्तर पर सफाया हो, जाने के कारण-सिक्किम कांग्रेस ने अपने पूरे दल को केन्द्र की सत्ता दल जनता पार्टी में मिला दिया। इस प्रकार दल परिवर्तन से कुछ विधायकों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री काजी दोरजी से असंतुष्ट होकर अपना नया दल बना लिया। विधान सभा के दूसरे चुनाव होने तक तीन प्रमुख दल सामने आये। वे तीन दल थे— (1) अखिल भारतीय जनता पार्टी, (2) सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेस तथा (3) सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी)।

दूसरे विधान सभा चुनाव में काजी दोरजी के नेतृत्व में सत्ता दल, अखिल भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो गया। यहां तक मुख्यमंत्री काजी दोरजी भी अपने क्षेत्र से जीत न सके। नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में गठित जनता परिपद को 17 सीटें प्राप्त हुईं तथा सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) को 12 सीटें मिली। सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेस केवल तीन सीटों पर जीत पाई। सिक्किम जनता परिपद ने भी बहुमत में आ जाने के बाद वही इतिहास दुहराया जो पूर्व मुख्यमंत्री काजी दोरजी ने 1978 के चुनाव में किया था। मुख्यमंत्री नर बहादुर भंडारी ने भी सत्ता में आने के बाद अपने दल को केन्द्र में सत्ताधारी दल में विलय कर लिया। दल बदल का क्रम सिक्किम में चलता रहा।

अचानक ही सिक्किम के राज्यपाल ने नर बहादुर भंडारी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। इस सरकार को उस समय समाप्त किया जब विधान सभा की अवधि की समन्वय में कुछ महीने ही शेष थे। राज्यपाल के इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर श्री भंडारी ने कांग्रेस (इ) से अपने सम्बन्ध तोड़ लिये और एक नये दल का निर्माण किया जिसका नाम सिक्किम संग्राम परिपद रखा। यह दल बाद में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आया। विधान सभा के तीसरे चुनाव में, जो 5 मार्च, 1985 को हुए, सिक्किम संग्राम परिपद को 32 सीटों में से 30 सीटें मिली। दो सीटों में से एक सीट कांग्रेस (इ) को तथा एक स्वतंत्र उम्मीदवार को मिली।

1975-1985 के बीच नीति सम्बन्धी प्रोग्राम

विधान सभा के चुनाव तीन बार हुए और मिश्र शासन काल में हर तरह के बिल व कानून पास किये गये। जो बिल पास हुए उनसे हवाला मिलता है कि मिश्र समय में शासक वर्ग का झुकाव किस ओर था।

पहली बार काजी दोरजी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। दोरजी के शासनकाल में लगभग 26 बड़े-छोटे बिल पास किये गये। [1975-79]

महत्वपूर्ण बिलों का विवरण इस प्रकार है :—

- [1] सिविकम के सेतिहर के लिये सुरक्षा बिल [1975] ।
- [2] भूमि का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग तथा उसके हस्तान्तरण को रोकने के लिए अध्यादेश [1975] ।
- [3] गंगटोक म्यूनीसिपल कोरपोरेशन बिल [1975] ।
- [4] सिविकम नगरीय भूमि संबंधी बिल [1976] ।
- [5] सिविकम पुलिस बिल [1978] ।
- [6] सिविकम खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड बिल [1978] ।
- [7] सिविकम बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन बिल [1978] ।
- [8] सिविकम सिनेमा बिल [1978] ।
- [9] सिविकम कोपरेटिव सोसायटीज बिल [1978] ।

उक्त पारित बिलों को देखकर यह संकेत मिलता है कि अधिकांश बिल कृषि के उत्थान तथा किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए थे । 9 मुख्य बिलों में से 5 ऐसे बिल हैं जो सेतिहर की भलाई के लिए बनाये गये और दो गाँव के विकास के लिये । बिलों को गौर से देखने के बाद लगता है कि बिलों का उद्देश्य प्राचीन सामाजिक ढाँचे को झकझोरने का है जोकि राजतंत्र व्यवस्था में अच्छी तरह चल रहा था । कुल मिलाकर सभी बिल नीचे और निर्धन लोगों का भला करने वाले थे ।

जब दूसरी विधान सभा के सदस्य चुनकर आये तो प्रशासन का अन्दाज कुछ और ही रहा । अक्टूबर, 1979 व मई, 1984 के बीच 31 बिल पास किये गये । इन पारित बिलों में से 14 वे बिल थे जो सशोधित बिल कहे जा सकते हैं । सबसे प्रमुख सशोधित बिल नई पंचायत व्यवस्था के बारे में है । 1965 के पंचायत एक्ट को सशोधित इस बिल ने किया । इसीलिये इससे प्रमुख माना गया ।

यदि हम दो विधान सभाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो यह जानकारी मिलती है कि दोनों सरकार की पद्धति व शैली में भिन्नता थी । पहली विधान सभा के द्वारा पारित बिलों को देखकर यह लगता है कि सरकार की नीति का झुकाव ग्रामीण लोगों की तरफ था और उनके कल्याण के लिये कई बिल पास किये । लेकिन दूसरी सरकार का झुकाव शहरी पर्यावरण को और भी विकास की ओर बढ़ाना था । पहली सरकार ने भूमि सुधार पर अधिक ध्यान दिया लेकिन दूसरी ने इस ओर उपेक्षा की । कहने का अभिप्राय है कि दोनों सरकार के द्वारा पारित बिलों में काफी भिन्नता थी ।

दूसरी सरकार को अधिक श्रेय इसलिये दिया गया कि इसके सानिध्य में सिविक पंचायत बिल पास किया गया जो एक भारी उपलब्धि थी। इस बिल के पारित हो जाने के बाद प्रयास किया गया कि इसको व्यावहारिक रूप दिया जाये। गांवों के स्तर पर पंचायती संस्थाओं का गठन हुआ जिससे कि गांवों में तरीके से विकास हो और वे प्रगति करें।

प्रस्तुत लेख को पूरा न्याय देने के लिये यह आवश्यक है कि प्रान्त के राजनीतिक प्रशासकों का सामाजिक-आर्थिक दर्जा व पृष्ठभूमि जान ली जाय। ऐसा करने से उनके द्वारा निर्धारित नीतियों तथा उनके संस्कार के बारे में तालमेल बिठाया जा सकता है।

उम्र—राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिमान को निर्धारित करने के लिये यह जरूरी है कि निर्णयकर्ता किस उम्र स्तर के हैं। इससे यह भी मालूम हो जाता है कि पुरानी पीढ़ी के सामने नई पीढ़ी का क्या रुख है और क्या वे चुनौती के रूप में उभर रहे हैं या सहयोगी के रूप में। तीन विधान सभाओं के विधायकों की उम्र का विश्लेषण निम्न तालिका से स्पष्ट है—

तालिका-3

विधायकों की उम्र

राज्य विधानसभा

	उम्र	1974	1979	1985
युवा	25—35	12[37.5]	14 [47.75]	9 [28.12]
	36—45	9[28.12]	10[31.25]	18[53.12]
मध्यम	46—55	7[21.87]	7[21.87]	4[12.5]
	56—65	2[6.25]	—	7[3.12]
वृद्ध	66—75	1[3.12]	—	—
	75—ऊपर	—	1[3.12]	—
		32[100.0]	32[100.0]	32[100.0]

तालिका सं० 3 से स्पष्ट होता है कि 1974 की विधान सभा के अधिकांश सदस्य (37.5%) 25-35 की उम्र के थे। 1979 की विधान सभा में अधिकार सदस्य 25-35 उम्र के थे। उसकी प्रतिशत बढ़कर 43.75 हो गई तथा 1985 की विधानसभा में इसी उम्र की श्रेणी की संख्या बढ़कर 56% हो गई। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरानी पीढ़ी के सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर कम हो रही है और युवाओं का राजनीति में प्रवेश बढ़ रहा है।

विधायकों की शिक्षा—यद्यपि राजनीतिज्ञों का शिक्षित होना और भी ठीक होता है, यदि गुणात्मक पक्ष को ध्यान में रखा जाय। शिक्षा निसंदेह व्यक्तित्व में निखार लाता है। राजनीति की शैली का स्वरूप भी उसके अनुसार बदल जाता है। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए तीनों विधानसभाओं के शिक्षित विधायकों का क्या प्रतिशत था तथा शिक्षा से राजनीति में किस प्रकार का व्यवहार दिखाई देता है। निम्न तालिका से विधायकों के शिक्षा का स्तर स्पष्ट होता है।

तालिका नं० 4
विधायकों के शिक्षा का स्तर
राज्य विधान सभा

शिक्षा का स्तर	1974	1979	1985
अशिक्षित	4 (12.5)	—	—
प्राथमिक	4 (12.5)	3 (9.37)	—
मिडिल क्लास	7 (21.5)	7 (21.5)	2 (6.25)
मैट्रिक	4 (12.5)	6 (18.75)	8 (25.00)
उच्च माध्यमिक शिक्षा	1 (3.12)	—	5 (15.62)
बी. ए.	9 (28.12)	14 (43.75)	15 (46.85)
एम. ए.	—	1 (3.12)	2 (6.25)
धार्मिक शिक्षा	4 (9.37)	1 (3.12)	—
कुल	32 (100.0)	32 (100.0)	32 (100.0)

उक्त तालिका से विधायकों की शिक्षा के बारे में जानकारी स्पष्ट होती है। पर्वतीय राजनीति में प्रवेश करने वालों की प्रतिशत अधिकतर शिक्षित होने का संकेत मिलता है। 1974, 1979 तथा 1985 में अधिकतर विधायक प्रोजेक्ट थे तथा सरकार का गठन भी उन्हीं शिक्षितों में से ही हुआ था। जहाँ तक धार्मिक-शिक्षा प्राप्त विधायकों का प्रतिशत गिरता गया, तीसरी विधानसभा में एक भी सदस्य स्थान नहीं पा सका।

जातीयता :—सिक्किम की राजनीति में जातीयता का प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है। आज भी यह मुद्दा अधिक विवादास्पद है। चोगियाल के शासन काल में भूरिया, तथा लंटचा तथा नेपालियों का प्रतिनिधित्व का अनुपात 50 : 50 था जो

कि "परिटी फार्मूला" के नाम से जाना जाता था। 1973 के विद्रोह की प्रमुख मांग यही थी कि इस प्रकार के फार्मूला को रद्द कर दिया जाय। 1974 के चुनाव में तो उक्त फार्मूला का अन्त नहीं हो सका लेकिन 1979 के चुनाव में कुछ संशोधन हुआ। दूसरे चुनाव में 12 सीटें भूरिया लैंटवाओं के लिये रखीं, दो सीटें अनुसूचित जाति के लिये, 1 सीट मठों के लिये तथा 17 सीटों पर खुला चुनाव घोषित किया गया। व्यवहार में एक सीट भूरिया-लैंटवा को जाती थी तथा 2 अनुसूचित सीटें नेपालियों को दे दी जाती थी। निम्न तालिका से जातीय प्रतिनिधित्व की तस्वीर स्पष्ट होती है :—

तालिका नं० 5

विधानसभा

विभिन्न जातियाँ	1974	1979	1985
लैंटवा	9 (28.12)	4 (12.5)	3 (9.37)
भूरिया (मठ भी सम्मिलित है।)	7 (21.87)	9 (28.12)	10 (31.25)
नेपाली (अनुसूचित जाति)	16 (15.00)	19 (17 + 2) (59.37)	18 (16 + 2) (56.25)
मारवाड़ी	—	—	1 (3.12)
कुल	32	32	32

आर्थिक पक्ष—राजनीति में प्रवेश के लिये किसी भी व्यक्ति का आर्थिक पक्ष कैसा है और राजनीति की अनिश्चितता को देखते हुए किसी में आर्थिक भार को वहन करने की कितनी ताकत है। इसको भी मालूम करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी राजनीतिज्ञ का आर्थिक पक्ष ही निश्चित करता है कि उसमें राजनीति के उतार-चढ़ाव की स्थिति के सामना करने की कितनी ताकत है। दी गई तालिका नं० 6 में विधायकों के आर्थिक स्रोत के बारे में तस्वीर स्पष्ट करती है कि राजनीति में हर तपके के व्यक्ति प्रवेश करते हैं। लेकिन राजनीति में लम्बे समय तक वे ही रह पाते हैं जिनकी

जनता के सामने आ नहीं सके जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तो भंडारी ने खुले आम राज्यपाल की गतिविधियों पर आपत्ति करना शुरू किया। भंडारी ने खुले आम राज्यपाल पर आरोप लगाया व उसके प्रशासन में ऐसा करने से मुख्यमंत्री भंडारी व्यक्तिगत दृष्टि से परेशान होने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि राज्यपाल का जनता से व्यक्तिगत संपर्क उनकी लोकप्रियता में कमी लायेगा। भंडारी के अतिरिक्त अन्य राजनेता भी राज्यपाल की गतिविधियों से अप्रसन्न थे। वरिष्ठ कांग्रेस (इ) के नेता सी. डी. राय तथा सिक्किम प्रजासन्न कांग्रेस के नेता एन. बी. काठीवाडा दोनों ने ही संपुक्त बयान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "राज्यपाल तेलियारखा की भूमिका पद की गरिमा से प्रतिकूल है। राज्यपाल ने जनता को आश्वस्त किया है कि वे गरीब जनता के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खुलवायेंगे, जबकि सरकार का आर्थिक बजट इन वायदों को पूरा करने में सक्षम नहीं है" साथ में यदि आर्थिक सीमाओं के कारण राज्यपाल द्वारा किये हुए वायदे पूरे नहीं हुए तो भंडारी को सरकार अपनी लोकप्रियता खो देगी जिसका सीधा प्रभाव उनके चुनावों पर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच मतभेद का मुद्दा एक और जुड़ गया वह था "हैलीकोप्टर की सेवा" से संबंधित। बागडोगरा (जो कि पश्चिमी बंगाल में है) से गंगटोक तक पहुँचने के लिये राज्यपाल ने अथक प्रयासों से इंडियन एयरलाइन्स की हवाई सेवा प्रारम्भ की गई। परन्तु यह सेवा एक साल के बाद स्थगित करनी पड़ी क्योंकि राज्य सरकार ने खर्च के सहभागी के रूप में 16 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था। भंडारी ने राज्यपाल को दोषी ठहराते हुए कहा कि तेलियारखा ने राज्य को इतने भारी कर्ज में दबा दिया है और अपने बयान में कहा "मैं प्रारम्भ से ही हैलीकोप्टर की सेवा के विरुद्ध था लेकिन मैंने इसका इसलिये कड़े रूप से विरोध नहीं किया, यह अनुमान लगाते हुए कि उक्त हवाई सेवा एक उपहार के रूप में प्रदान की गई जिसके साथ कोई आर्थिक दायित्व जुड़ा हुआ नहीं है। अब मेरे सामने एक भारी बिल रख दिया गया है जिसकी कुछ मुझे उम्मीद भी नहीं थी और न सरकार इसको वहन कर सकती है" भंडारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब हवाई सेवा प्रारम्भ की गई थी, उससे पूर्व इस प्रकार की कोई शर्त भी नहीं रखी गई थी जिस पर वे कुछ विचार कर पाते। इसके उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि जब हवाई सेवा शुरू हुई थी तो भंडारी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी तालियों के साथ स्वागत

आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यद्यपि तीन विधानसभा के चुनाव ने उक्त कथन को सही साबित नहीं किया है क्योंकि विधायकों का बहुमत उन लोगों का बढ़ गया जो पहले सरकारी नौकरी करते थे और उसको छोड़कर चुनाव में फंद पड़े। 1985 के चुनाव में 32 सीटों में से 16 सीटें उन्होंने प्राप्त कीं जो सरकारी नौकरी छोड़कर आये थे और दूसरा नंबर व्यापारी वर्ग तथा कृषि का आता है। अतः अभी तक सिक्किम की राजनीति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कृषि व व्यापार करने वाले राजनीतिज्ञ क्यों पिछड़े हुए हैं।

तालिका नं० 6

विधायकों का व्यवसाय

विधान सभा

व्यवसाय	1974	1979	1985
कृषि	13 (40.62)	10 (31.25)	11 (25%)
व्यापार	4 (12.5)	8 (25.00)	7 (21.87)
नौकरी	8 (25.00)	7 (21.87)	16 (50.00)
राजनीति व कृषि	6 (18.75)	6 (18.75)	1 (3.12)
घरेलू-मठ	1 (3.12)	1 (3.12)	1 (3.12)
कुल	32	32	32

सितम्बर, 1983 के महीने में कांग्रेस (इ) की वरिष्ठ नेता राजकुमारी बाजपेयी ने दोनों के बीच उत्पन्न विवाद को शान्त करने के लिये मध्यस्थता का प्रयास किया। बच्चों की तरह से राजकुमारी बाजपेयी की उपस्थिति में दोनों में हाथ मिलाया गया तथा विवाद को समाप्त करने का दिखावा किया गया।

दोनों के बीच मतभेद सभी से शुरू हो गये जिस दिन से कि राज्यपाल सिक्किम आये और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के प्रयास में प्रान्त के हर स्थान पर दौरे लगाने शुरू किये। मुख्यमंत्री भंडारी को इस प्रकार की गतिविधियाँ अच्छी नहीं लगी। एक ओर राज्यपाल के रूप में प्रान्त में नहीं रहना चाहते थे और दूसरी ओर मुख्यमंत्री चाहते थे कि राज्यपाल अपने पद की गरिमा व शालीनता का उत्खनन नहीं करें। प्रारम्भ के मतभेद तो

जनता के सामने आ नहीं सके जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तो भंडारी ने खुले आम राज्यपाल की गतिविधियों पर आपत्ति करना शुरू किया। भंडारी ने खुले आम राज्यपाल पर आरोप लगाया व उसके प्रशासन में ऐसा करने से मुख्यमंत्री भंडारी व्यक्तिगत दृष्टि से परेशान होने लगे। उन्हें यह लगने लगा कि राज्यपाल का जनता से व्यक्तिगत संपर्क उनकी लोकप्रियता में कमी लायेगा। भंडारी के अतिरिक्त अन्य राजनेता भी राज्यपाल की गतिविधियों से अप्रसन्न थे। धरिष्ठ कांग्रेस (इ) के नेता सी. डी. राय तथा सिक्किम प्रजातन्त्र कांग्रेस के नेता एन. बी. काठीवाडा दोनों ने ही संयुक्त बयान में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "राज्यपाल तेलियारखा की भूमिका पद की गरिमा से प्रतिकूल है। राज्यपाल ने जनता को आश्वस्त किया है कि वे गरीब जनता के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य केन्द्र खुलवायेंगे, जबकि सरकार का आर्थिक बजट इन बायदों को पूरा करने में सक्षम नहीं है" साथ में यदि आर्थिक सीमाओं के कारण राज्यपाल द्वारा किये हुए बायदे पूरे नहीं हुए तो भंडारी की सरकार अपनी लोकप्रियता खो देगी जिसका सीधा प्रभाव उनके चुनावों पर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के बीच मतभेद का मुद्दा एक और जुड़ गया वह था "हैलीकोप्टर की सेवा" से संबंधित। बागडोगरा (जो कि पश्चिमी बंगाल में है) से गंगटोक तक पहुँचने के लिये राज्यपाल के अथक प्रयासों से इंडियन एयरलाइन्स की हवाई सेवा प्रारम्भ की गई। परन्तु यह सेवा एक साल के बाद स्थगित करनी पड़ी क्योंकि राज्य सरकार ने खर्च के सहभागी के रूप में 16 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था। भंडारी ने राज्यपाल को दोपी ठहराते हुए कहा कि तेलियारखा ने राज्य को इतने भारी कर्ज में दबा दिया है और अपने बयान में कहा "मैं प्रारम्भ से ही हैलीकोप्टर की सेवा के विरुद्ध था लेकिन मैंने इसका इसलिये कड़े रूप से विरोध नहीं किया, यह अनुमान लगाते हुए कि उक्त हवाई सेवा एक उपहार के रूप में प्रदान की गई जिसके साथ कोई आर्थिक दायित्व जुड़ा हुआ नहीं है। अब मेरे सामने एक भारी बिल रख दिया गया है जिसकी कुछ मुझे उम्मीद भी नहीं थी और न सरकार इसको वहन कर सकती है" भंडारी ने अपने बयान में यह भी कहा कि जब हवाई सेवा प्रारम्भ की गई थी, उससे पूर्व इस प्रकार की कोई शर्त भी नहीं रखी गई थी जिस पर वे कुछ विचार कर पाते। इसके उत्तर में राज्यपाल ने कहा कि जब हवाई सेवा शुरू हुई थी तो भंडारी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी तालियों के साथ स्वागत

किया था। राज्यपाल ने यह भी कहा कि उनका हवाई सेवा प्रारम्भ कराने में केवल यह उद्देश्य था कि तीन घंटे की यात्रा का समय घटकर मात्र 20 मिनट रह गया था।

राज्यपाल तैलियारया उन अल्पसंख्यकों के भी समर्थक हो गये थे जिनको भंडारी सरकार अपने प्रान्त में कोई स्थान देने को तैयार नहीं थे। भंडारी सरकार ने यह लगभग तय कर लिया था कि 60,000 मैदानी लोगों को किसी न किसी पद्धति से प्रशासन से ही बाहर नहीं अपितु प्रान्त से भी बाहर कर देना है। यह मुद्दा भी दोनों के बीच मतभेद का कारण बन गया।

उक्त मतभेदों के कारण भंडारी को सरकार से बाहर निकाल दिया गया और कुछ दिन बाद ही राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ।

सिविकम में 5 मार्च, 1985 को 32 सदस्यीय विधानसभा के लिये चुनाव हुए। चुनाव के दौरान राजनीतिक घटना-चक्र बढ़ी गर्मी गर्मी में शुरू हुए।

चुनावी दौड़

भूतपूर्व सिविकम विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री साल बहादुर बासनेन (जो एक बुद्धिजीवी भी हैं) ने अपने प्रेस इन्टरव्यू में कहा कि, "यह चुनाव मुख्य रूप से कांग्रेस दल तथा सिविकम संग्राम परिपद के बीच में है जिनको नागनाथ तथा सांपनाथ की संज्ञा दी जा सकती है।"

श्री बासनेन की उक्त अभिव्यक्ति यथार्थ से कतई हटकर नहीं है। एक जीसतन मतदाता के समक्ष यह प्रश्न नहीं था कि कोई दल सत्ता में आने के बाद भूतभूत परिवर्तन ला पायेगा। मतदाता यह भी जानते थे कि राजनेता केवल बापदों के अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिविकम का राजनेता अन्य राजनेताओं की तरह आर्थिक पक्ष का तो जिक्र कभी करते ही नहीं। चुनाव में केवल एक ही मुद्दा था कि क्या नर-बहादुर भंडारी पुनः प्रान्त के मुख्यमन्त्री बनेंगे, जिन्होंने सिविकम संग्राम परिपद से जीतकर लोकसभा की सीट अर्जित की? इसी के साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि यदि भंडारी सत्ता में आते हैं तो क्या पुनः कांग्रेस में शामिल होंगे तथा सिविकम संग्राम परिपद को भंग कर देंगे।

दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु इसके ठोस आधार भी थे। जब से सिविकम भारत का 22वां राज्य हुआ है। तभी राजनेताओं का राजनीतिक व्यवहार अत्यधिक विचित्र रहा है। सिविकम के दलों की स्थिति का तालमेल

केन्द्र में सत्ता दल के साथ रहा है। 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी सत्ता में आई तो काजी लंडप दोरजी (जो उस समय मुख्यमंत्री थे) ने कांग्रेस का नाम बदल कर जनता पार्टी कर दिया। 1979 में श्रीमती इन्दिरा गांधी पुनः सत्ता में आई तो सिक्किम जनता परिषद दल के मुख्यमंत्री नरबहादुर भंडारी ने भी रातोंरात अपने दल को बदल कर कांग्रेस कर दिया। दिसम्बर, 1984 के लोकसभा के चुनाव में नर बहादुर भंडारी ने सिक्किम संग्राम परिषद दल चुनाव जीता और लोकसभा के सदस्य बन गये। परन्तु उनकी वास्तविक ललक सिक्किम का पुनः मुख्यमंत्री बनना था। इसी अभिलाषा को लेकर 5 मार्च, 1985 के चुनाव में फिर से आ गये हैं और उन्होंने अपने बयान में किसी को भी भ्रम में न रखते हुए कहा कि, "मैं कांग्रेस में फिर से आने के लिये नहीं हिचकूंगा। यदि मेरी मांगें केन्द्र स्वीकार कर लेता है" भंडारी ने यह स्पष्ट किया कि उनका अन्य विरोधी दलों से गठबन्धन करने का कोई इरादा नहीं है।

भंडारी की मांग— अपने मुख्यमंत्री पद के दौरान भंडारीजी ने सिक्किम के जोरबांग स्थान पर अपने भाषण में न केवल अपनी मांगों को दुहराया था अपितु केन्द्र सरकार की खुले आम आलोचना करते हुए कहा था कि केन्द्र की उनकी मांगों के प्रति उदासीनता न केवल असाध्य हो गई है बल्कि उनकी कुछ कड़े कदम उठाने के लिये मजबूर कर दिया है। भंडारी जी की मांग उन नेपालियों की नागरिकता के लिये है जिन्हें अभी संविधानिक रूप में नागरिकता नहीं मिली है। यह समस्या उन 75 प्रतिशत नेपालियों की है जिनको चोगियाल के शासन में वे सभी अधिकार प्राप्त थे परन्तु जनता पार्टी के शासन काल में अधिकार छीन लिये गये जिसके कारण मुख्यमंत्री काजी लंडप दोरजी के दल का ही पूरा सफाया नहीं हुआ बल्कि वे स्वयं भी सिक्किम विधान सभा की सीट के लिये पराजित हुए। 5 मार्च, 1985 को विधान सभा के चुनावी अभियान में उन नेपालियों को पूरी तरह जानकारी है कि भंडारी को पद से केन्द्र ने इसलिये हटाया था क्योंकि उन्होंने नेपालियों के अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी।

राज्यपाल की सिफारिश

पूर्व राज्यपाल श्री तेलियारखा ने भंडारी को हटाने में पूरा सहयोग दिया था, जो कि आम राय की दृष्टि से असंविधानिक था, इसलिये तुरन्त तेलियार खा को आन्ध्रप्रदेश की तरह से अपने पद से स्वीका देना पड़ गया था और नये राज्यपाल श्री कौना प्रभाकर राव ने शपथ ग्रहण की। हाल की

सूचना के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि श्री राव ने केन्द्र से सिफारिश की है कि भंडारी की मांगों को स्वीकार कर लिया जाय ।

यद्यपि उक्त सिफारिश का भविष्य से अधिक सम्बन्ध है । अभी तो भंडारी जी अपने चुनावी अभियान में बार-बार नेपासियों की नागरिकता का प्रश्न को दुहरा रहे हैं और समस्या का पूरा-पूरा लाभ लेना चाहते हैं । यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि यदि भंडारी जी अपने दल को बहुमत में लाने में सफल हो जाते हैं तथा साथ में केन्द्र भी उनकी मांगों को स्वीकार कर लेता है तो वे कांग्रेस में शामिल हो जायेंगे तथा दल-बदल विरोधी विधेयक भी उनके रास्ते में व्यवधान नहीं बनेगा ।

कांग्रेस पार्टी का रुख

इस समय कांग्रेस पार्टी का भी रुख भंडारी की मांगों के प्रति नज़र होता दिखाई देता है । कांग्रेस दल के एक उम्मीदवार जो गैंगटोक से लड़ रहे हैं । श्री मदनलाल जी का कहना है कि "सिक्किम राजनीति में ऐसा ही होता रहा है । हमने प्रान्तीय स्तर पर कांग्रेस दल को इसलिये बढ़ाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि अभी तक किसी भी दल का जो मुख्यमंत्री बना है वह समूचे रूप में कांग्रेस में शामिल होता रहा है । इसलिये मतदाताओं के लिए सिक्किम के राजनेता नागनाथ व सांपनाथ की कहावत को सच्चे रूप में चरितार्थ करते हैं ।

कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची

सिक्किम विधान सभा के लिये लड़ने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों की सूची देखने से हवाला मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ने किन-किन समूहों के लोगों को शामिल किया है । उदाहरण के लिये पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने शासन काल में जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया था—कांग्रेस दल से लड़ रहे हैं । इसी प्रकार रामचन्द्र पौदियाल जो सिक्किम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) के नेता थे वे भी कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं । सी०डी० राय भी कांग्रेस की ओर से चुनाव अभियान में हैं जो कुछ दिन पहले तक "हिमाली कांग्रेस संस्था" के नेता थे । जहाँ तक नर बहादुर भंडारी का सम्बन्ध है उनके सामने कांग्रेस में शामिल होने से पहिले एक ही रुकावट है वह है उनके खिलाफ सी०बी०आई० के द्वारा जांच । लेकिन भंडारी यदि पुनः राज्यीय सत्ता में आते हैं तो केन्द्र भी उनके प्रति नरमाई का व्यवहार दिखायेगा तथा सी०बी०आई० की जांच को वापस ले सकता है । इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिये कि अभी भंडारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने बाकी हैं, कांग्रेस दल ने आर०सी० पौदियाल को अपने दल में मिला लिया है तथा एक क्षेत्र का

इन्वांज भी बना दिया है, जबकि पोदियाल ने सुप्रीम कोर्ट में भूटिपा सीचाओ के लिए रिजर्वेशन सीटों के लिये याचिका दर्ज कर रखी है।

सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर ही कार्यकर्ताओं में असंतोष है कि पोदियाल को कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिये था। बी०वी० गुरुग, जो भंडारी के बाद 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, भी इससे घुस नहीं हैं। वेने रामचन्द्र पोदियाल नेपासी लोगो मे इतने लोकप्रिय नहीं हैं जितने काजी लंडप दोरजी तथा भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री मोमनाथ जैरिंग।

सिक्किम कांग्रेस पार्टी में आन्तरिक असंतोष इसलिये भी है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है उनकी सूची केन्द्र द्वारा घोषी हुई लगती है। उदाहरण के लिये मदन क्षेत्री जो अब तक एस० पी० थे, उन्होंने 24 घंटे के अन्दर अपने पद से स्तीफा देकर अपने चुनाव अभियान में लग गये। कांग्रेस दल के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को आश्चर्य हुआ जब मदन क्षेत्री का नाम विधान सभा की सीट के लिए सूची में देया गया। मदन क्षेत्री के पिताफ मुकुन्दमंथरी रहे नर बहादुर भंडारी की पत्नी श्रीमती बिल कुमारी भंडारी हैं। इसी क्षेत्र से एक विद्रोही कांग्रेस कार्यकर्ता बालचन्द्र सारदा भी निर्दलीय खड़े हुए हैं जो एक घतरा पैदा कर सकते हैं।

औद्योगिक कम्पनियों का सिक्किम से विदा

सिक्किम में ज्यों ही आवकारी कानून लागू होना शुरू हुआ, उसके आठ महिने बाद ही औद्योगिक कम्पनियों के गैर कानूनी गतिविधियों का भंडाफोड़ सामने दिखाई देने लगा। न केवल वे कल-कारखाने बंद होने लगे जिनके प्रारम्भ होने के साथ ही अनाप-शनाप लाभ अर्जित कर रहे थे अपितु वे भी अपने कारखाने बंद करते हुए पाये गये जो वषों से गैंगटोरु में गलत तरीके से घनाढ्य हो गये थे। सिक्किम मे तीन प्रमुख स्थान है जहाँ औद्योगिक कारखाने स्थित थे, वह हैं-सिमतांग, रायपो तथा गैंगटोक। टैक्स लाम के बिना, सिक्किम औद्योगिक व्यापारियों के लिये स्वर्ग नहीं है।

फरवरी, 1983 तक सिक्किम मे उन कम्पनियो की भीड़ सी लग गई जब तक वहाँ आवकारी तथा नमक कर अधिनियम लागू नहीं हुआ था। विशेष रूप से उन कम्पनियो का ताता-सा बंध गया जो अपनी कम्पनियो को ऊँचे कर क्षेत्रो मे चला रहे थे। सिक्किम में सिर्फ दो साल के अन्दर आठ सिगरेट फैक्टरियों की स्थापना हुई और उसी के साथ 2 करोड़ रुपये का टैक्स वचाने लगे। यह वचत 400 मिलियन सिगरेट के उत्पादन से होती है। कई शराब कारखाने भी स्थापित हो गये। इसके अतिरिक्त जिन कारखानो की

स्थापना हुई वे थे, रेफरीजिरेटर्स, एयरकंडीशनर्स, वनस्पति, गैस भरने के यंत्र, टूथपेस्ट, बैटरीज, स्टूपवस, दियासलाई तथा फलों के रस आदि।

ज्यों ही केन्द्रीय आवकारी कम प्रभावशाली होने लगा, तुरन्त ही सिगरेट की आठ फैक्ट्रियों में से 7 फैक्ट्री मालिकों ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं तथा जो कम्पनी वर्तमान में काम कर रही हैं वे केवल प्रान्तीय सरकार के अधीन हैं। उदाहरण के लिये हिन्दुरतान मशीन टूल्स वाच कम्पनी तथा इण्डिया कौसमेटिक (पौड) फैक्ट्री। शराब कारखाने इसलिये भी मौजूद हैं क्योंकि यह कारखाने केन्द्र आवकारी के अधीन नहीं आते। शराब पर कर का विषय प्रान्तीय सरकार के अधीन होता है।

इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 3000 कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा परन्तु सबसे ज्यादा नुकसान स्थायीय राजनेताओं तथा नौकरशाही को हुआ है जिनको कम्पनियों के मालिकों से गैर कानूनी लाभ लगातार मिल रहा था। इस आसान लाभ से वंचित होते हुए देश राजनेताओं का विरोध आवकारी कर के प्रति शुरू हो गया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि विरोध मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल अर्थात् नरबहादुर भंडारी हौमी जे. एच सेलियार खाँ के बीच शुरू हुआ।

विशेषकर सिगरेट कम्पनियों को, केन्द्रीय आवकारी के लागू होने से पूर्व अत्यधिक लाभ हुआ। राष्ट्रीय तंबाकू के मार्केटिंग मैनेजर राजा स्वामीनाथन का कहना था कि "प्रत्येक एक हजार सिगरेट, जो कम्पनी बनाती थी, पर लगभग 35 रुपये की बचत होती थी, जबकि यातायात का खर्च केवल 8 रुपये है। इस प्रकार 27 रुपये का शुद्ध लाभ आसानी से मिल जाता था।" "स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि पिछले सात महीने में हमने अनुमान से कही ज्यादा लाभ कमाया और इस लाभ की गति को देखते सोचने लगे थे कि हमारी आर्थिक समस्या का सिक्किम का प्रान्त आसानी से पूरा कर देगा।"

जो एक मात्र सिगरेट की कम्पनी सिक्किम में रह गई है वह आई. टी. सी. से सम्बन्धित मद्यपि कम्पनी की ओर से इस तथ्य को नकार दिया गया है। पौड की कम्पनी भी सिक्किम में रह गई है जिसकी भावी योजना है कि व अपना मातृ पूर्वी क्षेत्रों के बाजारों में उपलब्ध करा सकेगी। इसी कम्पनी की ओर से एक बयान में कहा गया था कि हमको पूर्वी भारत के क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता थी जिससे उत्पादित माल तुरन्त ही, कम खर्च पर बड़े बाजारों में जा सके। इसीलिये हमने सिक्किम इस फैक्ट्री को प्रारम्भ करने के लिये चुना जबकि कर माफ पहिले से ही है। अब जबकि

कर की ढील समाप्त हो गई है फिर भी हम अपने शुद्ध लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि यहां से हमारा माल आसानी से बड़े बाजारों में जा सकेगा। अपेक्षाकृत मद्रास से।

केन्द्रीय आवश्यकारी करों के हो जाने से न केवल अन्य औद्योगिक कम्पनियों पर ही प्रभाव हुआ अपितु इसकी आलोचना भी राजनीतिक स्तर पर भी हुई। विरोधी दल के नेता एन. बी. काठीवाड़ा (प्रजासत्तम कांग्रेस के नेता) ने आलोचना करते हुए कहा कि प्रान्तीय सरकार की रैवेन्यू पर गतत प्रभाव पड़ेगा। सिविकम कांग्रेस (क्रान्तिकारी) दल के नेता आर. सी. पोटियाल ने मुख्यमंत्री भंडारी की आलोचना करते हुए कहा कि जब तक सिविकम में केन्द्रीय आवश्यकारी कर लागू नहीं किये गये थे तब तक मुख्यमंत्री तथा कम्पनियों के मालिकों के बीच आर्थिक लाभ की गाजिश रही। दूसरी ओर भंडारी ने राज्यपाल तेलियार खां का पक्ष लेते हुए सार्वजनिक रूप से आवश्यकारी कर का समर्थन किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से राज्यपाल को खुला समर्थन एक दोहरी नीति का सूचक है। यह भी सूचना दूसरी ओर से आई कि राज्यपाल तेलियार खां ने सिविकम सरकार के निर्णय का खुले रूप में जितना समर्थन दिया होगा उतना शायद भंडारी ने भी नहीं दिया। राज्यपाल का कहना था कि 3000 लोगों का बेरोजगार होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। (क्योंकि वे मजदूर डेली वेजेज पर थे) जितना सिविकम सरकार को केन्द्र की भागीदारी पर आर्थिक लाभ होगा।

सच तो यह है कि जितनी भी औद्योगिक कारखाने सिविकम में लगे थे केवल कर से बचने के लिये गये थे। कई सिगरेट फैक्ट्रियां केवल कच्चे माल, वह भी थे। सिविकम कांग्रेस (ई) के जनरल सैक्रेटरी श्री सी. डी. राय ने स्वयं स्वीकार किया कि "मिरे दल के बहुत से नेता, कर के लागू होने से पूर्व, लाइसेंस को बेच-व्रेच कर मनमानी तरीके से लाभ ले रहे थे।"

मुख्यमंत्री भंडारी ने अपने वयान में कहा "कुछ कारखाने निश्चित ही बंद हो गये होंगे परन्तु केन्द्र की भागीदारी के साथ नई व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग प्रान्तीय सरकार को एक करोड़ प्राप्त हो सकेगा जो दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

सिविकम का बाहरी रूप में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। सिवाय लोगों की भीड़ में वृद्धि के अलावा। गैंगटाक में शून्य की स्थिति दिखाई देती है। जिस राजधानी पर चोगियाल शासन करता था उसने नीकरशाही के

बावजूद बायू लोग चुने हुए प्रतिनिधि तथा केन्द्र के अधिकारी वर्ग के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सामने है वह है नर बहादुर भंडारी का नेतृत्व जिसने सिक्किम के विलय का कड़ाई से विरोध किया था। दूसरी ओर काजी लेंडप दोरजी जो 1974 में पहले मुख्यमन्त्री बने थे। आज चुनाव में दो बार हारने के पश्चात राजनीति से लगभग सन्यस्त हो चुके हैं और आराम कर रहे हैं।

सिक्किम के अन्य मुख्य नेताओं ने भी वर्तमान परिस्थिति से समझौता सा कर लिया है। जैसे विलय के पदाधर नेता पी. बी. गुरंग जिन्होंने हाल ही में 13 दिन की मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, वे भी आज राजनीति के दावपेच में शिथिल हुए लगते हैं। रामचंद्र बोदियान भी उन नेताओं में से थे जिन्होंने विलय का पूर्ण समर्थन किया था। आज राजनीति में अकेले से लगते हैं। जहाँ तक 12 वें नवयुवक कॉलेज की बात है वे अपने महल में एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए लगते हैं। यह शाही भवन जहाँ हंगेशा कर्मचारियों व अधिकारी वर्ग की भीड़ लगी रहती थी वह भी वीरान हो गया है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी शेष है कि कुछ लोगों ने सिक्किम के विलय को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। नर बहादुर को दूसरी बार चुनाव में शानदार विजय तथा मुख्यमंत्री पद पर आ जाने से यह सिद्ध सा होता जा रहा है कि विलय के विरोध का समूह सिक्किम में घट रहा है। नर बहादुर की पार्टी सिक्किम सन्ग्राम परिषद ने विधान सभा की 30 सीटों में से 30 सीट जीती है जिससे हवाला मिलता है कि नर बहादुर भंडारी का नेतृत्व विलय के विरोधी लोगों को एक बार फिर से इकट्ठा करेगा तथा नई देहली के लिये सरदर्द बन सकता है।

नौकरशाही का वह तपका जो भूरिया है वे, मुख्यमंत्री भंडारी के दखल नीतियों को समझते हुए महसूस करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब नेपाली लोग उनको आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र से उपेक्षित कर देंगे और वे सभी सुविधाओं से वंचित कर दिये जायेंगे। सिक्किम प्रान्त की जनसंख्या भी तीव्र-गति से बढ़ती जा रही है। 1971 में सिक्किम की जनसंख्या 1.62 लाख थी और 1981 में बढ़कर 3.16 लाख हो गई। स्थानीय समाचार-पत्र के संपादक ने अधिकृत सूचना के आधार पर यह कहा है कि 1979 और 1984 के बीच में नेपालियों की संख्या में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि भूटिया लोगों में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सिबिरुम का सामाजिक तत्व एक चीज से और भी विन्न व नाराज है। स्वतन्त्र व मूल निवासी मंदानी लोग विरोधकर मारवाड़ियों से अधिक नाराज हैं जिन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में एक छत्र अधिकार कर रखा है। मारवाड़ियों का व्यापार कलकत्ता, कानपुर व सयनऊ तक फैला हुआ है जिसके कारण सिबिरुम के लोग अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त करने में वंचित रहे हैं।

परन्तु ठीक इसके विपरीत एकमात्र मंदानी विधायक बालचन्द्र सरदा, जो गैंगटोक से चुनकर आया है। उसका कहना है कि व्यापारी लोग किसी प्रकार में स्वतन्त्र व्यवसायियों को भोगण नहीं कर रहे हैं। उसका यह दृढ़ मत है कि मारवाड़ियों का एक छोटा-सा टुकड़ा जो 70 वर्ष पहले यहाँ आकर बसा, उसने ही बाजार में अपनी छाप बना रखी है जिससे सरकार आसानी से अधिकार को समाप्त कर सकती है। इसमें नवी मंदानी लोग तथा मारवाड़ी शामिल नहीं है। सिबिरुम के पश्चिमी जिले के कंसुटर टी. एन. वरफुंगा का यह मानना है कि थोड़े से ही मारवाड़ी व्यापारियों ने बाजार पर अधिकार कर रखा है अतः 1982 से सरकार ने ऐसे उपाय अवश्य किये हैं जिससे आधिपत्य में कमी आये। इस दिशा में सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है लेकिन यहाँ में चला आ रहा क्रम धीरे-धीरे ही कम होगा। □□

संदर्भ सूची

1. डॉ इण्डियन नेशन (पटना)
2. सिबिरुम एक्सप्रेस (गैंगटोक)
3. हिमालयन प्रोब्लेम्स (कलकत्ता)
4. सिबिरुम टाइम्स (गैंगटोक)
5. डॉ नेशन (गैंगटोक)
6. डॉ टुय (साप्ताहिक-गैंगटोक)

भूटान-अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से

भारत-चीन युद्ध के बाद से भूटान नरेश तथा अन्य सहयोगियों की एक तन्मय अवस्था आश्वस्त कर गया कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एकांगी नीति व अन्य राष्ट्रों से अलग-थलग रहने का इरादा यथार्थ से दूर हटकर है। स्वयं की बाहरी वातावरण में सम्पर्क को गुरु करना एक आवश्यक बुराई है जिसको अधिक दिन तक टाला नहीं जा सकता। 1958 में पं. नेहरू की भूटान यात्रा तथा उनसे वार्तानाप करने के पश्चात् यह बात अवश्य समझ आई कि यदि अपने राष्ट्र को जीवन तथा प्रगति प्रदान करना है तो बाहरी राष्ट्रों से सम्पर्क बढ़ाना आवश्यक है। अपने राष्ट्र की सदियों पुरानी संस्कृति व परम्पराओं के नष्ट होने के भय से अपने देश को इतने वर्षों अलग-थलग रहने में अधिक समझदारी नहीं है—यह बात प्रशासकों के पूरी तरह से गले से उतर गई थी। गकट या मुश्किल यही थी कि वह मंसी या पद्धति किस प्रकार की हो जिससे दोनों ही इच्छाओं की पूर्ति हो। इस प्रकार भूटान की राजतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रयास के दौर प्रारम्भ हुए। 1961 में देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारम्भ हुआ। भूटान-कोंबो योजना का भी सदस्य बना तथा 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री से संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य बनने के लिये आग्रह किया और अन्त में 1971 में भूटान पहली बार एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य बना जिसका सभी देशों ने स्वागत किया। इस प्रकार भूटान की अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर स्वयं की भूमिका अदा करने का एक अच्छा अवसर मिला। भूमिका अदा करने का नया उत्साह तथा हर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ कहना एक स्वाभाविक लक्षण होता है और भूटान कोई अपवाद नहीं है। परन्तु हर कदम पर फूंक-फूंक कर चलने की पद्धति भूटान की बाह्य नीति में प्रतिपल झलक देती रही।

भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में

28 सित., 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 27वें अधिवेशन में भूटान के प्रतिनिधि ने पहली बार अपने भाषण में 'तनाव रहित्व' का स्वागत किया और आगे कहा कि, "विश्व की दो महाशक्तियों के पारस्परिक सूझ-बूझ तथा सकारात्मक दृष्टिकोण से यह पूर्णरूपेण उम्मीद बनी है कि विश्व में वास्तविक शान्ति अवश्य स्थापित हो सकेगी।" इसी प्रकार उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करते समय भूटान के प्रतिनिधि ने कहा कि, "उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के बीच वार्ता का प्रारम्भ होना एक महत्व-

पूर्ण घटक है और वार्ता के माध्यम से तनावों में कमी आयेगी और समस्या के समाधान होने की संभावना बढ गई है ।” भूटान के प्रतिनिधि ने उपनिवेशवाद तथा रंग-भेद की नीति को प्रारम्भ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में आलोचना की है । संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में अक्टूबर, 1973 को भूटान के प्रतिनिधि ने कहा, “एक महत्वपूर्ण समस्या जो मेरे देश के लिए चिन्ता का विषय है तथा विश्व शान्ति के लिए खतरा है, वह दक्षिणी अफ्रीका की समस्या है जहाँ मुट्ठीभर भोरे लोग बहुसंख्यक काली चमड़ी की जनता पर अन्याय व अत्याचार की नीति वपों से अपनाये हुए हैं । नामबिया की जनता को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना सरासर अन्याय है । दक्षिण रोडेसिया में अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक जनता पर शक्ति के बल पर शासन कर रहे हैं । यह खेद का ही विषय है कि गैर कानूनी शक्ति रोडेसिया में शासन कर रही है । भूटान के प्रतिनिधि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “हमारा विश्वास है कि समस्त देश जो शान्ति, प्रेम की भावना पर विश्वास करते हैं तथा स्वतन्त्रता, समानता व मानवीय गरिमा के सिद्धान्तों के समर्थक राष्ट्र रोडेसिया में हो रहे अन्याय पर कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाने की पुष्टि करेंगे । पुर्तगाली सरकार की दमन नीति शान्ति व सुरक्षा के लिए एक खतरा है । उसका उपचार व विकल्प ढूँढना अति आवश्यक है । भूटान स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष का समर्थन करता है । भूटान ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अन्याय व अत्याचार के बारे में व्यक्त किये हैं । उक्त समस्याओं के समाधान के लिए एक समग्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता होगी और वे प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से ही सम्भव है । भूटान उन देशों के साथ है जो यह चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में हो रहे रंग-भेद व शोषण की नीति को न केवल वैचारिक स्तर पर ही आलोचना हो बल्कि एक प्रभावशाली तथा व्यावहारिक हल ढूँढ निकालने में सक्षम हैं । 8 अक्टूबर, 1976 की साधारण सभा के अधिवेशन में भूटान के प्रतिनिधि ने दक्षिण अफ्रीका की समस्या के बारे में चिन्ता को दुहराया और कहा, “संयुक्त राष्ट्रसंघ की समस्त शक्ति एक ऐसे हल निकालने में लगा दे जिससे कोई देश उन बुराइयों से पीड़ित न हो जो इस समय व्याप्त हैं । अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा, “यदि दक्षिण अफ्रीका में शक्ति तथा स्थायित्व कायम करना है तो यह आवश्यक होगा कि वहाँ हो रहे अन्याय, अत्याचार तथा शोषण को एकदम समाप्त करना होगा । इसके साथ एक नये समाज, मूल्य तथा प्रशासन का जन्म होगा जहाँ समानता, स्वतन्त्रता तथा राजनैतिक संतुलन होगा ।

30 नव., 1982 को 37वें अधिवेशन में बोली गई भूटान के प्रतिनिधि ने फिलिस्तीन की समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। भूटान के प्रतिनिधि ने कहा, मध्य पूर्व में सभी को एकमात्र प्रयास में जुट जाना चाहिए कि किस प्रकार सर्वभौमिक स्वतन्त्र फिलिस्तीन के देश की स्थापना हो। अरब में हुए सम्मेलन की प्रगति काफी सौजन्यपूर्ण है। अपने विचारों में यह बात भी कही कि सभी को ऐसा हल निकालना चाहिए जिसमें P. L. O. के दर्जे की सभी की ओर से मान्यता मिले और साथ में समझौते का हल निकालने की प्रक्रिया में P. L. O. पूरी तरह सहयोगी हो। भूटान के प्रतिनिधि ने इजराइल के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि इजराइल को उन सभी भूमि छह से हट जाना चाहिए जो उनके कब्जे में है।

संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा के 38वें अधिवेशन में भूटानी प्रतिनिधि ने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत किये। 38वां अधिवेशन 20 अक्टूबर, 1983 को प्रारम्भ हुआ। प्रतिनिधि ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र सभ के निरस्त्रीकरण से संबंधित उठाये गये कदमों की कुछ वेशों ने खुले रूप में अवहेलना की। हथियारों की होड़ जिस गति से बढ़ी है और राष्ट्रीय वजहों की समीक्षा के बाद इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी देश भयभीत हैं और अस्त्र-शस्त्रों का पारस्परिक आयात निर्यात या निर्माण का दौर बड़े जोरों से शुरू हो गया है। इस प्रकार की होड़ किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं है।

भूटान के प्रतिनिधि ने निरस्त्रीकरण पर बोलते हुए अपना विश्वास प्रकट किया कि निरस्त्रीकरण से ही समस्त विकासशील देशों का विकास सम्भव है। निरस्त्रीकरण का शुभ आरम्भ बड़ी शक्तियों से होना चाहिए जिससे वे अन्य देशों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। बार-बार आणविक हथियारों की कम करने की दुहाई दी जाती रही है परन्तु उसका व्यावहारिक पक्ष ठीक विपरीत सामने आता रहा है। एक से एक बढ़कर नष्टकारी हथियारों का निर्माण हो रहा है तथा अपने मित्र राष्ट्रों तक पहुँचाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है। यह सभी सम्भव हो सकता है जब महाशक्तियाँ उक्त सिद्धान्त पर ईमानदारी से अमल कर सकें।

भूटान ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया जो नामबिया के लोगों के समर्थन में बुलाया गया था। यह सम्मेलन 25 अप्रैल, 1983 से 29 अप्रैल, 1983 तक चला। इस सम्मेलन में लगभग 136 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें भूटान एक था। भूटान ने उन सदस्यों के साथ दक्षिण अफ्रीका की कठोर आलोचना की जिसने नामबिया पर गैरकानूनी तरीके से

अधिकार कर रखा है। नामबिया की सीमा से लगे अंगोला मोजांबिक, जिम्बावे तथा अन्य प्रान्तों में दक्षिण अफ्रीका की आक्रामक नीति की भी कड़ी आलोचना की गई। भूटान के प्रतिनिधि दाशो दोरजी ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा, "भूटान एक गुटनिरपेक्ष तथा शान्तिप्रिय देश है जिसने हर अन्तर्राष्ट्रीय जटिल समस्या के हल के लिए शान्ति के ही मार्ग का समर्थन किया है। नामबिया की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिसका हल शान्ति के ही मार्ग से होगा। दाशो दोरजी ने अपने भाषण में कहा कि नामबिया की समस्या तथा उस क्षेत्र में अन्य समस्याओं ने ऐसा विकट रूप धारण कर लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसी गम्भीर समस्या निःसंदेह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान आकर्षित करती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से यह अपेक्षा करती है कि उक्त समस्याओं का समाधान शीघ्र होना चाहिए।

४ दिसम्बर, 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 37वें अधिवेशन में बोलते हुए भूटान के प्रतिनिधि दाशो ओम प्रधान ने मध्य पूर्वी समस्या की ओर संकेत किया और कहा कि मध्यपूर्वी समस्या भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। दाशो ओम प्रधान ने इजराइल के सैनिक आक्रामक प्रवृत्ति की आलोचना की और कहा कि ईराक पर ध्वंसात्मक आक्रमण एक शर्मनाक बात है।

भूटान के प्रतिनिधि ने ईरान-ईराक के बीच कभी समाप्त न होने वाले युद्ध की आलोचना की तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी वर्ग से अपील की कि दोनों देशों के बीच युद्ध का समाधान निकट भविष्य में निकलना चाहिये।

फिलिस्तीन की समस्या पर बोलते हुए भूटान के प्रतिनिधि ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने मध्य पूर्व में फिलिस्तीन की गम्भीर समस्या को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस समस्या के समाधान में फिलिस्तीन लोगों को अपने राष्ट्र की सार्वभौमिकता की अखण्डता के लिए उचित अधिकार मिलने चाहिए। भूटान ने यह आशा व्यक्त की P.L.O. को भविष्य में वैध अधिकार प्राप्त होंगे तथा फिलिस्तीन की समस्या समाप्त हो जाएगी।

भूटान के प्रतिनिधि ने बैरुत में फिलिस्तीन शरणार्थियों की निर्मम हत्याओं की कड़ी आलोचना की और कहा कि जो लोग ऐसे जघन्य कार्य के लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो।

भूटान तथा गुटनिरपेक्ष

सम्मेलन में जो अलजीरिया में हुआ था

1973 में हुए गुटनिरपेक्ष ।। दस सम्मेलन में भूटान के स्थायी भूटान नरेश शामिल नहीं हो पाये थे किया जिन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट सदस्य सान्ये पेन्जोर ने प्रतिनिधित्व। शामिल होना भूटान के आधुनिक इति- किया कि "भूटान का गुटनिरपेक्ष में हमसे भूटान की जनता की आशाओं की हाथ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ कदम में कदम साथ चलने की प्रति हुई है तथा विकासशील देशों। क्षमता भी बढ़ेगी।"

जन कोतम्बो में हुआ जिसमें पहली बार

1976 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन शामिल हुए। भूटान नरेश ने अपने भूटान के राजा जिग्मे तिप्ते वांगचुकों पर प्रकाश डाला। जिन मुद्दों पर भाषण में समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्या, वे इस प्रकार हैं-

भूटान नरेश ने अपने मत व्यक्त निरन्तर प्रयास में एक बात जो सभव होती

"गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में उत्पन्न हुई दिखाई देती है वह यह कि विश्व इसी समस्या को दिया जाता है। शान्ति तनावों को कम करने का श्रेय मिलती जा रही है। विभिन्न देशों में यह शक्तियों को धीरे-धीरे सफलता विनिर्णयात्मक सफलता मिली है। विदेशी रहे राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को सफलता को जहाँ-तहाँ सफलता मिली है शक्तियों के वर्चस्व के विरुद्ध चल रहे महत्वपूर्ण सम्मेलन विशेष रूप में समुक्त- और मिलने की आशा रखते हैं। उप अधिवेशन का होना गुट निरपेक्ष अन्धो- राष्ट्रसंघ का छठा या सातवा बिन्दु क्योंकि उक्त अधिवेशन समस्या के आग्रह लन की ही सफलता मानी जायगी। आन्दोलन धीरे-धीरे विश्व पटल पर से ही बुलाया गया था। गुटनिरपेक्ष ऐसी विपरीत स्थिति में जब प्रगतिशील एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमें आम धृति दे रही है। गुट निरपेक्ष शक्तियाँ शान्ति तथा सुरक्षा को सज्जरी है।"

देशों में एकता का होना और भी राक्षस सधर्ष में बोलते हुए कहा कि पश्चिमी

भूटान नरेश ने अरब-इजरायल नहीं हो सकती जब तक इजरायल अपनी एशिया क्षेत्र में शान्ति सुरक्षा का पीछे नहीं हटायेगा जो उसने 1967 में सेना को अरब देशों की सीमा में

अपने अधिकार में कर ली थी। हुए भूटान नरेश ने कहा कि विश्व में अस्त्र-

निरस्त्रीकरण पर बोलते पंदा किया है। चारों ओर सदेह तथा शस्त्रों की होड़ ने अशान्ति की भी के कारण हुआ है। निरस्त्रीकरण पर बल अविश्वास का भाव सुरक्षा की क विश्व में निरस्त्रीकरण का एक आन्दोलन देते हुए भूटान नरेश ने कहा कि

होना चाहिए जिससे शान्ति-मुरझा का भाव जागृत हो तथा तीसरी दुनियाँ के देश विकास की ओर उन्मुख हों।

1983 मार्च को दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भूटान नरेश न केवल शामिल हुए अपितु उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से सशक्त व तटस्थ विचार प्रस्तुत किये, उन्होंने अपने भाषण में कहा—

“आज विश्व विघटनकारी शक्तियों के कारण टूटा व बिखरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय यथार्थ से हम मुछ नहीं मोड़ सकते। हम ईमानदारी व निष्ठा से बिगड़ी हुई स्थिति में सुधार ला सकते हैं। यह हमारा अटूट विश्वास है कि सच्चे रूप में माधुर्य तथा स्थायित्व का वातावरण तभी पैदा होगा जब हर देश की स्वतन्त्र नीति का मुख्य आधार सहअस्तित्व की भावना हो। गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य दासता, निर्भरता, हस्तक्षेप आदि सुराईयों की समाप्ति। उक्त आन्दोलन उन सभी दबावों, चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक या सांस्कृतिक, का विरोध करना है। सभी देशों में स्वतन्त्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना को जगाना है। अन्दोलन की सफलता चार मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करने में समझी जायगी। वे चार मुख्य सिद्धान्त हैं—पहला, हस्तक्षेप न करने का सिद्धान्त, दूसरा, अन्तर्राष्ट्रीय आपिक सहयोग का विकास जिसका मूल आधार होगा समानता। तीसरा समस्त गुट निरपेक्ष देशों की अखण्डता तथा स्वतन्त्रता के प्रति आदर और अन्तिम उद्देश्य स्वयं को निर्भय करने की स्वतन्त्रता जो देश बाहरी देश से शामिल हैं।

भूटान ने ‘मनीला घोषणा’ का स्वागत किया जिसमें विवादों को शान्तिपूर्वक समाधान करने का प्रावधान था। अन्दोलन का मुख्य उद्देश्य था शान्ति को स्थापित करना और सुरक्षा की भावना में वृद्धि करना। ‘मनीला घोषणा’ की विशेष बात यही थी कि यह उद्देश्यों में अमल करने की क्षमता को बढ़ाने वाली थी।

अतः 1980 से पूर्व तक भूटान की विदेश नीति में जो वर्षों से जड़ता आ गई उसमें परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिकांश चुप रहने वाला भूटान अब उन्हीं समस्त मंचों से खुले विचार प्रस्तुत करने की क्षमता बढ़ा चुका है। कभी भारतीय प्रेस से इस प्रकार की टिप्पणियों के समाचार आने लगे कि भूटान पर भारत का प्रभाव घट रहा है या भूटान का दृष्टिकोण भारत के प्रति उदासीन हो रहा है। परन्तु छोटे राष्ट्र की विचशताएँ कुछ ऐसी विचित्र प्रकार की होती हैं जिनको कहने में हास्यास्पद तथा स्वयं में सीमित रखने में संदेह तथा रहस्य लगते हैं। केवल भूटान के

प्रशासक ही अपनी पीड़ा को समझ सकते हैं और उस पीड़ा से मुक्त होने के प्रयास में विपत्तियों की पोजवीन फरते रहते हैं। भूटान की विदेशनीति में परिवर्तन करना उसकी ठेठ विवशता के अलावा और कुछ नहीं। प्रत्येक विकासशील देश की इसी प्रकार की मजबूरियाँ हैं लेकिन उन सभी को आवश्यक बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, बंगलादेश ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा अखंडता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय नियोजनों पर अपने देश में प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु मर्यादा के निकट आते ही यह अहसास किया कि देश के विकास के लिये MNC का प्रवेश अनिवार्य बुराई है। इसी प्रकार भूटान की निजी इच्छा तो अन्य राष्ट्रों से अलग-थलग रहने की थी जिसको शताब्दियों से निर्बाह करने का प्रयास भी किया लेकिन अन्त में अन्य राष्ट्रों की तरह वही मार्ग अपनाना पड़ा जिससे छुटकारा नहीं था। मध्ययुग के काल में रहने की किसी भी राष्ट्र की इच्छा नहीं है।

इसी सामान्य स्वरूप को ग्रहण करने की इच्छा ने भूटान की अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं में वृद्धि की जिसने आगे चलकर उसी व्यवहार को साकार रूप प्रस्तुत किया जैसा अन्य राष्ट्रों ने अब तक किया था। अन्तर्राष्ट्रीय सबंध का सामान्य तथा स्थूल सिद्धान्त यही है कि प्रत्येक राष्ट्र के व्यवहार उसके राष्ट्रीय हितों के इर्द-गिर्द नाचते हैं। जब भूटान को 'राष्ट्रीय हितों' का धीरे-धीरे ज्ञान हुआ तो उसके ठीक अनुरूप उसकी अभिव्यक्तियाँ भी स्पष्ट सामने आईं जिन पर अश्चर्य करना या चौकन्ने होना उसी के प्रति अन्याय करता है। कुछ एक मुद्दों पर भूटान ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध किया था उसके विरुद्ध अपनी राय प्रस्तुत की। जैसे कंबूजिया, अफगानिस्तान, तथा आणविक शक्ति के मुद्दे—ऐसे गम्भीर प्रश्न थे जिन पर भूटान ने भारत के विरोध में अपनी राय सामने रखी। यदि हम भारतीय दृष्टिकोण तथा राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय हितों को एक ओर हटाकर दक्षिण एशिया के सबसे छोटे राष्ट्र की मजबूरियों पर ध्यान दें तथा सहानुभूति रखें तो भूटान के प्रति अधिक उचित राय का निर्माण कर सकेंगे। जनतापार्टी के शासन में जब भारतीय जनतापार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी विदेशमन्त्री बने तभी उन्हें मर्यादा के दर्शन हुए तथा भारतीय विदेशनीति के निर्माता पं. जवाहरलाल नेहरू की विदेशनीति में दूरदर्शिता का अहसास हुआ। उससे पूर्व वे विरोधी नेता के रूप में संसद में अनेकों बार भारतीय विदेशनीति की आलोचना कर चुके थे। कहने का अर्थ यही है कि हर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहु-

आयामो दवावों के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने का प्रयास करता है और उस प्रक्रिया में अपने विचार-मत तथा निर्णयों को तै करता है। भूटान आज, यू. एन. ओ. एन. ए. एम तथा साकं का सक्रिय सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्रों को समझकर तथा राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखकर अपनी स्वतन्त्र राय बनाता है और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उसी के अनुरूप व्यवहार देने का प्रयास करता है। साकं का सक्रिय सदस्य हो जाने के बाद अपने ही देश में दो तीन बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की भेजवानी भी की है। पहली बार तो समिल समस्या के समाधान के प्रयास में तथा दूसरी बार साकं का सम्मेलन। कहने का अर्थ है कि भूटान में आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया उस स्तर पर पहुँच गई है जिसको देखकर भूटान को पिछड़े हुए देश की संज्ञा देना अब उसका अपमान करना होगा। भारत की आर्थिक सहायता शत-प्रतिशत से घटकर 87% रह गई है। पहले यू. एन. ओ. से आर्थिक सहायता मात्र 3 प्रतिशत थी लेकिन अब घटकर 18% हो गई है। यद्यपि इन सभी का विश्लेषण 'भूटान आर्थिक विकास की ओर' के शीर्षक में हो चुका है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय अस्तित्व को ऊपर लाने में सतत प्रयत्नशील है।

यद्यपि भूटान नरेश तथा उसके सहयोगी प्रशासकों को अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका को निभाने में एक दृष्टि में संतोष है लेकिन दूसरी ओर अपने ही घर की स्थिति को देखकर चिन्ता भी होने लगी है। हर राष्ट्र आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की इच्छा पूर्ति में एक महत्त्वपूर्ण चीज को उत्तरोत्तर खोने लगता है जो उसकी मूल निधि कमी थी। वह मूल निधि उसकी संस्कृति तथा पावन परम्पराएँ हैं जिन पर जनः जनः प्रहार होते देखकर चिन्ता होती है। यदि भूटान से मात्र प्रकाशित साप्ताहिकी बुलैटिन की ओर दृष्टिपात करें तो हर प्रति में यह पढ़ने को मिलेगा कि 'भूटान की संस्कृति की सुरक्षा' को प्राथमिकता दी जायगी। उक्त बुलैटिन में यही शिकायत पढ़ने को मिलेगी कि 'देश की संस्कृति खतरे में है।' उसमें यह भी पढ़ने को मिलेगा कि 'भूटान के युवा वर्ग की देश के बौद्ध धर्म के प्रति उदासीनता बढ़ रही है।' या यह भी ज्ञान होगा कि 'देश में मठों के धार्मिक नेताओं का सार्वजनिक रूप से अपमान करना देश की संस्कृति का अपमान करना है।' दूसरे शब्दों में यह कहना पर्याप्त होगा कि भूटान यदि आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की ओर बढ़ता

है तो उससे संलग्न उत्पन्न हुई बुराइयों को भी झेलना होगा जिनका होना अपरिहार्य है। सुखवाद तथा भोगवाद के समाज का सृजन तथा उससे लिपटी हुई बुराइयाँ साथ-साथ चलती हैं। भारत भी इन्हीं बुराइयों का शिकार हो चुका है—उससे बचना मुश्किल है। इसीलिये महात्मा गांधी ने 1947 में ही कहा था कि “औद्योगीकरण की व्यवस्था को लाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन स्वदेशी कुटीर उद्योगों की कीमत पर लाया जायेगा तो उस भारत को पहिचानना मुश्किल हो जायगा जिसके लिये यह देश पश्चिमी देशों में जाना जाता रहा है”। यह बात सही है कि राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण तभी होता है जिस देश के नागरिक भोगवाद या सुखवाद की ओर न्यूनतम उन्मुख होते हैं।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने से मठों के युवा धार्मिक नेता आधुनिकीकरण की चमक-दमक को देखकर गृहस्थ जीवन को बिताने के लिये लौट रहे हैं जिससे ‘सुखवाद’ की स्थिति से वंचित न रह जायें। □□

भूटान में नेपालियों की समस्या

अल्पसंख्यकों की समस्या न केवल दक्षिण एशिया में ही सीमित है अपितु यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। अन्तर केवल इतना है कि उच्च स्तर के विकसित देशों में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप शालीन होने के कारण उक्त समस्याओं को सार्वजनिक रूप से अधिक नहीं उछाला जाता जबकि ठीक इसके विपरीत विकासशील देशों में अल्पसंख्यकों की समस्या उनके राजनीतिक व्यवस्था के लिए निरन्तर चुनौती सी बन गयी है। दक्षिण एशिया के देश तो इस समस्या से निःसन्देह अधिक पीड़ित हैं। चाहे वह श्रीलंका हो या बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल-भूटान, समस्त क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गहरी होती जा रही है। जिनके कारण भारत पर अधिक दबाव पड़ता है। साथ में समस्या के समाधान में भारत की भूमिका निर्णायक एवं महत्वपूर्ण होती है।

इसी सन्दर्भ में भूटान की अल्पसंख्यकों की समस्या से परेशान है क्योंकि भूटान वर्षों तक ऐसा पर्वतीय राज्य रहा है जिसको बाहरी परिवर्तनशील वातावरण से अलग-थलग रखा गया। इसलिए भूटान की आन्तरिक समस्याओं के बारे में अधिकांशतः लोग अनभिज्ञ हैं। 1961 के बाद से ही भूटान ने अपनी विदेश नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन करना प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप उसकी आन्तरिक समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाएँ अब मालूम होने लगी हैं। भूटान में अल्पसंख्यकों की समस्या अपना भयंकर रूप धारण करती जा रही है।

भूटान के निवासी

भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा सा पर्वतीय राज्य है। जिसका क्षेत्रफल 18,000 वर्गमील तथा जनसंख्या 13-14 लाख के आस-पास है। यह माना जाता है कि भूटानी जनता का विशाल बहुमत भारतीय मंगोल

जाति से निर्मित है तथापि दक्षिण भाग में नेपालियों (नेपाल मूल के लोग) का अधिपत्य है। जिन स्थानों पर नेपाली बसे हुए हैं, वह है—चिरांग तथा सामची। नेपाली मूल के निवासी प्रारम्भ से भूटान के राजतन्त्र के लिए चुनौती बने हुए हैं जिसके कारण उनको वहाँ के अधिकारी वर्ग ने बसने का स्थान भी अलग रखा। नेपाली निवासियों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं। जिनका समाधान वहाँ का प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है। वे अपने आप भूटान के निवासी हैं उनको नम्बर 2 का दर्जा प्राप्त है। जिसके कारण उनमें असन्तोष व विद्रोह की भावना इतने वर्षों से पल रही है। भूटान की जनता का विभाजन मोटे रूप से तीन भागों में किया जा सकता है—(a) पुरोहित, (b) अधिशासी वर्ग (c) किसान एवं श्रमिक वर्ग। नेपाली लोगों की गणना किसान या श्रमिक वर्ग में की जाती है।

नेपाली लोगों की भी उपजातियाँ हैं जैसे रिचाए, गुरंग, लिम्बु, छेपी तथा धारस, ये लोग 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में असम एवं बंगाल से भूटान की तराई के क्षेत्रों में बसते चले गए। नेपालियों में गुरखा जाति अपेक्षाकृत विद्रोही तथा क्रान्तिकारी समझी जाती है। भूटान के नेपाली भाग (दक्षिण भूटान) चिरांग व सामची में नेपाली बसे हुए हैं। इनका व्यवसाय कृषि एवं शारीरिक श्रम है। नेपाली लोग भूटान के मूल निवासी भूटिया, लैप्चा, दुक्यास एवं दोयास, से अधिक मेहनती होने के कारण भूटान में नागरिकता प्राप्त करते गए। भूटान के प्रशासन ने यद्यपि अपने स्वार्थ के लिए नेपालियों को प्रवेश होने दिया एवं नागरिकता भी प्रदान की लेकिन उनको सम्माणीय दर्जा नहीं दिया। भूटान के आधुनिक निर्माण में नेपालियों का सर्वाधिक योगदान होने के बावजूद भी उनको दो स्थानों के अतिरिक्त बसने की स्वतन्त्रता नहीं दी। यही नहीं इतने लम्बे असे से बसे हुए लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार भी नहीं दिया। भूटान के प्रशासन में नेपालियों को कहीं भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। नेपाली जाति में एक पुरुष को कई-कई शादियाँ एवं पत्नियाँ रखने का अधिकार है जिसके कारण उनकी जनसंख्या वहाँ के मूल निवासियों के मुकाबले भविष्य में अधिक हो जाने की सम्भावना है। 1971 की जनगणना के अनुसार नेपालियों की जनसंख्या 20% से 30% आकी गई है परन्तु अनौपचारिक रिपोर्ट के अनुसार नेपालियों की जनसंख्या लगभग 30% से 40% है। यदि इस प्रतिशतता पर विश्वास किया जाये तो निःसन्देह भूटान के राजतन्त्र प्रशासन के लिए एक गम्भीर समस्या ही नहीं अपितु खतरा भी कहा जा सकता है।

भूटान के प्रशासन का नेपालियों के प्रति भेदभाव का व्यवहार शंकाओं के कारण हुआ, जिसमें अभी भी परिवर्तन नहीं हो पाया है, यह एक संक्षिप्त इतिहास है जिसे हम इस प्रकार स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं ।

1952 में डी. बी. गुरंग, डी. बी. छेत्री तथा जी. जी. शर्मा के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ जिसका नाम भूटान स्टेट कांग्रेस दल (Bhutan State Congress Party) रखा गया । प्रारम्भ में उक्त दल के मुख्य उद्देश्य केवल उन नेपाली शरणार्थियों की दिक्कतों तथा समस्याओं का समाधान करना था जो गोलपारा तथा जलपाईगुरी में बस गये थे । बाद में इस दल के उद्देश्यों का विस्तार राजनीतिक सुधारों तक हो गया था । भूटान कांग्रेस दल का सीधा सम्पर्क भारत के उन नेताओं से था जिनसे दल को पूरा-पूरा सहयोग, मदद मिलने की अपेक्षा थी । दल ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन करने की घोषणा कर दी थी । मुख्य उद्देश्य केवल भूटान सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का उन्मूलन करना था जिससे नेपाली लोग वर्षों से पीड़ित थे । नेपाली लोगों को भूटानी सरकार से निम्न शिकायतें थीं—

(A) भूटान में नेपाली निवासियों को नागरिकता प्रदान करने के बावजूद भी आवश्यक सुविधाओं से क्यों वंचित कर रखा है ?

(B) भूमि पर स्वामित्व एवं भूमि पर खेती करने से नेपालियों को क्यों वंचित एवं वर्जित कर रखा है ।

(C) नेपालियों का भूल निवासियों एवं अधिकारी वर्ग द्वारा क्यों शोषण किया जाता रहा है ।

उक्त समस्याओं को हल करने हेतु 22 मार्च, 1954 भूटान के दक्षिण भाग सारभाग (जहाँ सर्वाधिक नेपाली बसे हुए हैं) में सत्याग्रह करने का अभियान प्रारम्भ किया । दल के नेताओं ने भारतीय नेताओं से समर्थन प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया । परन्तु उस संकटकाल में इस दल को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हो सकी । जिसके परिणामस्वरूप भूटान के राजा को एक मात्र दल को कुचलने का पूरा-पूरा मौका मिला । भूटान में यह तब से प्रथम व अन्तिम आन्दोलन था, इस आशा में कि क्या सिविकम की तरह भूटान में भी नेपाली समस्या की पुनरावृत्ति होगी । इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार की नीति राजतन्त्र को समर्थन देने वाली थी जिसके कारण भूटान में आज तक जनतान्त्रिक शक्तियाँ उभरने नहीं पाई हैं ।

भूटान संसद का जन्म

उक्त आन्दोलन ने भूटान के राजा को झुकड़ोर कर रग दिया। वह जनतान्त्रिक शासन के पूर्णतः खिलाफ होने के बावजूद भी जनतन्त्र का आडम्बर करने के लिए अवश्य वाध्य हुआ। भूटान की 1953 में एक संसद को जन्म दिया जिसका संविधान बनाया गया। भूटानी भाषा में संसद को 'शोगदू' (Tsongdu) कहते हैं। यद्यपि चुनाव की व्यवस्था तथा पद्धति भाग्यीय व्यवस्था से भिन्न रखी गयी। लेकिन उनमें सदस्यों को राष्ट्रीय मुद्दों पर छलकर बहस करने का मौका अवश्य मिला। आज भूटान संसद में 150 सदस्य हैं, जिनमें से 100 सदस्यों का चुनाव द्वारा सीधा चुनाव होता है। शेष सदस्य भूटान के राजा द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूटान की संसद में नेपालियों का प्रतिनिधित्व तो है लेकिन उनकी संख्या नहीं के बराबर है।

भूटान के प्रशासन से नेपाली निवासियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

(A) भूटान में राजतन्त्र को समाप्त कर जनतान्त्रिक व्यवस्था हो।

(B) भूटान में भाषायी नीति भेदभावपूर्ण है, भूटानी भाषा जोन्खा (DZONKHA) अनिवार्य रूप से लागू करना अन्याय है।

(C) देश में नेपाली भाषा को उचित स्थान दिया जाए।

(D) भूटानी पोशाक (गाडो को अनिवार्य रूप में पहनना प्रजातन्त्र के खिलाफ है) इसलिए पोशाक पहनने पर छूट हो।

(E) भूटान में बौद्ध धर्म की मानना मानवीय भावनाओं के विरुद्ध है।

(F) भूटान में इस प्रकार के साहित्य पर पाबन्दी है जो जनतान्त्रिक भावनाओं को जगाता है, नेपाली निवासियों की यह मांग है कि हर तरह के साहित्य को पढ़ने की छूट होनी चाहिए।

(G) देश में दोहरी चुनाव की पद्धति को लागू करना जनतान्त्रिक भावनाओं के खिलाफ है। भूटान के दक्षिणी भाग में जहाँ नेपाली निवासी हैं। वहाँ सीधा चुनाव करने की व्यवस्था है, जबकि अन्य स्थानों पर अपरोक्ष चुनाव पद्धति का प्रावधान है।

उक्त आपत्तियों, दिक्कतों के अलावा नेपाली निवासियों का रहन-सहन परम्पराएँ व मूल्य भूटान के मूल निवासियों से भिन्न हैं। नेपाली लोग किसी भी प्रकार से भूटानी संस्कृति में आत्मसात नहीं कर पाये हैं। जिनके कारण उनको व सरकारी सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जितनी अन्य निवासियों को। इसके अतिरिक्त भूटान भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि नेपाली निवासियों के पारस्परिक सम्बन्धी रिश्तेदार या तो नेपाल में हैं, या भारत में हैं। इस कारण से भी भूटान के अधिकारी वगैरे नेपालियों पर सन्देह भरी नजरों से

निगरानी रखते हैं। नेपालियों की भूटान राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर आज तक सन्देह है। भूटान सरकार को अच्छी तरह जानकारी है कि नेपाली निवासी भारत के आदर्श परम्परा तथा रहन-सहन से अधिक प्रभावित हैं और उनके व्यवहार में उक्त लक्षणों की पूरी झलक मिलती है। भूटान में नागरिकता प्राप्त करने से पूर्व नेपाली लोगों की शिक्षा भी भारत के खुले वातावरण में मिली है इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे या तो जनतान्त्रिक मूल्यों को मानने वाले हैं या उनका झुकाव साम्यवाद की ओर है। वह भी मार्क्स साम्यवाद। नेपाली निवासी आज तक अपने आपको भावनात्मक एकता के सूत्र में हिमालयी राज्य भूटान से वंच नहीं पाये हैं। ऐसा अनुमान है कि यदि भूटान की नीति में परिवर्तन होता है तो वे प्रजासन के अंग बन जायेंगे, और उनकी शिकायतें, माँगें, दिक्कतें, समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। परन्तु वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल ठीक विपरीत होने के कारण अल्पसंख्यक की समस्या भूटान में अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तरह अभी जीवित है। भूटान स्टेट कांग्रेस दल जिमका गठन 1952 में हुआ था उस पर आज तक पाबन्दी लगी हुई है।

भूटान के अधिकारी वर्ग में नेपालियों के प्रति कुछ सन्देह में अधिक बल पड़ गये हैं। जिसके कारण उनके प्रति संभावित घटनाओं के बारे में सोचना काल्पनिक नहीं कहा जा सकता है। भूटान के मूल निवासी यह मोचने लगे हैं कि नेपाली निवासी जो कि दक्षिण भाग में बसे हुए हैं। भविष्य में भूटान के लिए चुनौती ही नहीं अपितु खतरा बन सकते हैं। उनका यह सोचना गलत तो नहीं है क्योंकि नेपाली निवासियों का सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध भारत के मैदानी नेताओं से बराबर बना रहा है। तथा 1954 में राजनीतिक दल पर लगाए गये पाबन्दी का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। भूटान स्टेट कांग्रेस दल के नेता यद्यपि अभी शान्त दिखाई देते हैं लेकिन वे इस भीके की तलाश में हैं कि जब वे उसका कायदा ले सकें। उनके मस्तिष्क में सिक्किम का उदाहरण हमेशा के लिए बस गया है और उम्मीद है कि शायद कभी सिक्किम की घटना भूटान में भी दोहराई जाए। इसलिए नेपाली निवासी यदाकदा भूटान के राजा से अपनी शिकायतें रखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी नेपाली निवासी, अपम, पश्चिमी बंगाल के मार्क्सवादी नेताओं से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं, और वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से निर्देशन लेते रहे हैं। कभी-कभी नेपाली नेता भारत सरकार से भी यह शिकायत करते हैं कि नई दिल्ली अपनी नीति को बदले जिससे उनके प्रति किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार हमेशा के लिए समाप्त हो।

भारत की भूमिका

1949 से वर्तमान तक भारत ने जिस तरीके से अपनी नीति को व्यावहारिक रूप से प्रस्तुत किया, उससे भूटान के राजा पूर्णतः आश्वास्त हैं कि सिक्किम की कहानी दुहराई नहीं जायेगी। यह शंका सिक्किम के उदाहरण को लेकर कही तो जा सकती है, परन्तु सिक्किम के साथ भारत ने 1950 में सन्धि जो की थी, उसका स्वरूप भूटान से भिन्न है। सिक्किम 1950 की सन्धि के अनुसार एक आरक्षित राज्य था, जबकि 1949 की संधि भूटान की अखण्डता व सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता पर किसी भी प्रकार से आंच नहीं आने देती है। इसलिए सिक्किम के उदाहरण को प्रस्तुत करना निराधार है। भारत की नीति विशेष रूप से भूटान के साथ पारस्परिक सहयोग तथा सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार की रही है। ऐसा डर या शंका तो भी जा सकती है, परन्तु उसको व्यावहारिक रूप देना अमंभव है।

आज भूटान का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा 1949 से कहीं ज्यादा ऊँचा है। यद्यपि सन्धि तो यों की स्थों बरकरार है और उसका सकलतापूर्वक निर्वाह हो रहा है। नेपाली निवासियों की समस्या को भारत ने भूटान की आन्तरिक समस्या समझा है और उसमें कभी भी हस्तक्षेप करने की सोचा भी नहीं है। भूटान के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में कभी नहीं रहेगा। पिछले 7 वर्ष से भूटान के अधिकारी वर्ग इस बात से परेशान हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भारत से शत-प्रतिशत सहायता लेना कहां तक उचित है? भारत ने उसकी परेशानी को अन्य दृष्टिकोण से समझा और तुरन्त ही आर्थिक सहायता धीरे-धीरे कम कर दी। उनके विबल्स के लिए भूटान अन्य देशों से आर्थिक सहायता लेने लगा, जिसका अर्थ पड़ोसी देशों ने कुछ और ही लिया। हाल ही में भूटान नेपाल सम्बन्धों के स्थापित हो जाने में यह शंका अवश्य उठ खड़ी हुई है कि क्या भूटान में नेपाली निवासी अपनी समस्याओं का समाधान नेपाल की सहायता से कर सकते हैं। यदि हाँ, तो दोनों के बीच नए सम्बन्धों का क्या भविष्य होगा?

इस सम्बन्ध में दो सम्भावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं—(1) भूटान सम्भवतः नेपाली निवासियों को अपने प्रशासन में उचित स्थान देना प्रारम्भ कर देगी। (2) नेपाल भूटान में इस समस्या को अधिक प्रज्ज्वलित कर सकता है जिसके फलस्वरूप भूटान नेपाल के सम्बन्धों में कटुता आ सकती है। ऐसी परिस्थितियों से भारत अवश्य समस्या के निराकरण के लिए हस्तक्षेप करे और वह हस्तक्षेप भूटान के ही पक्ष में होगा और नेपाल को दब जाना पड़ेगा।

पूर्वांचल की समस्या

कहा जाता है कि भारत का पूर्वांचल भाग मुख्य धारा से बंध नहीं पाया। यह भी निरन्तर आक्षेप दिल्ली के प्रशासन पर रहा कि उत्तरी-पूर्वी सीमा खंड पूर्णतया उपेक्षित रखा गया तथा लाभ का हिस्सा उनको नहीं मिल पाया। यह मत या पक्ष अपने आप में पूर्ण नहीं लगता। दूसरा पक्ष जो उभर कर आया है या प्रस्तुत किया जा सकता है वह यह कि उनकी भौगोलिक परिस्थितियों ने उनको मुख्य धारा में आने से रोके रखा तथा पारस्परिक विरोध तथा संघर्षों के कारण आपस की सीमा से सटे प्रान्तों को एक सूत्र में बांधने से रोके रखा। इसका ज्वलंत उदाहरण उनके दलीय गठन तथा पारस्परिक हितों की टकराहट से स्पष्ट होता है। उत्तर-पूर्वी सीमा के क्षेत्रीय दलों की स्थिति अत्यधिक दयनीय लगती है। दयनीय स्थिति का मात्र कारण आपस के हितों की टकराहट तथा प्रतिस्पर्धा।

1978 के बाद जब से पूर्वांचल लोक परिपद का गठन हुआ जिसके अन्तर्गत बराबर प्रयास किये गये कि उक्त सीमा खंड के लोग एक होकर काम करें तथा उत्तरी सीमा के विभिन्न प्रान्तों के बीच माधुर्य का वातावरण कायम रहे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पूर्वांचल लोक परिपद के गठन में भूतपूर्व समाजवादी नेता निवारन बोरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री बोरा ने उत्तर-पूर्वी सीमा के प्रान्तों को एक सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किया। इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य यही था उत्तर-पूर्वी सीमा के प्रान्त जो अब तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं—अब लोकपरिपद के गठन के बाद जुड़ पायेंगे तथा उन सभी लाभों को प्राप्त कर सकेंगे जिनसे अब तक वंचित रहे।

पूर्वांचल लोक परिपद को जिन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सक्रिय होना था वे थे—असम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर, मिजोरम, अरुणाचल तथा त्रिपुरा।

परन्तु आगे चलकर लोक परिपद का व्यावहारिक स्वरूप उद्देश्यों की विपरीत दिशा में सक्रिय दिखाई दिया। असम की ग्रहपुत्र घाटी तक ही लोक परिपद की सक्रियता धीरे-धीरे सीमित होती गई और अन्य छोटे-छोटे प्रान्तों के हितों की उपेक्षा का भाव स्पष्ट होता गया।

पूर्वांचल लोक परिपद (PLP) की प्रतिबद्धता समग्र उत्तर-पूर्वी राज्यों की न होकर अपने छोटे से दायरे में धीरे-धीरे बंधती गई जिसके परिणाम-स्वरूप उन उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई उपलब्धि न हो पाई जिस आधार पर उसका गठन हुआ था। यद्यपि प्रयास फिर भी चलते रहे जिससे सम्पूर्ण पूर्वांचल का भाग लाभान्वित हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा था—आर्थिक पिछड़ेपन का। लोक परिपद ने उन भागों को रखा जिससे स्थानीय आर्थिक दक्षिणता को दूर किया जा सके। वहाँ के आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का उद्देश्य सन्निहित था। लोकपरिपद के नेताओं का केन्द्र पर आरोप था कि उत्तर-पूर्वी भाग का खुले आम शोषण किया जा रहा है। नेताओं के आँकड़ों के आधार पर केन्द्र को स्पष्ट किया कि बाध्य तत्त्व स्थानीय लोगों का आर्थिक दृष्टि से शोषण करते रहे हैं। लोक परिपद ने स्थानीय आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सुझाव दिया कि यदि समस्त उत्तर-पूर्वी प्रान्त पारस्परिक आर्थिक सहयोग की योजना कार्यान्वित कर सकें तो उनका आर्थिक शोषण भी नहीं होगा और परस्पर सहयोग की बुनियाद पर उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। सामूहिक नेतृत्व की भावना ही इस क्षेत्र में न केवल आर्थिक सुधार लायेगी अपितु इसकी अपनी अलग से अहमियत भी उभरेगी। उद्देश्य कितने भी अच्छे क्यों न हों, उनकी व्यावहारिकता उतने अंश में ठीक नहीं होती। यही बात पूर्वांचल लोक परिपद के साथ हुआ। यदि हम समस्त पूर्वांचल के प्रान्तों की क्षेत्रीय दलों की स्थिति का विश्लेषण करें तो लगता है कि पी. एल.पी. तथा क्षेत्रीय दलों के बीच निरन्तर गतिरोध उत्पन्न होते गये। परिणामतः स्वरूप उन उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यवधान सामने आये जिन्होंने उनकी स्थिति में सुधार ला पाने में रुकावट डाली। धीरे-धीरे PLP के उद्देश्य केवल असम तक ही सीमित होकर रह गये।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका—असम आन्दोलन जिसकी पराकाष्ठा अगस्त, 1979 में विदेशी नागरिकों के मुद्दे को लेकर प्रारम्भ हुयी थी उसमें PLP एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उभरा। AAGSP (All Assam Ganga Sangram Parishad) को शक्ति प्रदान करने वाले और भी तत्त्व थे। उसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय दलों को शामिल किया जा सकता है। जब असम

का आन्दोलन आगे बढ़ रहा था उस समय मेघालय में बांग्लादेश से आये विदेशी नागरिकों की समस्या भी धीरे-धीरे पनप रही थी। मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल तथा नागालैंड के क्षेत्रीय दलों ने असम आन्दोलन को पूर्ण सहयोग दिया तथा PLP के गठन का महत्व उक्त समस्या को देखकर और भी बढ़ता गया। ऐसा अनुभव होने लगा कि PLP के माध्यम से क्षेत्रीय एकता में और भी वृद्धि होगी। 'Cut-off' की मांग पर सभी उत्तर-पूर्वी प्रान्तों ने असम आन्दोलन को शक्ति प्रदान की। इस प्रकार की एकता से सभी को अनुभव होने लगा कि पारस्परिक सहयोग की भावना अविष्य में और भी बढ़ेगी तथा PLP के उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं आयेगा। असम आन्दोलन के दौरान क्षेत्रीय दलों की वापिक सभा होती थी और पारस्परिक आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बहस होती थी। इस प्रकार की सभाओं को बुलाने का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना तथा विभिन्न प्रान्तों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने की रही। क्षेत्रीय दलों की तीसरी सभा इंकाल में अक्टूबर, 1984 को हुई। इस सभा में 'पूर्वांचल' की अखंडता तथा एकता को कायम करने के लिये इसका 'दिवस' मनाने का निश्चय किया। इस मीटिंग में लगभग ग्यारह क्षेत्रीय दलों ने भाग लिया जिसमें (a) Manipur Peoples Party, (b) Naga National Democratic Party (c) Peoples Conference of Mizoram, (d) The Hill People Democratic Party, (e) P.L.P.

इस मीटिंग में पूर्वांचल क्षेत्रीय दलों की एक (Action Committee) का भी गठन किया गया। एक्शन कमिटी का अध्यक्ष मेघालय के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बी. बी. Lyndoh को चुना गया। PLP के Pabendra Deka को Action Committee का महामंत्री नियुक्त किया गया।

जब असम गण परिषद का अक्टूबर, 1985 में गठन हुआ तो PLP ने अपने मुख्य उद्देश्यों को इसमें विलय कर दिया, उनके सभी प्रोग्रामों को AGP में समाहित कर दिया। इस नये क्षेत्रीय दल में PLP के पूर्व सचिव अतुल बोरा तथा पबिन्द्र डेका को महत्वपूर्ण पद प्रदान किये गये। AGP के चुनाव अभियान में अन्य क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। AGP की विजय तथा सरकार बनने से अन्य क्षेत्रीय दलों को और भी अधिक हिम्मत बंधी और इसी के साथ Concept of Regional Unity को भी अधिक उत्साहित किया। AGP की सरकार के गठन के तुरन्त बाद समस्त क्षेत्रीय दलों की एक सभा हुई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने की योजना बनाई गई जिनसे अब तक वरों से वंचित थे।

सीमा उत्खनन का आरोप लगाया है। असम-नागालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर आपस में हिंसात्मक झगड़े हुए हैं। सबसे प्रमुख झगड़ा जून, 1985 को मीरापाणी पर हुआ जब नागालैंड तथा असम की पुलिस के बीच सीमा के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये तथा सैकड़ों व्यक्ति हताहत हुए। इसी प्रकार 1979 में असम-नागालैंड के बीच आपसी झगड़े हुए जब नागालैंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, जो नागालैंड की पुलिस के द्वारा अनुप्रेरित थे, असम के गांवों पर कई हमला किया। जिन गांवों पर आक्रमण किया वे असम के दक्षिणी भाग नामबोर, रैनियमा, तथा दिफू। दोनों के बीच विवाद 434 किलो मी. फैला हुआ। नागालैंड ने सुंदरम कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जिसने 1925 के नियमों का समर्थन किया। वह कहना है कि 1925 के नियमों को न लेकर सुंदरम के नियमों को नजर में रखकर अपनी सिफारिशें भी उक्त मसले को लेकर दोनों के बीच भारी तनाव

यद्यपि समस्त क्षेत्रीय दलों में एक समान दृष्टिकोण तथा विचारधारा न होते हुए भी उनको एकता के सूत्र में बंधने का अच्छा अवसर मिला जिसके आधार पर वपों से वचित रहे उन लाभों को प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध हो गये। असम तथा मिजोरम में क्षेत्रीय दल की सरकार का बन जाना तथा मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड तथा त्रिपुरा में सशक्त विरोधी क्षेत्रीय दल के होने से स्पष्ट होने लगा कि क्षेत्रीय दलों के बीच एकता तथा अखंडता बनी रहेगी। लेकिन अच्छे उद्देश्य तथा प्रोग्रामों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया में व्यवधान न आये यह भी सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के विरोधी दलों की भूमिका शेष उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में नगण्य सी रह गई। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर के प्रान्तों में यद्यपि कांग्रेस (आई) सरकार बनाने में समर्थ तो हुई लेकिन उसने कुछ तो अन्तः पारस्परिक विरोध का लाभ उठाया और कुछ केन्द्र के सहारे जोड़ तोड़ के माध्यम से सफलता प्राप्त की। इस मत में कितनी विश्वसनीयता है, यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु व्यवस्था सिद्धान्त का व्यावहारिक पक्ष हर स्थान पर इन्हीं परिणामों को हमेशा प्रदान करता रहा है। उदाहरण के लिये मेघालय में कांग्रेस (आई) तथा ए. पी. एच. सी. एल का गठबंधन तथा नागालैंड में कांग्रेस (आई) व एन. एन. ओ. के तालमेल ने सत्ता में ठहरे रहने के लिये सत्ता पक्ष को मदद दी। साथ में केन्द्र के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को थोक में अनाप-सनाप आर्थिक सहायता ने भी कांग्रेस (आई) को सत्ता में ठहरे रहने में सहायता दी है। कांग्रेस (आई) की राजनीतिक चतुराई सरकार रही कि मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल के बीच सीमा विवाद हमेशा जिन्दा रहे जिसका लाभ उसे निरन्तर मिलता रहा।

लेकिन पिछले अनुभवों ने यह बात तो क्षेत्रीय दलों को अवश्य सिखा दी है कि वे बिना कांग्रेस (आई) से गठबंधन किये बिना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रख सकते हैं। साथ में क्षेत्रीय दलों के बीच एक उल्लेखन परेशान किये हुए है कि पारस्परिक सीमा विवाद का विकल्प क्या है जिसके फलस्वरूप यथार्थ लाभ कांग्रेस (आई) को मिल जाता है। इस तथ्य का ज्ञान होते हुए भी सीमा विवाद के मुख्य मुद्दे का हल क्षेत्रीय नहीं निकाल पाये हैं।

सीमा विवाद—समस्त क्षेत्रीय दलों को पारस्परिक सीमा विवाद परेशान करता रहा है। जब कभी भी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल एक मंच पर एकत्रित हुए हैं तो मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश ने असम पर

सीमा उत्खनन का आरोप लगाया है। असम नागालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर आपस में हिंसात्मक झगड़े हुए हैं। सबसे प्रमुख झगड़ा जून, 1985 को मोरापाणी पर हुआ जब नागालैंड तथा असम की पुलिस के बीच सीमा के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये तथा सैकड़ों व्यक्ति हताहत हुए। इसी प्रकार 1979 में असम-नागालैंड के बीच आपसी झगड़े हुए जब नागालैंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, जो संभवतः नागालैंड की पुलिस के द्वारा अनुप्रेरित थे, असम के गांवों पर कई बार हमला किया। जिन गांवों पर आक्रमण किया वे असम के दक्षिणी भाग थे जैसे नामदोर, रैनियमा, तथा दिफू। दोनों के बीच विवाद 434 किलो मी. की सीमा को लेकर हुआ। नागालैंड ने सुंदरम कमीशन की सिफारिशों को मानने से साफ इन्कार कर दिया जिसने 1925 के नियमों का समर्थन किया था। नागालैंड का कहना है कि 1925 के नियमों को न लेकर सुंदरम कमीशन को 1867 के नियमों को नजर में रखकर अपनी सिफारिशें पेश करनी थी। आज भी उक्त मसले को लेकर दोनों के बीच भारी तनाव चल रहे हैं।

इसी प्रकार असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद बढ़े तनाव की स्थिति में है। इस विवाद में अरुणाचल ने लगभग एक हजार कि. मी. की जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया है जो असम को मान्य नहीं है। दोनों प्रांतों के बीच एक और विवाद जुड़ जाने से तनाव और बढ़ गया है। यह विवाद सब-सिटी हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर है जिसे असम के लखीमपुर में प्रारम्भ करना है जबकि अरुणाचल चाहता है कि उक्त प्रोजेक्ट उनके भूखण्ड में शुरू हो। केन्द्र ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी है क्योंकि अरुणाचल ने विरोध किया था।

इसके अतिरिक्त मिजोरम की 'वृहत् मिजोरम' के निर्माण की मांग ने भी पारस्परिक सीमा विवाद को और आगे बढ़ाया है। यह भाग एम. एन. एफ. तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ मिजोरम की ओर से प्रस्तुत की गई थी। एम. एन. एफ. के सत्ता में आ जाने के बाद से मांग में ढिलाई आई है परन्तु मांग को शान्त नहीं माना जा सकता। मिजोरम के मुख्यमन्त्री यह भी जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता 'वृहद् मिजोरम' के मुद्दे को जब तब उठाने से ही बनी रह सकती है, लेकिन जब चर्चा ~~मिजोरम के निर्माण के मांग~~ ~~पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ मिजोरम~~ ~~उत्सर्ग लाभ लेकर मिजोरम के निर्माण के मांग~~ का प्रयास करते रहते हैं।

यद्यपि समस्त क्षेत्रीय दलों में एक समान दृष्टिकोण तथा विचारधारा न होते हुए भी उनको एकता के मूत्र में वधने का अच्छा अवसर मिला जिसके आधार पर यहाँ से वचित रहे उन सामों को प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध हो गये। असम तथा मिजोरम में क्षेत्रीय दल की सरकार का बन जाना तथा मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड तथा त्रिपुरा में सशक्त विरोधी क्षेत्रीय दल के होने से स्पष्ट होने लगा कि क्षेत्रीय दलों के बीच एकता तथा अखंडता बनी रहेगी। लेकिन अच्छे उद्देश्य तथा प्रोग्रामों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया में व्यवधान न आये यह भी सम्भव नहीं है। उल्लेखनीय है कि असम तथा त्रिपुरा को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर के विरोधी दलों की भूमिका शेष उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में नगण्य सी रह गई। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर के प्रान्तों में यद्यपि कांग्रेस (आई) सरकार बनाने में समर्थ तो हुई लेकिन उसने कुछ तो अन्तः पारस्परिक विरोध का लाभ उठाया और कुछ केन्द्र के सहारे जोड़ तोड़ के माध्यम से सफलता प्राप्त की। इस मत में कितनी विश्वसनीयता है, यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु व्यवस्था सिद्धान्त का व्यावहारिक पक्ष हर स्थान पर इन्हीं परिणामों को हमेशा प्रदान करता रहा है। उदाहरण के लिये मेघालय में कांग्रेस (आई) तथा ए. पी. एच. सी. एल का गठबंधन तथा नागालैंड में कांग्रेस (आई) व एन. एन. ओ के तालमेल ने सत्ता में ठहरे रहने के लिये सत्ता पक्ष को मदद दी। साथ में केन्द्र के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों को थोक में अनाप-सनाप अधिक सहायता ने भी कांग्रेस (आई) को सत्ता में ठहरे रहने में सहायता दी है। कांग्रेस (आई) की राजनीतिक चतुराई बरकरार रही कि मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल के बीच सीमा विवाद हमेशा जिन्दा रहे जिसका लाभ उसे निरन्तर मिलता रहा।

लेकिन पिछले अनुभवों ने यह बात तो क्षेत्रीय दलों को अवश्य सिखा दी है कि वे बिना कांग्रेस (आई) से गठबंधन किये बिना अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रख सकते हैं। साथ में क्षेत्रीय दलों के बीच एक उलझन परेशान किये हुए है कि पारस्परिक सीमा विवाद का विकल्प क्या है जिसके फलस्वरूप यथार्थ लाभ कांग्रेस (आई) को मिल जाता है। इस तथ्य का ज्ञान होते हुए भी सीमा विवाद के मुख्य मुद्दे का हल क्षेत्रीय नहीं निकाल पाये हैं।

सीमा विवाद—समस्त क्षेत्रीय दलों को पारस्परिक सीमा विवाद परेशान करता रहा है। जब कभी भी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल एक मंच पर एकत्रित हुए हैं तो मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश ने असम पर

सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया है। असम नागालैंड के बीच सीमा विवाद को लेकर आपस में हिंसात्मक झगड़े हुए हैं। सबसे प्रमुख झगड़ा जून, 1985 को मोरापाणी पर हुआ जब नागालैंड तथा असम की पुलिस के बीच सीमा के मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ओर से कई लोग मारे गये तथा सैकड़ों व्यक्ति हताहत हुए। इसी प्रकार 1979 में असम-नागालैंड के बीच आपसी झगड़े हुए जब नागालैंड के हथियारयुक्त नागरिकों ने, जो संभवतः नागालैंड की पुलिस के द्वारा अनुप्रेरित थे, असम के गांवों पर कई बार हमला किया। जिन गांवों पर आक्रमण किया वे असम के दक्षिणी भाग थे जैसे नामबोर, रैनिगमा, तथा दिफू। दोनों के बीच विवाद 434 किलो मी. की सीमा को लेकर हुआ। नागालैंड ने सुंदरम कमीशन की सिफारिशों को मानने से साफ इन्कार कर दिया जिसने 1925 के नियमों का समर्पण किया था। नागालैंड का कहना है कि 1925 के नियमों को न लेकर सुंदरम कमीशन को 1867 के नियमों को नजर में रखकर अपनी सिफारिशें पेश करनी थी। आज भी उक्त मसले को लेकर दोनों के बीच भारी तनाव चल रहे हैं।

इसी प्रकार असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद बड़े तनाव की स्थिति में है। इस विवाद में अरुणाचल ने लगभग एक हजार कि. मी. की जमीन पर अपने अधिकार का दावा किया है जो असम को मान्य नहीं है। दोनों प्रांतों के बीच एक और विवाद जुड़ जाने से तनाव और बढ़ गया है। वह विवाद सब-सिटी हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर है जिसे असम के लखीमपुर में प्रारम्भ करना है जबकि अरुणाचल चाहता है कि उक्त प्रोजेक्ट उनके भूखण्ड में शुरू हो। केन्द्र ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी है क्योंकि अरुणाचल ने विरोध किया था।

इसके अतिरिक्त मिजोरम की 'वृहत् मिजोरम' के निर्माण की मांग ने भी पारस्परिक सीमा विवाद को और आगे बढ़ाया है। यह भाग एम. एन. एफ. तथा पीपुल्स कॉफ़ेस ऑफ मिजोरम की ओर से प्रस्तुत की गई थी। एम. एन. एफ. के सत्ता में आ जाने के बाद से मांग में ढिलाई आई है परन्तु मांग को शान्त नहीं माना जा सकता। मिजोरम के मुख्यमंत्री यह भी जानते हैं कि उनकी लोकप्रियता 'वृहद् मिजोरम' के मुद्दे को जब तब उठाने से ही बनी रह सकती है, लेकिन जब उक्त मांग में ढिलाई आयी है तो पीपुल्स कॉन्फ़ेस ऑफ मिजोरम उसकी लाभ-लेखनीयता को देखते हुए का प्रयास करते रहते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के क्षेत्रीय दलों को अपने-अपने प्रान्तों में लोकप्रियता नहीं मिल पायेगी। यदि वे सभी असम से कोई भी समझौता करते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस (आई) भी इन प्रान्तों में असम के साथ सीमा विवाद पर समझौता करने के लिए बाध्य नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने पर उसे वहाँ के विद्यार्थी तथा युवकों को नाराज करना होगा जिसका खतरा वह मोल लेने के लिये तैयार नहीं। उल्लेखनीय है कि जब 1985 में असम-नागालैंड सीमा विवाद युद्ध हुआ था तब नागा स्टूडेंट फ़ेडरेशन ने आसाम के आक्रमण की कठोर आलोचना की थी तथा नागालैंड सरकार को उनके साहसी कार्यों के लिए बधाई दी थी।

उक्त पारस्परिक सीमा विवादों के आधार पर एक संभावना अवश्य व्यक्त की जा सकती है कि उत्तर-पूर्वी सीमा से सम्बन्धित क्षेत्रीय दलों की एकता का भाग्य अभी आशावादी नहीं है। चूंकि पारस्परिक सीमा विवाद का सम्बन्ध ऐतिहासिक है तथा आपस में बड़े हितों की पूर्ति के लिये छोटे हितों को त्यागने का ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति में एकता के सूत्र में कलहाल बंधनों की कोई उम्मीद नहीं है।

जब तक समस्त पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में व्यापकता का भाव जागृत नहीं होगा, संघर्ष निरन्तर चलते रहेगे तथा केन्द्र हमेशा लाभ की स्थिति में रहेगा।



तिब्बत और भारत

आज लगभग 28 वर्ष हो रहे हैं, दलाई लामा अपने देश को छोड़कर भारत में शरण लेने आये थे। वे स्वयं अकेले नहीं थे। उनके साथ लगभग एक लाख अनुयायी समर्थक थे जिन्होंने अपने जीवन को दलाईलामा के साथ निर्वाह करने का संकल्प किया था। ऐसा कहा जाता है कि दलाई लामा के शरण देने से चीन का रुख भारत के प्रति बदल गया था और 1962 का युद्ध उसी का परिणाम था।

इतने लम्बे अन्तराल के दौरान तिब्बत में क्या हुआ, यह एक लम्बी कहानी है जिसका जिक्र करना अधिक उचित नहीं है। केवल यह कहना ही पर्याप्त है कि माओ व चाओ के प्रशासन ने तिब्बतियों को न केवल दातनाएँ ही दीं अपितु उनके धर्म व संस्कृति पर पर्याप्त कुठाराघात किया। यद्यपि भारत में रह रहे धार्मिक नेता दलाई लामा चीन के प्रशासन से निरन्तर एक प्रार्थी के रूप में तिब्बत के स्वतन्त्रता की माँग करते रहे थे लेकिन उस दिशा में कोई सक्रिय कार्य किया गया हो या ऐसा कुछ भी दिखाई दिया। धार्मिक नेता दलाईलामा की स्वयं की भी सीमाएँ थीं जिनसे वे नैतिक दृष्टि से बंधे हुए थे। भारत सरकार ने दलाई लामा को एक लाख शरणार्थियों के साथ सभी शरण दी थी जब उनसे यह साफ कह दिया था कि वे भारत की भूमि से कोई राजनीतिक कार्यवाही नहीं करेंगे।

अमरीकी सीनेट का रुख:—6 अक्टूबर, 1987 को अमरीकी सीनेट ने एक संशोधन पारित किया जिसमें चीन के द्वारा किये गये भानवीय अधिकारों के उल्लंघन की कटु आलोचना की गई। संशोधन को सदन में पेश करने वाले सीनेटर्स थे जैसी हैल्मस ब्लाई बौन पैल। संशोधन 98-0 के मतों से पास हुआ।

न केवल आवाज उठाई अपितु हजारों की संख्या में एक प्रदर्शन किया तथा चीन के अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाये जिसके परिणामस्वरूप 5 धार्मिक कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु हो गई तथा सैकड़ों घायल हो गए। इस प्रदर्शन को हजारों विदेशियों ने अपनी आंखों से देखा और अपनी प्रतिक्रियाएँ अपने तरीके से विश्व में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त कीं।

यद्यपि 1980 से चीन की तिब्बत के प्रति नीति में परिवर्तन दिखाई दिया है। माओ और चाओ के अन्यायपूर्ण प्रशासन को नये नेतृत्व ने उदार-पूर्वक स्वीकार भी किया है। अतीत में जो कुछ भी तिब्बत के धार्मिक लोगों पर कठोरता से व्यवहार हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हजारों रुपये तिब्बत में नष्ट हुए मठों के पुनर्निर्माण के लिए खर्च किये जा चुके हैं। तिब्बत के विकास के लिए चीन का नया नेतृत्व बहुत कुछ कर रहा है। चीन के अधिकांश वर्ग को तिब्बती भाषा सीखने के लिए आवश्यक कर दिया है।

पिछले माह चीन की सरकार ने मिलियन डालर तिब्बत के आर्थिक विकास के लिए स्वीकृत किये हैं। तिब्बत को निःसंदेह नई नीतियों से लाभ हुआ है। तिब्बत में 6000 नष्ट हुए मठों का निर्माण ढोना शुभ चिन्ह अवश्य है लेकिन तिब्बती संस्कृति तथा धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। शायद चीन की नई व उदार नीति ने धार्मिक तिब्बतियों को बार फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया

एक अमरीकी बकीस का कहना था कि पारित किया गया बिल यदि राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे दें तो यह राष्ट्र का कानन बन जायेगा। यदि अनुमति नहीं देते हैं तो एक बार फिर ॥ संयुक्त रूप से दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा। यदि दूसरी मुनवार्ड में दोनों सदनों में स्वीकृति दे दी तो राष्ट्रपति की अनुमति न भी हो तो भी यह विधेयक कानून हो जायेगा। विधेयक का सार निम्न रूप से रखा जा सकता है—

(i) अमरीका के चीन से सम्बन्ध का स्वरूप अब इस प्रकार का होगा जो तिब्बती लोगों के साथ व्यवहार का निर्धारण करेगा।

(ii) राष्ट्रपति को दलाई लामा से मिलकर तिब्बतीवासियों की समस्या को शान्तिपूर्वक हल करने में प्रयत्न करने होंगे।

(iii) अमरीका को चीन से यह आग्रह करना चाहिए कि यह दलाई लामा के साथ बात करे तथा तिब्बत के बारे में भावी दर्जा क्या हो उसके सिलसिले में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप करे।

(iv) अमरीका राज्य सचिव के जरिये तिब्बती लोगों के अधिकारों तथा उनके अस्तित्व के बारे में ध्यान आकषिप्त करे। तिब्बती धर्म तथा संस्कृति को रक्षा के लिए भी प्रयास किया जाये।

(v) कांग्रेस का प्रतिनिधि मण्डल तिब्बत जाकर (खयाल और आमदो भी) यह जानकारी प्राप्त करे कि तिब्बतियों की वास्तविक समस्या क्या है और उसका कंसे समाधान हो सकता है।

(vi) राष्ट्रपति चीन में नियुक्त राजदूत को निर्देश दे कि वे भारत के साथ मिलकर किस प्रकार समस्या का विकल्प ढूँढ़ सकते हैं।

यद्यपि अमरीकी सीनेट ने विधेयक के संशोधन के माध्यम से न केवल चीन की आलोचना की है अपितु तिब्बत के दर्जे को ऊँचा करने के लिए प्रयास की दिशा भी सन्निहित है। परन्तु कूटनीतिज्ञों की दृष्टि भी विचित्र ही होती है जिनका यह कहना है कि अमरीकी सीनेट ने चीन की आलोचना चीन की सहमति से की है। विश्व राजनीति में कोई भी बात किस आवरण में कही जाती है इसको भी पढ़ लेना एक ठोस पक्ष है।

एक ओर सीनेट के सदस्य बहुमत से तिब्बती लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और दूसरी ओर सरकारी बयानों में चीन के प्रति वही दृष्टिकोण है जो अमरीका के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है।

हाल ही में 27 सित., 87 को 1959 के बाद पहली बार तिब्बत के सीमा तथा धार्मिक नेताओं ने त्हासा में अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए

न केवल आवाज उठाई अपितु हजारों की संख्या में एक प्रदर्शन किया तथा चीन के अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाये जिसके परिणामस्वरूप 5 धार्मिक कार्यकर्त्ताओं की मृत्यु हो गई तथा सैकड़ों घायल हो गए। इस प्रदर्शन को हजारों विदेशियों ने अपनी आंखों से देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं अपने तरीके से विश्व में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त कीं।

यद्यपि 1980 से चीन की तिब्बत के प्रति नीति में परिवर्तन दिखाई दिया है। माओ और चाओ के अन्यायपूर्ण प्रशासन को नये नेतृत्व ने उदार-पूर्वक स्वीकार भी किया है। अतीत में जो कुछ भी तिब्बत के धार्मिक लोगों पर कठोरता से व्यवहार हुआ उसकी क्षति पूर्ति के लिए हजारों रुपये तिब्बत में नष्ट हुए मठों के पुनर्निर्माण के लिए खर्च किये जा चुके हैं। तिब्बत के विकास के लिए चीन का नया नेतृत्व बहुत कुछ कर रहा है। चीन के अधिकांश वर्ग को तिब्बती भाषा सीखने के लिए आवश्यक कर दिया है।

पिछले माह चीन की सरकार ने मिलियन डालर तिब्बत के आर्थिक विकास के लिए स्वीकृत किये हैं। तिब्बत को निःसंदेह नई नीतियों से लाभ हुआ है। तिब्बत में 6000 नष्ट हुए मठों का निर्माण होना शुभ चिन्ह अवश्य है लेकिन तिब्बती संस्कृति तथा धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। शायद चीन की नई व उदार नीति ने धार्मिक तिब्बतियों को एक बार फिर से विद्रोह का झंडा खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। चीन की 'सांस्कृतिक क्रांति' (1966-76) ने तिब्बत के संपूर्ण समाज को बदल देने का अभियान शुरू किया था। लेकिन डेंग के नये नेतृत्व ने बुनियादी आदर्शों को ध्यान में रखकर पुरानी नीतियों में परिवर्तन किया। डेंग तथा नई पीढ़ी के नये प्रशासक यह अच्छी तरह जानते हैं किसी भी धर्म या संस्कृति को लौकिक दृष्टि से नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। 28 वर्ष की दबी हुई भावनाएं 27 सित., 87 को फिर से उठकर सामने आईं। यह इसका ज्वलंत उदाहरण है।

विश्व की राजनीति

तिब्बत की समस्या को विश्व राजनीति के परिधि में रखकर ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। विश्व के सभी बड़े देश दबी या खुली जवान से धार्मिक नेता दलाई लामा का समर्थन करते हैं परन्तु उनको वास्तविक अधिकार दिलाने में सभी राष्ट्रों की धिक्कता है। यदि हम अपने प्यार से ही

चनें अर्थात् भारत सरकार की नीति को ही ध्यान से देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत चाहते हुए भी तिब्बत को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का समर्थन नहीं दे सकता। उसकी विवशता यही है कि 1950 में भारत सरकार तिब्बत को चीन का अंग मान चुका है। अपने दिये हुए अभिव्यक्तियों को आज के सन्दर्भ में बदलने का साहस नहीं। भारत चीन के साथ संबंध बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। अमरीका-चीन की समीकरण भी तिब्बत के भविष्य के लिए कर्म के दृष्टिकोण से कुछ नहीं कर सकता। अमरीका की विदेश नीति के अन्तर्गत केवल तिब्बतियों के लिए सहानुभूति ही शेष है। 27 सितम्बर, 87 को ल्हासा में जो कुछ हुआ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में अमरीका के समाचार पत्रों ने चीन की आलोचना की है तथा तिब्बती लोगों के प्रति सहानुभूति के शब्दों का प्रयोग किया है परन्तु इस दिशा में करने के नाम कुछ नहीं दिखाई देता। कहने का अर्थ यही है कि बड़े देशों की राजनीति में तिब्बतियों की ओर से यू. एन. ओ. में कोई खोलने वाला नहीं।

सामान्य दृष्टि से तिब्बत की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिये तत्कालीन राजनीतिज्ञ तथा निर्णयकर्ताओं को दोषी ठहराया जाता है। दोषी ठहराना आसान है लेकिन उसके लिए न्याययुक्त पक्षों को ढूँढना अधिक मुश्किल है। तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो लगता है कि ऐसा होना अनिवार्य बुराई थी लेकिन स्मगित कर पाना आसान नहीं थी। नेहरू-पटेल के समीकरण को गौर से देखें तो तस्वीर स्पष्ट होती है कि नेहरूजी की परिधि में जो मामले थे वे एक मात्र निर्णयकर्ता थे और उनके दृष्टिकोण और दूरदर्शिता को आज के सन्दर्भ में टीका-टिप्पणी की जा सकती है लेकिन 'विवशता' को भी प्रशंसन के अन्तर्गत स्थान देना होगा। भारत की समग्र पर्वतीय राज्यों के प्रति नीतियाँ भी कुछ इस प्रकार की थीं जिनका हल या समाधान राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देता। आज भारत का तिब्बत के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विदेश नीति का अंग भी है और साथ में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के अनिवार्य भी उचित व अनुचित का निर्णय किसी न किसी व्यवस्था से जोड़कर ही कर सकते हैं। जो नैतिकता की दृष्टि से ठीक लगता है वह राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से उचित न हो। गांधीजी को कभी कभी इस सन्दर्भ में जोड़ दिया जाता है और उनके कहे हुए वाक्यों को अधिकांश उद्धृत कर देते हैं जो नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं वह राजनीतिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता। गांधीजी के कुछ आदर्श व्यवस्था से स्वतन्त्र

अस्तित्व रखने वाले हैं इसलिए यह आम बात कह दी जाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को संतुलन में रखने के लिये राजनीतिक दृष्टि ही अनिवार्य हो जाती है। 1947 के बाद से प्रशासकों पर चारों ओर से कितने दबाव थे, इसकी भी कल्पना करना जरूरी है। निर्णय देने से पहले समग्र दृष्टि का होना भी अति आवश्यक है।

‘तिब्बत’ के प्रति भारत सरकार आज सहानुभूति रख सकती है परन्तु चीन के सन्दर्भ में यह स्पष्ट नहीं कह सकती कि ‘तिब्बत’ एक स्वतन्त्र प्रदेश है। तिब्बत के लोग ही अपने तरीके से ही चीन से अपनी मांगें मनवाने में सक्षम होंगे। यह बात दूसरी है कि तिब्बतियों की अपने संघर्ष की शैली क्या होगी। अपने अस्तित्व को फिर से ऊपर साने के लिए तिब्बती लोग स्वयं प्रयास करेंगे। कोई बाहरी हस्तक्षेप अधिक स्थायी नहीं हो सकता। बंगला देश की स्वतन्त्रता में अधिकांश क्रम वहाँ के निवासियों का है जिन्होंने संघर्ष का जिहाद छेड़ दिया था, भारत तो केवल निमित्त मात्र था। यदि बंगालियों ने कटिबद्ध होकर संघर्ष का अभियान अपने हाथ में नहीं लिया होता तो भारत भी कुछ नहीं कर सकता था। तिब्बत के धार्मिक लोग बौद्ध धर्म के बुनियादी आदर्श का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सहिष्णुता या अहिंसा का अर्थ आज के सन्दर्भ में कभी भी नहीं होता कि वे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलन्द न करें। संघर्ष की शैली उन्हें स्वयं ढूँढनी होगी। तभी स्वतन्त्र तिब्बत का स्वप्न साकार हो सकता है।

निष्कर्ष

पिछले समस्त निबंधों में प्रयास किया गया है कि पर्वतीय राज्यों में भूटान के ऐतिहासिक अनुभव तथा राजनीतिक यथार्थ ने उसे वर्षों बाद आश्वस्त किया कि उसकी सीमा से जुड़े पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति ने उसे अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को उठाने में अधिक मदद नहीं दी। नेपाल तथा सिक्किम अपने राष्ट्रीय स्तर को ऊपर साने में सतत प्रयत्नशील रहे तथा भूटान के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव रखा। यही नहीं भारत की सीमा से जुड़े हिमालयी क्षेत्रों की भी अपने हितों में संलग्न अपनी राजनीति में बराबर चलती रही। भूटान का नेपाल तथा सिक्किम से अपेक्षाकृत पिछड़ापन भी इसी राजनीति का परिणाम था। उल्लेखनीय है कि सिक्किम में आर्थिक विकास का क्रम भूटान की तुलना में कई वर्ष पहले प्रारम्भ हो गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही सिक्किम के चोगियाल (राजा) ने भारत सरकार से निरन्तर यही मांग की थी कि ‘सिक्किम को भूटान के बराबर दर्जा प्रदान किया जाय’। यह बात दूसरी है कि उसका परिणाम किस ओर मुड़ गया। दूसरे शब्दों में समस्त पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति मात्र अपने हितों की पूर्ति करने तक सीमित रह गया था। भारत सरकार की नीति क्या

थी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व की बात यह है कि तीनों पर्वतीय राज्यों ने पारस्परिक हितों की पूर्ति के लिये एकता के सूत्र में बंधकर कभी भी ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे भारत पर सामूहिक रूप से एक दबाव पड़ता। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में एकता का भाव कभी जागृत ही नहीं हो पाया जिसके परिणाम स्वरूप भूटान उस राजनीति से अनभिज्ञ रहा जिसका उस पर निरन्तर प्रभाव रहा।

इसी प्रकार भारत से लगे हुए उत्तर-पूर्वी सीमा के पर्वतीय क्षेत्रों के बीच पारस्परिक समझ न होने के कारण पूर्वांचल के दल में दरार पड़ गई और एकता के प्रयास विफल हो गये। उत्तर-पूर्वी सीमा के पर्वतीय स्थानों पर रहने वाले के व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों में भिन्नता होने के कारण उन लोगों में एकता का भाव जागृत होते-होते टूट जाता है। कभी आर्थिक हितों को लेकर तो कभी सीमा विवाद को लेकर संघर्ष लगातार होते रहते हैं जिसमें व्यक्तियों की जानें भी चली जाती हैं। कहने का अर्थ यही है कि पर्वतीय क्षेत्र, चाहे भारत की सीमा में हों या उसके बाहर, उसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है जिसके कारण बाहर तथा अन्दर के पर्वतीय स्थानों पर रहने वाले लोगों में एकीकरण की भावना का अंकुर फूट ही नहीं पाया है। अपनी-अपनी समस्याओं से इस प्रकार से उलझ गये हैं कि उनमें आपसी एकता का निर्माण होना सम्भव नहीं लगता। मोरखालैंड की समस्या अपने किस्म की अलग ही उभर कर आई है जिसमें नेपालियों ने विभिन्न स्थानों पर वसे नेपालियों को आह्वान किया है कि व्यवस्था उनके साथ वषों से अन्याय व अन्याचार करती आ रही है जिसके विरुद्ध कटिबद्ध होकर विरोध करना है। भूटान में वसे नेपालियों ने राजतन्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध 1950 से ही आन्दोलन कर रहा है। सिक्किम के अन्तिम भविष्य का निर्णय भी वहाँ के नेपालियों ने ही किया था। यह कहना पर्याप्त होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों की एक दूसरे से गुथी राजनीति ने भूटान को यदा कदा भयभीत तथा सशंकित किया है। भूटान को बाहरी राजनीति ने उसे हमेशा भय तथा शंका की स्थिति में रखा जिसके परिणाम स्वरूप भूटान ने बाहरी देशों से अपने आप को अलग पलग रखा। भूटान पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित रहा। 1975 में सिक्किम की ऐतिहासिक घटना ने उसकी आँखें खोल दी और तब से ही भूटान अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाने में भरसक प्रयत्न करता रहा है। आज तो भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार से स्पष्ट लगने लगा है कि भूटान निसंदेह भारत के सशक्त प्रभाव से लगभग बाहर निकल चुका है। ऐसा हर उठते हुए देश के साथ होता है—भूटान कोई अपवाद नहीं है।

है। भूटान को बाहरी राजनीति ने उसे हमेशा भय तथा शंका की स्थिति में रखा जिसके परिणाम स्वरूप भूटान ने बाहरी देशों से अपने आप को अलग घलग रखा। भूटान पर्वतीय क्षेत्रों की राजनीति से अत्यधिक प्रभावित रहा। 1975 में सिक्किम की ऐतिहासिक घटना ने उसकी आँखें खोल दी और तब से ही भूटान अपने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ऊँचा उठाने में भरसक प्रयत्न करता रहा है। आज तो भूटान के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार से स्पष्ट लगने लगा है कि भूटान निसंदेह भारत के सशक्त प्रभाव से लगभग बाहर निकल चुका है। ऐसा हर उठने हुए देश के साथ होता है—भूटान कोई अपवाद नहीं है।



परिशिष्ट 1.

गोरखालड समस्या से सम्बन्धित प्रकाशित समाचारों के कुछ अंश (सभी प्रकाशित अंश विभिन्न समाचार पत्रों से लिये गये हैं। इसमें प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र हैं—टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्स-मैन, इण्डियन एक्सप्रेस, पेंद्रिमट आदि।)

पश्चिमी बंगाल उन छपे हुए पत्रों को पढ़कर अधिक चिन्तित है जिसमें 'गोरखालैंड' की मांग को जिस भाषा में छापा है। पत्रों अंग्रेजी में छपे हैं और अंग्रेजी भाषा भी उच्चस्तरीय है जिसको पढ़कर संदेह होता है कि इतनी उच्चस्तरीय भाषा नेपाली आन्दोलनकारियों की नहीं हो सकती। यह भाषा या तो दिल्ली में तैयार हुई है या उन पढ़े-लिखे ईसाइयों के द्वारा तैयार की गई है जो प्रारम्भ से ही गोरखालैंड की मांग का समर्थन करते रहे हैं। पश्चिमी बंगाल प्रशासन को यह भालूम करना है कि उक्त पत्र कहां से छपे हैं उससे संदेह का समाधान हो पायेगा।

एक प्रकार के पत्रों का शीर्षक 'गोरखा डायरी' है जिसमें लिखा है कि गोरखा नेपालियों का किस प्रकार केन्द्रीय सरकार व पश्चिमी बंगाल सरकार शोषण करती रही है। पत्रों में यह भी लिखा हुआ है कि सरकार गोरखा सैनिकों को उत्तर-पूर्वी सीमा पर आन्दोलनों को दबाने व कुचलने के लिए प्रयोग करती है जिसके परिणामस्वरूप गोरखा सैनिकों के दिल में घृणा पैदा हो गई है। यही नहीं सम्पूर्ण क्षेत्र में गोरखा नागरिकों के लिए जीवन मुश्किल हो गया है।

पत्रों में आगे लिखा है "क्या यही तरीका है गोरखाओं के साथ बर्ताव करने का?"

उक्त पत्रों के जवाब में पश्चिमी बंगाल सरकार ने अंग्रेजी व नेपाली भाषा में पत्र छापने और गोरखा लोगों के बीच बाटने की योजना बनाई है जिससे वे लोग समझ सकें कि वाभपंथी सरकार ने अब तक उनके लिए क्या किया है ?

(2) प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री नर-बहादुर भंडारी को पूर्ण आश्वस्त किया कि उन्होंने उन निराधार आरोपों

पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जो भंडारी पर यह कहकर लगाये गये हैं कि वो GNLF के आन्दोलन को बढ़ाने के लिए सहायता दे रहे हैं।

जिस समय भंडारी प्रधानमंत्री से मिले उस समय वे बड़े उत्तेजित थे और उसी उत्तेजना के भाव से और देकर कहा कि प्रधानमंत्री शुरुत एक जांच समिति बैठायें और फंसला करें कि उक्त आरोपों में कुछ सत्यता है कि नहीं।

मुख्यमंत्री भंडारी ने पश्चिमी बंगाल के एक CPM सांसद के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनके सिलाफ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया है कि सिक्किम में ऐम् केम्पों का आयोजन किया है जिससे GNLF के आन्दोलन को और भी बढ़काने की योजना बनाई गई है। क्या सिक्किम में ऐसी कोई Central Agency नहीं है जो इस बात का ध्यान रखे कि सिक्किम में क्या हो रहा है?

पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री भंडारी जी ने कहा कि "हमको दार्जिलिंग नहीं चाहिए। हम उसको प्राप्त करने की क्यों इच्छा करें? सिक्किम की जनसंख्या 3 लाख है और दार्जिलिंग की 14 लाख। हम भारत में मिल गये, लेकिन दार्जिलिंग में मिल जाने का अर्थ होगा हमारा अस्तित्व लगभग समाप्त।"

भंडारी ने आगे कहा, "सिक्किम भारत का अंग है और एक पूर्ण राज्य है। दार्जिलिंग में शामिल होकर वे एक जिसे का भाग नहीं बनना चाहेंगे। क्या मुझे राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं करनी है?"

भंडारी ने अपनी बातचीत में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी दो महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार करने के लिए आश्वासन दे दिया है। पहली मांग तो 30,000 नेपाली निवासियों की है जिनको कानूनी नागरिकता प्राप्त नहीं है और दूसरी नेपाली बोलने वाले लोगों के लिए विधानसभा में सीट का आरक्षण। भंडारी ने कहा कि उक्त दोनों ही मांगें शीघ्र ही स्वीकार कर ली जायेंगी।

(3) पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि 'बोरबासैड' का आन्दोलन जल्दी समाप्त होने वाला नहीं। आन्दोलन की छुटपुट घटनाओं से यह स्पष्ट बाहिर है कि GNLF घन व हथियारों के आधार पर एक लम्बी अवधि तक आन्दोलन चलायेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे आन्दोलन के लिए सतर्कता से निबटा जाए और उसके लिए तैयारी भी की जाय।

पत्रकारों से बात करते हुए ज्योति बसु ने कहा कि GNLF के आन्दोलन के लिए घन कहीं से आ रहा है, यह तो नहीं कहा जा सकता

लेकिन उनका धींशिंग से मिलने का कोई इरादा नहीं है जो 'राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियों' में जुटे हुए हैं और बाहरी शक्तियों से अपने आन्दोलन के लिए सहायता ले रहे हैं।

ज्योति बसु ने दार्जिलिंग की घटनाओं के बारे में केन्द्र को सूचना दे दी है और GNLFF के आन्दोलन से निवटने के लिए अतिरिक्त पुलिस की सहायता मांगी है।

श्री बसु ने अपनी पार्टी (CPM) की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि दार्जिलिंग को 'स्थानीय स्वायत्तता' प्रदान कर देनी चाहिये। चूंकि गोरखा लोग कबौले (Tribals) नहीं हैं इसलिए संविधान में उसी के अनुसार संशोधन होता चाहिए। श्री बसु ने यह भी कहा कि संविधान में 8वीं धारा में नेपालियों के लिये नेपाली भाषा को सम्मिलित कर लेना चाहिए।

मुख्यमंत्री बसु ने प्रेस से भी यह अनुरोध किया कि वह इस प्रकार के समाचार प्रकाशित न करें जिससे राज्य में अकारण उपद्रव हो और लोगों में आग भड़के।

(4) दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में एक नये प्रकार का विद्रोह-उठ खड़ा हुआ है। वहाँ के ठेकेदारों ने जिला प्रशासकों को एक नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि स्थानीय समस्त ठेकेदार 9 सितम्बर, 1986 से रास्ता रोकों 'आन्दोलन' प्रारम्भ कर देंगे यदि उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया।

विरुद्ध सूचनाओं के आधार पर यह कहा गया कि ठेकेदारों को भुगतान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इंजिनियर्स हड़ताल पर चले गए थे जो बिलों का असली भुगतान करते थे।

(5) 13 सित०, 1986 'GNLFF' के आंदोलनकारी नेताओं ने अध्यात्म (बिना किसी धोषणा के) 'टिबर रोको' आंदोलन शुरू कर दिया और GNLFF के अध्यक्ष सुभाष धींशिंग ने कहा कि 'टिबर रोको' कदम उनके आंदोलन का एक हिस्सा है। धींशिंग का कहना था कि वे मंदानी लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में व्यापार नहीं करने देंगे और न पहाड़ी लोगों का शोषण बर्दाश्त करेंगे। धींशिंग ने आगे कहा कि वर्षों से भ्रष्ट मंदानी व्यापारियों ने दार्जिलिंग तथा जलपायगुड़ी के जंगलों का गन्तव्य तरीके से शोषण किया जिसे भविष्य में नहीं होने देंगे। 'टिबर रोको' आंदोलनकारी नेताओं ने टिबर से भरे ट्रक को खाली करवा लिया।

उक्त आंदोलन के परिणामस्वरूप दार्जिलिंग घाटी के पर्यटक होटल श्री 'पूजा-मोसम' में भरे रहते थे, वे इस समय लगभग खाली हैं।

(6) दार्जिलिंग, कलिंगपोंग तथा कुरसोंग (Kurseong) में जीवन अस्तव्यस्त रहा। एकदिन पहले सी० पी० एम० के कार्यकर्ताओं ने GNLF के आन्दोलनकारियों पर हिंसात्मक कार्यवाही की, उसके फलस्वरूप पहाड़ी क्षेत्रों में काम-काज ठप्प रहा।

घटनाओं के सिलसिले में एक नया मोड़ दिखाई दिया वह यह कि लैप्चा नेपालियों के लोगों ने 'गोरखालैंड' की मांग का विरोध करने का निश्चय किया। लैप्चा नेपालियों का कहना है कि वे दार्जिलिंग के मूलनिवासी हैं और वे नहीं चाहते कि दार्जिलिंग को पश्चिमी बंगाल से अलग कर दिया जाय। इस घटनाचक्र के मोड़ ने साम्प्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। इस प्रकार का तनाव कलिंगपोंग में भी घटित होने की संभावना है क्योंकि कलिंगपोंग में लैप्चा नेपाली अधिक संख्या में हैं। लैप्चा नेपालियों के एक प्रतिक्रियारमक कार्यवाही से सिक्किम के लैप्चा नेपालियों पर प्रभाव पड़ने का आशा है।

(7) पश्चिमी बंगाल कांग्रेस विधायक दल की कमेटी-दो घटे विमर्श करने के बाद भी यह निर्णय नहीं कर पाई कि क्या 'गोरखालैंड' की मांग की आलोचना करनी चाहिये जब कि वे भी जानते हैं कि इस प्रकार की मांग राष्ट्र-विरोधी है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रान्तीय विधान में रखा जा चुका है। कांग्रेस विधायक दल ने इसलिए भी अभी आलोचना नहीं की है क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बयान में यह स्पष्ट कहा था कि गोरखालैंड की मांग किसी भी प्रकार से राष्ट्रविरोधी नहीं है। परन्तु कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रियरंजनदास मुंशी ने उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिये जो 'गोरखालैंड' आन्दोलन को राष्ट्रविरोधी घोषित कर रहा था। श्री दास मुंशी के हस्ताक्षर करने में अन्य कांग्रेसी विधायकों ने उनको बाड़े हाथ लिया और कहा कि उन्होंने प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर बिना केन्द्र के संकेत प्राप्त किए क्यों किये।

मुंशी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने उन विधायकों को किसी प्रकार से गुमराह नहीं किया है। अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 'गोरखालैंड' की समस्या के बारे में श्री अर्जुनसिंह से खुलासा बात कर ली थी तथा श्री बृट्टासिंह ने भी उन्हें सर्वदलीय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए अनुमति दे दी थी। श्री दास मुंशी ने आगे यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राय तथा संभावित बयानों के बारे में

पूर्णतया अनभिज्ञ थे। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य अतिथि श्री सुप्रत मुखर्जी श्री मुंशी ने अधिक आलोचक सगे।

श्री दास मुंशी ने अपनी राय को दुहराते हुए पुनः वही बात कही कि 'GNLF' का आन्दोलन राष्ट्र विरोधी है। यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री की राय उससे विपरीत है। दास मुंशी ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें पहले ही पमकी मिल चुकी है कि अगले चुनाव में कांग्रेस सीट नहीं मिलेगी।

(7) गोरखालैंड से आन्दोलन के बारे में निम्न विभिन्न संदेह प्रकाशित किए गये।

1. गोरखालैंड की मांग के पीछे बाहरी शक्तियों का हाथ है विशेष रूप से चीन।
2. सुभाष घोषिंग ने अपनी मांग को पूरा होने के लिए चीन, नेपाल पाकिस्तान पत्र भेजे हैं। यहाँ तक संदेह है कि उसने पत्र हंगलैंड तथा अमरीका भी भेजे हैं जो राष्ट्रविरोधी हरकत है।
3. ऐसा अनुमान है कि गोरखा आन्दोलन का लाभ नेपाल के उठता हुआ बुजुर्ग वर्ग ले रहा है। नेपाल का उठता हुआ बुजुर्ग वर्ग गोरखा आन्दोलन का प्रयोग इसलिये भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भारतीय व्यापारी वर्ग जिसने बाजार को पूर्णतया नियंत्रण कर रखा है उनके सामने कमजोर पड़ते हैं।
4. नेपाली, बुजुर्ग वर्ग तथा भारतीय बुजुर्ग वर्ग में एक निरन्तर संघर्ष है।

(8) सुभाष घोषिंग गोरखालैंड के आन्दोलन की निरन्तर रूप से चलाने में अब असमर्थ पाते हैं। उनके नेतृत्व की शक्ति धीरे-धीरे कम होती जा रही है। अपने सशक्त समर्थकों पर नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। आन्दोलन के समर्थकों के बीच संघर्ष पैदा हो गया है जिसके फलस्वरूप लोग दो भागों में विभाजित हो गये हैं। एक ओर उपवादी नेता जिनकी मात्र एक ही मांग है कि 'गोरखालैंड' एक अलग से प्रान्त हो और केन्द्र से सम्बन्धित करने को तैयार नहीं। दूसरी ओर घोषिंग के समर्थक हैं जो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, केन्द्र से किसी ठोस हल की तलाश में हैं वे उपवादी समर्थक जिनका अत्यधिक प्रभाव कलिंगपोंग, मिरिक (Mirick) तथा अन्य स्थानों पर अधिक है। घोषिंग ने सार्वजनिक बयानों में यह स्वीकार किया

है कि वे अपना प्रभाव धीरे-धीरे खी रहे हैं। उग्रवादियों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र का दायरा सिलीगुड़ी तथा अन्य द्वारों तक बढ़ाना है। उनकी यह धारणा है कि अपनी मार्गों की पूर्ति के लिए एक ही रास्ता है वह यह कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानी है।

(9) सुभाष घोषिंग के अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण नेता है जिनमें से कुछ तो निरन्तर आन्दोलन में सक्रिय हैं और कुछ उसमें से मारे गये।

आर. पी. बघवा, सी. के. प्रधान, छितेन शेरपा, (छात्र सभा), एन. डी. मौकतन, के. बी. राय, निर्मल खालिग, बी. बी. गुरंग तथा रत्नकुमार प्रधान, महिलाओं में श्रीमती इन्द्रकला प्रधान जो अब तक फरार है। आर. पी. बघवा (रामप्रसाद बघवा) को सभी आक्रमणों के पीछे मास्टर माइंड कहा जाता है सीक्योरिटी फोर्स, पर जितने भी आक्रमण हुए उसमें श्री बघवा की सक्रिय भूमिका रही। बघवा इस समय नेपाल में बताये जाते हैं। बघवा अवकाश प्राप्त नेवी आफीसर रह चुके हैं जो 1930 में थे। 1982 तथा 1986 के बीच दो बार गिरफ्तार भी किये गये जो कि 'चुनाव बहिष्कार' का मामला था। लेकिन दोनों बार उनको रिहा कर दिया गया। औपचारिक दृष्टि से इन्हें गोरखा आन्दोलन फ्रन्ट से निकाल दिया गया है। 9 फरवरी, 1987 को मिदिक पुलिस स्टेशन तथा आर्मरी पर आक्रमण करने का दोषी बघवा को ठहराया गया था। तीन सुरक्षा सैनिकों की हत्या के दोषी भी बघवा हैं जिनकी पुलिस को तलाश है।

ऐसा कहा जाता है कि बघवा गुरिल्ला ट्रेनिंग कैम्प का संचालन कर रहे हैं जिसका केन्द्र नेपाल के इस्लाम तथा लातरा के जिले में है। बघवा श्री हांडा (डी. आई. जी) पर आक्रमण करने के दोषी ठहराये गये थे।

उक्त घटनाओं के बाद घोषिंग ने घोषणा की कि बघवा अकेले ही काम कर रहे हैं तथा बघवा का हांडा पर आक्रमण सिर्फ व्यक्तिगत मतभेदों का परिणाम था और इनका आन्दोलन से कोई संबंध नहीं है।

सी. के. प्रधान आन्दोलन से संबंधित कलिगपोंग इकाई के संयोजक कहे जाते हैं। लगभग 35 वर्ष की उम्र है तथा उनको कोपरेटिव बैंक से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने धन का गैरकानूनी दुरुपयोग किया था। प्रधान एक अच्छे वक्ता है तथा अपने भाषण के माध्यम से भीड़ को अपने समर्थन में बहा ले जाने की क्षमता है। प्रधान अपने साथ हमेशा कुछ अंगरक्षक भी रखते हैं जिनमें चार महिलाएं भी हैं। कलिगपोंग के मेलाप्राउण्ड पर प्रधान ने ही भीड़ का नेतृत्व किया था जहाँ भारत-नेपाल

संघि (1950) को जवाने का आह्वान था। यह प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हो गया था जिसने पुलिस कर्मचारियों पर प्रहार भी किया था। यहाँ पुलिस फाईरिंग से 18 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई थी जिसमें आधी महिलाएँ थीं। इस प्रदर्शन में एक पुलिस जवान की मृत्यु हो गई थी तथा कमाल मजमूदार (डी. आई. जी. सी. आई. डी.) गंभीर रूप से घायल हो गये थे। कहा जाता है कि इस समय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी (सिविल) में हैं और वहाँ से अपनी रणनीति का संचालन कर रहे हैं।

छिन्नेन गोरपा लगभग 40 वर्षों से ऊपर हैं और नागालैंड के निवासी हैं। गोरपा नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री के अंगरसक भी रह चुके हैं। गोरपा को भी श्री हाडा (डी. आई. जी.) पर आक्रमण करने का दोषी ठहराया गया है।

बी. बी. गुरंग लगभग 50 से ऊपर हैं। एक कुशल पैराट्रॉपर हैं जिन्होंने बर्मा युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुरंग एक नाटकीय तरीके से कवि का आवरण लिए (1947) माइकल मधुमदन के रूप में अपने आपको दूसरों के सामने प्रस्तुत करते रहे। इसके बाद गुरंग पूर्वी पाकिस्तान चले गये। बाद में एक तिब्बती महिला के साथ शादी कर तिब्बत में रहे। तिब्बत के बाद भारत में पुनः प्रकट हुए। गुरंग एक प्राइवेट इन्श्योरेंस कम्पनी में फील्ड-एजेंट रहे और तब तक काम करते रहे जब तक 1985 में गोरखा आन्दोलन में शामिल नहीं हो गये।

इन्द्रकला प्रधान (35 वर्ष) जो अभी फरार हैं। ये टरबुल बाँइज हाई स्कूल में अध्यापन का काम कर चुकी हैं। गोरखा आन्दोलन की सचिव हैं तथा रुद्र कुमार प्रधान की पत्नी हैं।

□□

सिचुला की सन्धि, 1865

अनुच्छेद 1—ब्रिटिश सरकार और भूटान सरकार के मध्य में अब से चिरस्थायी शान्ति और मित्रता रहेगी ।

अनुच्छेद 2—क्योंकि भूटान सरकार ने बारम्बार आक्रमण किए और बदले में हुरजाना देने से इन्कार कर दिया; और क्योंकि सपरिपद् महामहिम गवर्नर जनरल ने जिन अधिकारियों को दोनों राज्यों के मध्य वर्तमान मतभेदों का सौहार्दपूर्ण समायोजन प्राप्त करने के प्रयोजन से भेजा था, उनके साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया । अतः ब्रिटिश सरकार सशस्त्र सेना की सहायता से सम्पूर्ण बंगाल दुअस-क्षेत्र और भूटान में प्रवेश करने वाले दरों की रक्षक कुछेह पहाड़ी चौकियों को जीत लेने के लिए विवश हो गई और चूंकि अब भूटान सरकार ने अपने पिछले दुराचरण पर भेद प्रकट किया है तथा ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है, अतः एतद् द्वारा यह तय किया जाता है कि रंगपुर-तिला, कूचबिहार और असम की सीमा से लगा हुआ वह सम्पूर्ण इलाका जो अठारह-दुअस के नाम से प्रसिद्ध है तथा उसके साथ-साथ अम्बारी फालकोटा तास्तुका एवं सीस्ता नदी के बांये तट पर स्थित पर्वतीय प्रदेश भूटान सरकार द्वारा चिरकाल के लिए ब्रिटिश सरकार को अर्पित किया जाता है । सीस्ता नदी के बांये तट का पर्वतीय प्रदेश तथा अम्बारी फालकोटा तानुबका उस सीमा तक ही दिया जायेगा जो कि इसी काम के लिए नियुक्त किए गए ब्रिटिश आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

अनुच्छेद 3—भूटान सरकार इस सन्धि द्वारा यह स्वीकार करती है कि वह उन तमाम ब्रिटिश नागरिकों तथा उनके साथ-साथ सिविकम् व कूचबिहार के सरदारों के उन नागरिकों को भी समर्पित कर देगी जो कि इस समय भूटान में अपनी इच्छा के विरुद्ध हैं; और वह इससे भी सहमत है कि ऐसे समस्त व्यक्तियों या किसी भी व्यक्ति की ब्रिटिश प्रदेश में वापसी के दौरान उनकी राह में कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी ।

अनुच्छेद 4—भूटान सरकार ने इस सन्धि के अनुच्छेद 2 में जिन प्रदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उनका अर्पण कर दिया है, किः उसने अपने भूतकालीन दुराचरण पर खेद प्रकट किया है, कि वह एतद् द्वारा भविष्य के लिए वचनबद्ध हो गई है कि सभी दुराशयी व्यक्तियों को ब्रिटिश

प्रदेश में, तथा सिक्किम या कूचबिहार के राजाओं के प्रदेश में अपराध-कर्म करने से रोका जाएगा; तथा यह स्वीकार किया है कि उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए इस प्रकार के जितने भी अपराध होंगे उन सबके लिए तत्काल पूर्ण हरजाना दिया जाएगा। इसलिए इसके बदले में, ब्रिटिश सरकार इस बात पर राजी हो गई है कि भूटान सरकार को प्रतिवर्ष पचास हजार रुपये के बराबर भत्ता देगी, उससे ज्यादा नहीं। इस भत्ता राशि का भुगतान जुंग-पेन के पद से नीचे के पदाधिकारी को नहीं किया जाएगा तथा वह इस प्रयोजन से भूटान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त होगा और इसके अतिरिक्त एतद्द्वारा हम इसके प्रति भी सहमत हैं कि भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जाय—

भूटान सरकार द्वारा सन्धि की शर्तों की पूर्ति किए जाने पर पच्चीस हजार रुपये (25,000 रुपये)।

प्रथम भुगतान के बाद आने वाली 10 जनवरी को पैंतीस हजार रुपये (35,000 रुपये)

आगामी 10 जनवरी को पैंतालीस हजार रुपये (45,000 रुपये)।

परवर्ती प्रत्येक 10 जनवरी को पचास हजार रुपये (50,000 रुपये)।

अनुच्छेद 5—यदि भूटान की ओर से दुर्व्यवहार किया गया अथवा वह अपनी प्रजा की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोकने में असफल रहेगी अथवा कि यदि वह इस सन्धि के उपबन्धों का पालन नहीं करेगी तो उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार स्वयं के इस अधिकार को सुरक्षित रखती है कि वह क्षतिपूर्ति राशि के पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान को किसी भी समय स्थगित कर देगी।

अनुच्छेद 6—ब्रिटिश सरकार एतद्द्वारा सहमत है कि भूटान सरकार यदि 1854 के सप्तम अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित रूप से विधिवत् भाग करेगी तो उन सभी भूटानी नागरिकों का अभ्यर्णन कर दिया जाएगा जिनके द्वारा ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ की गई है तथा जिन पर निम्नलिखित अपराध-कर्मों का दोषारोपण किया गया है। सन् 1854 के सप्तम अधिनियम की एक प्रतिलिपि भूटान सरकार को दे दी जाएगी। वे अपराध इस प्रकार हैं—हत्या, हत्या का प्रयत्न करना, बलात्कार, अपहरण, ध्वंसितगत् भयंकर मारपीट, अंग-भंग करना, डकैती, ठगी, लूटमार या चोरी, भवेशियों की चोरी किसी के घर में संध मारकर घुसना तथा उसमें चोरी करना, आगजनी, किसी ग्राम, घर या कस्बे में आग लगा देना, जालसाजी करना या जाली दस्तावेज तैयार करना, प्रचलित सिक्कों के जैसे ही जाली सिक्के बनाना, जानबूझ कर

छोटे या जाली सिक्के जारी करना, झूठी कसम खाना, झूठी कसम दिलाना सार्वजनिक अधिकारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा भवन तथा उपरोक्त अपराधों में से किसी भी एक अपराध में सहायक होना ।

अनुच्छेद 7—भूटान सरकार एतद्द्वारा सहमत है कि बंगाल प्रेसिडेंट गवर्नर द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के माध्यम पर विधिवत् भूमि कब्जा जाने पर वह उस किसी भी ब्रिटिश नागरिक का अभ्यर्पण कर देगी जिस पर कि पूर्वोक्त अनुच्छेद में वर्णित किसी भी अपराध का दोषारोपण किया गया है तथा जिसने भूटान सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश में शरण ली है । इसके अलावा भूटानी सरकार भूटानी नागरिकों का भी यदि उन्होंने उक्त अपराधों में से कोई सा भी अपराध ब्रिटिश भूमि पर किया है और तदुपरान्त भूटान में भाग आए हैं—अभ्यर्पण कर देगी; बशर्ते कि उनके अपराध का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए जो कि जिस जिले में अपराध घटित हुआ हो उसके स्थानीय न्यायालय को सन्तुष्ट कर सके ।

अनुच्छेद 8—भूटान सरकार एतद्द्वारा सहमति प्रकट करती है कि वह सिक्किम और कूचबिहार के राजाओं के विरुद्ध अपनी शिकायतों के तमाम कारणों को अथवा अपने विवादों को ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए सुपुर्द करेगी एवं उसके द्वारा दिए निर्णय का पालन करेगी और ब्रिटिश सरकार भी एतद्द्वारा प्रतिज्ञा करती है कि वह ऐसे तमाम विवादों और शिकायतों के बारे में पता लगा कर उन पर न्याय की अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय देगी तथा इस बात पर जोर देगी कि सिक्किम और कूचबिहार के राजा भी उस निर्णय का पालन करें ।

अनुच्छेद 9—दोनों सरकारों के बीच मुक्त व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था होगी । ब्रिटिश भू-भाग में निर्यातित की जाने वाली भूटानी वस्तुओं पर कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा और न ही भूटान सरकार भूटान में निर्यातित अथवा भूटान में से होकर गुजरने वाले ब्रिटिश माल से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल करेगी । ब्रिटिश भू-भाग में रहने वाले भूटानी नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकों के समान ही न्याय सुलभ होगा और इसी प्रकार से भूटान में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को भूटान सरकार की जनता के समान ही न्याय सुलभ होगा ।

अनुच्छेद 10—प्रस्तुत 10 अनुच्छेदों वाली यह सन्धि तारीख 11 नवम्बर 1865 को तदनुसार भूटिया वर्ष शिमलुंग के नवम् माह के 24 वें दिन को सिंचुला में की गई है । इस पर लेफ्टिनेंट कर्नल हरबर्ट घुस सी.वी.

पुनाखा की सन्धि, 1910

क्योंकि दिनांक 11 नवम्बर, 1865 तदनुसूय भूटानी वषं शिगलांग के नवम् माह के 24 वें दिन को सिचुला मे ब्रिटिश और भूटान सरकार के बीच सम्पन्न हुई सन्धि के चतुर्थ और अष्टम अनुच्छेद को संशोधित करना वांछनीय है अतः निम्नलिखित संशोधनों के प्रति एक ओर से तो सिक्किम के राजनीतिक अधिकारी श्री सी. ए. बेल सहमत हैं; उनके द्वारा सहमति इस आधार पर दी गई है कि परममान्य सर गिल्बर्ट जॉन इवियट-मुरे-किनिमोंड पी. सी., जी एम. एस. आई. ई., जी. सी. एम. जी., अर्ल आफ मिण्टो, बाइ-सराय और भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल ने उनमे सम्पूर्ण शक्तियां इसी आशय से निहित की थी। दूसरी तरफ से महामान्य सर उम्बेन वाग्बुक, के.सी. आई.ई. भूटान के महाराजा ने इसे स्वीकार किया है।

सन् 1965 की सिचुला-सन्धि के चतुर्थ अनुच्छेद मे निम्नलिखित परि-
वर्धन किया गया है :

ब्रिटिश सरकार ने तारीख 10 जनवरी, 1910 से भूटान-सरकार को बी जाने वाली वापिक भत्ता धनराशि को पचास हजार रुपये (रु 50,000) से बढ़ाकर एक लाख रुपये (रु. 1,00,000) कर दिया है।

सन् 1865 की सिचुला-सन्धि के अष्टम अनुच्छेद को संशोधित कर दिया गया है; संशोधित अनुच्छेद इस प्रकार है :

भारत भूटान सन्धि 1949 Article 2

“ब्रिटिश सरकार विश्वास दिलाती है कि वह भूटान के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अपनी ओर से भूटान सरकार यह मंजूर करती है कि वह अपने विदेश-सम्बन्धों के मामले में ब्रिटिश सरकार की सलाह से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। कूचबिहार और सिक्किम के महाराजा के साथ उत्पन्न होने पर अथवा उनके विरुद्ध शिकायत का कारण पैदा होने वाले ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए सुपुर्द किये जायेंगे।

इस तरह के विवादों का निपटारा न्यायिक अपेक्षाओं के अन-

एवं सम्बोजय देव जिम्मे तथा देमसेरेन्से दोनाई ने हुस्तासर किये हैं तथा मुहर मंकित की है । सत्यांकन एक ओर तो महामहिम वाइसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया जायेगा तथा दूसरी ओर महामान्य देवराजा और धर्मराजा द्वारा किया जाएगा एवं इस तारीख से लगाकर एक महीने के भीतर सन्धि का उनके मध्य परस्पर आदान-प्रदान किया जाएगा ।

एच० ब्रूस

सेप्टिनेंट कर्नल

प्रमुख सिविल और राजनीतिक अधिकारी

देवनागरी में,

भूटानी भाषा में,

इस सन्धि को मेरे द्वारा कलकत्ता में 29 नवम्बर, 1865 को सत्यांकित किया गया ।

दिनांक 25 जनवरी, 1866

जॉन सॉरेन्स
गवर्नर जनरल

□]

पुनाखा की सन्धि, 1910

क्योंकि दिनांक 11 नवम्बर, 1865 तदनुरूप भूटानी वर्ष शिंगलांग के नवम् माह के 24 वें दिन को सिचुला में ब्रिटिश और भूटान सरकार के बीच सम्पन्न हुई सन्धि के चतुर्थ और अष्टम अनुच्छेद को संशोधित करना वांछनीय है अतः निम्नलिखित संशोधनों के प्रति एक ओर से तो सिक्किम के राजनीतिक अधिकारी श्री सी. ए. बेल सहमत हैं; उनके द्वारा सहमति इस आधार पर दी गई है कि परममान्य सर गिल्बर्ट जॉन इलियट-मुरे-किनिमोंड पी. सी., जी एम. एस आई. ई, जी. सी. एम जी, अर्ल आफ मिंटो, बाइ-सराय और भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल ने उनमें सम्पूर्ण शक्तियाँ इसी आशय से निहित की थी। दूसरी तरफ से महामान्य सर उम्येन वाग्चुक, के सी. आई.ई. भूटान के महाराजा ने इसे स्वीकार किया है।

सन् 1965 की सिचुला-सन्धि के चतुर्थ अनुच्छेद में निम्नलिखित परि-
वर्धन किया गया है :

ब्रिटिश सरकार ने तारीख 10 जनवरी, 1910 से भूटान-सरकार को दी जाने वाली वार्षिक भत्ता धनराशि को पचास हजार रुपये (रु 50,000) से बढ़ाकर एक लाख रुपये (रु. 1,00,000) कर दिया है।

सन् 1865 की सिचुला-सन्धि के अष्टम अनुच्छेद को संशोधित कर दिया गया है; संशोधित अनुच्छेद इस प्रकार है :

भारत भूटान सन्धि 1949 Article 2

“ब्रिटिश सरकार विश्वास दिलाती है कि वह भूटान के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अपनी ओर से भूटान सरकार यह मंजूर करती है कि वह अपने विदेश-सम्बन्धों के मामले में ब्रिटिश सरकार की सलाह से मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। कूचबिहार और सिक्किम के महाराजा के साथ विवाद उत्पन्न होने पर अथवा उनके विरुद्ध शिकायत का कारण पैदा होने पर ऐसे मामले ब्रिटिश सरकार के विवाचन के लिए सुपुर्दे किये जायेंगे। ब्रिटिश सरकार इस तरह के विवादों का निपटारा न्यायिक अपेक्षाओं के अनुरूप करेगी तथा वह इस बात पर जोर देगी कि उसके निर्णयों का नामित महाराजाओं द्वारा अनुपालन किया जाय।”

पुनाखा, भूटान में इसकी चार प्रतियाँ दिनांक 8 जनवरी, 1910 तदनुरूप भूटानी धरा-पक्षी (सा-जा) वर्ष के ग्यारहवें महीने की 27वीं तारीख को तैयार की गई।

सा. एल. वेल सिविकम के
 सिविकम-स्थित राजनीतिक अधिकारी
 राजनीतिक अधिकारी की मुद्रा
 दिनांक 8 जनवरी, 1910

धर्मराजा की मुद्रा
 महामान्य भूटान-नरेश की मुद्रा
 तात्सांग लामाओं की मुद्रा
 टांगसा पेनलोप की मुद्रा
 पारो पेनलोप की मुद्रा
 जुंग ड्रोनिर की मुद्रा
 यिम्बु जोंगपेन की मुद्रा
 पुनाका जोंगपेन की मुद्रा
 बाग्डु पोटांग जोंगपेन की मुद्रा
 टाका पेनलोप की मुद्रा
 देय जिम्पोन की मुद्रा

भारत का मिन्टो वाइसराय और गवर्नर-जनरल इस सन्धि को भारत
 के वाइसराय और सपरिपद गवर्नर-जनरल ने फोर्ट विलियम नामक स्थान पर
 24 मार्च, 1910 को सत्यांकित किया था।

एस. एच. बटलर
 सचिव, विदेश-विभाग, भारत सरकार

राष्ट्रीय-सभा का संविधान सभा-बैठकों के नियम-विनियम

निम्नलिखित नियमों को आदेश के रूप में प्रसारित करते हुए महा-गरिमामय नरेश को प्रसन्नता अनुभव होती है। इन नियमों का पालन राष्ट्रीय सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है (साही सलाहकार परिपद् के सदस्यों से निर्मित)।

अपने इस सुहाने और आकर्षक देश का राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में नवोत्थान करना सभी देशवासियों का एक पवित्र कर्त्तव्य है। जब हमारा देश विकसित होगा तो हरेक जोंग और उसमें रहने वाली जनता भी सुखी और समृद्ध होगी।

हमारा संविधान शायद उतना बड़ा नहीं है जितने कि अन्य देशों के संविधान हैं। किन्तु क्योंकि जनता की जीवन-दशाओं के उत्थान और कल्याण को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्यों ने जरूरी उपायों को हाथ में लेने के प्रति अपनी सहमति प्रकट की, अतः महागरिमामय ड्रक ग्याल्पो ने कृपापूर्वक राष्ट्रीय-सभा की स्थापना की है।

कई बुद्धिजीवियों के परामर्श से हिंसी निर्णय (अपने देश की उन्नति के लिए) पर पहुँचना मदैव ही अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण है, बनिस्पत इसके कि सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा एकान्त में वह निर्णय किया जाय। ऐसा करना न सिर्फ समकालीन युग के लिए लाभदायक सिद्ध होगा अपितु इससे भावी पीढ़ियों को भी लाभ होगा, राष्ट्रीय-सभा की स्थापना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है।

राष्ट्रीय सभा द्वारा लिये गए निर्णयों के अनुसार ही देश के प्रशासन का संचालन किया जायगा। ईश्वर की अनुकम्पा और हमारे पूर्ववर्ती शासकों द्वारा उठाए गए सही कदमों के परिणामस्वरूप हम अपने देश की स्वाधीनता और राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने में सफल रहे हैं। यद्यपि स्वाधीनता रत्न का परिरक्षण करने में तो हम सफल रहे हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण हम अभी भी पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण हम बहुत अधिक उन्नति करने में असमर्थ रहे हैं।

शिक्षा में तेज प्रगति के कारण विश्व के दूसरे देशों ने तेजी के साथ उन्नति की है। वर्तमान परिस्थितियों में हमें भी स्वयं को विकसित राष्ट्रों की

समस्या स्पष्टि-जन-माना हो-डेगा। अतः हमें राष्ट्रीय विकास पर ज्यादा जोर देना चाहिए। अतः राष्ट्रीय विकास के लिए प्रयत्न करना ही हम सबका प्रमुख ध्येय-एव-केतव्य होना चाहिए।

अतः सभी सदस्यों को देश की उन्नति के लिए संस्कृति, धार्मिक विरासत और अतीत की परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए एकता और सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। हमें अपनी स्वार्थी मनोवृत्तियों को एक ओर ढकेल कर राष्ट्रीय निर्माण के कार्य के प्रति स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हमें भूतकाल की भूलों से पाठ सीखना चाहिए। उपर्युक्त निर्देशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए 18 नियम-विनियमों का राष्ट्रीय-सभा द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

नियम 1 : महागरिमामय नरेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों में से शाही सलाहकार परिषद् के सदस्य मनोनीत किये जाएंगे। बौद्ध भिक्षुओं के समूह द्वारा केन्द्रीय बौद्ध भिक्षु-संस्था में से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा तथा जन-प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किये जाएंगे।

नियम 2 : शाही सलाहकार परिषद् के सदस्यों को महा गरिमामय द्वारा परिचय-पत्र दिए जाएंगे। बौद्ध-भिक्षु-समूह के सदस्यों को केन्द्रीय भिक्षु संस्था द्वारा परिचय-पत्र जारी किए जाएंगे। जन-प्रतिनिधियों को जन-निकाय द्वारा परिचय-पत्र जारी किए जाएंगे।

नियम 3 : जो सदस्य बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रीय-सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ होंगे वे अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेज सकेंगे। अपनी अनुपस्थिति की सूचना अध्वक्ष को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

नियम 4 : भूटान विधि-ग्रन्थ ए (12) अध्याय द्वितीय के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति राष्ट्रीय सभा की सदस्यता के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे -

- (1) वह व्यक्ति जो कि भूटानी नागरिक नहीं है।
- (2) वह व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष से कम है।
- (3) वह व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से निर्योग्य (Mentally Disabled) है।

(4) दोषसिद्ध व्यक्ति (A Convict)।

(5) वह व्यक्ति जो कि कारागार की सजा भुगत चुका है।

नियम 5 : एक सदस्य अपने पद पर तीन वर्ष तक बना रहेगा; लेकिन

यदि सदस्य को बदलना आवश्यक हो जाए तो अध्यक्ष को आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिए।

नियम 6 : यदि कोई सदस्य के रूप में काम करने के अयोग्य पाया जाए तो राष्ट्रीय-सभा उसे पदच्युत करने के पक्ष में निर्णय ले सकती है।

नियम 7 : राष्ट्रीय सभा की सदस्य संख्या हर पाँच साल में एक बार स्वयं राष्ट्रीय सभा निर्धारित करेगी। जो संख्या निश्चित की जाएगी, वह स्थिर होगी, उसे कम ज्यादा नहीं किया जाएगा।

नियम 8 : प्रति तीन वर्ष के बाद राष्ट्रीय सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष रुग्णता अथवा किसी अन्य कारण से उपस्थित होने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सभा के पास दूसरे अध्यक्ष को निर्वाचित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नियम 9 : अध्यक्ष को सभा भवन में उचित व्यवस्था बनाए रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कोई भी सदस्य उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं कर सकेगा।

नियम 10 : अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय-सभा के अधिवेशनों की तिथि निर्धारित की जाएगी। वर्ष में दो अधिवेशन होंगे। किन्तु संकटकाल और असाधारण परिस्थितियों में महागरिमामय नरेश के राजसी आदेश पर अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है।

नियम 11 : प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह राष्ट्रीय-सभा में अपने विचारों को व्यक्त कर सके। कोई भी नियम अथवा कानून सदस्य के अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

नियम 12 : राष्ट्रीय-सभा में प्रत्येक सदस्य की समान स्थिति होगी और सभी सदस्य किसी भी विषय पर तब तक बहस कर सकेंगे जब तक कि वे किसी उपयुक्त निर्णय पर नहीं पहुँच जाते।

नियम 13 : किसी भी सदस्य द्वारा सभा-भवन में कोई भी इस तरह की प्रकृति का विषय नहीं उठाया जा सकेगा जो कि उसके निजी स्वार्थों या रिश्तेदारों के स्वार्थों की पूर्ति करने की इच्छा से प्रेरित हो। ऐसे मामलों पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

नियम 14 : सदस्यगण राष्ट्रीय-सभा द्वारा लिए गए किसी निर्णय का न तो खण्डन कर सकते हैं और न ही उस निर्णय से वैयक्तिक लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई सदस्य निर्णय में दोष खोजने की कोशिश करेगा, झगड़ा शुरू

करेंगे। अथवा भामले को न्यायालय में घसीटेगा तो उसे धोपसिंद अपराधी घोषित कर न केवल सदस्यता से बल्कि समाज और अन्ततोगत्वा देश से भी निष्काशित कर दिया जाएगा।

नियम 15 : यदि कोई सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहता है जिसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति के कल्याण से हो है, किन्तु उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय सभा के किसी सदस्य के कल्याण से नहीं है तो वह सदस्य सभा में आ सकता है और अध्यक्ष को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दे सकता है। यदि अध्यक्ष चाहे तो उस पर विचार करने के बारे में अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

नियम 16 : किसी भी सदस्य द्वारा बाहरी व्यक्ति के समक्ष सभा-सदन में हुए गोपनीय विचार विमर्श को प्रकट नहीं किया जायेगा।

नियम 17 : राष्ट्रीय-सभा की बैठकों की समस्त कार्यवाही (Proceedings) चाहे वह विस्तृत हो अथवा संक्षिप्त एवं मासूली, दो तिहाई बहुमत से पारित की जाएंगी।

नियम 18 : राष्ट्रीय-सभा के समस्त निर्णय स्वयं राष्ट्रीय-सभा अथवा राजा द्वारा बदले जा सकते हैं। इन निर्णयों को किसी अन्य द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता।

भारत-भूटान सन्धि, 1949

एक ओर से तो भारत-सरकार तथा दूसरी ओर से महामान्य ब्रिटिश ग्याल्पो की सरकार दोनों ही पक्ष इस इच्छा से प्रेरित होकर कि भारत में ब्रिटिश-प्राधिकार की समाप्ति से जो स्थिति पैदा हुई है उसे मित्रतापूर्ण वास्तविक और ठिकाऊ आधार पर विनियमित किया जाए एवं साथ ही अपनी अपनी जतना के कल्याण हेतु बेहद जरूरी मंत्री-सम्बन्धों और पड़ोस-धर्म के सम्बन्धों को प्रोत्साहित और विकसित किया जाए निम्नलिखित सन्धि करने की इत्सुकल्प है और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने-अपने प्रतिनिधि नामित किये हैं, अर्थात् भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व श्री हरिस्वर दयाल करेंगे जिन्हें कि भारत-सरकार की ओर से कथित सन्धि पर सहमत होने के पूर्ण अधिकार दिये गए हैं तथा भूटान-लरेण ब्रिटिश ग्याल्पो की सरकार का प्रतिनिधित्व श्री देब जिम्पोन सोनम सोम्बी दोर्जी, यांग-सोप सोनम, छो-जिम-योण्डुप, दिनजिम टाण्डिन, हा-डांग जिम्पी एवं पाल्देन दोर्जी करेंगे जिन्हें कि भूटान सरकार की ओर से उक्त पर सहमत होने के पूर्ण अधिकार प्रदान किये गए हैं—

अनुच्छेद 1—भारत सरकार और भूटान सरकार के मध्य चिरस्थायी शान्ति और मित्रता रहेगी ।

(पुनाखा संधि 1910-Article 2)

अनुच्छेद 2—भारत सरकार यह वचन देती है कि भूटान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी । अपनी ओर से भूटान सरकार भी यह स्वीकार करती है कि वह अपने विदेश कार्य के संचालन में भारत सरकार के परामर्श से मार्गदर्शन ग्रहण करेगी ।

अनुच्छेद 3—सिन्धुला सन्धि के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत भूटान सरकार के लिए स्वीकृत मुआवजा तथा उसमें 8 जनवरी, 1910 की सन्धि द्वारा की गई वृद्धि एवं 1942 में स्वीकृत की गई एक लाख रुपयों के बराबर की वार्षिक आर्थिक-सहायता (Subsidy) के स्थान पर भारत सरकार भूटान सरकार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया देना मंजूर करती है । इसके अतिरिक्त एतद्वारा यह भी स्वीकार करती है कि उक्त वार्षिक भुगतान हर साल 10 जनवरी को किया जाएगा । यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक सन्धि लागू रहेगी तथा इसकी शर्तों का यथोचित अनुपालन होता रहेगा ।

अनुच्छेद 4—इसके अतिरिक्त कथित सरकारों के बीच की वर्तमान अविच्छिन्न मित्रता को व्यक्त और चिह्नित करने के लिए भारत सरकार इस

सन्धि पर हस्ताक्षर होने के एक वर्ष के भीतर भूटान सरकार को देवगिरि नाम के प्रसिद्ध क्षेत्र में लगभग 32 वर्गमील भू-भाग हस्तान्तरित कर देगी। भूटान सरकार को इस प्रकार से सौटाये जाने वाले क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए भारत सरकार एक सहाय अधिकारी अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

अनुच्छेद 5—भारत सरकार और भूटान सरकार के प्रदेशों के बीच पहले के समान ही मुक्त व्यापार और वाणिज्य होता रहेगा। भारत सरकार इसके प्रति भी सहमत है कि वह भूटान सरकार को अपनी उपज के लिए, भू अथवा जलमार्गों द्वारा सारे भारतीय भू भाग में परिवहन की हरेक सुविधा प्रदान करेगी, जिनमें ऐसे वन-भागों का उपयोग भी शामिल है जिनको समय-समय पर किये गए समझौतों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 6—भारत सरकार इसके लिए भी सहमत है कि भूटान सरकार, भारत सरकार के सहयोग और अनुमोदन से अपने लिए जो भी शस्त्र, गोला-बारूद मशीनरी, युद्ध-सामग्री और युद्ध-भण्डार जरूरी होगा अथवा जो भूटान की मजबूती और कल्याण के लिए वांछित होगा, उसका भारत से अथवा भारत में से होकर आयात करने को स्वतन्त्र होगी और यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक भारत सरकार को यह सतोष अनुभव होता रहेगा कि भूटान सरकार के द्वारादे मंत्रीपूर्ण हैं और इस तरह के आयात से भारत को कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर भूटान सरकार यह वचन देती है कि इस प्रकार के शस्त्रों, गोला-बारूद इत्यादि का न तो भूटान सरकार द्वारा और न ही निजी व्यक्तियों द्वारा भूटान की सीमा के पार निर्यात किया जाएगा।

अनुच्छेद 7—भारत और भूटान की सरकार इस बात के लिए सहमत है कि भारतीय भू-भाग में निवास कर रहे भूटानी नागरिकों को भारतीय नागरिकों के समान ही न्याय सुनम होगा और इसी प्रकार से भूटान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भूटान सरकार के नागरिकों के समान ही न्याय प्राप्त होगा।

अनुच्छेद 8—भूटान सरकार द्वारा लिखित में विधिवत मांग किये जाने पर भारत सरकार भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, 1903 (जिसकी एक प्रति भूटान सरकार को मुलभ कराई जाएगी) के उपबन्धों के अनुसार उन समस्त भूटानी नागरिकों के अभ्यर्पण की कार्यवाही करेगी जिन पर कथित अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का अभियोग लगाया गया हो तथा जिनके द्वारा भारतीय भू-भाग में शरण ली गई हो।

(2) भारत सरकार द्वारा विधिवत अधिग्रहण (Requisition) किये जाने पर अथवा भारत सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर भूटान-सरकार उन भारतीय नागरिकों या उन विदेशी-शक्तियों के नागरिकों का अभ्यर्पण करेगी जिनका प्रत्यर्पण भारत सरकार द्वारा कथित विदेशी शक्ति के साथ किये गए समझौते अथवा प्रबन्ध के अनुशीलन में आवश्यक होगा तथा जिन पर कि 1903 के 15वें अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का अभियोग लगाया गया है और भूटान सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रदेश में शरण ली है, और इसके अतिरिक्त भूटान सरकार उन भूटानी नागरिकों का भी अभ्यर्पण करेगी जो भारतीय भूमि पर कोई सा भी उल्लिखित जुर्म करने के उपरान्त भूटान में भाग जाएँगे बशर्ते कि उनके जुर्म के सम्बन्ध में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए जो कि उस स्थानीय न्यायालय को सन्तुष्ट कर सके जिसमें कि सम्भवतः अपराध किया गया था ।

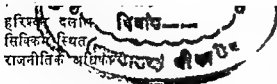
अनुच्छेद 9—इस सन्धि को लागू करने और निर्वाचन के विषय में जो भी मतभेद या विवाद पैदा होंगे वे सर्वप्रथम बातचीत द्वारा सुलझाए जाएँगे । यदि बातचीत आरम्भ होने के तीन माह के भीतर कोई समझौता नहीं हो सकेगा तो मामले को तीन विवाचकों के हाथों में विवाचन हेतु सौंपा जाएगा । ये विवाचक भारत या भूटान के राष्ट्रिय होंगे और उन्हें निम्नानुसार चुना जाएगा—

- (1) एक व्यक्ति का मनोनयन भारत-सरकार द्वारा होगा ।
- (2) एक व्यक्ति भूटान सरकार द्वारा मनोनीत होगा ।
- (3) भारत के संघीय न्यायालय या उच्च-न्यायालय का एक न्यायाधीश जो कि भूटान सरकार द्वारा चुना जाएगा, इस अधिकरण (Tribunal) का अध्यक्ष होगा ।

इस अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों द्वारा उस निर्णय को अविलम्ब अमल में लाया जाएगा ।

अनुच्छेद 10—यह सन्धि चिरकाल तक लागू रहेगी जब तक इसे परस्पर सहमति द्वारा संशोधित अथवा समाप्त न कर दिया जाए ।

इस सन्धि की दो प्रतियाँ आज 8 अगस्त, 1949 को तदनुसार भूटानी-वर्ष पृथ्वी-वृषभ (Earth-Bull) के छठे माह की 15 तारीख को दार्जिलिंग में तैयार की गई ।



देव जिम्पोन सोनम
तोन्गी दोर्जी
यांग-सोप सोनम
छो जिम थोण्डुप
रिनजिम टाण्डिन
हा-डांग जिमी
पाल्देन दोर्जी

अनुसमर्थन सेतपत्र (Instruments of Ratification)

8 अगस्त, 1949 को मित्रता और प्रतिवेशी-धर्म (Neighbourliness) के सम्बन्धों का पोषण करने एवं उन सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित जिस सन्धि पर दार्जिलिंग में भारत सरकार और परम महामान्य भूटान के महाराजा झुक ग्याल्पो की सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये, वह सन्धि शब्दशः निम्नानुसार है—

भारत सरकार पूर्वोक्त सन्धि पर विचार कर उसकी पुष्टि और उसका अनुसमर्थन करती है और उसमें अन्तर्विष्ट सभी अनुबन्धों को निष्ठापूर्वक पूरा करने और कार्यान्वित करने का वचन देती है।

जिसकी साक्षी के तौर पर यह अनुसमर्थन-लेखापत्र भारत के गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया जाता है।

22 सितम्बर, 1949 को नई दिल्ली में यह विधि सम्पन्न हुई।

सी. राजगोपालाचार्य
भारत के गवर्नर जनरल

8 अगस्त 1949 को मित्रता और प्रतिवेशी-धर्म के सम्बन्धों का पोषण करने और उन सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित जिस सन्धि पर दार्जिलिंग में मेरी सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे, वह सन्धि शब्दशः निम्नानुसार है—

मेरी सरकार ने पूर्वोक्त सन्धि पर विचार किया एवं वह एतद्द्वारा उस सन्धि की पुष्टि और उसका अनुसमर्थन करती है और उसके अन्तर्विष्ट सभी अनुबन्धों को पूरा करने और कार्यान्वित करने का वचन देती है।

जिसकी साक्षी के तौर पर मैंने इस अनुसमर्थन-लेखापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं तथा इस पर मेरी मुद्रा अंकित है।

यह विधि 15 सितम्बर, 1949 को टोंगा में सम्पन्न हुई।

जे. वांग्चुक
झुक ग्याल्पो

ग्रन्थ-सूची

1. 'भूटान एण्ड सिक्किम' भारत की सूचना-सेवा, राजनीतिक-कार्यालय, गंगटोक, सिक्किम द्वारा प्रकाशित (1967)।
2. कोएलो वी०एच०, सिक्किम एण्ड भूटान, मांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिपद् द्वारा प्रकाशित (1967)।
3. ईडन एश्ले, 'रिपोर्ट ऑन दि स्टेट ऑफ भूटान' (1865)।
4. "फोरेन पोलिसी ऑफ इण्डिया, टेक्स्ट ऑफ डोकुमेन्ट्स (1947-1959)" द्वितीय संस्करण, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. जवाहरलाल नेहरू, इण्डियाज फोरेन पोलिसी, सिलेक्टड स्पीचज, सितम्बर, 1948 से अप्रैल 1961 तक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
6. करन प्रद्युम्न पी०, एण्ड जेकिन्स, विलियम एम० जूनियर, "दि हिमालियन किंगडम्स : भूटान, सिक्किम एण्ड नेपाल" केन्दुकी विश्वविद्यालय प्रेस, लेक्सिंगटन (1967)।
7. करन, प्रद्युम्न पी०, "भूटान-ए फिजिकल एण्ड कल्चरल ज्योग्राफी", केन्दुकी विश्वविद्यालय प्रेस, लेक्सिंगटन (1947)।
8. 'कुएन्सल' भूटान की शाही सरकार का अधिकृत साप्ताहिक बुलेटिन ग्रन्थ 6. अंक 12, 14 नवम्बर (1971 से 1988 तक)।
9. भारत और चीन सरकार के मध्य हुए पत्रों और ज्ञापनों का आदान-प्रदान सितम्बर-नवम्बर 1959-वाइट पेपर संख्या 2, विदेश मंत्रालय (1959)।
10. लोकसभा डिबेट्स, 1960(66); कोल. 2711।
11. प्राइम मिनिस्टर ऑन माइनो इण्डियन रिनेशन्स ग्रन्थ 1, 'इन पार्लियामेंट' विदेश प्रचार डिवीजन, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
12. राहुल, राम, दि हिमालयन बोर्डर लैंड, विकास पब्लिकेशन्स (196५)।
13. सर बेनेगल राय, "इण्डियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन दि मेकिंग" (1960)।
14. रेनो डेविडफील्ड, भूटान एण्ड दि स्टोरी ऑफ दि दोअर बार" एल्ब-मार्कल स्ट्रीट लन्दन 1866 में सर्वप्रथम जॉन मुरे द्वारा प्रकाशित, बिबलिओयेका हिमालयिका द्वारा पुनर्मुद्रित, (सन् 1970)।
15. रोनाल्डशे, अर्ले ऑफ, "लैंड्स ऑफ दि थण्डर बोल्ट" (1923)।
16. सेण्डबर्ग जी०, "भूटान-दि अननोन इण्डियन स्टेट" (1897)।
17. डॉ०एस०एन०सेन, 'प्राचीन बंगला पत्रिका संकलन' 1942 (कलकत्ता)।

18. मनजीतसिंह 'हिमालयन आर्ट', यूनेस्को आर्ट्स बुक्स, न्यूयॉर्क ग्राफिक सोसाइटी लिमिटेड द्वारा सन् 1868 में प्रकाशित ।
19. ट्रेवेलियन जी० एम० ब्रिटिश हिस्टरी इन दि नाइन्टीन्थ सेन्चुरी (1782-190.) ।
20. ट्रेवेलियन जी० एम०, "हिस्टरी ऑफ इंग्लैंड" (1934) ।
21. "शोगदू-दि नेशनल असेम्बली ऑफ भूटान", भारत की सूचना-सेवा द्वारा प्रकाशित राजनीतिक कार्यालय, गंगटोक सिविकम (1969) ।
22. कप्तान मेमूअल टर्नर, "एकाउण्ट ऑफ एन एम्बेसी टु दि कोर्ट ऑफ दि लेग् लामा इन टिबेट" (1800) ।
23. यू०एन०डोक०ए/पी वी./1934 ऑफ 21 9. 71.
24. यू०एन०डोक०आर.इ.एस/2751 (xxvi) ऑफ 24.9.71.
25. यू०एन०डोक०एस०/10109 ऑफ 9.2.71.
26. यू०एन०डोक०एस/पी.वी. 1566 ऑफ 10.2.71.
27. वाइट जॉन क्लॉडे, "सिविकम एण्ड भूटान" भारत कार्यालय के प्रकाशक एडवर्ड अनौलड द्वारा प्रकाशित (1909) ।

लेखक के बारे में

डॉ० प्रार. सी. मिश्रा—एम.ए (अंग्रेजी) करने के बाद डॉ. मिश्रा ने 8 वर्ष विभिन्न संस्थाओं में आंग्ल भाषा का अध्यापन किया। तत्पश्चात् राजनीति विज्ञान में एम.ए. किया और उसी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इस समय डॉ. मिश्रा दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र में कार्यरत हैं। आप शोध कार्य के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से दो बार भूटान व सिक्किम रह आये हैं। डॉ. मिश्रा की पी.एच.डी. की डिग्री भी भूटान के विषय पर प्रदान की गई। आपकी विशेषज्ञता पर्वतीय राज्यों (नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत) पर है और उसका गहन अध्ययन निरन्तर करते रहता है।

आपकी एक शोध पुस्तक 'सिक्किम' पर प्रकाशित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त डॉ. मिश्रा के लगभग 20 शोधपत्र महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छप चुके हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की 'समीनार' में कई स्थानों पर शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। हाल ही में डॉ. मिश्रा ने एक शोध प्रबन्ध 'भूटान-चीन सम्बन्ध' को पूर्ण किया है और आजकल 'भूटान का संविधानिक विकास' पर गहन कार्य कर रहे हैं। डॉ. मिश्रा, 'साउथ एशियन रिपोर्टर' पत्रिका के सम्पादक भी हैं।

डॉ. मिश्रा के निर्देशन में दो छात्र भूटान के विभिन्न विषयों पर एम. फिल-डिग्री हेतु सशु-शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत कर चुके हैं।

